

**“CHANGES IN DIRECTION OF INDIA’S
FOREIGN TRADE DURING FIFTY YEARS
OF INDEPENDENCE”**

**आजादी के पचास वर्षों के दौरान भारतीय
विदेशी व्यापार में दिशा परिवर्तन**

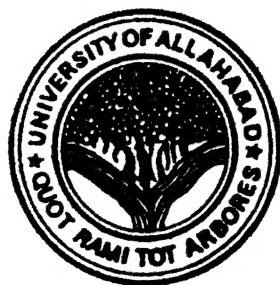
डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध

शोध-निर्देशक

डॉ० ए० ए० सिद्दीकी
उपाचार्य

प्रस्तुतकर्ता

सत्येन्द्र कुमार सिंह



**वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद**

2002

विश्व की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन देशों को हम आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं उनका आर्थिक विकास भी विदेशी व्यापार के द्वारा ही सम्भव हो पाया है। आज के इस विशिष्टीकरण के युग में कोई भी राष्ट्र स्वयं अपने ससाधनों से अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे धनी देश को भी अनेक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मुख्य कारण अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन की क्रियाएँ हैं। इस सम्बन्ध में "एडम स्मिथ" ने ठीक ही लिखा है "प्रत्येक समझदार व्यक्ति की यह मान्यता है कि वह कोई भी ऐसी वस्तु घर पर नहीं बनावे जिसे वह बाजार से सस्ता खरीद सकता है"। एक देश को दूसरे देश के ऊपर कुछ विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में प्राप्त प्राकृतिक सुविधाएँ कभी-कभी इतनी अधिक होती हैं कि यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि उसके उत्पादन के लिए किसी अन्य का संघर्ष करना व्यर्थ है।

भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुआयामी प्रयोजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रधान विशेषता आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। यहाँ औद्योगिक विकास यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद काफी हुआ है, परन्तु वृद्धि का दर और उसका प्रभाव अपर्याप्त है। औद्योगिक विकास कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित है कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योग आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। वर्तमान में असन्तुलन बना हुआ है। इसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर और भूमि सुधार का अल्प क्रियान्वयन है। यदि विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगाह डाले तो इसकी भूमिका उत्साहवर्धक साबित होती है।

यद्यपि एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में भारत का भरभूर आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ है, ऐसे में किसी भी देश के बहुमुखी विकास में इतिहास के अनुशीलन का काफी महत्व होता है और उससे भूल सुधार एवं और बेहतर करने का मौका मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य प्रस्तुत है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न नियमों के अनुशीलन के पश्चात् भारत के सदर्भ में उसकी विशिष्टताओं को दृष्टिगत करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उसे अपने कृषि क्षेत्र के विकास सम्भाव्यता की ओर तीव्र गति से बढ़ने के पश्चात् ही व्यापार की

सरचना या निर्यात की सरचना सीमा ओर दिशा मे यथोचित और द्रुतगति से विस्तार किया जा सकेगा, परन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि मात्र कृषिगत निवेश और विकास से ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेगे। यह सही है कि निर्यात की सम्भावना कृषि क्षेत्र मे ज्यादा है, परन्तु इस सन्दर्भ मे व्यापार की शर्त प्रायः प्रतिकूल ही रहती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा निर्यात के बावजूद भी निर्यात मूल्य कम ही रहता है, जबकि औद्योगिक उत्पादो के सन्दर्भ मे इसके विपरीत स्थिति होती है। इसलिए जरूरत एक सन्तुलित व्यापार और विकास नीति की होती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था मे व्यापार बढ़ाने की सम्भावना बहुत ज्यादा हो गयी है। जरूरत है तो दृढसंकल्प शक्ति, त्वरित कार्यवाही, प्रशासनिक गतिशीलता, प्रोत्साहन मूलक नीति और सही विषय की ओर दिशा तलाशने की। जबकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे है। क्षेत्रीयता का स्थान सकृचित हो रहा है। नये-नये आर्थिक संगठन बन रहे है। सबका उद्देश्य अपने-अपने व्यापारिक नीति का प्रयोग अधिकतम लाभ उठाने का है, तो इस परिस्थिति मे भारत भी अपने पड़ोसी देशो तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर व्यापारिक गतिशीलता बढ़ाते हुए बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक ससाधन और तकनीक प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह सही है कि अन्ततः इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमो के लिए आन्तरिक ससाधनो पर ही निर्भर रहना पडता है, फिर भी ससाधनो की कमी की वजह से अन्य देशो से मदद लेना ही पड जाता है। आधुनिक युग मे भारतीय अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी के पश्चात् इसमे होने वाले परिवर्तनो को दृष्टिगत करते हुए, प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की पूर्णता मे विश्वविद्यालय की जनरल लाइब्रेरी, अर्थशास्त्र की विभागीय लाइब्रेरी, लोकसभा, नई दिल्ली की लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं वहाँ के अधिकारियो एवं कर्मचारियो का हृदय से आभारी हूँ।

शोध प्रबन्ध के निर्देशक, डॉ० ए०ए० सिद्दीकी ने अपनी अस्वस्थता, पारिवारिक समस्याओ एवं अत्यन्त व्यस्तता के बावजूद समय-समय पर मार्गदर्शन किया। यह शोध प्रबन्ध परम श्रद्धेय गुरु प्रवर के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं उनके प्रति आभार किन शब्दो मे व्यक्त करूँ। कबीर दास जी ने कहा है कि — क्या दू गुरु सतोषिये, हौंस रही मनमाहि ।

चूँकि विषय बिल्कुल समसामयिक है, अतः उस पर कार्य करने का प्रोत्साहन देने वालों में मेरे निर्देशक के अतिरिक्त परम पूज्य डॉ० ब्रह्मानन्द सिंह, उपाचार्य, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का है। मैं उनको कैसे आभार व्यक्त करूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं हैं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ वह सब कुछ इन्हीं के सहयोग से सम्भव हो सका है। इन्होंने ही मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तथा यदा-कदा की गई उनसे उक्त विषय सम्बन्धी बातचीत ने शोध कार्य में मेरी काफी सहायता की।

मैं वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन सभी गुरुजनों के प्रति, विशेष रूप से अपने विभागाध्यक्ष प्रो० के०एम० शर्मा तथा सकायाध्यक्ष प्रो० पी०एन० महरोत्रा, प्रो० जगदीश प्रकाश, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं पूर्व कार्यवाहक कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रो० एस० ए० अन्सारी, प्रो० पी०सी० शर्मा, प्रो० एस०पी० सिंह, डॉ० जे०एन० मिश्र, डॉ० जे०के० जैन, डॉ० एच०के० सिंह, डॉ० आर०एस० सिंह के प्रति अपना हार्दिक अभिवादन एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनका आशीर्वाद एवं सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होता रहा है।

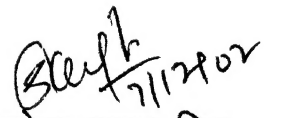
प्राक्कथन का समापन करने से पूर्व मैं अपने पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री जगबहादुर सिंह को सादर नमन करता हूँ जिनका विराट व्यक्तित्व मुझे हमेशा सघर्षरत रहने की प्रेरणा देता रहा है, मेरी ममतामयी माँ श्रीमती दुलारी देवी का स्नेह एवं आशीर्वाद ही है जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा है। अपने दोनों अग्रजों के विषम परिस्थितियों में भी सघर्षरत रहने की प्रेरणा, मुझे इस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है, परन्तु आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक पहुँचाने में सर्वाधिक योगदान मेरे चाचा श्री भानु प्रताप सिंह एवं चाची स्व० श्रीमती गोदावरी देवी का है। बचपन से पिता जी के स्वर्गवास के पश्चात् इनके लालन-पालन ने ही मुझे इस लायक बनाया और इन्हीं के कन्धों पर बैठकर घुमते हुए, मैं यहाँ तक पहुँचा। निराशा एवं सकट की घड़ी में दीदी श्रीमती सुमति सिंह के योगदान और सहयोग से ही शोध पूर्णता को प्राप्त किया। शोध कार्य की पूर्णता हेतु मेरे श्वसुर श्री राजबहादुर सिंह का जिन्होंने मेरी अधिकांश जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया, का महत्वपूर्ण योगदान है, मैं इनका भी अभारी हूँ। प्रो० शिव शंकर वर्मा, आचार्य, भूगोल विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का भी विशेष रूप से अभारी हूँ जिनकी प्रेरणा से यह शोध प्रबन्ध अल्प समय में पूरा हुआ।

पत्नी श्रीमती पूनम सिंह ने इस गुरुत्तर कार्य को सम्पादित करने में पूर्ण सहयोग दिया, जो मेरे दो पुत्रों कुमार पुनतेश व कुमार आदित्य के साथ रहकर उनका विधिवत पालन-पोषण, अपनी पढायी करते हुए मुझे घरेलू समस्याओं की भनक तक नहीं लगने दी। इसके अतिरिक्त अपने छोटे भाई श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह एवं दिनेश प्रताप राव का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध की पूर्णता में पुनर्लेखन का कार्य किया।

श्री अशोक कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर एवं प्राचार्य श्री शिवदत्त नारायण सिंह के साथ विद्यालय के अपने अन्य सहयोगी अध्यापक श्री हरिबल्लभ सिंह, श्री कमलेश प्रताप सिंह, श्री शिवनाथ सिंह, श्री उमेश उपाध्याय, श्री वीरेन्द्र शर्मा श्री जय कृष्ण सिंह व श्री नागेन्द्र उपाध्याय व मित्रगण श्री मनोज कुमार द्विवेदी, श्री राज कुमार द्विवेदी, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, सर्वेश सिंह का भी सहृदय आभारी हूँ।

अन्त में मैं श्री महेन्द्र प्रसाद निराला, कनिष्ठ आशुलिपिक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद व श्री देवेन्द्र कुमार, को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शोध प्रबन्ध के टंकण का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया। मैं उन सभी सस्थाओं, पुस्तकालयों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शोधकर्ता को सहायता प्रदान करके शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

दिसम्बर — 2002


सत्येन्द्र कुमार सिंह

विषय—सूची

	पृष्ठ	सख्या
प्राक्कथन	I	- IV
तालिका सूची	VI	- VII
अध्याय — 1		
भूमिका	1	— 16
अध्याय — 2		
आजादी के समय विदेशी व्यापार की स्थिति	17	— 36
अध्याय — 3		
विभिन्न आयात—निर्यात नीतियाँ एवं हमारा विदेशी व्यापार	37	— 101
अध्याय — 4		
विदेशी व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं की स्थापना	102	— 137
अध्याय — 5		
क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता एवं विदेशी व्यापार	138	— 217
अध्याय — 6		
स्वतन्त्रता के पचास वर्षों के दौरान हमारा विदेशी व्यापार	218	— 289
तथा हाल के उदारीकरण कार्यक्रम एवं उनका प्रभाव		
अध्याय — 7		
निष्कर्ष एवं सुझाव	290	— 305
संदर्भ ग्रंथ	306	— 314

तालिका सूची

क्र०स०	तालिका—स०	शीर्षक	पृ०स०
1	2 1	आजादी के पूर्व विदेशी व्यापार की सरचना	21
2	2 2	आजादी के समय भारत का विदेशी व्यापार	22
3	2 3	आजादी के समय भारतीय निर्यातो का ढँचा	23
4	2 4	आजादी के समय भारतीय आयातो का ढँचा	25
5	2 5	प्रथम योजना काल में भारत के प्रमुख आयात	28
6	2 6	प्रथम योजना काल में भारत के प्रमुख निर्यात	29—30
7	2 7	आजादी के समय प्रमुख देशों से होने वाले भारत के आयात	31
8	2 8	आजादी के समय प्रमुख देशों से होने वाले भारत के निर्यात	32
9	2 9	भारत का व्यापार शेष	33
10	2 10	आजादी के समय भारत का विश्व व्यापार में भाग	35
11	5 1	दक्षेस शिखर सम्मेलन कब और कहाँ	173
12	5 2	जी—15 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ	187
13	5 3	विश्व के प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक गुट	191—195
14	5 4	विश्व व्यापार संगठन के मन्त्रियस्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ	196

15	5 5	यूरो की एक इकाई का विभिन्न मुद्राओं में मूल्य	212
16	5 6	ऐपेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ	214
17	6 1	आजादी के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार	219—220
18	6 2	आजादी के प्रथम दशक में विदेशी व्यापार	222
19	6 3	साठ के दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति	223
20	6 4	सत्तर के दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति	225
21	6 5	अस्सी के दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति	226
22	6 6	नब्बे के दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति	229
23	6 7	निर्यात—आयात की मुख्य वस्तुएँ	231—234
24	6 8	भारतीय आयातों की संरचना	238
25	6 9	तीव्रता से बढ़ने वाली आयात वस्तुएँ	239—240
26	6 10	भारतीय निर्यातों की संरचना	245
27	6 11	तीव्रता से बढ़ने वाली निर्यात वस्तुएँ	247
28	6 12	भारत के आयातों पर टैरिफ भिन्न बाधाओं की किस्में	257
29	6 13	भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों का निर्यात	264—265
30	6 14	कृषि आयात	271
31	6 15	आयात व्यापार की दिशा	275—276
32	6 16	निर्यात व्यापार की दिशा	281—282

अध्याय-1

भूमिका

अध्याय – 1

भूमिका

विदेशी व्यापार का महत्व आज के युग में सभी राष्ट्रों के लिए होता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, विकासशील अथवा अविकसित। प्रत्येक देश कुछ विशेष भौतिक एवं मानवीय ससाधनों से सम्पन्न होता है, और वह कुछ ही वस्तुएँ अच्छी व सस्ती उत्पादित कर सकता है। उन वस्तुओं का वह प्रचुर मात्रा में उत्पादन करके विदेशों में बेच देता है और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ आयात कर लेता है, इससे दोनों देशों को लाभ होता है और वे एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। इससे विश्व बन्धुत्व की भावना एवं सहयोग को बल मिलता है। चूँकि हमारा देश विकासशील राष्ट्र है और एक अल्प विकसित राष्ट्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत ही अधिक होता है। उनके सम्मुख विद्यमान निर्धनता के दुश्चक्र को तोड़ने हेतु पूँजी निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति व आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में एक महत्वपूर्ण श्रोत के रूप में उसके विदेशी व्यापार उल्लेखनीय भूमिका अदा कर सकते हैं। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ एक चिन्ता का विषय हैं, इस स्थिति से उबरने के लिए विश्व व्यापार में भारत का प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है, ताकि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

विदेशी व्यापार की आवश्यकता :-

वर्तमान समय में विश्व की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन देशों को हम आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं उनका आर्थिक विकास भी विदेशी व्यापार के द्वारा ही सम्भव हो पाया है। आज के इस विशिष्टीकरण के युग में कोई भी राष्ट्र स्वयं अपने साधनों से अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे धनी देशों को भी अनेक वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मुख्य कारण अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन की क्रियाएँ हैं। विशिष्टीकरण से तात्पर्य है कि प्रत्येक देश उसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए उसके प्राकृतिक साधन, पूँजी तथा श्रम आदि बातें दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छी हैं, अर्थात् जिनकी उत्पादन लागत निम्नतम होती है। इस प्रकार कम लागत वाली वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करके

उसका निर्यात करता है एव उन वस्तुओं का आयात करता है जिनका उत्पादन देश में महंगा पड़ता है। इस सम्बन्ध में "एडम स्मिथ" ने ठीक ही लिखा है "प्रत्येक समझदार व्यक्ति की यह मान्यता है कि वह कोई भी ऐसी वस्तु घर पर नहीं बनावे जिसे वह बाजार से सस्ता खरीद सकता है।" एक देश को दूसरे देश के ऊपर कुछ विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में प्राप्त प्राकृतिक सुविधाएँ कभी-कभी इतनी ज्यादा होती हैं कि यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि उसके उत्पादन के लिए किसी अन्य का संघर्ष करना व्यर्थ है। उदाहरणार्थ खाद डालकर तैयार की गयी भूमि तथा कृत्रिम गर्म दीवारों के प्रयोग से स्काटलैण्ड में अच्छी किस्म का अंगूर पैदा किया जा सकता है और उसकी बहुत अच्छी शराब बनायी जा सकती है। किन्तु विदेश से आयात की गयी उतनी ही अच्छी मदिरा पर करीब तीस गुना व्यय होगा। ऐसी स्थिति में क्या यह तर्क सगत होगा कि फ्रांस में भी बनी हुई मदिरा तथा स्पेन की बनी हुई शराब को स्काटलैण्ड में बनने के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से समस्त विदेशी शराब के आयात पर रोक लगा दी जाय? जब तक एक देश को वे सुविधाएँ प्राप्त हैं और दूसरा देश उन्हें चाहता है तो दूसरे प्रकार के देश के लिए स्वयं बनाने की अपेक्षा प्रथम प्रकार के देश से आयात करना हमेशा लाभप्रद होगा। यह एक अर्जित सुविधा है जो एक शिल्पी को अपने पड़ोसी, जो अन्य व्यवसाय करता है के ऊपर प्राप्त है। फिर भी दोनों के लिए यह लाभप्रद होगा कि वे उन वस्तुओं को खरीदे जिसका सम्बन्ध उनके व्यवसाय से नहीं है।

विदेशी व्यापार अधिक मनुष्यों को जीने की अनुमति देता है, विभिन्न रुचियों को प्रदान करके जनता को उच्च जीवन स्तर का आनन्द देता है, जो शायद उसकी अनुपस्थिति में सम्भव नहीं होता। इस प्रकार विदेशी व्यापार से सभी उपभोक्ताओं को अच्छी एवं सस्ती वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं और विदेशी व्यापार स्वतन्त्र प्रतियोगिता को जन्म देता है तथा एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति से उपभोक्ता के शोषण की रक्षा करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता का एक पहलू यह भी है कि वह देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करने में भी सहायक होता है। क्योंकि प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में अपने साधनों को लगाता है जिनमें उसका तुलनात्मक लाभ अधिकतम होता है, जैसे अल्पविकसित देशों में कृषिगत वस्तुओं एवं कच्चे माल की बहुतायत होती है, अतः ये देश उन वस्तुओं का निर्यात करके अन्य देशों से बनी हुई वस्तुओं का आयात करते हैं। इस प्रकार आयात एवं निर्यात से प्रत्येक देश को लाभ प्राप्त होता है तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता है उन्हें विदेशों से आयात करके उपभोग किया जा सकता है।

स्वतन्त्र विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त होता है सभी देश विश्व-बाजार में अपने माल का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। विदेशी व्यापार की सहायता से कोई भी राष्ट्र अपने उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित कच्चे माल, मशीनरी, तकनीकी ज्ञान आदि का आयात करके वस्तुओं के निर्माण द्वारा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करता है।

विदेशी व्यापार आर्थिक संकट के समय में सहायक होता है। प्राकृतिक एवं आर्थिक संकट जैसे बाढ़, भूकम्प, अकाल, युद्ध आदि के समय में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु विदेशी व्यापार आवश्यक है।

विदेशी व्यापार से आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिरता को भी प्रोत्साहन मिलता है इसके फलस्वरूप विश्व शान्ति उत्पन्न होती है। राजनैतिक स्तर पर सुलह होने से आपसी सद्भाव में वृद्धि होने के साथ-साथ आयात एवं निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलता है। इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार बढ़ने से एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों के सम्पर्क में आते हैं। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक सम्पर्कों में वृद्धि होती है तथा एक दूसरे राष्ट्र के रीति-रिवाज, आचार-विचार आदि का आदान-प्रदान सम्भव हो जाता है, इससे विश्व सहयोग एवं विश्व एकता में वृद्धि होती है।

विदेशी व्यापार का अध्ययन .—

विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से होता है जो एक देश की सीमाएं पार कर जाता है। विदेशी व्यापार में आयात एवं निर्यात दोनों को सम्मिलित किया जाता है। आयात से तात्पर्य विदेशों से माल मगाना है तथा निर्यात से तात्पर्य विदेशों को सामान बेचना है। आज के युग में यातायात एवं संचार के साधनों की उपलब्धता, मितव्ययिता एवं सुरक्षा के कारण एक देश अपने उत्पादों को विश्व के कोने-कोने में बेचता है। स्वतन्त्रता के बाद से भारत का विदेशी व्यापार विभिन्न मोड़ों से होकर गुजरा है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व भारत ने निर्यात-नियन्त्रण की नीति अपनाई थी, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद यह आवश्यक हो गया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया जाय। 1947 के बाद निर्यात व्यापार का मुख्य उद्देश्य प्रसारवादी दशाओं को रोकना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना बन गया।

“1947 के बाद भारत के निर्यात व्यापार में अनेक परिवर्तन हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को उचित आधार प्रदान करने के लिए देश के निर्यातों को बढ़ाने की दिशा में विभिन्न प्रयास किये गये। भारत के निर्यात व्यापार में किये गये इन परिवर्तनों के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न कठिनाइयों तथा समस्याओं ने भारतीय व्यापार को अवरुद्ध

कर दिया। यातायात की कठिनाइयों, कच्चे माल तथा रसायनों का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाधाएँ और सरकारी नियंत्रण का बाहुल्य आदि के कारण निर्यात व्यापार की मात्रा घट गई। स्वतंत्रता के बाद व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना परमावश्यक बन गया। क्योंकि ऐसा करके ही आयातों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सकता था।¹

निर्यातों की मात्रा में वृद्धि के कई कारण हैं। सरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रेरणाएँ प्रदान करती है। सरकार द्वारा निर्यात उद्योगों को आयात की अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। चाय, आदि विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात करों की मात्रा कम कर दी गयी है। पहले जो तेल, तिलहन तथा खली के निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगे हुए थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। जो चीजें निर्यात की वस्तुओं को बनाने के काम आती हैं उन पर से करों को या तो हटा दिया गया है अथवा कम कर दिया गया है। 1962-63 में देश में जूट का उत्पादन अधिक हुआ तथा विदेशी मंडियों में उसकी मांग अधिक रही। जिसके परिणामस्वरूप जूट से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात अधिक किया गया। उस वर्ष हथकढ़ों के कपड़े का निर्यात बढ़ा और चाय का घटा।

1963 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर से पाबन्दियों को हटाया गया। कपास, खली तथा हथकढ़ों का कपड़ा आदि विषयों पर निर्यात के नियन्त्रण को बढ़ाया गया। निर्यात सम्बन्धी प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न उपाय किये गये वस्तुओं की किस्म पर नियन्त्रण रखा जाने लगा। जहाज में माल लाने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिये कानून बनाया गया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई, जिनका कार्य सरकारी व्यापार की देख-रेख करना था। विभिन्न वस्तुओं के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन परिषद' बनाई गई और रेलवे द्वारा यह घोषणा की गई कि इंजीनियरिंग उद्योग के 65 वस्तुओं के भाड़े में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अवमूल्यन का प्रभाव भी निर्यात की मात्राओं पर पर्याप्त पड़ा। रुपये का अवमूल्यन करते समय सरकार ने आयात अधिकार और कर प्रत्यय प्रमाण पत्र योजना तथा सीधी राज्य सहायताओं को बन्द कर दिया जो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारम्भ की गई थी। रुपये का अवमूल्यन निर्यातों के लिए अधिक लाभकारी रहेगा क्योंकि कोई भी निर्यात-कर्ता विदेशी

¹ डा० डी० एन० गुर्तू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर 1971-72, पृष्ठ-471

मुद्रा की किसी भी राशि के बदले रूपयों की दृष्टि से 59.5 प्रतिशत अधिक रकम पा सकता था।

“आर्थिक विकास की प्रक्रिया में किसी भी विकासशील देश को किसी न किसी कारणों से विदेशी विनिमय की समस्या का सामना करना पड़ता है जिसके निम्न सम्भावित कारण हो सकते हैं—

(A) विदेशी माग की प्रतिकूल दशाएँ।

(B) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलन और ढाँचे की कठोरताएँ।

(C) आर्थिक सहायता व नीतियों के सही कार्यान्वयन का अभाव।

यदि विदेशी सहायता पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती तो विदेशी विनिमय के संकट को दूर करने के लिए इन देशों के पास दो विकल्प रह जाते हैं।

(I) आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातों में कमी।

(II) निर्यातों को प्रोत्साहन देकर उनसे अर्जित आय में वृद्धि।

अल्प-विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए निरन्तर अधिक आयातों की आवश्यकता होती है, अतः आयातों को कम नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में केवल एक ही उपाय रह जाता है, कि निर्यात को बढ़ाया जाय। निर्यात अपने आप में लक्ष्य नहीं है वरन् ऐसा माध्यम है जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है जिससे हम आयातों का भुगतान कर सकते हैं। निर्यातों से अर्जित आय का आर्थिक विकास की गति से निकटतम सम्बन्ध है।

विदेशी व्यापार का महत्व .—

विदेशी व्यापार के महत्व को जानने के लिए हमें उसके लाभों पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। विदेशी व्यापार से विनिमय के दोनों पक्षों को लाभ होता है। इससे औसत उत्पादन लागत में कमी करके लाभ प्राप्त करने के साथ विशिष्टीकरण के सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार घरेलू व्यापार में विनिमय का कार्य दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करना है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के हितों की पूर्ति करता है। अतः विदेशी व्यापार के अध्ययन का महत्व उसके लाभों की जानकारी में निहित है।

विदेशी व्यापार अल्पविकसित राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि विश्व के विकसित देशों के आर्थिक

विकास में विदेशी पूँजी तथा श्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अल्प विकसित देशों को आवश्यक मात्रा में विदेशी पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक विकास की दर में वृद्धि की जा सकती है। इसके अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि विश्व के देशों की अनेक समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल की जा सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गैट (अब WTO), अकटाड, आदि का निर्माण किया है। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में इन सभी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विदेशी व्यापार के महत्व को हम निम्न बिन्दुओं के माध्यम से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।

(1) नये-नये उद्योग धंधों को प्रोत्साहन :- निर्यात से प्रोत्साहन पाकर देश में नये-नये उद्योग धंधों का विकास होता है। जिससे देश में रोजगार एवं आय अर्जन के अवसर बढ़ते हैं और सम्पन्नता आती है।

(2) आयात के लिए आवश्यक :- किसी देश के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं एवं साधनों का उत्पादन सम्भव नहीं है अथवा कठिन है। अतः उन चीजों का विदेशों से आयात आवश्यक होता है। यदि एक देश निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं करता, तो वह अपनी आवश्यक वस्तुओं का आयात भी नहीं कर सकेगा।

(3) बड़ी मात्रा में उत्पादन - एक देश अपना सारा ध्यान उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर केन्द्रित कर सकता है जो वहाँ प्रकृति की दान के कारण सुगमता से पैदा की जा सकती हैं। इससे उत्पादन विधि में सुधार, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन तथा अनावश्यक व्ययों का अन्त होता है। बृहत उत्पादन की अन्य मितव्ययिताएँ भी आती हैं। अतः अतिरिक्त माल का निर्यात बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ को सम्भव बनाता है।

(4) अतिरिक्त उत्पत्ति का अच्छे मूल्यों पर विक्रय - निर्यात के द्वारा एक देश प्रचुर मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन करके उसे विदेशी बाजार में बेच सकता है। इससे एक ओर उत्पादन लागत गिरती है और दूसरी ओर उसका अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाता है।

(5) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग :- आयात एवं निर्यात के कारण प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग एवं विकास करने में समर्थ होता है। एक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण पर सबसे अधिक ध्यान देता है, जिनसे उसे न्यूनतम लागत एवं अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात करके वह अपनी अन्य वस्तुओं का आयात कर सकता है।

(6) उपभोक्ताओं को लाभ — विश्व के उपभोक्ताओं को अच्छे और सस्ते उत्पादों को उपभोग करने का अवसर मिलता है। विश्व एकाधिकार की भावना समाप्त होती है। विश्व के मूल्यों में एकरूपता और स्थायित्व आता है और विश्व के उपभोक्ताओं का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठता है।

(7) सभ्यता का प्रतीक .— विदेशों से आयात एवं निर्यात के कारण दो देशों के निवासी एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। इससे पारस्परिक ज्ञान, कला, सभ्यता और संस्कृति का दो देशों में आदान-प्रदान बढ़ता है। दो देशों के बीच मित्रता, सहयोग एवं सद्भावना का विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता एवं भाईचारे का विकास होता है।

(8) अन्य —

(I) यातायात संचार एवं उत्पादन तकनीकों में सुधार।

(II) कुशलता में वृद्धि।

(III) विदेशी मुद्रा का अर्जन।

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शान्ति।

(V) मूल्यों में स्थायित्व।

(VI) सकटकालीन सहायता।

(VII) विदेशी भ्रमण का अवसर आदि।¹

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में आत्मनिर्भरता की जो संकल्पना स्वीकार की गयी उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता देश के वाह्य सतुलन को बनाये रखना है, जिसकी प्राप्ति हेतु आयात पर निर्यात मूल्यों की अधिकता अति आवश्यक बन जाता है। विदेशी व्यापार के इसी महत्व के कारण निर्यात की संरचना, दिशा, सम्वर्द्धन के उपाय, व्यापार शर्त और इस सन्दर्भ में सरकार की भूमिका से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ उभर कर सामने आती हैं। जिसके समाधान के लिए आवश्यक सिद्धान्तों, नियमों और उपायों का अन्वेषण और व्यावहारिक उपयोग की जरूरत होती है।

¹ जे०के०जैन क्रियात्मक प्रबन्ध, प्रतीक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998 पृष्ठ — 338

साधन समानीकरण प्रमेय में प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हेक्सचर ओहलिन ने यह बताया कि एक देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसको उत्पादित करने के साधन तुलनात्मक रूप में प्रचुर हो और इसके विपरीत आयात होना चाहिये। ऐसा करने से ही तत् सम्बन्धित देश का लाभ अधिकतम हो सकता है।

विदेशी व्यापार में विदेशी विनिमय की भूमिका को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार और घरेलू बाजार में आर्थिक गतिशीलता को सन्तुलित ढंग से उपयोग में लाना होता है। चूँकि व्यापार का आर्थिक कारको पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, अतः व्यापार के संरचना निर्धारण में व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धान्त और साधन समानीकरण सिद्धान्तों का उपयोग किया जा सकता है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इस तथ्य को निर्दिष्ट करता है कि भारत को उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिये जिसमें तुलनात्मक लाभ अधिकतम हो। यदि किसी वस्तु का निर्यात हानिप्रद है परन्तु आवश्यक है तो इस सन्दर्भ में उचित है कि हानि को न्यूनतम करने के उपाय किये जाने चाहिये।

उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों के निष्कर्ष के आधार पर भारत के सन्दर्भ में उचित यही लगता है कि कृषि तथा उससे सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिये। परन्तु यही पर एक बहुत ही प्रबल और यथार्थ समस्या उभरती है, जिसका अनुभवगम्य विश्लेषण प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री राउल प्रेविश, गुन्नारमिरडल, जगदीश भगवती ने किया, वह है प्रतिकूल दीर्घकालीन व्यापार की शर्त। इन अर्थशास्त्रियों ने अनुभव किया कि भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निरर्थक है। क्योंकि उनकी व्यापार की शर्त दीर्घकाल तक प्रतिकूल रहता है, वे कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है और जो विकासात्मक आयात मूल्यों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होता। फलतः दीर्घकाल तक भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल बना रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के लिए भारत को कुछ विशेष उपायों की जरूरत होगी, क्योंकि वर्तमान विश्व में नयी आर्थिक व्यवस्था में अपने को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जोड़ते हुए उन उपायों को तलाशना होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे निर्यातों का अंश बढ़े विदेशी पूँजी का आयात अपेक्षाकृत सुलभ और सस्ती रहे, विदेशी विनिमय की स्थिति सुधरे, विनिमय दर में ज्यादा उच्चावचन न हो, घरेलू आर्थिक विकास को अन्तर्राष्ट्रीय जगत का भरपूर समर्थन मिले।

इस सन्दर्भ में एक ध्रुवी विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु गुटनिरपेक्षता की नीति से व्यापक लाभ होने की सम्भावना बनती है। उदारीकरण भी देश

की सम्प्रभुता को बनाये रखते हुए निर्यात सम्वर्द्धन सहायक होनी चाहिये। जिन वस्तुओं के निर्यात की सम्भावना हाल के वर्षों में बढ़ी है उसका विदोहन होना चाहिए। इसके लिए व्यापारिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। निर्यात सम्वर्द्धन क्षेत्र का विस्तार हो, आयात प्रतिस्थापन की गति को और तीव्र करना होगा।

विदेशी व्यापार से उत्पन्न लाभ :-

विदेशी व्यापार के परिणामस्वरूप उसमें भाग लेने वाले देशों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार, “विदेशी व्यापार किन्हीं भी स्थानों के बीच हो इसमें यह लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं कि जिस वस्तु की एक स्थान पर माँग नहीं है, उसके स्थानान्तरण के बदले में विदेशी व्यापार के कारण वह वस्तु प्राप्त होती है जिसकी उस स्थान पर माँग है। एक स्थान पर लोगों के पास जो वस्तुएँ आवश्यकता से अधिक हैं विदेशी व्यापार के कारण उसका भी मूल्य प्राप्त हो जाता है तथा उसके बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुओं के उपभोग से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। फलस्वरूप उनकी सन्तुष्टि में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं विदेशी व्यापार के कारण बाजार की सीमितता किसी विशेष स्थान पर श्रम विभाजन में रुकावट नहीं डाल पाती है। विदेशी व्यापार देश की उत्पादक शक्तियों में वृद्धि को प्रेरित करता है तथा देश की वास्तविक आय में वृद्धि करता है, इस प्रकार विदेशी व्यापार के तीन लाभ प्रमुख रूप से सामने आते हैं।

- (a) विदेशी व्यापार बाजार को विस्तृत करता है फलस्वरूप घरेलू उपभोग से अधिक उत्पादन के लिए बाजार तैयार करता है।
- (b) बाजार के विस्तार के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में श्रम विभाजन की सम्भावना को बढ़ाता है तथा परिणामस्वरूप देश में उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है।
- (c) उत्पादन में वृद्धि, बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति के परिणामस्वरूप देश में उपभोग स्तर के फलस्वरूप कुल सन्तुष्टि में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभों का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं।

(1) विदेशी व्यापार से उत्पन्न होने वाले स्थैतिक लाभ :- स्थैतिक लाभ की स्थिति में प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होता है क्योंकि व्यापार के कारण बाजार का विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की सम्भावना बढ़ जाती है तथा इसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादक साधनों के कुशलतम तथा

अनुकूलतम आवटन के लिए प्रेरित होते हैं। स्थैतिक स्थिति में व्यापार के कारण उत्पादक दी हुई उत्पादन सम्भावना वक्र के ही साथ चलते हैं, इस प्रकार उत्पादन सम्भावना वक्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परन्तु उपभोग की सीमा में विस्तार होता है।¹ इस प्रकार उपभोक्ता समुदाय अनुकूल व्यापार की शर्त के कारण उच्चतर “सामुदायिक तटस्थता वक्र” को प्राप्त करता है। इस प्रकार समुदाय की कुल सन्तुष्टि में वृद्धि होती है।

(2) विदेशी व्यापार से प्रवैगिक लाभ — विदेशी व्यापार से मात्र स्थैतिक लाभ ही उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् इसके परिणामस्वरूप केवल उपभोग की मात्रा में ही वृद्धि नहीं होता है इसके परिणाम स्वरूप अनेक गत्यात्मक या प्रवैगिक लाभ भी प्राप्त होते हैं प्रविधि में सुधार तथा नयी प्रविधि के स्थानान्तरण से उत्पादन सम्भावना वक्र ही स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। विदेशी व्यापार कभी-कभी औद्योगिक क्रान्ति के लिए रास्ता तैयार करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप देश का औद्योगिक तथा कृषि विकास प्रेरित होता है, रोजगार तथा आय सृजित होते हैं तथा अधोसंरचना विकसित होती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार आर्थिक विकास के इंजिन के रूप में कार्य कर सकता है। पी0टी0 एल्सवर्थ के अनुसार— व्यापार एक प्रवैगिक शक्ति है जो नवप्रवर्तन को प्रेरित करता है। व्यापार के माध्यम से उत्पादन करने तथा उत्पादन संगठन के नये रास्ते स्थानीय अर्थव्यवस्था में फैलाते हैं तथा व्यापार की प्रतियोगितात्मक शक्तियाँ लागत कम करने वाली तकनीकों को प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अनेक वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर मितव्ययिता पूर्ण उत्पादन सम्भव हो जाता है जिनका उत्पादन, व्यापार के अभाव में सम्भव ही नहीं रहता।

उक्त के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है।

(A) आर्थिक लाभ

1 श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश अपने निर्यात होने वाली वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करता है। इस प्रकार उस देश में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण और अधिक होता है।

2 प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग — विदेशी व्यापार की दशा में प्राकृतिक साधन केवल एक देशवासी ही नहीं प्रयोग करते बल्कि पूरा विश्व उनका प्रयोग करता है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग होता है।

¹ डा0 एस0एन0लाल, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लोकवित्त, शिव पब्लिशिंग हाउस—1985 पृष्ठ— 61

- 3 कच्चे माल की उपलब्धता - विदेशी व्यापार से उन देशों को भी कच्चा माल मिल जाता है जहाँ वह उपलब्ध नहीं होता।
- 4 औद्योगीकरण - विदेशी व्यापार के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे देशों का औद्योगीकरण होता है।
- 5 आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध - विदेशी व्यापार से देशों को उनकी आवश्यकता की चीजें उपलब्ध हो जाती हैं।
- 6 बड़े पैमाने पर उत्पादन - विदेशी व्यापार से उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है और बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ मिलने लगते हैं।
- 7 तकनीकी विकास - विदेशों से बढ़िया तकनीक मँगाकर स्वयं के देश में भी तकनीकी विकास लाया जा सकता है।
- 8 एकाधिकार पर रोक - आयात के कारण देश में एकाधिकार की प्रवृत्ति नहीं बनने पाती।
- 9 रोजगार एवं आय में वृद्धि - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन अधिक पैमाने पर होता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और इस प्रकार राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है।
- 10 मूल्यों में स्थिरता - आयात-निर्यात से वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति इच्छित स्तर पर रखी जा सकती है। ताकि मूल्य स्तर में अव्योचित परिवर्तन न आने पाये।
- 11 बाजार का विस्तार :- विदेशी व्यापार के कारण देशों के क्रय-विक्रय का क्षेत्र बढ़ जाता है। इस प्रकार बाजार का विस्तार होता है।
- 12 विदेशी मुद्रा की प्राप्ति - निर्यात के कारण देशों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे वह दूसरी आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकते हैं।
- 13 उत्तम आयातित वस्तुओं का उपभोग - आयात-निर्यात के कारण अविकसित देश भी विकसित देशों के बढ़िया उत्पादों का भोग कर सकते हैं।
- 14 संकटकाल में सहायक :- विदेशी व्यापार का सबसे अधिक महत्व तब दिखता है, जब कभी-कभी एक देश में खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखों मरने लगते हैं और जब वही खाद्यान्न विदेश से आयात होता है तब लोगों की जान बचती है।

(B) गैर आर्थिक लाभ –

ऐसे लाभ जो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से सम्बन्धित नहीं हैं, गैर-आर्थिक लाभ कहे जा सकते हैं। विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाले प्रमुख गैर-आर्थिक लाभ निम्न हैं।

- 1 सांस्कृतिक आदान प्रदान – विदेशी व्यापार से दो देशों के बीच सम्बन्ध बढ़ जाते हैं और इस प्रकार दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति का आदान-प्रदान करने लगते हैं।
- 2 राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध – विदेशी व्यापार के फलस्वरूप देशों के बीच सम्बन्ध बढ़ते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न देश एक दूसरे के काम आते हैं।
- 3 शिक्षा – विदेशी व्यापार से देशों को शिक्षा मिलती है कि अमुक देश में यह हो रहा है, तो हम भी कुछ करें। दूसरे विदेशों की चीजें जब आती हैं, तो उन्हीं की देखा देखी से आयातक देश कई प्रकार से लाभान्वित होता है।¹

विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास :-

भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुआयामी प्रयोजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। यहाँ औद्योगिक विकास यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद काफी हुआ है। परन्तु वृद्धि की दर और इसका प्रभाव अपर्याप्त है। औद्योगिक विकास कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित है। कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योग आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। क्षेत्रीय असन्तुलन बना हुआ है। इसका कारण प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर और भूमि सुधार का अल्प क्रियान्वयन मुख्य है। यदि विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगाह डालें तो इसकी भूमिका उत्साहवर्धक साबित होती है।

व्यापार के माध्यम से पूँजी निर्माण और तकनीकी पिछड़ापन की आधारभूत आर्थिक समस्या से निपटने में काफी हद तक सहायता मिलती है। उल्लेखनीय है कि पूँजी निर्माण के दो मुख्य स्रोत होते हैं। पहला आन्तरिक स्रोत तथा दूसरा वाह्य स्रोत। घरेलू सीमा के अन्दर प्राप्त बचत और इसके निवेश के लिए गतिशील आन्तरिक स्रोत है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं, निजी उद्यमियों और व्यावसायों, विदेशी सरकारों, अप्रवासी नागरिकों, बहुराष्ट्रीय निगमों से हमारे देश के भीतर किये गये पूँजी निवेश वाह्य स्रोत का पूँजी निर्माण है।

¹ डा० ए०ए० सिद्दीकी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशुल्क नीति, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण-2002, पृष्ठ - 5

यह निवेश या तो मौद्रिक होता है या भौतिक परिसम्पत्ति या तकनीकी कौशल के रूप में। स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश के माध्यम से किसी देश के लिए पूँजी निर्माण का एक अहम श्रोत है। जिस पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है। यही बात हिन्दुस्तान के सन्दर्भ में भी लागू होता है।

आर्थिक सिद्धान्त में व्यापार गुणक की अवधारणा सिद्ध करती है कि निर्यात और रोजगार तथा आय सवृद्धि में धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। यद्यपि यह जरूरी है कि आयात पर यथोचित नियन्त्रण भी बना रहे।

व्यापार से विविध प्रकार की सांस्कृतियों के आपसी समामेलन और सम्पर्क से मानवता भी विकसित होती है। आर्थिक भूमण्डलीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान से वैश्विक एकता मजबूत होती है।

विभिन्न देशों की आन्तरिक निर्भरता बढ़ती है। फलतः मानवता के खिलाफ प्रत्येक कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जाता है। व्यापार और आर्थिक हित ही वह तत्व हैं जो शक्ति सन्तुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ही वर्ष पहले विश्व की एक महाशक्ति सोवियत संघ की वर्तमान परिस्थिति में विकसित रूस (सोवियत संघ का 80 प्रतिशत) की तवहिनी, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर ही की जा रही है।

भारत योजनागत विकास का जो ढाँचा तैयार किया वह सोवियत संघ और फ्रांस से आयातित है। हरित क्रान्ति में मैक्सिको, अमेरिका और इजराइल की मुख्य भूमिका रही है। आधारभूत आर्थिक संरचनाओं के निर्माण में विश्व बैंक, जी-7, आईडी0ए0 ने सहयोग किया। आज भी विश्व बैंक के सहयोग से बहुत से शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जनसंख्या नियन्त्रण, सफाई, सामुदायिक विकास आदि के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

यद्यपि एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में भारत का भरपूर आर्थिक और सामाजिक शोषण, हुआ परन्तु भारत के औद्योगिक क्रान्ति में इंग्लैंड की भूमिका से मुकरा नहीं जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् मोटे रूप में सीमा पार आर्थिक गतिशीलता का भारत जैसे अविकसित देशों के लिए भूमिका सराहनीय है। फिर भी आयातों की भरपाई के लिए निर्यात सम्बर्द्धन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न नियमों के अनुशीलन के पश्चात् भारत के सन्दर्भ में उसकी विशिष्टताओं को दृष्टिगत करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उसे अपने कृषि क्षेत्र के विकास सम्भाव्यता की ओर तीव्र गति से बढ़ने के पश्चात् ही व्यापार की संरचना या निर्यात

की सरचना सीमा और दिशा में यथोचित और द्रुतगति से विस्तार किया जा सकेगा। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मात्र कृषिगत निवेश और विकास से ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। यह सही है कि निर्यात की सम्भावना कृषि क्षेत्र में ज्यादा है। परन्तु इस सन्दर्भ में व्यापार की शर्त प्रायः प्रतिकूल ही रहती है जिसके कारण बहुत ज्यादा निर्यात के बावजूद भी निर्यात मूल्य कम ही रहता है। जबकि औद्योगिक उत्पादों के सन्दर्भ में इसके विपरीत स्थिति होती है। इसलिये जरूरत एक सन्तुलित व्यापार और विकास नीति की होती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाएं बहुत ज्यादा हो गयी हैं। जरूरत है तो दृढसंकल्प शक्ति, त्वरित कार्यवाही, प्रशासनिक गतिशीलता, प्रोत्साहन मूलक नीति और सही विषय और दिशा को तलाशने की। जबकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। क्षेत्रियता का स्थान, सकुचित हो रहा है। नये-नये आर्थिक संगठन बन रहे हैं। सबका मकसद अपने-अपने व्यापारिक नीति का प्रयोग अधिकतम लाभ उठाने का है तो इस परिस्थिति में भारत भी अपने पड़ोसी देशों तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर व्यापारिक गतिशीलता बढ़ाते हुए बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक साधन और तकनीक प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह सही है कि अन्ततः इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए आन्तरिक ससाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, फिर भी ससाधनों की कमी की वजह से अन्य देशों से मदद लेना पड़ जाता है। इस दृष्टि से नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था में जिसमें विभिन्न देशों द्वारा आयात शुल्क में कटौती की जा रही है। घरेलू उत्पादों पर सरक्षण कम हो रही है। सहाइकियों में कटौती की जा रही है। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात बखूबी कर सकता है। ये हैं हस्तनिर्मित वस्तुएँ, रेडीमेड कपड़े, हीरे-जवाहरात, इन्जीनियरिंग वस्तुएँ, चाय, जूट एवं सम्बन्ध उत्पाद, चावल, मछली आदि।

भारत उस स्थान पर भी खड़ा है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी कुछ वस्तुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। न केवल तकनीकी श्रेष्ठता बल्कि मूल्य की निम्नता के लिये अभी हाल ही में ओमान, मलेशिया जैसे अल्प विकसित राष्ट्र में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत सयन्त्रों के निर्माण के आर्डर प्राप्त हुए हैं। भारतीय वस्तुशिल्प की श्रेष्ठता उस समय भी प्रमाणित हुई जब कम्बोडिया में अकोरवाड के मन्दिर जिर्णोद्धार हेतु आमन्त्रित किया गया। इन तथ्यों से यही तात्पर्य निकलता है कि यदि हमारे सम्बन्ध अन्य राष्ट्रों से मधुर रहे तो हम हर एक क्षेत्र में निर्यात बढ़ा सकते हैं।

सम्भवतः अपनी इसी क्षमता को पहचानते हुए नयी व्यापारिक नीति में आवश्यक बदलाव किया गया। नयी निर्गम नीति बनायी गयी। इसके परिणाम भी सार्थक नजर आ रहे हैं। 1991

के अन्त तक जो विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार 3,300 करोड रूपये था। जून 2002 के अन्त तक 57 अरब 96 करोड 20 लाख डालर तक पहुँच गया। जो कि कीर्तिमान है। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा का व्यापार और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसी से आवश्यक साज-समान किसी देश को मिल पाता है और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास का आधार भी विदेशी रिजर्व ही है। इसके अभाव में घरेलू मुद्रा और अर्थव्यवस्था में अन्य देशों का विश्वास नहीं जमता और विदेशी विनिमय दर में उच्चावचन होने लगता है। जैसा कि 1990 के अन्त तक भारत में एक विकट स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में सोना गिरवी रखा गया तथा आगे चलकर रूपये का लगभग 22% अवमूल्यन कर दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से निर्यात की भूमिका का पता चलता है। निर्यात ही वह तत्व है जब किसी देश के घरेलू और विदेशी बाजार में सन्तुलन बनाये रख सकता है। आर्थिक विकास का अनुपूरक निर्धारक तत्व है। सम्भवतः इसीलिए एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इन्जन है।" अर्थात् विदेशी व्यापार जितनी मजबूत और सक्षम होगी देश की अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी विकास के मार्ग पर उतनी ही द्रुत गति से चलेगी। इस प्रकार व्यापार से बेरोजगारी गरीबी, जैसे समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिल जाता है।

अध्याय दो

“आजादी के समय विदेशी व्यापार की
स्थिति”

अध्याय – 2

आजादी के समय विदेशी व्यापार की स्थिति

किसी देश के विदेशी व्यापार की संरचना तथा दिशाएँ प्रायः उस देश के शासन तन्त्र (Administrative machinery) तथा आर्थिक नीतियों पर निर्भर करती हैं। भारत में शताब्दियों तक विदेशी शासन रहा। अंग्रेजी शासन के लगभग 150 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जनता का जितना शोषण हुआ उतना सम्भवतः पहले कभी नहीं हुआ था। वास्तव में, ब्रिटिश शासन ने भारत में भाषा व्यावसाय, उद्योग, परिवहन तथा अन्य सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की नीति का अनुसरण किया जिससे यह देश सदा सर्वदा के लिए आर्थिक दासता की श्रृंखलाओं में जकड़ जाय। वैसे तो अति प्राचीन काल से ही भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत की बनी हुई वस्तुओं जैसे सूती कपड़े, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला आदि की माँग मिस्र, यूनान, रोम तथा इरान आदि स्थानों में बहुत अधिक थी। इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया में अपने उपनिवेश बनाए थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनों जल और स्थल दोनों ही मार्गों से होता था। भारत में प्राचीन काल में आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी, हमारे व्यापार का भुगतान सोने-चादी में करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश में करोड़ों रुपये का सोना आ जाता था।

किसी भी देश में कुल व्यापार को घरेलू अथवा राष्ट्रीय तथा विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि संसार के सभी देशों के लिए विदेशी व्यापार का समान महत्व नहीं होता है, परन्तु वर्तमान युग में सभी देशों के लिए विदेशी व्यापार का कुछ न कुछ महत्व अवश्य है। जबकि इंग्लैण्ड तथा डेनमार्क के समान छोटे राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि में विदेशी व्यापार का काफी अधिक महत्व रहा है। चीन, रूस तथा अमेरिका के समान विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार का सम्भवतः बहुत अधिक महत्व नहीं है। किन्तु अर्द्धविकसित देशों के लिए विदेशी व्यापार, आर्थिक विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन होता है।

1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के पूर्व भारत इंग्लैण्ड का उपनिवेश था परिणाम स्वरूप भारत के विदेशी व्यापार का ढाँचा अथवा स्वरूप भी उपनिवेशी था। भारत इंग्लैण्ड तथा अन्य

पाश्चात्य औद्योगिक देशों को कच्चे माल, खाद्यान्न एवं अर्धनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता था तथा विदेशों से निर्मित वस्तुओं का आयात करता था। विनिर्मित वस्तुओं के लिए विदेशी आयातों पर निर्भर रहने का देश के औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा देश में अंग्रेजी सस्ती विनिर्मित वस्तुओं का मुक्त आयात होने के परिणाम स्वरूप घरेलू शिशु उद्योगों को विदेशी घातक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत के हस्तशिल्प उद्योगों को गहरी क्षति पहुंची तथा देश के शिल्पकार भारी संख्या में बेरोजगार हो गये।

अगस्त 1947, में स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात देश के विदेशी व्यापार के उपनिवेशी ढांचे में राष्ट्रीय आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तन करना आवश्यक था। किसी भी उस देश के लिए जो तीव्र गति से आर्थिक विकास करना चाहता है, तो उत्पादन क्षमता में तीव्र गति से वृद्धि करना आवश्यक है। परन्तु आर्थिक विकास के लिए देश को पूंजी उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनका आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में देश को, विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे आयातों को, जो देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, विकासात्मक आयात कहते हैं। उदाहरणार्थ देश में इस्पात कारखानों की स्थापना तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए जिन पूंजी उपकरणों का आयात करना आवश्यक होता है, वे विकासात्मक आयात कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवधि में देश के औद्योगिकरण का क्रम विद्यमान हो जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल तथा अन्य अर्धकच्ची एवं अर्ध निर्मित वस्तुओं का आयात करना आवश्यक होता है। जिन वस्तुओं का आयात देश में उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए आवश्यक होता है, उन आयातों को सधारण आयात (Maintenance imports) कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विकासात्मक तथा सधारण आयात आवश्यक होते हैं। ये दोनों प्रकार के आयात किसी दी हुई समय अवधि में विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की सीमा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के आयात स्फीति निवारक होते हैं, क्योंकि इनके उत्पादक उपयोग द्वारा देश में उपभोग वस्तुओं की दुर्लभता समाप्त होती है।

इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में देश के कुल आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में देश का व्यापार शेष तथा भुगतान शेष प्रतिकूल होंगे। व्यापार-शेष के घाटे की पूर्ति करने के लिए विकासशील देश के कुल निर्यातों में वृद्धि होना आवश्यक है। यद्यपि अल्पावधि में वाह्य सहायता, देश के आर्थिक विकास के भार को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है परन्तु दीर्घावधि में विकासशील देशों को विकास

का भार स्वयं सहन करना होता है। मूल्य निरपेक्ष आयातों के कारण बढ़ते हुए विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए देश के निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि करना अति आवश्यक है। आरम्भ में ही अर्धविकसित देश खाद्यान्न तथा परम्परागत कच्ची वस्तुओं के निर्यातकर्ता रहे हैं। जैसे-जैसे देश का आर्थिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे देश में स्वयं खाद्यान्न तथा कच्चे माल का अधिक उपभोग होने के कारण इन वस्तुओं का निर्यात कम हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण देश खाद्यान्नों के निर्यातकर्ता देश के स्थान पर खाद्यान्नों के आयातकर्ता देश की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, परिणामस्वरूप, विकासशील अर्थव्यवस्था को नई विनिर्मित वस्तुओं को विश्व के नए बाजार को निर्यात करने के प्रयासों में व्यस्त होना पड़ता है। विकसित राष्ट्र अपने आयातों पर से रोक को हटा कर विकासशील राष्ट्रों को विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि विदेशी सहायता विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, परन्तु विदेशी व्यापार का महत्व अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इससे अधिक है।

विदेशी व्यापार का परिणाम और विस्तार मुगल शासन काल में और भी बढ़ा। अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसका सारा ढाँचा ही बदल गया। विदेशी सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि देश के उद्योग धंधे शनै-शनै नष्ट होने लगे, और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया। भारत इंग्लैण्ड के निर्मित माल का आयात करने वाला तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया। संक्षेप में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ इस प्रकार हो गयी –

- (अ) हम सामान्यतः निर्मित वस्तुओं का आयात करते थे और कच्चे माल का निर्यात करते थे।
- (ब) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर इंग्लैण्ड और कामनवेल्थ देशों से होता था।

हमारे निर्यात सदैव ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन हमेशा ही हमारे पक्ष में रहता था।

- (स) विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा था इस वृद्धि के प्रमुख कारण थे स्वेज नहर का निर्माण और परिवहन साधनों में उन्नति।

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं भारत का विदेशी व्यापार –

भारत के विदेशी व्यापार पर सन् 1929-30 की भयानक आर्थिक मंदी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। निर्यात की मात्रा में बहुत कमी आ गई। आयात की जाने वाली वस्तुओं में निर्यात वस्तुओं का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होने लगा तथा कच्चे पदार्थों तथा खाद्यान्नों का

प्रतिशत बढ़ने लगा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा कच्चे पदार्थों व खाद्यान्नों की प्रधानता बनी रही। नीचे की सारणी के अंकों से भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में हुए परिवर्तन का स्पष्ट पता चलता है—

तालिका संख्या-21

आजादी के पूर्व विदेशी व्यापार की संरचना

वस्तुएं	कुल आयात के प्रतिशत		कुल निर्यात के प्रतिशत	
	1920-21	1938-39	1920-21	1938-39
खाद्यान्न, पेय एवं तम्बाकू	10 00	15 7	28 0	27 8
कच्चा माल	5 00	21 7	35 0	34 1
निर्मित माल	84 0	62 6	37 00	68 1
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

भारत के आयात व्यापार में इंग्लैण्ड का हिस्सा सन् 1913-14 में 64 प्रतिशत था जो घटकर 1933-34 में 42 प्रतिशत और 1938-39 में 25 प्रतिशत रह गया। निर्यात में भी इंग्लैण्ड का हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा था, सन् 1923-24 के बाद जर्मनी के साथ भारत के व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

निर्मित वस्तुओं के निर्यात के परिणाम स्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि हुई और हमारे निर्यातों में कच्चे माल का प्रतिशत घट गया। अब रुई के स्थान पर सूती वस्त्र, जूट के स्थान पर वनस्पति तेल एवं खालों के स्थान पर चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात होने लगा। इस प्रकार कच्चे पदार्थों का निर्यात सन् 1924-25 में जो कुल निर्यात व्यापार का 50 प्रतिशत था, घटकर सन् 1941-42 तक केवल 28 प्रतिशत हो गया।

विदेशी व्यापार की दशा का ठीक ढंग से अध्ययन करने के लिए इसे हम दो भागों में बाँट सकते हैं —

(अ) स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति।

(ब) स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति।

(अ) स्वाधीनता के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार :—

प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारत को इंग्लैण्ड के कर्जों, अंग्रेज अधिकारियों के वेतनों तथा अंग्रेज निवेश पूँजी पर लाभों का भुगतान करने हेतु काफी धनराशि निर्यात करने पड़ते थे।

परिणाम स्वरूप, भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहता था। भारत के कुल निर्यात इसके कुल आयातों की तुलना में अधिक थे। द्वितीय महायुद्ध काल में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल परिवर्तन हुआ। इस अवधि में भारत ने इंग्लैण्ड को काफी मात्रा में वस्तु-निर्यात किए परन्तु इन निर्यातों के भुगतानों के बदले भारत को इंग्लैण्ड द्वारा बहुत कम आयात प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप स्टर्लिंग शेष (Sterling Balance) की घटना उत्पन्न हो गयी थी। प्रत्येक वर्ष आयातों की तुलना में अधिक राशि के निर्यात करने के कारण स्टर्लिंग शेष की राशि में वृद्धि होती गई। इंग्लैण्ड के साथ भारत का व्यापार शेष इतना अधिक अनुकूल नहीं था कि इंग्लैण्ड को स्टर्लिंग ऋण का भुगतान करने के पश्चात् भी 5 अप्रैल, 1946 को भारत के पक्ष में इंग्लैण्ड की ओर 1733 करोड़ रुपये राशि के स्टर्लिंग शेष एकत्र हो गये थे।

इसके अतिरिक्त युद्ध का भारत के विदेशी व्यापार पर यह भी प्रभाव पड़ा था कि जापान, जर्मनी तथा इटली के शत्रु राष्ट्र बन जाने के कारण इन देशों से विनिर्मित वस्तुओं के भारत तथा मध्य पूर्व देशों के निर्यात समाप्त हो गये। परिणामस्वरूप, भारत तथा मध्य पूर्व के देशों में विनिर्मित वस्तुओं की काफी अधिक माँग होने के कारण भारत में उपभोग वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले उद्योगों का विकास सम्भव हो गया।

व्यापार का ढाँचा — 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरम्भ होने से लेकर 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने तक भारत के कुल आयातों तथा कुल निर्यातों के मूल्य में वृद्धि होती रही। यद्यपि इस अवधि में देश के निर्यातों का मूल्य आयातों की तुलना में अधिक था। निम्नांकित सारणी द्वारा यह स्पष्ट है कि 1938-39 से लेकर 1947-48 तक आयातों तथा निर्यातों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही थी।

तालिका सख्या-22

आजादी के समय भारत का विदेशी व्यापार

(1938-39 से 1947-48)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1938-39	169 9	152.34	+16.85
1945-46	265 53	244 85	+20 68
1946-47	319 28	288 43	+30 45
1947-48	403 19	389 62	+13 57
राशि करोड़ रुपये में			

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1947-48 में भारत के निर्यातों का मूल्य 1938-39 की तुलना में दो गुना से अधिक था। निर्यातों का कुल मूल्य 169 19 करोड़ रुपये से बढ़कर 403 19 करोड़ रुपये हो गया था। कुल आयातों में भी वृद्धि हुई थी, जो 152 34 करोड़ रुपये से बढ़कर 389 62 करोड़ रुपये हो गयी थी।

देश के निर्यातों का ढाँचा — इस अवधि में देश के निर्यातों के कुल मूल्य में परिवर्तन होने के साथ-साथ इन निर्यातों के ढाँचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। निर्यातों में कच्चे माल के निर्यातों के अनुपात में भारी कमी तथा विनिर्मित वस्तुओं के अनुपात में काफी वृद्धि हो गयी थी। युद्ध के पूर्व 1938-39 में कुल निर्यातों में 45 1 प्रतिशत निर्यात, कच्चे माल के निर्यात थे। 1947-48 में कुल निर्यातों में कच्चे माल के निर्यातों का हिस्सा 45 1 प्रतिशत से घटकर केवल 31 3 प्रतिशत रह गया था इसके विपरीत विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों में काफी वृद्धि हो गयी तथा यह 1947-48 में 30 00 प्रतिशत से बढ़कर कुल निर्यातों के 48 8 प्रतिशत हो गये थे। जहाँ तक खाद्यान्नों का प्रश्न है, यद्यपि भारत युद्ध के पूर्व खाद्यान्नों का निर्यात किया करता था परन्तु युद्ध के पश्चात काल में तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये निर्यात स्वाधीनता पश्चात युग में पूर्णतया समाप्त हो गये थे। निम्नांकित तालिका 1938-39 से लेकर 1947-48 तक भारत के निर्यातों के ढाँचे को व्यक्त करती है।

तालिका संख्या-23

आजादी के समय भारतीय निर्यातों का ढाँचा

वस्तु	वर्ष (कुल निर्यातों का प्रतिशत)		
	1938-39	1946-47	1947-48
खाद्यान्न	23 3	48 6	19 1
कच्चा माल	45 1	33 3	31 3
विनिर्मित वस्तुएँ	30 6	46 7	48 8

इस अवधि में (1938-39 से 1947-48) भारत के निर्यातों का भौगोलिक ढाँचा इस प्रकार का था कि राष्ट्रमण्डल देशों के साथ भारत का निर्यात व्यापार काफी अधिक था तथा युद्ध के पूर्व भारत अपने कुल निर्यातों का 53 6 प्रतिशत राष्ट्रमण्डल देशों को निर्यात करता था। राष्ट्रमण्डल देशों में इंग्लैण्ड का प्रथम स्थान था। भारत अपने कुल निर्यातों का 14 3 प्रतिशत

भाग इंग्लैण्ड को निर्यात करता था। जापान तथा अमरीका को जो निर्यात किए जाते थे, वे भारत के कुल निर्यातो के क्रमश 88 प्रतिशत तथा 84 प्रतिशत थे। फ्रांस, इटली, हालैण्ड, बेल्जियम तथा जर्मनी के साथ कुल निर्यात व्यापार का केवल 15 प्रतिशत निर्यात व्यापार होता था। युद्ध काल में जर्मनी तथा जापान के साथ भारत का निर्यात व्यापार बिल्कुल समाप्त हो गया था क्योंकि ये दोनों देश शत्रु देश घोषित हो गये थे। इसके अतिरिक्त युद्ध काल में यूरोप के अन्य देशों, विशेष रूप से इंग्लैण्ड को भारत के निर्यात काफी कम हो गये थे। परिणाम स्वरूप देशी कच्चे माल का खपत स्वयं देश में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में होने लगा था। युद्ध काल में जर्मनी, जापान तथा इंग्लैण्ड अपने निर्यात बाजारों में वस्तुओं की पूर्ति करने में असमर्थ होने के परिणाम स्वरूप भारत को अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा आस्ट्रेलिया को अपनी विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था। युद्ध पश्चात काल में भारत के विदेशी व्यापार विशेष रूप से निर्यातों पर प्रभाव डालने वाली घटना 1947 में देश का विभाजन था जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के बन जाने से अन्तरक्षेत्रीय व्यापार का कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में सम्मिलित हो गया था।

देश के आयातों का ढोँचा — युद्ध के पूर्व भारत के कुछ आयातों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। 1938-39 से लेकर 1947-48 तक लगभग 10 वर्ष की अवधि में भारत के आयातों का मूल्य बढ़कर 25 गुना से अधिक हो गया था। युद्ध तथा युद्ध के पश्चात की अवधि में भारत के आयातों के मूल्य में हुई इस वृद्धि के अनेक कारण थे प्रथम, युद्ध की अवधि में देश के आयातों में तीव्र कमी हो जाने के कारण स्थगित माँग ने उपयोग तथा पूँजी वस्तुओं के आयातों की माँग में आश्चर्यजनक वृद्धि उत्पन्न कर दी थी। युद्ध काल में सरकार द्वारा अपनी कुल आय की तुलना में अधिक व्यय करने के परिणाम स्वरूप देश में लोगों की आयों में काफी वृद्धि हो जाने से उनकी क्रयशक्ति में वृद्धि हो गयी थी। परन्तु देश में उपभोग वस्तुओं की कमी होने के कारण लोग अपनी इस बड़ी हुई क्रयशक्ति का वस्तुओं को खरीदने में उपयोग नहीं कर सके थे। परिणामस्वरूप युद्ध की समाप्ति पर सामान्य स्थिति के विद्यमान होने पर वे रुकी हुई उपभोग माँग की पूर्ति करने के लिए आतुर थे। इसके अतिरिक्त युद्ध काल में पूँजी उपकरणों की घिसावट होने के परिणाम स्वरूप इन यन्त्रों तथा अन्य पूँजी सज्जा की स्थापन करने हेतु युद्ध के पश्चात पूँजी उपकरणों की प्रतिस्थापन माँग उत्पन्न गयी थी।

भारत के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने का दूसरा कारण यह था कि भारत में कीमत स्तर में अन्य देशों की तुलना में अधिक वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप आयात-निर्यात स्थिति भारत के प्रतिकूल हो गयी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशों से जहाँ भारत की तुलना

मे मूल्यो मे कम वृद्धि हुई थी, भारत मे अधिक आयात होने लगे। तीसरे, देश के विभाजन तथा जनसंख्या मे वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न देशी घाटे मे परिवर्तित हो गई, तथा भारत जो युद्ध के पूर्व खाद्यान्नो का निर्यात करता था स्वाधीनता के पश्चात खाद्यान्नो का आयात करने के लिए विवश हो गया। 1947-48 तक खाद्यान्नो के आयात 3 मिलियन टन हो गये थे। चौथे, पाकिस्तान बन जाने के कारण देश मे कुछ वस्तुओ के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडने से भारत के आयातो मे वृद्धि हो गयी थी। पाँचवे युद्ध के तत्काल पश्चात केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के आर्थिक विकास योजनाओ पर अधिक धनराशि व्यय करने हेतु पूँजी उपकरणो के आयातो मे वृद्धि हो जाने से देश के कुल आयातो मे वृद्धि हो गयी। बहुद्देशीय सिचाई योजनाओ तथा भारतीय रेल के विकास के लिए काफी मात्रा मे पूँजी वस्तुओ के आयात किए गए।

तालिका संख्या-24
आजादी के समय आयातो का ढोँचा

वस्तु	वर्ष (कुल आयातो का प्रतिशत)			
	1938-39	1946-47	1947-48	1948-49
खाद्यान्न	15 8	13 4	11 8	17 8
कच्चा माल	21 8	26 0	23 1	24 5
विनिर्मित वस्तु	60 9	58 1	63 4	56 9

उक्त तालिका देश के वस्तु आयातो के ढोँचे को व्यक्त करती है, आयात वस्तुओ को देखने से ज्ञात होता है कि खाद्यान्नो के आयात देश के विभाजन तथा घरेलू उत्पादन मे वृद्धि न होने का परिणाम था। इस अवधि मे विनिर्मित वस्तुओ के आयातो मे कमी हो गयी थी।

देशानुसार आयातो का ढोँचा इस प्रकार था कि 1938-39 मे कुल आयातो का 31.4 प्रतिशत भाग इंग्लैण्ड से आयात किया जाता था। द्वितीय महायुद्ध की अवधि मे इंग्लैण्ड से आयातो मे काफी कमी हो गयी थी तथा भारत के कुल आयातो मे इंग्लैण्ड का हिस्सा 31.4 प्रतिशत से घटकर केवल 19.8 प्रतिशत रह गया था। परन्तु 1947-48 मे इंग्लैण्ड के हिस्से मे पुन वृद्धि हो गयी थी तथा यह बढ़कर कुल आयातो मे 30.2 प्रतिशत हो गया था। यद्यपि 1938-39 मे भारत के कुल आयातो मे अमरीका का हिस्सा केवल 7.4 प्रतिशत था, परन्तु 1944-45 मे बढ़कर 25.7 प्रतिशत तथा 1947-48 मे 30.3 प्रतिशत हो गया था। अमरीका से होने वाले आयातो मे प्रमुख आयात वस्तु खाद्यान्न पदार्थ थे। यद्यपि खाद्यान्नो के अतिरिक्त

उपभोग वस्तुओं तथा पूँजी उपकरणों का भी आयात किया गया था। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत को कच्चा जूट कच्ची रुई, खाले, तथा ऊन आदि वस्तुएँ पाकिस्तान से आयात करने की आवश्यकता थी। जापान से भारत मशीन उपकरण तथा अन्य औद्योगिक वस्तुएँ आयात करता था।

(ब) स्वतन्त्रता के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार :—

भारत को सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, किन्तु इस स्वतन्त्रता में देश विभाजन का विष घुला हुआ था, जिसके फलस्वरूप भारत तथा नवोदित पाकिस्तान को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों में खाद्यान्नों की समस्या, मुद्रा तथा बैंकिंग सम्बन्धी व्यवस्था तथा व्यापार सम्बन्धी अस्तव्यस्ता मुख्य है।

1. देश विभाजन और भारत का विदेशी व्यापार :— भारत के विभाजन से देश के व्यापार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा —

(i) कच्चे माल का आयात — विभाजन के फलस्वरूप बढ़िया पटसन लम्बे रेशे की रुई तथा अन्न उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। अतः भारत को पटसन रुई तथा खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। यह एक विडम्बना ही थी कि पटसन और रुई निर्यात करने वाले भारत को 1948 में ही 71 करोड़ रुपये के पटसन का आयात करना पड़ा। इसी वर्ष लगभग 87 करोड़ रुपये का अन्न भी विदेशों से मगाया गया।

(ii) प्रतिकूल व्यापार शेष — विभाजन का दूसरा परिणाम यह हुआ कि भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल होने लगा। 1948-49 में ही भारत का व्यापार सन्तुलन 283 करोड़ रुपये से प्रतिकूल था। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत के अनेक आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े। इस प्रकार भारत में स्वतन्त्र व्यापार नीति समाप्त हो गयी।

(iii) व्यापार का स्वरूप — स्वतन्त्रता से पहले पूर्वी बंगाल पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त से होने वाला व्यापार भारत का आन्तरिक व्यापार ही कहलाता था, किन्तु विभाजन के फलस्वरूप इन क्षेत्रों का व्यापार विदेशी व्यापार बन गया। इससे व्यापार सम्बन्धी असुविधाएँ उत्पन्न हो गयीं और कुछ समय तक तो दोनों देशों का लेन-देन प्रायः बन्द ही रहा। बाद में पारस्परिक समझौते द्वारा कुछ वस्तुओं का आदान-प्रदान आरम्भ किया गया।

2. अवमूल्यन तथा उसके प्रभाव :— युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन को 'डालर संकट' का सामना करना पड़ा। यह संकट भारत के सामने भी उपस्थित हुआ। इसका अनुमान इस बात से

लग सकता है कि 1946 में भारत के पास केवल 5 करोड़ रुपये डालर मुद्रा की कमी थी। यह कमी 1947 में बढ़कर 86 करोड़ रुपये के तुल्य हो गयी। इसके साथ ही 1947-48 में अमरीका को किये गये निर्यातों का मूल्य 80 करोड़ रुपये था जो 1948-49 में घटकर 70 करोड़ रुपये के तुल्य रह गया। अतः जब 18 सितम्बर 1949 को ब्रिटेन ने पौण्ड के अवमूल्यन की घोषणा की तो भारत ने भी रुपये का (डालर की तुलना में) 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। इस अवमूल्यन से व्यापार पर कई प्रभाव पड़े।

(i) निर्यातों में वृद्धि — अवमूल्यन के फलस्वरूप दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों में भारतीय माल-कपड़ा, तिलहन, चमड़ा, तम्बाकू, चाय, मसाले, मैगनीज आदि की माँग बहुत बढ़ गयी, जिससे इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर सूती वस्त्र का निर्यात अवमूल्यन के अगले वर्ष ही 31 करोड़ रुपये से बढ़कर 82 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। डालर मुद्रा क्षेत्र में भारत द्वारा 1948-49 में कुल 91 करोड़ रुपये के लगभग मूल्य का माल निर्यात किया गया था। इसकी राशि 1949-50 में लगभग 125 करोड़ रुपये के तुल्य हो गयी।

(ii) आयातों में कमी — अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत में डालर क्षेत्रों का माल महँगा पड़ने लगा जिससे इन देशों से आयात में कमी हो गयी। 1948-49 में डालर मुद्रा क्षेत्र से भारत का आयात लगभग 125 करोड़ रुपये के तुल्य था जो अगले वर्ष ही घटकर लगभग 115 करोड़ रुपये के तुल्य रह गया।

(iii) डालर ऋण में वृद्धि — अवमूल्यन के कारण अमरीका से आयात होने वाले खाद्यान्नों तथा मशीनों आदि का भारत को अधिक मूल्य चुकाना आवश्यक हो गया। अतः इनका भुगतान करने के लिए भारत को अमरीका से ऋण लेना पड़ा। इस प्रकार भारत के डालर ऋण में निरन्तर वृद्धि होने लगी।

(vi) व्यापार सन्तुलन में सुधार :— आयातों में कमी तथा निर्यातों में वृद्धि होने के कारण भारत की व्यापार सन्तुलन स्थिति ठीक हो गयी। 1948-49 में भारत का व्यापार सन्तुलन 127 करोड़ रुपये से प्रतिकूल था जो 1949-50 में लगभग 50 करोड़ रुपये से अनुकूल हो गया।

वास्तव में भारत के निर्यातों में वृद्धि का कारण केवल अवमूल्यन था यह कहना सही नहीं है। क्योंकि कोरियाई युद्ध के कारण भी भारतीय माल की माँग बढ़ गयी थी। यह स्थिति सर्वथा अल्पकालीन थी, क्योंकि कोरिया में युद्ध बन्द होते ही निर्यातों की राशि

कम होने लगी। इधर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना भी आरम्भ कर दी गयी, जिसके कारण विदेशों से अनेक प्रकार की मशीनों तथा निर्मित माल का आयात करना आवश्यक हो गया। अतः भारत के विदेशी व्यापार का सन्तुलन पुनः भारत के प्रतिकूल हो गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् योजना काल के बाद देश के प्रमुख आयात एवं उनमें परिवर्तन निम्नलिखित हैं—

तालिका सख्या-25
प्रथम योजना काल में भारत के प्रमुख आयात
(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	वस्तु	1950-51	1979-80
1	लोहा एवं इस्पात	14	872
2	मशीनें विद्युत मशीनें अलग	67	1295
3	पेट्रोलियम उत्पाद	54	3024
4	विद्युत मशीनें	22	155
5	खाद्य तेल	-	442
6	रसायनिक खाद	-	403
7	कागज	10	155
8	रसायनिक पदार्थ	9	312
9	मोती एवं जवाहरात	-	347

उक्त तालिका से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

- मशीनें** — योजनाओं की अवधि में आयात बीस गुने से भी अधिक हो गये। अनेक प्रकार की मशीनें देश में ही बनने लगी हैं। फिर भी मशीनों की माँग के कारण आयात बढ़े हैं।
- खाद्यान्न** — योजनाकाल में अनाज के आयात में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं। अनेक बार सूखा या बाढ़ के कारण फसले खराब होती रही हैं जिसके फलस्वरूप अधिक अनाज आयात करना पड़ा। खाद के आयात में वृद्धि का भी मूल कारण यही है कि देश में कृषि पदार्थों की उपज बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। गत वर्षों में खाद्यान्न के आयात समाप्त हो गये हैं।
- लोह इस्पात** — खनिज लोहा तो भारत निर्यात करता है परन्तु बढ़िया किस्म का इस्पात व शुद्ध किया हुआ लोहा, आयात करता है। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् से अनेक नये इस्पात

कारखानों के खुलने के बाद भी इस्पात की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है, और इस मद में भी प्रायः आयात की मात्रा बढ़ रही है।

4 खनिज तेल – भारत की आर्थिक उन्नति एवं औद्योगिक विकास से देश में खनिज तेलों की माँग में लगातार वृद्धि हो रही है। खनिज तेल का आयात करने का एक कारण सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करना है, परन्तु मूल्यों में वृद्धि भी इनके आयातों की राशि में वृद्धि का मुख्य कारण है।

5 रसायन – देश में रसायनिक सामानों की माँग बढ़ने का एक मुख्य कारण देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास है। जिसमें प्रयोग के लिए उद्योगों की माँग को पूरा करने के आयात करना पड़ा, वैसे देश में रसायनिक उद्योगों के विकास के कारण इस मद में कमी आने की आशा है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के समय से जो आयातों में वृद्धि हुई है उसमें अधिकांश वृद्धि उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए की गयी प्रतीत होती है साथ ही निर्यात को देखे तो स्वतन्त्रता के समय व योजना काल के बाद देश के प्रमुख निर्यात निम्नलिखित रहे हैं –

तालिका सख्या-26
प्रथम योजना काल में भारत के प्रमुख निर्यात

	मद	1950-51 (करोड़ रुपये में)	1979-80 (करोड़ रुपये में)
1	जूट का निर्मित माल	133	341
2	चाय	80	355
3	सूती वस्त्र तथा सूत	120	285
4	चमड़ा एवं चमड़े का सामान	26	525
5	कच्चा लोहा	नगण्य	289
6	लोहा इस्पात	नगण्य	101
7	इन्जीनियरिंग का सामान	-	422

8	तम्बाकू	1 4	102
9	चीनी (शक्कर)	-	146
10	कॉफी	-	163
11	मोती एव जवाहरात	-	481
12	सिले हुए कपडे	-	454
13	मछली एव सम्बन्धित पदार्थ	-	249
14	रसायन	-	200
15	मसाले	-	149

उक्त तालिका को देखने से निर्यातो की निम्नलिखित प्रवृत्तिया स्पष्ट होती है—

परम्परागत निर्यातो मे वृद्धि — स्वतन्त्रता के समय के बाद भारत मे चमडा एव चमडे का सामान, चाय सूती वस्त्र, तम्बाकू आदि के निर्यात मे निरन्तर वृद्धि हुई। वही इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चाय के निर्यात मे भारत को अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड रहा है। बांग्ला देश से प्रतिस्पर्धा बढने के कारण पटसन की स्थिति डवाडोल हो गई है।

काजू अन्नक, कहवा, खली आदि का निर्यात — काजू अन्नक, कहवा, खली आदि के निर्यात मे विशेष वृद्धि नही हुई। बीच-बीच मे उनमे थोडे बहुत उतार चढाव आते रहे किन्तु आगामी वर्षों मे इनमे निर्यात बढने की सम्भावना है।

नई वस्तुएँ — यहाँ निर्यातो की मुख्य विशेषता यह है कि स्वतन्त्रता के समय से पिछले कुछ वर्षों मे देश से कुछ नई वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ मोती, जवाहरात, लोहा और इस्पात, रसायन तथा इजीनियरी का सामान शक्कर हस्तशिल्प का सामान और बने हुए कपडे मुख्य है।

स्वतन्त्रता के समय विभिन्न देश से होने वाले आयात तथा उनमें परिवर्तन — स्वतन्त्रता के समय की तुलना मे, गत वर्षों मे भारत के आयात व्यापार की दिशा मे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। अनुमानत निम्न तालिका द्वारा इन परिवर्तनो का पता लगाया जा सकता है।

तालिका सख्या-27

आजादी के समय प्रमुख देशो से होने वाले भारत के आयात

देश	(करोड रुपये में)			
	1950-51	1960-61	1979-80	1998-99
अमरीका	119	328	870	15339
ब्रिटेन	135	217	664	10793
सोवियत रूस	नगन्य	16	729	22218
पश्चिमी जर्मनी	-	123	645	8998
जापान	10	61	610	10032
कानाडा	22	20	223	1560
आस्ट्रेलिया	-	18	150	6282
ईरान	37	30	620	2044
इराक	-	-	858	636
वेलजियम	-	-	266	10596

उक्त तालिका का अध्ययन करने पर निम्न स्थिति स्पष्ट ही रही है -

1 भारत में अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा जापान में होने वाले आयातों में विशेष वृद्धि हुई है। 1960-61 में भारत के कुल आयात का लगभग 21 प्रतिशत ब्रिटेन से आयात होता था किन्तु वही आयात बाद में चल कर 1979-80 में केवल 9 प्रतिशत के लगभग रह गया। अमरीका का भाग आज भी भारत के कुल आयात का 12 प्रतिशत ही है जापान, सोवियत संघ, पश्चिमी जर्मनी से होने वाले आयातों में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई। इन देशों से मुख्यतः विभिन्न वर्गों की मशीनों बिजली सम्बन्धी उपकरण आदि मगाये गये जो अपने देश के विभिन्न योजनाओं के विकास विस्तार एवं कुशल संचालन के लिए आवश्यक पड रहे थे इन्हीं परिपेक्ष में ईरान तथा इराक से खनिज तेल का आयात होता है।

2 स्वतन्त्रता के पश्चात नये देशों से व्यापार - भारत के आयातों में न केवल ब्रिटेन का स्वतन्त्रता के बाद एकाधिकार समाप्त हो गया बल्कि स्वतन्त्र भारत में अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य नये देशों से भी व्यापार बढ़ने की प्रवृत्ति है। ईरान तथा इराक से मुख्यतः खनिज तेल तथा संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात किया जाता है।

स्वतन्त्रता के समय भारत से विभिन्न देशों को होने वाले निर्यात तथा उनमें परिवर्तन :-
स्वतन्त्रता के पश्चात गत वर्षों में भारत के निर्यात की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन

हुए। निम्न तालिका द्वारा हम निर्यात की स्थिति तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सकते हैं।

तालिका सख्या-28
आजादी के समय प्रमुख देशों से होने वाले भारत के निर्यात

देश	1950-51	1960-61	1979-80	1998-99
अमरीका	116	103	809	30842
ब्रिटेन	140	172	474	8028
सोवियत संघ	14	29	640	3038
पश्चिमी जर्मनी	-	20	365	7229
जापान	10	35	665	6945
कनाडा	14	18	61	2006
ऑस्ट्रेलिया	30	22	100	1640
ईरान	अनु०	5	100	667

स्रोत - आर्थिक समीक्षा 1999-2000, S 91 - 92

उक्त तालिका के अध्ययन से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं -

- 1 सोवियत रूस एवं जापान का स्थान स्वतन्त्रता के समय के पश्चात महत्वपूर्ण हो गया। किन्तु सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका अंश कम हो गया है।
- 2 1950-51 में कुल निर्यातों का लगभग 24 प्रतिशत माल अकेले ब्रिटेन भेजा जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। परन्तु अब भी अमरीका का प्रभाव यथावत है। यद्यपि सोवियत संघ (विघटन के पूर्व) तथा जापान की क्रमशः कुल निर्यात का 14 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत भाग रहा इस प्रकार नये देशों का महत्व भारत के निर्यातों में अधिक बढ़ा है।
- 3 भारत का अपने पड़ोसी देशों से स्वतन्त्रता के समय जिनके साथ व्यापार था अब कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो उनसे हमारे वो मधुर सम्बन्ध नहीं रहे अथवा वो कठोर आयात नीति अपना रहे हैं।

4 भारतीय व्यापार में अधिकाधिक सहयोग साम्यवादी देशों से मिलता रहा है उदाहरणार्थ 1979-80 में भारत ने पोलैण्ड को 40 करोड़ रुपये चेकोस्लोवाकिया को 43 करोड़ रुपये रूमानिया को 50 करोड़ रुपये तथा सोवियत संघ को 645 करोड़ रुपये का माल निर्यात किया।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में पूँजीगत माल का आयात और निर्यात स्वतन्त्रता के पश्चात् निरन्तर बढ़ रहा है। परम्परागत वस्तुओं (चाय, पटसन) का भी निर्यात बढ़ रहा है इसके अतिरिक्त व्यापार की सभी सीमाओं को भारत लॉघ चुका है। वह न केवल अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान सरीखे पूँजीवादी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर चुका है। बल्कि पूर्वी जर्मनी अब एकीकृत जर्मनी, पोलैण्ड, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा सोवियत रूस सरीखे साम्यवादी देशों से भी उनके लेन-देन में वृद्धि हुई है। देश के स्वतन्त्रता के पश्चात् व्यापार की दशा नित नयी दिशाएँ आर्थिक उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

व्यापार सन्तुलन — द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तथा कुछ समय पश्चात् भारत का व्यापार सन्तुलन उसके अनुकूल रहा। परन्तु वह योजनाकाल में निरन्तर प्रतिकूल रहा है। केवल 1971-72 और 1976-77 में व्यापार शेष में कुछ अनुकूलता दिखलायी पड़ी थी किन्तु यह भी अधिक दिन तक स्थिर न रह सकी, और पुन 1977-78 में प्रतिकूल हो गया। निम्न तालिका द्वारा इसकी स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं।

तालिका सख्या-29

आजादी के समय भारत का व्यापार शेष

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष (अनुकूल / प्रतिकूल)
1950-51	650	601	-49
1960-61	1140	660	-480
1970-71	1634	1535	-99
1972-73	1797	1970	+173
1976-77	5074	5142	+68
1979-80	8908	6459	-2,449
1980-81	12484	6709	-5775

उक्त तालिका से व्यापार सन्तुलन की स्थिति के बारे में स्पष्ट होता है कि व्यापार सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल रहा है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जो इस प्रकार हैं —

- 1 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग स्वतन्त्र देश बन गया जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अन्न, रुई, पटसन के अधिक आयात के लिए बाध्य होना पड़ा जबकि देश विभाजन के पूर्व यह स्थिति देश के सामने नहीं थी।
- 2 जनसंख्या वृद्धि भी व्यापार सन्तुलन को प्रतिकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष सवा करोड़ से अधिक बढ़ जाती है। जिसकी तुलना में खाद्यान्नों का उत्पादन देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं रहा है। अतः गत वर्षों में देश को खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ा।
- 3 भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रायः सभी महत्वपूर्ण उद्योगों में मशीनें बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि उनमें अत्यधिक मशीनें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं। इसके अलावा नयी विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए भी मशीनों का आयात करना पड़ा उदाहरणार्थ 1951-56 की अवधि में लगभग 125 करोड़ रुपये वार्षिक मशीनों तथा उपकरणों के आयात पर खर्च करना पड़ा। 1951-61 की अवधि में यह औसत 323 करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँच गया। यह तीसरी योजनाकाल के पाँच वर्षों में कुल 2,158 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें विदेशों से आयात की गयीं। इस प्रकार मशीनों के आयात का वार्षिक औसत 431 करोड़ रुपये हो गया। 1978-79 में मशीनों का आयात 784 करोड़ रुपये के तुल्य था।
- 4 भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् चीन और पाकिस्तान के गैर-मित्रतापूर्ण रुख के कारण अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए सुरक्षा सामग्री का आयात करना पड़ा। जबकि स्वतन्त्रता के पूर्व यह स्थिति नहीं थी।
- 5 खनिज तेलों के मूल्य में वृद्धि उत्पादन देशों द्वारा बार-बार किया जाता रहा है। जिसके कारण देश के पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बिल बढ़ता गया। यह 1950-51 में 543 करोड़ से बढ़ कर 1979-80 तक 3023 करोड़ हो गया था।

विदेशी व्यापार पर बढ़ता हुआ सरकारी नियन्त्रण — द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारत में सरकार के पूर्व अनुमति के बिना अधिकांश वस्तुएँ आयात हो सकती थीं। सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध काल में आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। योजना काल में यह नियन्त्रण निरन्तर कड़े होते गये। योजनाओं में व्यय की जाने वाली बड़ी-बड़ी धनराशियाँ एवं उत्पादन स्तर पर असफलता के कारण जो विदेशी विनमय सकट उत्पन्न हुआ उसका हल निकालने के लिए सरकार ने प्रायः सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इन वस्तुओं के आयात लाइसेंसों के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था रही है। भारतीय निर्यातों की भी यही स्थिति

है क्योंकि लाइसेंस लेना निर्यातको के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया। अतः भारत के आयात निर्यात पूर्णतः सरकारी नीति के अनुसार ही हो सकते थे। सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी विदेशी व्यापार में भाग लेने लगी। इस कार्य हेतु सरकार कई निगम स्थापित की जैसे राजकीय व्यापार निगम, भारतीय काजू निगम, हस्तकला एवं हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, प्रोजेक्ट एण्ड इंक्विपमेन्ट निगम आदि।

भारत का विश्व व्यापार में घटती हिस्सेदारी – स्वतन्त्रता के पश्चात के वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा है यह सच है परन्तु यह वृद्धि संसार के कुल व्यापार की तुलना में शिथिल है। इस बात का अनुमान निम्न तालिका द्वारा लगाया जा सकता है।

तालिका संख्या-2 10

आजादी के समय भारत का विश्व व्यापार में भाग

वर्ष	मिलियन डालर में		
	विश्व निर्यात	भारत के निर्यात	भारत का प्रतिशत भाग
1951	7800	1611	2 11
1961	117400	1387	1 2
1981	1100000	5000	0 49

विश्व व्यापार में भारत के घटते हुए भाग का मुख्य कारण यह है कि भारत के निर्यात अभी भी परम्परागत हैं तथा नयी वस्तुओं के निर्यातों का योगदान विशेष उल्लेखनीय नहीं हो पाया है। यद्यपि 1991 में उदारीकरण के बाद स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

किसी भी देश का नियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रवैगिक व्यापारिक नीति का होना आवश्यक है एक देश प्रवैगिक व्यापारिक नीति के अन्तर्गत यह निर्धारित करता है। कि किस प्रकार तथा किस देश के साथ व्यापार किया जाय कि लाभ हो। भारत की व्यापारिक नीति इस सन्दर्भ में काफी लोच पूर्ण रही है। स्वतन्त्रता के तत्कालीन वर्षों में देश का व्यापारिक ढाँचा औपनिवेशिक था। तत्पश्चात् व्यापार का सम्बन्ध विदेशी सहायता से जुड़ गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में बड़ा परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1970-71 में 27.7 प्रतिशत का हिस्सा भारतीय विदेशी व्यापार के कुल आयातों में था। जो घटकर 1974-75 में मात्र 16.3 प्रतिशत ही रह गया था, इसी प्रकार भारत द्वारा अमरीका को किए जाने वाले निर्यात भी क्रमशः घटे। 1971-72 में भारत के निर्यातों में अमरीका का हिस्सा 16.4 प्रतिशत था जो 1974-75 में घटकर केवल 11.4 प्रतिशत ही रह गया।

भारत के कुल आयातों में इंग्लैण्ड का हिस्सा भी घटता बढ़ता रहा है। 195-56 में भारत के कुल आयातों में इंग्लैण्ड का हिस्सा 25.4 प्रतिशत था। 1970-71 में घटकर केवल 7.8 प्रतिशत ही रह गया। पर अगले वर्ष स्थिति में कुछ सुधार हुआ और कुल आयातों का हिस्सा भारतीय विदेशी व्यापार में 12.7 प्रतिशत हो गया। इसके पश्चात् क्रमशः कुल आयातों का प्रतिशत घटता ही जा रहा है। 1974-75 में इसका हिस्सा 4.8 प्रतिशत हो गया। भारत का निर्यात में भी ह्रास होता रहा है। भारत का जो हिस्सा 1970-71 में 11.1 प्रतिशत था 1974-75 में घटकर केवल 9.3 प्रतिशत ही रह गया। परन्तु इसके ठीक विपरीत रूस (सोवियत संघ के विघटन के पूर्व) और भारत के विदेशी व्यापार में व्यापारिक सम्बन्धों में दिनों दिन सुधार होने के कारण अप्रत्याशित प्रगति हुई। भारत के कुल आयातों में रूस का हिस्सा वर्ष 1951-52 में जो कुल 0.1 प्रतिशत ही था वर्ष 1970-71 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया इसी क्रम में 1974-75 में कुल आयातों का हिस्सा बढ़ कर 9.0 प्रतिशत हो गया। निर्यातों में भी क्रमशः वृद्धि होती रही है। वर्ष 1951-52 में कुल निर्यात मात्र 9 प्रतिशत ही था 1970-71 में बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गया किन्तु 1974-75 में घटकर 12.7 प्रतिशत हो गया। देश के व्यापार में अमरीका ब्रिटेन तथा रूस के अतिरिक्त जर्मनी जापान आस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, पोलैण्ड, चेकोस्लाविया आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मिस्र तथा बंगलादेश के साथ व्यापार में कुछ ह्रास हुआ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हाल के कुछ वर्षों में देश का व्यापार बहुविध हो गया है तथा यह प्रवृत्ति देश के लिए हितकर है।

अध्याय तीन

विभिन्न आयात-निर्यात नीतियाँ एवं हमारा विदेशी व्यापार

अध्याय – 3

विभिन्न आयात-निर्यात नीतियाँ एवं हमारा विदेशी व्यापार

आजादी के पहले भारत की अपनी स्पष्ट व्यापारिक नीति नहीं थी, यद्यपि सरकार ने विभेदात्मक संरक्षण की नीति (Discriminating Protection) 1923 से ही अपनायी थी ताकि विदेशी प्रतियोगिताओं से कुछ उद्योगों की रक्षा की जा सके। भारत की कोई स्पष्ट व्यापारिक नीति आजादी के पश्चात् ही सामने आ सकी, क्योंकि तब से ही व्यापारिक नीति को, सामान्य आर्थिक नीति के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। आजादी के पश्चात् मुख्यतः योजनाकाल में भारतीय व्यापारिक नीति को अर्थव्यवस्था में विकास लाने तथा अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया गया। व्यापारिक नीति प्रारम्भ में आयात के नियन्त्रण तथा निर्यात के प्रोत्साहन पर आधारित थी। व्यापारिक नीति का मुख्य आधार आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन को तीसरी योजना के पूर्व कम महत्व दिया गया था, किन्तु बाद में व्यापारिक नीति आयात की उदारता तथा साथ ही निर्यात सम्बर्धन पर आधारित हुई।

आजादी के पश्चात भारत के सम्यक विकास हेतु आयात-निर्यात नीति की आवश्यकता महसूस की गयी। चूँकि स्वतन्त्रता के पश्चात् देश का भुगतान सन्तुलन सदैव प्रतिकूल रहा और इन्हीं कारणों से भुगतान सन्तुलन भी विपक्ष में बना रहा। इसके लिए अनेक उपायों के अतिरिक्त देश में एक उचित व्यापार नीति को अपनाया जाना परम आवश्यक है। एक उत्तम व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यातों एवं आयातों में इस प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करना है कि देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सके तथा देश आत्मनिर्भर हो सके। देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने पर आर्थिक विकास सम्भव किया जा सकता है। देश की उत्पादित एवं विदेशों से आयातित, आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति पर ही औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति निर्भर करता है। देश के निर्यात में वृद्धि होना भी परम आवश्यक है। व्यापारिक नीति का मुख्य उद्देश्य आयातों को सीमित करना व निर्यातों को प्रोत्साहित करना, देश में आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करना, निर्यात प्रोत्साहित करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना, उचित मूल्य पर घरेलू बाजार में वस्तुओं का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण किया जाना, देश की आयात प्रतिस्थापित वस्तुओं

के उद्योगों की स्थापना व उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना, निर्यात क्षेत्र में अतिरेक का सृजन व निर्यातों में वृद्धि करना। भारतीय व्यापारिक नीति को हम अध्ययन की दृष्टि से व्यावहारिक रूप में तीन भागों में बाँट सकते हैं¹ —

- (अ) आयात नीति
- (ब) निर्यात नीति
- (स) विदेशी व्यापार की सगठनात्मक नीतियाँ

(अ) आयात नीति

सरल अध्ययन के लिए हम आयात नीति को दो भागों में बाँट सकते हैं —

- (i) नियोजन से पूर्व आयात नीति
- (ii) योजना अवधि में आयात नीति

(i) नियोजन से पूर्व आयात नीति आजादी के पूर्व यदि हम देश की आयात नीति को देखें तो यह पायेंगे कि इस देश की आयात नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था तथा ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का आयात किया जाना था परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् विकासजनित आयात नीति को अपनाया गया। वस्तु स्थित यह थी कि 1951 के पूर्व विकास से सम्बन्धित कोई आयात नीति थी ही नहीं। इसके पूर्व समय-समय पर सरकार ने जो आयात नीति अपनाई थी वह केवल तत्कालीन समस्याओं के निराकरण से सम्बन्धित थी, दीर्घकालीन आर्थिक विकास से प्रभावित नहीं थी। 1951 के पूर्व विकास जनित आयात नीति के निर्धारक तत्वों में मुख्यतया आयातों की प्रकृति इस ढंग से रखना कि उससे निर्यात प्रोत्साहन में सहायता मिले, उन वस्तुओं के आयातों को प्रोत्साहित करना जिससे औद्योगिकरण में सहायता मिले, देश में उत्पादित होने वाले वस्तुओं के आयातों को रोकने का प्रयास, विदेशी विनमय की सुरक्षा हेतु आयातों को सीमित करना आदी। 1949-52 में विवेचनात्मक आयात नीति को अपनाया गया तथा डालर क्षेत्र से आयातों को प्रतिबन्धित कर दिया गया। इंग्लैण्ड से उदार आयात नीति को जारी रखा गया। 1949 में अवमूल्यन के कारण आयातों की कठोर नीति अपनायी गयी। अवमूल्यन से निर्यात बढ़े तथा आयातों को प्रतिबन्धित करने से भुगतान शेष की स्थिति में सुधार

¹ डॉ० एस०एन० लाल — पेज 182

नोट — विदेशी व्यापार की सगठनात्मक नीतियों का विस्तृत विवरण हम अगले अध्याय में प्रस्तुत करेंगे।

हुआ। कठोर आयात नीति के उपरान्त भी खाद्यान, मशीनो व कच्चे माल के आयात पर उदार नीति अपनायी गयी। भारत मे 1 अप्रैल, 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई और उसके साथ ही अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास की रुपरेखा सामने आयी। विकास सम्बन्धित आर्थिक नीतियो को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अपनी आयात नीति को समन्वित करने का प्रयास किया। इस तरह से अप्रैल 1951 मे ही दीर्घकालीन विकासात्मक योजनाओ की पृष्ठ भूमि मे आयात नीति का निर्धारण किया गया। भारतीय आयात नीति का अध्ययन करने के पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आयात एव भुगतान सन्तुलन के बीच एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध है अर्थात् एक सीमा तक भुगतान सन्तुलन आयात के स्वभाव एव मात्रा को प्रभावित करना है।

सन् 1950 मे श्री जी०एल० मेहता की अध्यक्षता मे सरकार ने आयात नियन्त्रण जॉच समिति नियुक्त की, जिसने देश की औद्योगिकरण की समस्या एव सीमित साधनो को देखते हुए आयात नीति के सम्बन्ध मे निम्न लिखित सिफारिशो की -

- (1) सरकार तथा व्यापारिक इकाइयो द्वारा समग्र आयात की मात्रा को प्राप्त विदेशी विनमय तक सीमित होना।
- (2) प्राप्त विदेशी विनमय के साधनो को कृषि एव औद्योगिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एव उपभोक्ताओ को अति आवश्यक आवश्यकताओ की सतुष्टि के लिए वितरित करना।
- (3) उन वस्तुओ के सम्बन्ध मे कीमत मे होने वाले बदलाव को नियन्त्रित करना जिसकी कीमत सामान्य कीमत स्तर से अधिक हो गया हो।

मेहता समिति का यह भी मत था कि समयावधि पर आवश्यकता के अनुसार आयात मे प्रथमिकताओ का निर्धारण किया जाय। तत्कालीन परिस्थितियो को देखते हुए समिति ने आयात के सम्बन्ध मे प्राथमिकता का क्रम भी निर्धारित किया। मेहता समिति की सिफारिशो को सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस तरह से मेहता समिति ने भारत मे आयात नीति को एक निश्चित दिशा अर्थात् आयाम प्रदान किया।

हमारी आयात नीति का मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करना है। इस नीति मे लिए गये निर्णयो के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आये है। देश विभिन्न ऐसी वस्तुओ के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हुआ है। जिसके लिए पहले विदेशो पर निर्भर रहना पडता था। यह विदित है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए मशीन एव अन्य वस्तुओ के लिए विदेशो पर पूर्णत निर्भर रहना पडता था, परन्तु अब ऐसी स्थिति नही है, अब कम मशीनो के आयात पर भी हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जा रही है।

कुछ समय पहले तक विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति आयातों द्वारा ही की जाती थी, इसके लिए आयातों की मात्रा न्यूनतम किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ शोधों के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किन-किन उद्योगों में आयातित कच्चे माल की जगह देश में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ — तौबा। यह जानते हुए कि देश में तौबे की मात्रा खानों में पर्याप्त नहीं है तो तौबे के बदले एल्युमिनियम का अत्याधिक उपयोग किया जा रहा है जिससे कच्चे माल के प्रतिस्थापन द्वारा भी देश करोड़ों रुपये का विदेशी विनमय का बचत कर रहा है।

आयात प्रतिस्थापन का एक ज्वलन्त उदाहरण पेट्रोल एव पेट्रोलियम पदार्थों का आयात भी है। आजादी से पूर्व हमें कुल माँग का 90 प्रतिशत भाग आयात द्वारा पूरा करना पड़ता था। विगत में यह माँग कई गुनी और अधिक हो गयी। जबकि माँग की तुलना में आयातों की मात्रा में कम वृद्धि हुई एव इनके मूल्यों में वृद्धि के कारण आयात बिल भी काफी चढ़ गया। इसके मद्देनजर देश में ही इसकी पूर्ति हेतु खोज का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप गौहाटी, बरौनी, कोहली, कोचीन, व चन्नेई में तेलशोधक कारखानों की स्थापना हुई है। बाम्बे हाई में तेल का विशाल भण्डार 'सागर सम्राट' का पता चला तथा चार कुओं से उसी समय तेल निकालना प्रारम्भ भी कर दिया गया। 1950-51 में शोधित पेट्रोलियम पदार्थों का 2 लाख टन उत्पादन था। वह बढ़ कर 1973-74 में 2 करोड़ टन हो गया। बाम्बे हाई में प्राप्त स्रोतों से 1982-83 तक खनिज तेल का उत्पादन 120 लाख टन के लगभग हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप देश पेट्रोल एव पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरतों का अधिकांश भाग स्वयं के उत्पादन से करने लगा।

शक्कर के क्षेत्र में देश 1955-56 तक माँग का अधिकांश भाग आयात द्वारा पूरा करता था। परन्तु 1982-83 के पूर्व ही देश शक्कर की कुल माँग को पूरा ही नहीं बल्कि पर्याप्त मात्रा में विदेशों में निर्यात भी करने लगा। इसी प्रकार सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सिलाई की मशीन, साइकिलों, रेडियो आदि के क्षेत्र में देश की माँग की पूर्ति 80-90 प्रतिशत आयात द्वारा करना पड़ता है। परन्तु विगत 80 से 90 प्रतिशत भागों को देश में ही पूरा करने लगे हैं। इसी प्रकार इस्पात, एल्युमिनियम, कागज, गत्ता, कृत्रिम रेशे एव सूत तथा ब्लीचिंग पाउडर के क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन द्वारा प्रगति हुई।

(ii) योजना अवधियों में आयात नीति :- प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रधानता दी गयी फिर भी अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की सर्वथा अवहेलना नहीं की गई। अतएव स्वाभाविक था कि पूँजीगत वस्तुओं तथा औद्योगिक कच्चे माल के आयातों को प्रोत्साहित किया जाता।

नीति को निर्धारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सीमित साधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाय। यद्यपि स्टर्लिंग शेष पर्याप्त मात्रा में थे फिर भी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्राकृतिक कारणों के फलस्वरूप खाद्यान्न की पूर्ति में गिरावट आ गई, जिससे खाद्यान्नो का आयात करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार को नियन्त्रित एवं सन्तुलित आयात नीति की आवश्यकता महसूस की गई। परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा गया कि आयात नीति देश के उद्योगिकरण में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करे। गुणात्मक आयात नीति को सरकार ने अपनाया। उन वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण लगाया गया जिनको उत्पादित करने की क्षमता घरेलू उद्योग में थी तथा जिन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक था। अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रशुल्क की दर बढ़ा दी गई पर कच्चे माल तथा पूँजीगत वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित नहीं किया गया। प्रथम योजना के उत्तरार्द्ध में देश में खाद्यान्न की स्थिति सुधर जाने से सरकार ने एक बार पुनः उदार आयात नीति को अपनाया। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में मशीन, औद्योगिक कच्चा माल तथा खाद्यान्नो के आयात के सम्बन्ध में उदार नीति अपनायी गयी। राज्य व्यापार निगम की स्थापना इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता रही। भारतीय सरकार ने 18 मई, 1956 को इस निगम की स्थापना की जो कि मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का परिणाम था। इस निगम के माध्यम से सरकार ने अनेकों व्यापारिक समझौता भिन्न-भिन्न राष्ट्रों से किये। इन व्यापारिक समझौतों के अनुसार आयात का भुगतान निर्यात के माध्यम से होना था, जिसका महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि देश को निर्यात की सुविधा मिली। निजी व्यापार को स्वीकार न करने वाले पूर्वी यूरोप के देश भी इस समझौते में सम्मिलित हुए।

द्वितीय योजना जो कि 1954-55 तथा 1955-56 में अपनायी गयी के प्रथम वर्ष से ही उदार आयात नीति का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देने लगा। इस योजना में उदारता के साथ ही साथ नियंत्रित आयात नीति का सरकार ने अनुसरण किया। उद्योगिकरण की दृष्टि से भारतीय फर्मों को मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं के आयात के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में आयात में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। निर्यात में उतनी वृद्धि नहीं हो सकी कि आयात की वृद्धि को पूरा किया जा सके। परिणामतः योजना के प्रारम्भ में जितना स्टर्लिंग शेष था सब समाप्त हो गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अत्यन्त ही गम्भीर विदेशी विनमय सकट सामने आ गया। जिसके कारण जनवरी 1957 से सरकार ने प्रगतिशील रूप से नियंत्रित आयात नीति को स्वीकार किया तथा यह निर्णय लिया गया कि आन्तरिक बजट के साधनों एवं बाह्य बजट साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करने के

लिए “आयात लाइसेंसिंग नीति” को वित्त वर्ष से सम्बन्धित किया जाय। आयात की लाइसेंसिंग पर नियन्त्रण लगाया जाय।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय आयात नीति शुरू से ही नियन्त्रण की नीति रही। उक्त अवधि में नियन्त्रण को और अधिक सख्त कर दिया गया। उपभोग की वस्तुओं का आयात लगभग नगण्य हो गया, इसके अतिरिक्त मशीनों के आयात के भी सम्बन्ध में सरकार ने गुणात्मक नीति का प्रयोग किया। सरकार ने समय-समय पर आयात के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित कीं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रारम्भ तक देश का समस्त स्टर्लिंग-अतिरेक न केवल समाप्त हो गया था बल्कि भारतीय भुगतान सन्तुलन में भी लगातार घाटा चल रहा था।

इस योजना काल में सरकार ने आयात नीति के अन्तर्गत आर्थिक विकास एवं उद्योगिकरण से सम्बन्धित नीतियों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए समय-समय पर कुछ समितियों की स्थापना की। मार्च 1961 में श्री मुदालियर की अध्यक्षता में आयात-निर्यात नीति की स्थापना की गई। समिति का मुख्य कार्य आयात नीति का मूल्यांकन करना था। समिति का मत था कि सर्वप्रथम आयात एवं निर्यात के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में आयात में प्राथमिकता उन वस्तुओं को दी जानी चाहिए जिससे निर्यात में बढोत्तरी हो सके। इस तरह समिति ने यह भी कहा कि आयात में लगातार कटौती आर्थिक विकास में रुकावट ला सकती है। समिति का यह भी कहना था कि विदेशी व्यापार को देश के आर्थिक विकास में सहायक बनाना है।

समीक्षात्मक रूप में यह कहा जा सकता है कि मुदालियर की अध्यक्षता में जो आयात नीति की समीक्षा की गयी, उसमें अनुरक्षण एवं विकासात्मक आयात देश के लिए आवश्यक माने गये। इनके अनुसार निम्न क्षेत्रों में नवीन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए—

- (1) निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले उद्योग।
- (2) कच्चा माल एवं आयात वाले सामान को उत्पादित करने वाले उद्योग।
- (3) परिवहन एवं शक्ति के अभाव में उद्योग में व्यवधान उत्पन्न करने वाले उद्योग।
- (4) घरेलू कच्चे माल पर पूर्ण रूप से आधारित उद्योग।

मई, 1962 में व्यापार-मण्डल की स्थापना सरकार ने की। व्यापार मण्डल का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को प्रवैगिक रूप प्रदान करना था अर्थात् नये बाजार एवं नयी वस्तुओं में निर्यात की सम्भावनाओं का अध्ययन करना था। इसी तरह 1962 में Technical Panel of

Import Substitution की स्थान हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य आयात की स्थानापन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में अध्ययन करना था। यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना अवधि में सरकार ने घरेलू उद्योगों के विकास के आधार पर विकास में स्वावलम्बी होने के दृष्टिकोण से आयात प्रतिस्थापन की नीति के ऊपर विशेष बल दिया गया।

सन् 1962 के चीनी हमले से भी तत्कालिन आयात नीति प्रभावित हुई। आयात निर्यात नीति में कुछ परिवर्तन देश की सुरक्षा के सन्दर्भ में लाये गये। सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के आयात पर बल दिया गया। उन मशीनों को आयात में प्राथमिकता दी गई जो युद्धकालीन सामग्रियों के उत्पादन से सम्बन्धित थी। इन सबके आलावा औद्योगिक विकास के बढ़ते स्तर के कारण भी आयात में वृद्धि हुई।¹

1966 का अवमूल्यन : — अवमूल्यन से उदार आयात नीति को अपनाया गया तथा 59 प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल, कल पूर्ण, आदि के आयात को उदार बनाया गया, जिससे उद्योगों द्वारा पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सके। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के आयात को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर आयात लाइसेन्स प्रदान किये गये। इसके लिए निर्यातकों के नाम दर्ज करने की नीति चालू की गई।²

चौथी पंचवर्षीय योजना काल की आयात नीति :— आयात नीति की घोषणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व ही कर दी जाती है, अनेकोंबार सरकार ने यह घोषणा स्पष्ट की है कि हमारी आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य आयातों पर नियन्त्रण लगाना न होकर अपनी विदेशी व्यापार नीति को विवेकपूर्ण आधार प्रदान करना है। जिनमें खाद्यान्नों एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति करना, कृषि उद्योगों एवं परिवहन के दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल, साज-सज्जा एवं यन्त्रों की पर्याप्त पूर्ति करना तथा, उन उद्योगों का विस्तार करना जिनमें अन्ततः हमारा निर्यात व्यापार बढ़ने की आशा है। अनेक ऐसी वस्तुओं के आयात का पूर्ण अधिकार सरकार अपने नियन्त्रण में ले लेती है, जिनके लिए निजी क्षेत्र को छूट देना उपयुक्त नहीं समझा जाता है उक्त दृष्टिकोण से 1969-70 में 38 एवं 1970-71 में 22 वस्तुओं के आयात-व्यापार पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण में ले लिया गया। 1971 अप्रैल 30 को घोषित 1971-72 आयात नीति के अधीन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा आयात हेतु

¹ बरला अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा — 3 पृष्ठ 434

² वार्षिक अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र — पेज नं० 143

51 वस्तुओं का उक्त सूची में सम्मिलित किया गया। किन्तु इस योजना काल में अपनायी गयी आयात नीति में इसका ध्यान रखा गया कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों, लघु औद्योगिक इकाइयों, निर्यात व्यापार में सलग्न औद्योगिक इकाइयों तथा पिछड़े इलाकों में स्थापित उद्योगों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताएँ अवश्य पूरी की जाय। 1972-73 में 54 उद्योगों को इनकी उत्पादन क्षमता दुगुनी करने के साथ-साथ उन्हें विदेशी विनमय का विशेष आवंटन किया गया तथा अतिरिक्त कच्चे माल के आयात की छूट दी गई। इसके अलावा विदेशी विनमय की उपलब्धि को देखते हुए उद्योगों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहले ही की तरह पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

यद्यपि देश की आयात नीति में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया। फिर भी विदेशी सहायता की सीमित उपलब्धि को देखते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को आगे बढ़ाने हेतु आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम लगातार चलाये गये। आयात प्रतिस्थापन के लिए चुनी गई वस्तुओं के चुनाव में देश में कच्चे माल तथा साज-सामान की उपलब्धि एवं वस्तु विशेष की अनिवार्यता को ध्यान में रखा गया है। 1972-73 में घोषित आयात नीति में 160 ऐसी वस्तुओं के आयात को निषिद्ध कर दिया गया जिनकी पहले वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात करने की छूट थी। इसके पूर्व 1971-72 में 170 वस्तुओं पर आयात पूर्णतः प्रतिबन्धित थी। इसके अलावा 1972-73 में 87 वस्तुओं के आयात को प्रतिबन्धित किया गया। पूर्णतः प्रतिबन्धित वस्तुओं में अनेकों प्रकार के बाल-बेयरिंग, टेपर्ड रोलर वेयरिंग, 21 प्रकार के रंग, 26 प्रकार के रसायनिक पदार्थ, सामुद्रिक डीजल इंजन, बिजली के पखों में लगने वाले कुछ पुर्जें, सूत आदि सम्मिलित थे। उन वस्तुओं को जिनका आयात सीमित किया गया उनमें स्टेनलैस स्टील के पाइप व ट्यूब, द्विधातु वाली पट्टियाँ, मिश्रित धातु वाले पेन पाइण्ड्स, नीडल, बुशेज एवं वेयरिंग, 14 प्रकार की रंग बनाने में प्रयुक्त सामग्री, लीड ग्लास ट्यूबिंग, 24 प्रकार के रसायन, कार्बन स्टील आदि सम्मिलित थे।

इन सभी बाधाओं के होते हुए भी 1972-73 की आयात नीति का प्रमुख प्रयोजन विनियोग, औद्योगिक लाभों, निर्यात, की मात्रा तथा रोजगार के स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के बिना देश के कुल आयात-बिलों में कटौती करना था। इस योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973-74 की आयात नीति भी 1972-73 की नीति के ही अनुरूप थी।

1974-75 की आयात नीति — चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अपनायी गयी सफलतापूर्ण आयात-नीति के निर्धारित करने पर भी विश्व के बाजारों में वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों तथा भारत में कृषि उत्पादन की अनिश्चिता के कारण हमारा आयात-बिल बढ़ता गया। हमारे विदेशी विनमय

साधनों पर बढ़ते हुए दबाव के कारण यह आवश्यक समझा गया कि 1974-75 में पहले की आयात नीति की आधारभूत विशेषता एव ढाँचे को यथावत रखते हुए निर्यात व्यापार में सलग्न उद्योगों के लिए हमारी आयात नीति में प्राथमिकता पूर्ण स्थान रखा जाय। 1974-75 में आयात लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निर्यात व्यापार में सलग्न कुछ उद्योगों को उनकी निष्पत्ति के आधार पर प्राथमिकता दी गई। अतिरिक्त कल पूर्जों के आयात में अधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया, तथा निर्यात व्यापार में सलग्न सस्थाओं को निर्यात बढ़ाने हेतु अधिक सुविधाएँ देने की घोषणा की गई।

उद्योगपतियों तथा प्रतिष्ठित आयातकर्ताओं के लिए निर्यात करने हेतु आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाया गया। जितना लाइसेन्स लघु औद्योगिक इकाइयों को 1973-74 में आयात करने हेतु दिया गया था उसके 50 प्रतिशत मूल्य का आयात 1974-75 के प्रथम छ माह में ही आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसे "रिपीट आपरेशन" की सजा दी गई।

1973-74 में दिये गये आयात लाइसेन्सों के आधार पर ही निर्यात करने वाले उद्योगपतियों को "रिपीट आपरेशन" की सुविधा 1974-75 में भी दी जाती रही। किन्तु यह आदेश दिया गया कि लाइसेंसिंग अधिकारियों से नये सूत्र के लिए पुराने आयात लाइसेन्स के उपयोग की छूट एव रिलीज आर्डर प्राप्त करने के पूर्व वे पुनः प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। उक्त सुविधा के अन्तर्गत उपयोग में लिए गये आयात लाइसेन्सों का मूल्य 1 अप्रैल, 1974 से डेढ़ वर्ष के भीतर प्राप्त सामान्य आयात अधिकारों को देखकर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार प्रतिष्ठित आयातकर्ताओं को 1973-74 में प्राप्त आयात कोटे का उपयोग 1974-75 में करने की छूट की शर्तों की अनुपालन के आधार पर प्रदान की गयी।

निर्यात निष्पत्ति के आधार पर एव प्राथमिकता के आधार पर वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को आयात लाइसेन्स देने की नीति में 1974-75 में कुछ संशोधन किया गया। 1973-74 के वर्ष में जिन औद्योगिक इकाइयों ने अपना उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात किया था उनकी उत्पादन क्षमता को अगले वर्ष बढ़ने हेतु दी गई सुविधाओं के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर उनमें कच्चे माल एवं साज-सज्जा की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखी गई। किन्तु गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के इकाइयों को कच्चा माल एवं साज-सज्जा के आयात हेतु प्राथमिकता के आधार पर अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करने को कहा गया। कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आयात करने वाली इकाइयों को खुले विदेशी विनमय के बदले अपनी आवश्यकता

का और अधिक भाग आयात करने की छूट दी गई। उन लघु औद्योगिक इकाइयों को जो अपने कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से कम निर्यात करने वाली हो को भी आयात हेतु उक्त सुविधा दी गई, जो 25 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करने वाली बड़ी इकाइयों को उपलब्ध थी। वे छोटी ईकाइयाँ जिनका निर्यात 1972-73 की तुलना में 1973-74 में दुगुना था के लिए भी यही सुविधा रखी गई।

अनेक उद्योगों में उनके उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग के लिए अतिरिक्त कल पूर्ण के आयातों में 1974-75 में ढील दी गयी। आयातित मशीनों के मूल्य का ढाई प्रतिशत बड़ी इकाइयों को तथा 4 प्रतिशत आयातित मशीनों के कल पूर्णों के रूप में मँगाने की छूट दी गई। यह अनुपात 1973-74 तक क्रमशः 2 प्रतिशत व 3 प्रतिशत था।

1974-75 में प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन देकर उनके निर्यातों में वृद्धि हेतु उदारतापूर्वक आयात अधिकार देने की व्यवस्था रखी गई। गैर परम्परागत वस्तुओं की न्यूनतम निर्यात-राशि 25 लाख ही आयात अधिकार प्रमाण पत्र लेने के लिए रखी गई। किन्तु उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु अवेदक निर्यातकर्ता के लिए यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया कि 3 करोड़ रुपये के निर्यात तक उनकी निर्यात वृद्धि दर पिछले वर्षों में 10 प्रतिशत था या इससे अधिक रही है। उन निर्यातकर्ताओं में से प्रत्येक के द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुएँ निर्यात की जाती रही हैं। उन्हें उक्त प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण हेतु यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है कि उनके निर्यात विगत कुछ वर्षों में कम से कम 5 प्रतिशत रहे हैं। प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओं के लिए सरकार ने यह भी घोषणा करना अनिवार्य कर दिया कि उक्त में से प्रत्येक द्वारा निर्यातित वस्तुओं का 60 प्रतिशत उन औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित किया गया था जिन्हें कच्चा माल एवं सामग्री बेची गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की सस्थाओं का आयात व्यापार में अधिकार बढ़ाने हेतु 1974-75 में 10 नई वस्तुओं के आयात अधिकार इन्हें सौंपे गये। इस प्रकार 1974-75 के अन्त तक इन सस्थाओं को 210 वस्तुओं के आयात का अधिकार प्राप्त हो गया।

1973-74 तक देश में वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने हेतु पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित 220 वस्तुओं के अलावा 1974-75 में 75 नई वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया। शेष वस्तुओं के आयातों के हतोत्साहित करने के लिए उन पर विद्यमान आयात कर की दर में भी वृद्धि कर दी गई। 60 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक आयात कर वाली वस्तुओं पर विद्यमान

सहायक कर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया।¹ विस्की, ब्राडी, जिन एव अन्य प्रकार की स्पिरिट पर आधारभूत आयात कर 60 रु0 प्रति लिटर या मूल्य के 200 प्रतिशत में, जो भी अधिक थी, से बढ़ाकर 80 रु0 प्रति लिटर या मूल्य के 270 प्रतिशत में, जो भी अधिक हो, कर दी गई।

1975-76 की आयात नीति — इस वर्ष की आयात नीति की विशेषताओं को हम निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

विगत वर्ष में उपभोग की गई आयातित सामग्री के आधार पर इस वर्ष हेतु स्वमेव आयात लाइसेन्स की प्राप्ति हो सकेगी।

विगत वर्ष तक विद्यमान “प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों” की सूची के स्थान पर अब “विशिष्ट उद्योगों” को नई सूची के आधार पर अतिरिक्त आयात लाइसेन्स दिये गये।

इस वर्ष में 20 प्रतिशत या इससे अधिक उत्पादन का निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाइयों को पूरक आयात लाइसेन्स दिया गया। 29 उद्योगों को उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। शीघ्रतापूर्वक आयात लाइसेन्स जारी करने का प्रस्ताव भी इस नीति में था।² विशिष्ट उद्योगों में सलग्न छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक के आयात अधिकार दिये गये। प्रत्येक उद्योग के लिए निर्यात के बदले कितना आयात लाइसेन्स दिया गया, इसकी भी स्पष्ट घोषणा इस आयात नीति के अन्तर्गत की गई।

सरकार ने सभी प्रतिष्ठित निर्यातकर्ताओं को दी गई आयात सुविधा में भी परिवर्तन कर दी। न्यूनतम 50 लाख की वस्तुओं का निर्यात ऐसे प्रत्येक निर्यातकर्ता को करना पड़ा, जबकि विगत वर्ष तक यह धनराशि 25 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा थी। उक्त नीति के अन्तर्गत आयात प्रमाण-पत्र के नवनीकरण हेतु प्रत्येक प्रतिष्ठित निर्यातकर्ता को यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक था कि जिन वस्तुओं के निर्यात के बदले आयात अधिकार प्राप्त करना चाहता है। उनका न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग या 25 लाख रुपये के मूल्यों की वस्तुओं में जो भी कम हो, लघु इकाइयों द्वारा निर्मित किया गया था।

1976-77 की आयात नीति — भारत सरकार द्वारा लोक सभा में 14 अप्रैल, 1976 को वर्ष 1976-77 की आयात नीति घोषित की गई। यह नीति भी आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने

¹ बरला अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा — 3 पेज न0 435

² द इकोनामिक टाइम्स, 8 अप्रैल, 1975

के उद्देश्य पर आधारित थी। अब तक की सर्वाधिक उदार एव लचीली नीति यह थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में उद्यमियों के प्रति इस विश्वास एव आस्था को दुहराया गया कि वे उत्पादन में वृद्धि करके निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायक होंगे। दूसरे, राजकीय सस्थाओं द्वारा आयातित कच्चे माल का आवंटन सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं में किया जाएगा तथा इसके लिए लाइसेन्स प्रदान करने वाले अधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। इसकी तीसरी विशेषता में यह था कि सामान्य लाइसेन्स व्यवस्था को और अधिक उदार बनाया गया तथा पहले की अपेक्षा आयात परिपूर्ति अधिकारों को बढ़ा दिया गया। चौथी विशेषता में, यह व्यवस्था थी कि अगले सत्र में मशीनों के आयात को अधिक उदारता पूर्वक करने दिया जाय। इसकी पाँचवी विशेषता यह थी कि लघु औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इसकी अन्तिम विशेषता यह थी कि आयात हेतु समस्त औपचारिकताओं एव प्रक्रियाओं को काफी सरल कर दिया गया था।¹

इस आयात नीति का अधिक विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न बिन्दुओं द्वारा वर्णन कर सकते हैं —

स्वचालित लाइसेन्स प्रणाली — यह प्रणाली 1975-76 में ही लागू की गई। इसमें वास्तविक उपयोग करने वालों को सीधे ही आवश्यक कच्चे माल एव पूर्जों को आवंटन करने की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में उत्पादन में वृद्धि को जारी रखने के लिए इस प्रणाली को 1976-77 में भी जारी रखा गया। इस सत्र में इसे और अधिक लचीला बनाया गया। अतिरिक्त कच्चे माल व पूर्जों की आवश्यकता वाले औद्योगिक इकाइयों भी लाइसेन्स अधिकारियों को पूरक लाइसेन्स जारी करने हेतु आवेदन कर सकते थे। किन्तु उन्हें अपनी जामिन (Sponsoring) सस्थाओं के माध्यम से ही आवश्यक कदम उठाने होते थे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि चाय, काफी, सूती वस्त्रों को इस नीति में पूरक आयात लाइसेन्स के हकदार उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया था।

बिचौली सस्थाओं के माध्यम से आयात :— इस व्यवस्था के अधीन राजकीय व्यापार सस्थाएँ इन वस्तुओं को सीधे लाइसेन्सिंग अधिकारियों की अनुमति के बिना उपभोक्ता को दे सकते थे। उक्त व्यवस्था में लगभग 43 वस्तुओं की पूर्ति की गई। जिसमें 11 वस्तुएँ मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, 8 स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन तथा, 24 वस्तुएँ स्टील अथोरिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (SAIL) द्वारा वितरित की गई। सीधे आवेदन पत्र, उक्त

¹ State Bank of India, Monthly review, April 1976 (Vol XV No 4)

वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ता, सम्बन्धित सस्थाओं को कर सकते थे। सम्बन्धित सस्था द्वारा आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति करने में समर्थ न होने पर वास्तविक उपभोक्ता लाइसेन्सिंग अधिकारी को आवेदन कर सकता था।

निर्यात की वस्तुएँ एवं प्रतिपूर्ति योजनाएँ :- उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य से रजिस्टर्ड निर्यात करने वालों के लिए आयात नीति में परिवर्तन किए गए। अब वस्तुओं एवं कच्चे माल के आयात की भी छूट दी गई जो देश में उपलब्ध थी। किन्तु या तो जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी या कीमते देश में अन्तराष्ट्रीय स्तर से ऊँची थी तथा इस कारण निर्यातित वस्तुओं की उत्पादन लागतें बढ़ने की आशंका थी। इस परिप्रेक्ष्य में 129 वस्तुओं के निर्यात के बदले नई आयात वस्तुओं के आयात की छूट दी गई। इसमें 83 वस्तुओं के निर्यात पर अधिक परिपूर्ति आयात किए जा सकते थे, जबकि 46 ऐसी नई वस्तुओं को निर्यात सूची में शामिल किया गया जिनके परिपूर्ति आयात किए जा सकते थे।

निर्यात भवन (Export Houses) :- इस स्कीम के अन्तर्गत एक निर्यात सस्थान, मुख्य आयात व निर्यात कन्ट्रोलर को आवेदन करके ही एक्सपोर्ट हाऊस सर्टीफिकेट प्राप्त कर सकता था। मुख्य आयात व निर्यात कन्ट्रोलर से प्रमाण पत्र बिना वाणिज्य मन्त्रालय से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भी, लिए जा सकते थे। किन्तु आयात के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु निर्यात सस्था द्वारा कम से कम 50 लाख रुपये को वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता था। पूर्व में यह न्यूनतम सीमा 25 लाख थी। यह नई सीमा विशिष्ट वस्तुओं के सन्दर्भ में लागू की गई। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के लिए यह सीमा 3 करोड़ रुपये रखी गई। किन्तु लघु औद्योगिक इकाइयों को निर्यात-गृह प्रमाण पत्र दो करोड़ वस्तुओं का निर्यात करने पर भी प्रदान किया जा सकता था। 25 लाख रुपये की न्यूनतम निर्यात सीमा लघु उद्योगों के लिए विशिष्ट वस्तुओं के सन्दर्भ में रखी गई।

कस्टम ड्यूटी :- इस आयात नीति के अनुसार जिन कच्चे माल, पूर्जों आदि को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता था, उसके आयात पर कोई आयात कर नहीं होता था। किन्तु इनके लिए पूर्व में आयात लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक था। प्रारम्भ में यह रियायत 55 निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए दी गई। स्वयं निर्यात करने वाले उत्पादकों को भी यह सुविधा दे दी गई अथवा उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की गई जिन्हें निर्यात गृहों द्वारा मनोनीत किया गया था।

मशीनो का आयात — ऐसे उद्यमियों को जो निर्यात उत्पादन में सलग्न थे, को सम्पूर्ण आयात परिपूर्ति का उपभोग ऐसी मशीनों के आयात करने की छूट दी गई जो प्रतिस्थापन, नवीकरण, रिसर्च तथा विकास के लिए प्रयुक्त की जाती थी। इनमें जिग्स, टूल्स एवं परीक्षण उपकरण भी शामिल किये गये। आयात परिपूर्ति के अन्तर्गत आयात किये जाने वाले यन्त्रों की अधिकतम मूल्य सीमा अब तक निर्धारित थी। किन्तु इस योजना वर्ष में इन सीमाओं को घटा दिया गया। 15 लाख रुपये तक मशीनों के आयातों हेतु अब विज्ञापन देने की कोई जरूरत नहीं थी।

खुला सामान्य लाइसेन्स (OGL) - 1976-77 की आयात नीति में खुली लाइसेन्स नीति का प्रावधान स्पेयर पुर्जों व कच्चे माल के आयात हेतु रखा गया। चमड़े की वस्तुओं के लिए मशीनों का आयात इसी श्रेणी में रखा गया। कुछ लौह एवं इस्पात की वस्तुएँ भी इसी श्रेणी में रखी गईं।

स्पेयर पुर्जे — नई आयात नीति में स्पेयर पार्ट्स की आयात प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया। स्पेयर पुर्जों के आयात हेतु सम्बन्धित आयातकर्ता को केवल यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना था कि मशीनों के रख-रखाव हेतु ये पुर्जे आवश्यक होते हैं। गैर अनुमति प्राप्त पुर्जों के आयात की सीमा पहले लाइसेन्स पर उद्धृत मूल्य की 10 प्रतिशत थी जो 20 प्रतिशत हो गई। परन्तु किसी एक स्पेयर पुर्जे का आयात मूल्य 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

लघु औद्योगिक इकाईयाँ — इस वर्ष आयात नीति के लिए अत्याधिक उदारतापूर्वक व्यवस्था रखी गई थी। इन इकाईयों को सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य के कच्चे माल व पुर्जों के आयात लाइसेन्स दिये गये थे। इनसे अपेक्षा यह थी कि इन उद्योगों की पूरक लाइसेन्स हेतु माग काफी कम हो जायेगी। एकल पारी के आधार पर ही इन उद्योगों की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता रहेगा। परन्तु अविरल रूप से उत्पादन करने वाली इकाईयों के लिए या अन्य परिस्थितियों में किसी अन्य आधार पर भी क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकेगा। पिछले वर्ष तक कोई भी लघु इकाई 10 हजार रुपये तक विदेशी विनमय का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकती थी, किन्तु इस सीमा को इस वर्ष में बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। इस सीमा तक कच्चे माल या यन्त्रों का उपयोग हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी।

1976-77 की आयात नीति की उक्त वर्णित विशेषताओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विगत वर्ष में भारत सरकार आयात प्रतिस्थापन की अपेक्षा निर्यात उत्पादन को अत्याधिक महत्व दे रही थी। हाल ही के वर्षों में निर्यात व्यापार में आशातीत वृद्धि होने के पश्चात् भी हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है तथा आयातों में निर्यातों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हो

रही है। 1974-75 में यह घाटा 1189 95 करोड़ रुपये का था जो 1975-76 में काफी अधिक (1216 20 करोड़ रुपये) हो गया, उस वर्ष हमने 3941 60 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया। यद्यपि भारत को 1975-76 एवं 1976-77 में पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त हुई, तथापि हमारी भुगतान सन्तुलन स्थिति में अनिश्चितता बनी हुई है। 1976-77 में घोषित आयात नीति उत्साहजनक रही थी क्योंकि इसके अन्तर्गत उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया गया, जिसका हम निर्यात करते हैं।

1977-78 के लिये निर्धारित आयात नीति - 27 अप्रैल, 1977 को सरकार द्वारा लोकसभा

में घोषित 1977-78 की नई आयात नीति लगभग पूर्व वर्ष की आयात नीति के अनुकूल थी।¹ फिर भी मूल अन्तर आयात निर्यात प्रणाली को सरल बनाने की प्रक्रिया दृष्टि गोचर होता है। 1977-78 आयात नीति देश में उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और निर्यात की वृद्धि में सहायक होगी। इस आयात नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् थीं

- (1) इसकी प्रमुख विशेषता में आयात निर्यात प्रणाली को सरल बनाना एवं लाइसेन्स देने की सुविधा को विकेंद्रित करने का प्रयास किया गया।
- (2) इस नयी आयात नीति में इस उद्देश्य का ध्यान रखा गया है कि निर्यात की आय से आयात के व्यय को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
- (3) इसके अन्तर्गत देश की औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग करने और आयात में वृद्धि की दर को बढ़ाने का उद्देश्य सामने रखकर कई परिवर्तन किये गये।
- (4) इस नीति की यह भी विशेषता थी कि खुलेआम लाइसेन्स और मुक्त लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत आयात की वस्तुओं की सूची को काफी विस्तृत किया गया। इस उदार नीति के अन्तर्गत लघु उद्योगों को कच्चे माल और पुर्जों के आयात में 20 प्रतिशत वृद्धि की सुविधा दी गई। रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिए इसके अन्तर्गत यह सुविधा प्रदान की गई कि वे अपना कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर ही प्राप्त कर सकते थे।
- (5) इस नीति में जीवन रक्षक और कैंसर के इलाज की औषधियों के साथ-साथ नेत्रहीनो, चिकित्सको, अस्पतालो, चिकित्सा सस्थान की आवश्यकता की वस्तुओं तथा आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के विकास करने में सहायक सामग्री के आयात की व्यवस्था भी थी।

¹ The Economics Times, April - May, 77

- (6) इसमें विज्ञान, टेक्नालोजी और विशिष्ट विषयो पर भारत में अनुपलब्ध पुस्तको के सरलता से आयात की व्यवस्था की गई। कलाकारों के लिए आवश्यक उपकरणों एवं वस्तुओं को भी उदारतापूर्वक आयात करने की सुविधा प्रदान की गई।
- (7) नये उद्योगपतियों और निर्यातकों को सुविधा देने हेतु यह निर्णय किया गया कि सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जाय, जहाँ से आवश्यक सूचनाएँ दी जा सकें। इसके साथ देश में अनेक शारुम का प्रस्ताव था, जिससे आयातित वस्तुओं के सन्दर्भ में तकनीकी एवं अन्य सूचनाएँ उत्पादकों को मिल सकें।
- (8) इसमें आयात लाइसेन्स की स्वीकृति में लगने वाले समय को कम करने का सकल्प किया गया।
- (9) इस विशेषता के अनुसार यह व्यवस्था कि इसे निर्धारित करते समय व्यापार में वृद्धि और औद्योगिक विकास के साथ-साथ जनता के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में वृद्धि का भी ध्यान रखा गया। आयात की उदार नीति का देश के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने हेतु मुख्य आयात-निर्यात नियन्त्रक के कार्यालय में एक विशेष विभाग का गठन किया गया। यह विशेष विभाग समय-समय पर समुचित कदम उठाए ताकि कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उक्त विशेषताओं के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि देश में खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता प्राप्त होने से विदेशी व्यापार में देश को लाभ हुआ। तिल तथा कपास जैसी व्यापारिक फसलों की कमी से देश को प्राप्त होने वाले लाभ का अंश समाप्त हो गया। अतएव देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का सबसे बड़ा आधार भारत सरकार की आयात निर्यात नीति में कृषि उत्पादन को वरीयता देना रहा। एकाएक ऐसी स्थिति वर्ष 1976-77 के अन्त में उत्पन्न हो गयी कि थोक मूल्य 12 प्रतिशत बढ़ गये, इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार का अपनी निर्धारित नीतियों पर नियन्त्रण नहीं रखना ही कहा जा सकता है। अतएव मार्च 1976 से ही क्रमशः बाद में प्रत्येक महीने में आयात स्थिति में मूल्यों की स्थिरता को जो लाभ मिला वह कम होता गया। अतः 1977-78 की आयात नीति का मुख्य आधार यही रखा गया कि पहले घाटे को पूरा किया जाये तथा पुनः लाभ प्राप्त किया जाये। इस वर्ष की नीति से यह भी स्पष्ट है कि सरकार ने आयात नीति व्यापारिक समुदाय की नेकनीयती पर भरोसा करके तैयार की और अनेक उदार कदम उठाये हैं किन्तु इन सुविधाओं का दुरुपयोग करने पर सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही करने की व्यवस्था की थी।

वर्ष 1977-78 में 164 वस्तुएँ इस नीति के अर्तगत सरकारी सगठनों द्वारा आयात की सूची में रखी गयी। जबकि विगत वर्ष 1976-77 में इसकी संख्या 196 थी। वस्तुतः सरकार हर कीमत पर निर्यात करना उचित नहीं समझती। उक्त आर्थिक स्थिति में सरकार ने यह महसूस की कि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि केवल विकसित देशों को सस्ते दामों पर चीजे उपलब्ध कराने के लिए निर्यात हेतु सरकारी सहायता दी जाए। भारत के मुद्रा आरक्षण ने देश की व्यापारिक स्थिति को मजबूत किया।

1978-79 आयात नीति :- जनता सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) की आयात नीति निर्धारित करते समय यह माना गया कि हमारी विदेशी विनमय स्थिति सुधरी हुई है। जिसके अनुसार इस योजना के प्रारम्भ में ही भारत के पास 4500 करोड़ रुपये के विदेशी विनमय का रिजर्व कोष जमा हो चुका था। इस योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व सरकार को श्री पी०सी० (P C) एलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी थी। एलेक्जेंडर समिति की नियुक्ति इस बात का पता लगाने के लिए 1977 की गई थी कि देश की आयात नीति किस सीमा तक उदार बनाना सम्भव है। समिति ने अच्छी साख वाले आयातकर्ताओं के लिए लागू आयात कोटा लाइसेन्स प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया। इस समिति की और प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी—

- (1) आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य 'नियन्त्रण' की अपेक्षा अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख बनाना हो।
- (2) आयातित वस्तुओं को केवल उन वस्तुओं तक सीमित रखना, जिनसे सामूहिकीकरण, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना, व्यापार पर अनुचित नीति लागू करने पर अकुश लगाना, तथा लम्बे समय तक पर्याप्त उपलब्धि आदि से सम्बद्ध शर्तों को पूरा करने की क्षमता हो।
- (3) कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स तथा औद्योगिक प्रयोजन वाले अशो के आयात को दो सूचियों में बाटा जाय—
 - (A) वे जिन पर पाबन्दी हो।
 - (B) जिनका आयात पूर्णतया निषिद्ध हो।
- (4) निर्यात करने वाली संस्थाओं को आयात प्रतिपूर्ति की सुविधाएँ जारी रखी जाएं तथा छोटी इकाइयों का निर्यात करने हेतु आवश्यक साज-सज्जा व कच्चे माल के आयात हेतु मुक्त रूप से विदेशी विनमय दी जाये।

- (5) टेक्नालॉजी के आयात में उदारता बरती जाए।
- (6) निर्यातकों को दी जाने वाली नकदी सहायता को विवेकशील बनाया जाए।

इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मुख्य निर्यात-आयात नियन्त्रक के पद को विदेशी व्यापार महानिदेशक के रूप में परिवर्तित किया जाए।

वस्तुतः जनता सरकार ने आयात नीति का जो रूप-रेखा बनाई उसमें एलेक्जेंडर समिति के सुझावों को भी दृष्टिगत रखा गया था। उस आयात नीति का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक उद्योगों एवं निर्यात योग्य वस्तुओं को बनाने वाली इकाइयों के लिए कच्चे माल, मशीनें, पूर्ण आदि को सुलभ कराना था। साथ ही उन इकाइयों की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा किये जाने का उद्देश्य था जो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही थी तथा जिनके आधुनिकीकरण तथा तकनीकी सुधार से जिनकी उत्पादन क्षमता में सुधार की अपेक्षा की जा सकती थी।

देश के अनेक उद्योगों में उत्पादन लागते ऊँची होने के कारण उनके द्वारा निर्मित वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धाशील स्थिति में नहीं थी। अतएव इन उद्योगों के लिए आयात होने वाली वस्तुओं पर विद्यमान प्रशुल्क दरों में उपयुक्त कटौती करने का 1978-79 की इस नीति में प्रावधान रखा गया।

1979-80 की आयात नीति :- 3 मई, 1979 को सरकार ने अपनी 1979-80 की आयात नीति की घोषणा की। इस नीति को पूर्व की भाँति जारी रखते हुए इस नीति में आग्रिम लाइसेन्सों के द्वारा शुल्क में छूट देने की सुविधा प्रदान की गई तथा कल पूर्जों के सम्बन्ध में थोड़ी सी उदारता भी दिखाई गई, परन्तु सेम्पल्स के आयात के सम्बन्ध में आवश्यक सशोधन किये गये। इस नई नीति की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम यह था¹ कि विदेशों में बसे भारतीयों को यहाँ के औद्योगिक उपक्रमों में विनियोजन करने के लिए अधिक रियायतें दी गईं। दूसरी विशेषता में, अन्य देशों के प्रोजेक्टों पर प्रयुक्त उपकरणों (उन प्रोजेक्टों के पूरा हो जाने पर) भारत में आयात की व्यवस्था की गयी। तीसरी विशेषता में, वैज्ञानिक एवं माप के उपकरणों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इस आयात नीति की चौथी विशेषता यह थी कि जिम्स, फिक्सचर्स व प्रेस टूल्स के आयातों को OGL पर (मुक्त सामान्य लाइसेन्स) आयात किया जाय। पाँचवी विशेषता यह थी कि बिक्री के बाद सेवा के लिए कल पूर्जों के आयात की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई। इसकी छठी विशेषता में सैम्पलों का आयात 10 हजार

¹ The Economic Times, May 4, 1979

रूपये से बढ़ाकर रूपये 50 हजार कर दिया गया। डाक व हवाई मार्ग से आयात किये जाने वाले सेम्पलो की सीमा 500 रूपये से बढ़ाकर रूपये 50 हजार कर दी गई। सातवीं विशेषता यह थी कि इस नीति के अन्तर्गत आधुनिक कैमरो के आयात की अनुमति दी गई। वर्ष 1979-80 के आयात नीति की अन्तिम विशेषता यह थी कि पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में कुछ वस्तुओं का आयात सीमित किया गया।

वर्ष 1980-81 की आयात नीति :- 1980-81 की आयात नीति में सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के आयात को अत्यधिक सरल बना दिया। इस आयात नीति का मुख्य उद्देश्य आवश्यक पदार्थों की कीमत में स्थिरता उत्पन्न करना था। 1980-81 की इस आयात नीति में सरकार ने यह घोषणा की कि वह देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में कृषि को उन्नत करने, निर्यात को प्रोत्साहन देने, तथा छोटे उद्योगों के विकास को बढ़ाने में पूर्ण-योगदान देगी। यहाँ यह उल्लेख समीचीन होगा कि उदार आयात नीति का परिणाम व्यापार के घाटे में वृद्धि करना होता है। अतएव हमें अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के आयातों पर रोक लगाना अत्यधिक आवश्यक होता है। इस आयात नीति की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि औद्योगिक विकास एवं आयात निर्भरता को कम करने के लिए 57 मदों को खुली सामान्य लाइसेन्स (OGL) व्यवस्था हटा कर नियमित सूची में सम्मिलित किया गया। दूसरी विशेषता में निर्यातित इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए आयात लाइसेन्सों के उपयोग पर बल दिया गया। इस आयात नीति की तीसरी विशेषता में आयात लाइसेन्स प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया। चौथी विशेषता, निर्यात गृहों को प्रोत्साहित करने के लिए आयात नीति में अनेक सुविधाएँ घोषित की गईं। पाँचवीं विशेषता में यह था कि खुली सामान्य लाइसेन्स सुविधा के अन्तर्गत आयातों का विस्तार किया गया तथा रेलवे उद्योग के लिए भी यह सुविधा प्रदान की गई है। इस नई आयात नीति की अन्तिम विशेषता यह थी कि यह आयात नीति विदेशियों को भी विशेष सुविधाएँ प्रदान करती रहेगी।

1981-82 की आयात नीति — भारत सरकार ने 1981-82 में चौथी बार लगातार ऐसी आयात नीति की घोषणा की जिसमें अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु प्रयत्नशील वास्तविक प्रयोग कर्ताओं की आयात सम्बन्धी जरूरतों को लचीली व उदारतापूर्वक नीति के माध्यम से पूरा किया जाय। इन प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कच्चे माल व उपकरणों का आयात यथासंभव खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के तहत करने की छूट को जारी रखा गया। पुनः लाइसेन्स जो लघु इकाईयों प्राप्त करना चाहती थी वे उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना भी इस सुविधा से लाभ उठा सकती थी। 1980 में पुनः लाइसेन्स की सीमा को 50

हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। सरकार का ऐसा अनुमान था कि इस छूट से 40 हजार औद्योगिक इकाइयाँ लाभान्वित होंगी।

इस नीति के तहत आयातों पर प्रशुल्क छूट के लिए अग्रिम लाइसेन्स की व्यवस्था को नई वस्तुओं के लिए लागू करने के अतिरिक्त अग्रिम लाइसेन्स जारी करने की प्रणाली को सरल बनाने की घोषणा भी की गई। पूर्व निर्धारित आदान-प्रदान अनुपात को आधार मान कर तथा पजीकृत इंजीनियर के प्रमाण पत्र की जरूरत के बिना अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई। तीन साल से या इससे अधिक समय से जो निर्माता निर्यात कर रहे हैं उन्हें सशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त हो सकेंगे।

सार्वजनिक इकाइयों को उनकी औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत और अधिक वस्तुएँ आयात करने की छूट दी गई बशर्ते ये आयात उन्हें प्रदत्त सीमाओं के भीतर किये जाएँ। एल्यूमीनियम राइस, लेखन व मुद्रण योग्य कागज तथा सभी प्रकार के खाद्य व खाद्य तेलों को कैनलाइज्ड सूची में रखा गया।

1981-82 की आयात-निर्यात नीति में विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश में पूँजी लगाने हेतु अनेक रियायतें दी गईं। वे व्यक्ति केवल नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु, अपितु किसी विद्यमान प्रयोग के विस्तार में भागीदार हेतु भी मशीनों का आयात कर सकेंगे। ऐसे आयातों पर नई मशीनों के आयात हेतु 25 लाख रुपये की तथा पुरानी मशीनों के आयात हेतु 15 लाख रुपये की जो सीमाएँ थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया।

इस नीति के अन्तर्गत तकनीकी विशेषज्ञ विदेश से प्रतिबधित मशीनें व कम्प्यूटर भी ला सकते थे। बशर्ते ये उपकरण आवश्यक हों तथा इनका वह विशेषज्ञ एक साल से अधिक से प्रयोग कर रहा हो। विदेशों से आने वाले भारतीय अपनी विदेशी आय में से कारखानों के निर्माण हेतु सीमेन्ट या कृषि में प्रयुक्त मशीनों का भी आयात कर सकेंगे।

1981-82 में प्रतिपूर्ति लाइसेन्स तथा खुले सामान्य लाइसेंस के तहत मशीनों के आयात की सीमा को भी बढ़ाया गया। इस प्रकार पूर्ण व टूल्स के आयात प्रणाली में पूर्वापेक्षा सुधार किया गया।

भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये की पूँजी से एक निर्यात आयात बैंक की स्थापना करने का भी निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को 1981 में ससद से भी स्वीकृति मिली।

1982-83 की आयात नीति— अप्रैल 1982 से लागू की गई इस आयात नीति में कुल मिलाकर पिछले वर्ष की नीतियों को जारी रखने का ही निर्णय लिया गया।¹ फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने तथा निर्यातकों को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आयात-निर्यात नीति में कुछ आवश्यक संशोधन किए गये।

इस आयात नीति में पूर्णतः प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची में 134 प्रकार की पूँजीगत वस्तुएँ रखी गईं। जबकि OGL के अन्तर्गत आयात की जानी वाली वस्तुओं की सूची को भी इस नीति के अन्तर्गत काफी विस्तृत रूप दे दिया गया। इसके अलावा रसायनिक उर्वरकों, न्यूजप्रिंट, आधारभूत दवाइयों, शक्कर, सीमेंट, विद्युत उत्पादन व संचरण सम्बन्धी उपकरण, साज सज्जा आदि 13 प्रकार की वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेन्सधारी को विश्व भर से टेण्डर मँगने होंगे। टेण्डर प्रस्तुत करने वाले भारतीय या विदेशी संस्थाओं में आपूर्तिकर्ता के चुनाव हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग में स्थापित एक समिति जाँच करेगी। पूँजीगत वस्तु के आयात हेतु प्राप्त लाइसेन्स की राशि का 10 प्रतिशत पूर्जों के आयात हेतु भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

इस नीति के अन्तर्गत यह भी प्रावधान रखा गया कि वास्तविक प्रोगकर्ता आयातित प्लाट या मशीन की कीमत के 2 प्रतिशत मूल्य के सामान पूर्जों के आयात हेतु आवेदन कर सकता। परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये रखी गई। विद्युत उत्पादकों के लिए यह सीमा 1 करोड़ रुपये की कर दी गई।

1985-1988 की आयात नीति :— अप्रैल 12, 1985 को तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस आयात नीति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने आयात नीति को न तो बहुत अधिक उदार और न बहुत अधिक नियन्त्रित कहा। पहली बार सरकार ने 3 वर्षीय आधार पर नीति बनाई। नई नीति का मूल उद्देश्य आयातित आदानों की सुगम तथा शीघ्र उपलब्धि द्वारा उत्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्यात-आयात नीति द्वारा निरन्तरता और स्थिरता कायम की जाय, निर्यात-उत्पादन आधार को मजबूत बनाया जाए, टेक्नालॉजी उन्नति को सुविधाजनक बनाया जाए, और आयात में सभी सम्भव बचत की जाय। इस नीति में प्रमुख लक्षण निम्न थे — प्रथम 53 मदों के आयात को वांछित दिशाओं में परिवर्तित कर दिया जाए। दूसरा लक्षण यह है कि औद्योगिक मशीनरी की 201 मदों को आयात नीति के अनुरूप सामान्य लाइसेन्स के अधीन रखा गया। जिन क्षेत्रों को इस नीति से लाभ होना था वे थे चमड़ा,

¹ Import and Export Policy, April 1982 to March 1983 Vol -I, Government of India, Ministry of Commerce

आटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, जूट का कपडा और तेल क्षेत्र सेवाएँ। तीसरे लक्षण में एक नई योजना “आयात-निर्यात पास बुक” चालू की गई। इस योजना द्वारा निर्माताओं एवं निर्यातकों का निर्यात-उत्पादन के लिए आयातित अदान शुल्क मुक्त प्राप्त करने की सुविधा दी गयी। चौथी विशेषता यह थी कि कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के लिए दो स्तरीय नीति अपनाई गई।¹ वे जिनकी लागत 16 लाख रुपये से कम होगी, को अपने प्रयोग के लिए सभी व्यक्तियों को आयात की इजाजत होगी। इसके अन्तिम लक्षण में प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से बसने के लिए वापिस नहीं आ रहे हों, को सामान्य नीति के अनुसार ही आयात सुविधाएँ दी जाएंगी और उन्हें कोई विशेष सुविधाएँ प्राप्त नहीं होगी।

इस आयात नीति का उद्योग एवं वाणिज्य के चैंबर, व्यापारिक एवं औद्योगिक घरानों और प्रसिद्ध उद्योगपतियों द्वारा स्वागत किया गया। यह नीति आवश्यक आयात को सीमित करती थी, परन्तु देशी उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आयात की इजाजत देती थी। यह नीति आयात द्वारा टेक्नोलॉजी उन्नति को बढ़ावा देना चाहती थी। यह नीति बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा देश में वस्तुओं के राशिपतन को रोकने के बारे में सजग थी और इस के लिए यह देशी उत्पादन को आयात पर चयनात्मक प्रतिबन्ध लगाकर आलम्बन देना चाहती थी। इस नीति का एक और अभिन्नोद्देश्य पहलू लघु-स्तर एवं कुटीर उद्योगों एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देना था। इस प्रकार हमारे मानव-शक्ति और कृषि-ससाधनों के अधिकतम प्रयोग को सहायता मिले। जहाँ तक निर्यात को बढ़ावा देने का सम्बन्ध है, आयात नीति बहुत ही स्पष्ट उपायों द्वारा भारतीय निर्यात का विस्तार करना चाहती थी। विभिन्न उपाय सीधे और सकारात्मक थे और हर एक इस बात से सहमत थे कि यह भारतीय आयात नीति स्पष्ट निर्यात प्रेरित है।

इस नियोजन काल में भारत सरकार की यह पहली एक त्रिवर्षीय आयात नीति की घोषणा थी। वस्तुतः यह नीति जो 2 अप्रैल, 1985 को घोषित की गई, 1984 के अन्त में व्यापार नीति समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर आधारित थी तथा इसमें आयातों को नियन्त्रित करने हेतु प्रशुल्क नीति का आश्रय लिया गया था। क्षेत्रीय लाइसेन्स अधिकारियों को पूँजीगत वस्तुओं के अधिक आयात देने हेतु प्रदत्त सीमा को बढ़ा दिया गया। अग्रिम लाइसेन्स को बिना विलम्ब निर्गमित करने हेतु कोलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई तथा नई दिल्ली में क्षेत्रीय समितियाँ गठित की गईं। किन्तु इस नीति में कुछ पाबन्दियाँ भी लगाई गईं जो इस प्रकार थी—

¹ दत्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 राम नगर, नई दिल्ली 05 पृष्ठ-740 ।

- 1 ऐसी वस्तुओं के आयात पर अधिक पाबन्दियाँ लगाई गईं जिनका देश में पर्याप्त उत्पादन होता था।
- 2 उदारतापूर्ण आयात नीति का दुरुपयोग करने वाली इकाइयों व व्यक्तियों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।

व्यवसायिक व औद्योगिक क्षेत्र में 1985-88 की इस नीति को तकनीकी उत्थान व आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाली नीति के रूप में सराहा गया। इसके द्वारा एक प्रगतिशील औद्योगिक व राजकोषीय नीति का क्रम जारी रखा गया। इसमें पिछले वर्षों में अपनायी गयी उदारता की प्रवृत्ति को स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारत में व्यापार, उद्योग व राजस्व तीनों क्षेत्रों में एक एकीकृत नीति का विकास किया गया।

वर्ष 1988-91 की त्रिवर्षीय आयात नीति :- अप्रैल 1988 से मार्च 1991 तक की अवधि के लिए एक नई त्रिवर्षीय आयात नीति 30 मार्च, 1988 को घोषित की गई। इस आयात नीति में आयातों को इस प्रकार नियमित किया गया कि जिससे अर्थव्यवस्था की आवश्यक जरूरतें पूरी हो सकें। विकास प्रोत्साहित हो एवं निर्यात में वृद्धि हो। इस नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं —

- 1 औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक आयातित पूंजीगत वस्तुओं कच्चे माल तथा कल पूर्णों की व्यवस्था करना ताकि आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास एवं उत्तरोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की ओर अग्रसर हुआ जा सके।
- 2 कार्यकुशल आयात प्रतिस्थापन व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- 3 आयात की 26 मदों को सरकारी आयात की सूची से हटा लिया गया।
- 4 सामान्य खुली लाइसेन्स नीति (OGL) को विस्तृत कर दिया गया तथा इसके अन्तर्गत आयात किये जाने वाले कच्चे माल व उपकरण एवं उपयोगी वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 944 कर दिया गया।
- 5 आधुनिकीकरण एवं तकनीकी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक मशीनों की 99 इकाइयों को पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया गया, जिन्हें OGL के अन्तर्गत आयात किया जा सकता।
- 6 209 जीवनरक्षक उपकरण एवं 108 जीवन रक्षक इकाइयों को OGL के अन्तर्गत रखा गया।

- 7 अस्पतालो एव चिकित्सा सस्थानो द्वारा आयात की जाने वाली इकाइयों की सीमा 25 हजार से बढ़कर 50 हजार कर दी गई।
- 8 नई नीति का मुख्य बिन्दु सशोधित आयात पुनर्पूर्ति योजना (Replenishment Scheme) है, जिसके अन्तर्गत निर्यातक, कच्चे माल की पूर्ति करने हेतु आयात लाइसेन्स प्राप्त कर सकते हैं। आयातों की सीमा विस्तृत करने के लिए पूरक लाइसेन्स प्रणाली को स्वतः पूर्ण बनाया गया। इसके अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक के पूँजीगत माल को आयात करने के लिए किसी घरेलू बन्धन की आवश्यकता नहीं है।
- 9 आयात-निर्यात पास-बुक योजना के अन्तर्गत बिना शुल्क के कच्चे माल और कल पूर्जों को आयात करने की सुविधा अन्य प्रतिष्ठित उत्पादकों को भी प्रदान की गई। इसके फलस्वरूप जिन उत्पादकों का तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर 15 करोड़ रुपये का था। उन्हें इसके 10 प्रतिशत तक पास बुक की सुविधा दी जाएगी।
- 10 इस नीति में छोटी पैमाने की दवाइयों को पूँजीगत वस्तुओं, कच्चा माल, कल पूर्जें तथा उपभोग पदार्थों (Consumables) के आयात की सुविधा बढ़ाई गई।

इस योजना काल में आयात नीति की रुपरेखा भारी व्यापार घाटा और बढ़ते हुए ऋणभार को दृष्टि में रखकर तैयार की गई और आशा की गई कि इससे निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी। देश में औद्योगिक आधुनिकीकरण की दृष्टि से 1989-90 के वार्षिक बाजार में पूँजीगत एवं मशीनों के आयातों को उदार बनाया गया।

इस प्रकार यह दूसरी त्रिवर्षीय आयात नीति पहली त्रिवर्षीय आयात नीति की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई। इस अवधि के पश्चात् आयात-निर्यात नीतियाँ सम्मिलित रूप से घोषित की गयी जिसका विस्तृत अध्ययन हम इसी अध्याय के "भाग-ब" में करेंगे।

(ब) निर्यात नीति (Export Policy)

1947-48 और 1950-51 के बीच निर्यात नीति का आधार दो मुख्य बातें थीं। दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से प्राप्ति को अधिकतम करना और यह अश्वस्त करना कि जब तक घरेलू माँग को पर्याप्त रूप में पूरा न किया जाय, तब तक निर्यात नहीं किया जाएगा। युद्धोपरान्त काल में विद्यमान दुर्लभता के कारण यह अनिवार्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की स्थिति को

दूर किया जाये। बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। अतः इस अवधि के दौरान निर्यात नीति प्रतिबन्धात्मक थी। 1949 के अवमूल्यन और कोरिया के युद्ध के कारण हमारे निर्यात को कुछ प्रोत्साहन अवश्य मिला। परन्तु कोरिया के युद्ध की समाप्ति और बाद में घटित प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यात नीति में उदारता के प्रति रुख बदलना पड़ा। कुछ निर्यात-शुल्क तो हटा दिए गए परन्तु पहली योजना से अन्तिम दो वर्षों में अधिकतम आर्थिक विकास को आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए निर्यात-प्रोत्साहन पर गम्भीर रूप से विचार किया गया।

स्टार्लिंग अधिवेशन के सग्रहण के कारण निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता कम अनुभव की गई। दूसरी योजना में इस बात पर बल देते हुए लिखा गया कि भारत को निर्यात से प्राप्त होने वाली आय कुछ ही वस्तुओं पर निर्भर है। इनमें से तीन अर्थात् चाय, पटसन और कपड़ा हमारे निर्यात के लगभग आधे के बराबर है। इन मुख्य निर्यात पदार्थों को स्वदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस कारण अल्पकाल में निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव नहीं, चाहे नई वस्तुओं के निर्यात के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए और मुख्य निर्यात-वस्तुओं के लिए नई-नई मण्डियाँ ढूँढनी चाहिए, परन्तु यह बात स्वीकार करनी होगी कि औद्योगिकरण की क्रिया जब तक आगे नहीं बढ़ जाती और देशीय उत्पादन में वृद्धि नहीं हो जाती, तब तक निर्यात में अधिक मात्रा में प्राप्ति होने की कोई सम्भावना नहीं।

सन् 1951 से भारत के निर्यात व्यापार को दो मुख्य चरणों में विभाजित करना उचित होगा। प्रथम 1959-60 का दशक, जिसमें भारत के निर्यात लगभग स्थिर रहे। द्वितीय 1961-71 का दशक जिसमें कुछ समय तक निर्यातों में साधारण वृद्धि हुई। परन्तु 1968 के बाद से हमारे निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हुई।¹

योजनाविधि में निर्यात में वृद्धि अवश्य हुई पर इसमें वृद्धि सन्तोषजनक नहीं रही। विश्व निर्यात में जिस दर से वृद्धि हुई, उससे अत्यन्त ही कम दर से भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा निरन्तर गिरता ही गया। 1950 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत था जो 1960 में घटकर 1.2 प्रतिशत तथा 1970 में 7 प्रतिशत तथा 1982 में घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया। यह हिस्सा वर्तमान में भी इसी दर के आस पास बना हुआ है।

¹ डॉ० एस०एन० लाल - अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं लोक वित्त, शिव पब्लिशिंग हाउस - वर्ष 1985, पेज-192।

भारत की निर्यात नीति के समीक्षात्मक अध्ययन के लिए इसे हम प्रमुख रूप से दो भागों में बाट सकते हैं

(A) योजना से पूर्व निर्यात नीति

(B) योजनावधि में निर्यात नीति

(A) योजना से पूर्व निर्यात नीति —

योजना से पूर्व भारतीय निर्यात की मुख्यतः दो विशेषताएँ थी — पहला, सीमित आधार तथा द्वितीय सीमित बाजार। सीमित आधार से यह आशय है कि भारतीय निर्यात का बड़ा भाग कुछ विशेष वस्तुओं का था जिन्हें परम्परागत वस्तुएँ कहते हैं। दीर्घकाल से भारतीय निर्यात मुख्यतः दो-तीन वस्तुओं पर आधारित रहा। इसी प्रकार सीमित बाजार से तात्पर्य यह है कि अर्द्ध विकसित राष्ट्रों का व्यापार मात्र कुछ राष्ट्रों तक ही सीमित रहा है। इसका मुख्य कारण उपनिवेशवाद रहा है जब किसी राष्ट्र का निर्यात केवल कुछ राष्ट्रों तक सीमित रहता है तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र का निर्यात राजनैतिक सम्बन्धों तथा आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगा। इन दोनों के अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियाँ जैसे व्यापार दर की प्रतिकूलता, निर्यात वस्तुओं की माँग में कमी, इत्यादि वे कारण थे जिनके कारण निर्यात-नीति के नये ढंग से निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की गयी। आकड़ों के अनुसार 1944-45 की अवधि में कुल निर्यात का 75 प्रतिशत भाग परम्परागत वस्तुओं का था अर्थात् जूट, चाय, कपास, चमड़ा इत्यादि। उपर्युक्त स्थिति में आर्थिक विकास के सर्दभ में परिवर्तन के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने निर्यात नीति को नया रूप दिया।

(B) योजनावधि में निर्यात नीति :—

प्रथम योजना काल में भारतीय योजना आयोग के अनुसार व्यापारिक नीति के मुख्य उद्देश्य में एक यह भी रहा है कि निर्यात के स्तर सदैव बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय। प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय भारतीय निर्यात अपनी चरम सीमा पर था अर्थात् कोरिया युद्ध से उत्पन्न अन्तराष्ट्रीय आर्थिक दशाओं से भारतीय निर्यात में तीव्र निर्यात वृद्धि हुई। चूँकि बढ़ते हुए अन्तराष्ट्रीय मूल्यों ने घरेलू मूल्यों को भी प्रभावित किया। अतएव भारतीय सरकार ने कई वस्तुओं पर निर्यात कर में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय सरकार को काफी आय प्राप्त हुई। किन्तु सन् 1951 में कोरिया युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारतीय निर्यात में गिरावट आयी। निर्यात जो कि सन् 1951-52 में 733 करोड़ रुपये था। 1952-57 में घटकर 577 करोड़ रुपये

रह गया। इस निर्यात में कमी के प्रमुख दो कारण थे। पहला युद्ध समाप्ति के साथ युद्ध जनित माँग की समाप्ति हो गई तथा दूसरा, भारतीय निर्यात वस्तुओं के मूल्यों में भी गिरावट आयी। यहाँ यह उल्लेख समीचिन होगा कि पाकिस्तान के बन जाने से भारत की निर्यात करने की शक्ति में न केवल कमी आयी अपितु प्रतियोगिता भी बढ़ गयी। ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार ने उदार निर्यात नीति का निर्धारण किया, यह भी प्रयास किया गया कि चावल, दाल, इत्यादि का निर्यात किया जाय जो कि इससे पूर्व निषिद्ध था। इसी प्रकार चाय की अनुकूल उपज के फलस्वरूप सरकार ने चाय के निर्यात में वृद्धि की।

द्वितीय योजना अवधि —

द्वितीया योजना अवधि में एक बार पुनः निर्यात वृद्धि पर बल दिया गया। विदेशी मुद्रा के प्रभाव में दूसरी योजना में यह और भी आवश्यक हो गया कि निर्यात में वृद्धि के लिए प्रयास किये जायें। निर्यात-आयात के बीच अन्तर कम करने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग 200 वस्तुओं के ऊपर से नियन्त्रण हटा लिया। इन वस्तुओं में सूती वस्त्र, जूट के समान इत्यादि सम्मिलित हैं। कई वस्तुओं जैसे कच्चा कपास, चाय इत्यादि के अभ्यस में वृद्धि की गई। इसी प्रकार वित्तीय सुविधाएँ दी गई जिससे भारतीय वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता के समक्ष टिक सकें। भारत सरकार ने निर्यात सम्बर्धन के दृष्टिकोण से औद्योगिक इकाइयों के आयात अभ्यस एवं सुविधाएँ व उनकी निर्यात प्राथमिकताओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया अर्थात् वे इकाइयाँ जो निर्यात में वृद्धि करती थी, उनको आयात का सुविधा प्रदान करने का सरकार ने प्रलोभन दिया। साथ ही यह भी प्रबन्ध किया गया कि यदि कोई औद्योगिक इकाई अपने प्रतिनिधियों को बाजार सर्वेक्षण के लिए विदेशों में भेजना चाहे तो उसे विदेशी मुद्रा की सहायता दी जाएगी। 1957 में निर्यात जोखिम बीमा सरकारी समितियों की स्थापना कर सरकार ने निर्यात सम्बर्धन के लिए एक और प्रभावशाली कदम उठाने का प्रयास किया। विदेशों में नए बाजार की खोज के लिए सरकार ने बहुत से व्यापार दलों को विदेश भेजा। इसी प्रकार दूसरे देशों के "व्यापार दलों" को आमंत्रित भी किया। इस अवधि में सरकार ने कई व्यापारिक समझौते करने का प्रयास किया। इस व्यापार समझौते के द्वारा भारतीय निर्यात में जो कि साम्यवादी देशों में लगभग नगण्य था, तीव्र बढ़ोत्तरी आई। सन् 1950-51 में भारतीय व्यापार का 1 प्रतिशत भाग रूस के साथ था। किन्तु 1959-60 में यह बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया, किन्तु जहाँ तक व्यापार की कुल मात्रा का प्रश्न है वह लगभग स्थिर रहा, निर्यात जो कि सन् 1955-56 में राष्ट्रीय आय का 5.9 प्रतिशत था सन् 1959-60 में 5 प्रतिशत हो गया। गुण नियन्त्रण की दृष्टिकोण से भी सरकार ने प्रयास किया। प्रयत्न इस बात का भी किया गया कि

था। यदि पूँजीगत वस्तुओं का आयात नये उद्योगों के लिए न भी किया जाए तो परितोषक आयात की मात्रा, जो तृतीय योजना में 3570 करोड़ रुपये आकी गई, के लिए तो निर्यात आवश्यक ही था। साथ ही पिछले ऋणों के भुगतान के लिए भी निर्यात वृद्धि आवश्यक हो गई। एक अध्ययन के अनुसार कुल योजना काल में लगभग 6170 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी जबकि निर्यात की मात्रा 3570 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार तृतीय योजना में 2600 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान लगाया गया। ऐसी स्थिति में निर्यात सम्बर्द्धन बहुत ही आवश्यक था। आवश्यकता एक इस प्रकार के निर्यात नीति की थी जो कि निर्यात अतिरेक उत्पन्न करने में मदद कर सके क्योंकि जब तक निर्यात अतिरेक नहीं होगा, तब तक निर्यात सम्बर्द्धन सम्भव नहीं होगा और निर्यात अतिरेक अन्य नीतियों पर जैसे आम नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, इत्यादि पर निर्भर करता है। जब तक अन्य नीतियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं लाया जायेगा, केवल निर्यात नीति निर्यात सम्बर्द्धन करने में सफल नहीं होगी।

श्री ए० रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सरकार ने मार्च 1961 को एक समिति की स्थापना की। समिति निर्यात की समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन हेतु बनाई गई थी। समिति निर्यात की समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन हेतु बनाई गई थी। समिति ने अनेक सुझाव दिए जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने बहुउद्देशीय दृष्टिकोण द्वारा निर्यात-वृद्धि का प्रयास किया। निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाइयों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सुविधा दी गई। कच्चे पदार्थों के आयात की सुविधा ऋण सुविधा, रेल-भाड़ा एवं कर की कटौतियाँ आदि कुछ उदाहरण हैं। निर्यात सम्बर्द्धन समितियों को अनुदान भी दिये गये। यह भी निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापारिक सघों को निर्यात-सम्बर्द्धन योजनाओं के लिए ऋण सम्बन्धी सहायता दी जाए। एक लागत-कटौती समिति की भी स्थापना की गई। समिति का कार्य विभिन्न निर्यात की वस्तुओं की लागत का अध्ययन करना था और यह विश्लेषण करना था कि किन उपायों द्वारा अथवा किस प्रकार की नीति के द्वारा लागत में कमी लाने का प्रयास किया जाय। बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्थिति में यह आवश्यक था कि भारतीय निर्यात की वस्तुओं की कीमत प्रतियोगिता की दृष्टि से अनुकूल हो। इसी प्रकार बाजार को प्राप्त करने की दृष्टि से यह भी आवश्यक था कि भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी की जाये। इस दृष्टिकोण से भारत कई प्रदर्शनियों में सम्मिलित हुआ। सन् 1962 में व्यापार सघ की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य निर्यात सम्बर्द्धन के लिए प्रयास करना था। आकड़ों के अनुसार भारतीय निर्यात जो कि सन् 1960-61 में 64232 करोड़ रुपये था, सन् 1963-64 में 80241 करोड़ रुपये तथा 1964-65 में

814 56 करोड रुपये हो गया। सरचना की दृष्टि से भी भारतीय निर्यात में परिवर्तन आया। वस्तुतः बढ़ते निर्यात का मुख्य कारण भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि थी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भारतीय परम्परागत वस्तुओं का इस वृद्धि में योगदान नहीं था। सन् 1964-65 में जूट की वस्तुओं का निर्यात 166 करोड रुपये रहा, सूती वस्तुओं का निर्यात जो कि कम हो रहा था वह न केवल रुक गया अपितु उसमें कुछ वृद्धि भी हुई। व्यापार की दिशा में भी परिवर्तन परिलक्षित हुए। इस अवधि में इंग्लैण्ड तथा अमेरिका अब भी मुख्य क्रेता रहे। किन्तु रूस को निर्यात जहाँ 1961-62 में केवल 3221 लाख रुपये था बढ़कर 1964-65 में 7793 लाख रुपये हो गया। ऑकड़ों का अध्ययन भारतीय निर्यात की विविधता को इंगित करता है। भारतीय निर्यात पूर्व यूरोपीय देशों के साथ सन् 1961-62 में 33 करोड रुपये था। यह बढ़कर 1964-65 में 144 करोड रुपये हो गया।

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर भारतीय निर्यात नीति को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, “निर्यात नीति सामान्य तथा सगठित निर्यातों को ऐसे सम्बर्धन के जो कि देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध थे प्रसविदों के शिथिलीकरण की एक प्रगतिशील नीति थी।” इस योजना काल में निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात सम्बर्धन के राजकोषीय व अन्य उपाय किए गये, जिसकी विस्तृत विवेचना हम निम्न बिंदुओं द्वारा कर सकते हैं —

- (1) निर्यातकों को करो में प्रत्यक्ष छूट — सबसे पहले 1962 में निर्यातकों को करो में प्रत्यक्ष छूट दी गई। 1963 में करो में यह छूट निर्यातित वस्तुओं के मूल्य (f.o b) से सम्बद्ध कर दी गई। 1962 में अलग अलग दरों पर करो में छूट की घोषणा की गई।
- (2) रेल भाड़े में छूट — निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से कुछ पर रेल-भाड़े में भी छूट दी गयी। इस छूट का प्रयोजन निर्यातकर्ताओं को रेल भाड़े में हुए घाटे की क्षतिपूर्ति करना था, यद्यपि परिवहन लागतों में इस छूट का कोई औचित्य नहीं था।
- (3) निर्यातकों को दुर्लभ वस्तुओं की उपलब्धि करना — नियन्त्रित मूल्यों पर निर्यातकों को दुर्लभ कच्चे माल तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि प्राथमिकता के आधार पर कराने की व्यवस्था की गई। आज भी अनेक औद्योगिक इकाइयों को महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धि प्राथमिकता के आधार पर करायी जाती है, यदि वे अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करती हों। इस नीति के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों की उत्पादन क्षमता में सुधार तथा विस्तार हेतु दी गयी सुविधाएँ भी शामिल हैं।

- (4) बजट में अनुदान का प्रावधान — सरकार ने शक्कर के निर्यात हेतु नकद रूप में तथा अन्य कुछ वस्तुओं के निर्यात में हुई क्षति की पूर्ति के लिए राजकीय व्यापार निगम (STC) को परोक्ष रूप में अनुदान देने की घोषणा की। राजकीय व्यापार निगम को कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को आयात हेतु एकाधिकार दिए गये, जिनके लाभों का उपयोग कुछ वस्तुओं के निर्यात में हुई क्षति को पूरा करने के लिए किया गया। इन वस्तुओं में सीमेंट, मूँगफली का तेल, खली एवं कुछ रासायनिक पदार्थ सम्मिलित थे।
- (5) निर्यात सम्बर्धन परिषदों के लिए बजट में प्रवधान — हर वर्ष सरकारी बजट में निर्यात सम्बर्धन परिषदों की गतिविधियों के लिए प्रावधान रखा गया। इन गतिविधियों में प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों का आयोजन अथवा ऐसे मेलों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण एवं ऐसे कार्य सम्मिलित थे जिनके द्वारा भारतीय वस्तुओं की विदेशों में माँग बढ़ायी जा सकती थी इस प्रकार के बजट का प्रवधान आज भी रखा जा रहा है।
- (6) बिक्री कर में छूट तथा उत्पादन शुल्क व कच्चे माल पर प्राप्त प्रशुल्क की वापसी
निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर सरकार ने बिक्री-कर तथा उत्पादन शुल्क में छूट देने के अतिरिक्त उस कच्चे माल पर वसूल किये गये प्रशुल्क को वापस करने की घोषणा भी की, जिसका उपयोग निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता था। वैसे 1954 में इस प्रकार के कच्चे माल पर आयात कर में छूट देने की नीति लागू की गई थी तथा 1956 में उत्पादन करों में छूट दी गई थी। परन्तु इन सब रियायतों का क्षेत्र एवं सीमा सीमित होने के कारण इनका पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। तीसरी योजना अवधि में निर्यातों को प्रोत्साहन देने हेतु इन सब रियायतों के क्षेत्र एवं इनकी सीमाओं में पर्याप्त विचार किया गया। परन्तु इस सब रियायतों को प्राप्त करने में अनेक कठिनाई थी, जिसे आगे की योजना अवधियों में दूर किया जा सका।

आयात का अधिकार — इस योजना काल के अन्तर्गत निर्यातकों को निर्यातित वस्तु के एक अनुपातिक विदेशी विनमय विदेशों से निर्दिष्ट वस्तु/वस्तुओं का आयात करने के लिए दिये जाने का प्रावधान किया गया तथा इसके अन्तर्गत विभिन्न निर्यातकों को निर्यात के मूल्य (f o b) के आधार पर आयात लाइसेन्स दिये गये। निर्यातकों को यह छूट दी गई कि वे इस लाइसेन्स को उन व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर दें जिन्हें सम्बद्ध वस्तुओं की वास्तव में आवश्यकता थी। प्रायः अधिकांश निर्यातकों को आयात लाइसेन्स पर 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि प्राप्त हो जाती थी। कुछ वस्तुओं के आयात लाइसेन्सों पर 200 प्रतिशत से 300 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त की जा सकती

थी। 1963 में इस योजना के अन्तर्गत 65 करोड़ रुपये के आयात लाइसेन्स जारी किये गये। यह उल्लेखनीय है कि भारत से पहले इस प्रकार की योजना पाकिस्तान व जापान में लागू की जा चुकी थी। परन्तु भारत में लागू की गई इस योजना में निम्न लिखित विशेषताएँ रही हैं —

- (1) निर्यात के मूल्य से कम मूल्य के आयात लाइसेन्स जारी किये जाते रहे, तथापि अन्य देशों की तुलना में आयात लाइसेन्स की राशि के अनुपात में भारत अधिक है। इन अनुपातों में परिवर्तन किये जाते हैं।
- (2) हस्तान्तरणीय लाइसेन्सों के बाजार पृथक् होने के कारण विभिन्न लाइसेन्सों पर अतिरिक्त राशि की दरें भी भिन्न थीं।
- (3) इस योजना के अन्तर्गत उपयोग की वस्तुओं के आयात लाइसेन्स नहीं दिये जाते।
- (4) इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात सम्मिलित नहीं है एवं केवल 30 प्रतिशत निर्यातों पर कठोर नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स देने की व्यवस्था है।
- (5) उक्त आयात अधिकारों के अन्तर्गत प्राप्त कुल आयात के मूल्य के लगभग 5 प्रतिशत रहे हैं।

वस्तुतः यह योजना उस समय लागू की गई जबकि भारतीय रुपये का अर्थ (Value) कृत्रिम रूप से ऊँचा रखा गया था तथा विदेशी विनमय की कलाबाजारी अधिक होने के कारण आयात लाइसेन्सों पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से घाटा उठा कर भी निर्यात में वृद्धि की। परन्तु इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसके अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त राशि विभिन्न वस्तुओं के सन्दर्भ में असमान एवं अस्थिर थी। इस नीति ने बीजक में निर्यातों के मूल्य बढ़ाकर प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सभी निर्यातकर्ता अधिक से अधिक राशि का आयात लाइसेन्स प्राप्त करना चाहते थे। यह उल्लेखनीय है कि जैसे-जैसे निर्यात का मूल्य अधिक होता है वैसे-वैसे आयात लाइसेन्सों पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का अनुपात घटता जाता है जिसके अन्तर्गत निश्चित माँग के सन्दर्भ में पूर्ति बढ़ते जाने पर वस्तु का मूल्य घटता जाता है।

अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात नीति :- 5 जून, 1966 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने के बाद सरकार ने निर्यात-सम्बर्धन के अधिकांश उपायों को समाप्त कर दिया। परन्तु जब यह अनुभव किया गया कि अवमूल्यन के पश्चात् निर्यातों में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो अनुदान सम्बन्धी योजना पुनः लागू की गई। अवमूल्यन के पश्चात् लागू की गई निर्यात सम्बर्धन नीति में

आयात लाइसेन्स के साथ 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत नकद अनुदान देने की भी व्यवस्था रखी गई। विभिन्न वस्तुओं पर उपलब्ध अनुदान एवं नकद अनुदानों की दरों में विभिन्नता है। यद्यपि प्रत्यक्ष अनुदान की योजना ही अधिकांश वस्तुओं के लिए प्रचलित है। 1967-68 में अनेक वस्तुओं के लिए सहायता की दरें बढ़ाई गई। पुनः 1968-69 में जिन क्षेत्रों के निर्यात में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी, वहाँ नकद सहायता के स्तर में 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि की गई। 1967-68 तक निर्यात की गई वस्तुओं में 10 प्रतिशत पर नकद अनुदान की योजना लागू की जा चुकी थी। इसके अगले दो वर्षों में कुछ नयी वस्तुओं को इस अनुदान में शामिल किया गया।

हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि भारतीय निर्यात नीति में एक तरह से अवमूल्यन के पश्चात् एक नया चरण प्रारम्भ हुआ। अवमूल्यन से लाभ उठाने के लिए भारतीय निर्यात नीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। कुछ मुख्य परिवर्तन ये थे— नकद सहायता में वृद्धि, निर्यात के लिए ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, कुछ चुनी हुई निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर देशी कच्चे माल की व्यवस्था करना, निर्यात-शुल्कों में परिवर्तन करना इत्यादि। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात शुल्क परिवर्तित किये गये। परम्परागत वस्तुओं की मांग विदेशों में बेरोच थी अथवा जिनकी पूर्ति की स्थिति लचीली नहीं थी या जिन पर ये दोनों बातें लागू होती थी उन पर निर्यात शुल्क लगाये गये। इन शुल्कों के पीछे उद्देश्य व्यापारिक शर्तों की रक्षा करना तथा विदेशी कीमतों की ऐसी गिरावट के कारण होने वाली उस हानि से विदेशी मुद्रा को बचाना था, जो निर्यात की वृद्धि के बराबर न हो। नयी निर्यात नीति में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि विदेशी मुद्रा की वृद्धि के दृष्टिकोण से यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि निर्यात संरचना में विभेदीकरण किया जाय। चालू निर्यात को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा गया — पहला, सबसे अधिक प्राथमिकता वाला वर्ग जिसमें इजीनियरिंग प्लास्टिक एवं रसायनिक उद्योग सम्मिलित थे। इन उद्योगों के लिए विश्व मांग अनुकूल थी और निकट भविष्य में भारत प्रतियोगिता की स्थिति में पहुँच सकता था। किन्तु लागत अधिक होने के कारण विश्व बाजार में पहुँचने में कुछ कठिनाई थी। यह बात दृष्टिगत करते हुए सरकार ने इन उद्योगों को नकद अनुदान देने की घोषणा की। इजीनियरिंग उद्योगों को तीन वर्गों में बाँटा गया और 12, 15 तथा 20 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया गया। दूसरे भाग में वे वस्तुएँ सम्मिलित थीं जिन पर न तो अनुदान ही था और न ही निर्यात कर ही लागू होता था। इस वर्ग में चमड़े की निर्मित वस्तुएँ, हस्तकला, इत्यादि सम्मिलित थीं। कुल निर्यात में इसका 32.5 प्रतिशत भाग था। तीसरे भाग में परम्परागत वस्तुएँ रखी गईं। इस वर्ग की अनेक वस्तुएँ जैसे चाय, माइका,

पीपर, इत्यादि ऐसी वस्तुएँ थी जिनकी विश्व माग की पूर्ति भारत बहुत सीमा तक करता था परिणाम यह रहा कि भारतीय वस्तु निर्यात जो कि सन् 1965-66 में 801 65 करोड़ रुपये था बढ़ाकर सन् 1967-68 में 1998 67 करोड़ रुपये हो गया। सूती वस्त्रों का निर्यात 52 37 करोड़ रुपये (61-62) से बढ़ाकर 79 44 (1967-68) हो गया। अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई जो कि निश्चय ही एक स्वस्थ चिन्ह था।

इस योजना काल में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक संस्थाएँ स्थापित की गईं अथवा इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। राजकीय व्यापार निगम (STC) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (MMTC) तथा हथकढ़ा व हस्तकला निर्यात निगम (HHEC) इनमें से प्रमुख संस्थाएँ हैं। जिनका उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहन देना है। यह उल्लेखनीय है कि राजकीय व्यापार निगम की स्थापना मई 1956 में की गई थी तथा इसे विविध प्रकार की वस्तुओं के आयात व निर्यात करने हेतु एकाधिकार दिये गये थे। 1956-57 में इस निगम के कुल व्यापार की राशि लगभग 9 करोड़ रुपये थी। परन्तु शीघ्र ही इसका कार्यक्षेत्र बढ़ने के साथ-साथ आयात व निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। फलस्वरूप अक्टूबर 1963 में खनिज व धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य सम्बन्ध खनिज व धातु के आयात व निर्यात से है। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ही विदेशी व्यापार संस्थान (IFT) की स्थापना की गई। इस संस्थान के मुख्य कार्यों में निर्यात व्यापार से सम्बद्ध अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना, बाजार सम्बन्धी सेवाओं की जानकारी देना तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी शोध शामिल है। इस क्षेत्र की उन्नति हेतु वर्तमान में व्यापार विकास संस्था का निर्माण किया गया जिसका कार्य चुने हुए तथा गहन निर्यातों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा निर्यात उत्पादन एवं बिक्री के क्षेत्र में विभिन्न सेवाएँ प्रदान करना है। एक स्वतन्त्र विदेशी व्यापार मन्त्रालय की भी स्थापना की गई। यह सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन की समस्या को तीव्र गति से हल करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात नीति :-

इस पंचवर्षीय योजना काल में प्राथमिकता प्राप्त व अन्य उद्योगों को निर्यात सम्बर्धन हेतु और अधिक सुविधाएँ दी गईं। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक निर्यात करते थे, उत्पादन में वृद्धि करने तथा कच्चे माल एवं साज-सज्जा की उपलब्धि हेतु प्राथमिकता दी गई। साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत या अधिक का निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाईयों को अधिक प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के अनुरूप ही गैर प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को भी सुविधाएँ देने का निश्चय किया गया, यदि वे भी अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक का निर्यात करती हों। प्राथमिकता प्राप्त 12 उद्योगों में सलग्न इकाइयों, जैसे साइकिलों व इनके पूर्जों का निर्माण, निर्दिष्ट किस्म के डीजल इंजन, आटोमोबाइल्स के पूर्जों, दवाइयों व रसायनिक पदार्थों आदि के उत्पादन के 5 प्रतिशत से कम निर्यात करने पर प्राप्त आयात लाइसेन्स में कटौती करने तथा प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल व साज-सज्जा की उपलब्धि स्थगित करने की घोषणा की गई। यह उल्लेखनीय है कि यह नीति तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भी प्रचलित थी, परन्तु इसको और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने का निर्णय इस योजना काल में लिया गया। इन 12 उद्योगों में सलग्न 342 इकाइयों में से 1971-72 के केवल 88 (26 प्रतिशत) ही उत्पादन के 5 प्रतिशत भाग का निर्यात करने की शर्त पूरी कर सकी।

भारत सरकार ने 1970 में निर्यात सम्बर्द्धन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए “निर्यात नीति प्रस्ताव” पारित किया। इस प्रस्ताव में इस योजना काल में तथा उसके बाद अपनायी जाने वाली निर्यात नीति की स्पष्ट घोषणा की गई। इस प्रस्ताव में यह बताया गया कि निर्यातों से प्राप्त आय में वृद्धि का उतना ही महत्व है जितना कि देश के आन्तरिक साधनों के विदोहन का है। देश के आर्थिक स्वावलम्बन की प्राप्ति तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी लाने हेतु निर्यात-आयात में तीव्र गति से वृद्धि की जानी आवश्यक है।

इन प्रस्तावों में उन विषयों को भी शामिल किया गया, जो भारत सरकार द्वारा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, फलों के उत्पादन, रेशम, वन, मत्स्य पालन, खनिज, वस्त्र उद्योगों, रसायन पदार्थों, इंजीनियरिंग उद्योगों एवं विद्युत उद्योगों, आदि के सम्बन्ध में अपनायी जाती हैं। उक्त प्रस्ताव में कृषि के लिए व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु किये जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में ऐसा कहा गया कि इन फसलों, विशेष रूप से काजू की गुली, तिलहन, कपास, कच्ची जूट, गर्म मसालों, तम्बाकू आदि के निर्यात में वृद्धि की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान थीं। इस प्रस्ताव में इन वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार हेतु भी सरकार को उत्तरदायी बनाया गया।

इसी प्रकार फलों, सब्जियों व फूलों की वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर “निर्यात नीति प्रस्ताव” में बल दिया गया। इनके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के आवश्यक कदम उठाये जाने की घोषणा की गयी। विशेष रूप से असली रेशम के उत्पादन में वृद्धि तथा इसकी क्वालिटी में सुधार हेतु आवश्यक उपायों पर बल दिया गया।

विदेशो मे समुद्र से प्राप्त खाद्य वस्तुओ (मछली, घोघा, केकडा, आदि) की भारी माँग की तुलना मे इन वस्तुओ का भारत मे बहुत कम उत्पादन है। निर्यात नीति प्रस्ताव मे इस तथ्य को स्वीकार करते हुए इन साधनो के उपयुक्त विदोहन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त समुद्री खाद्य-वस्तुओ के परिनिर्माण हेतु भी आवश्यक कदम उठाने का निश्चय किया गया।

इसी प्रकार उक्त प्रस्ताव मे हमारे वनो मे प्राप्त साधनो के समुचित विदोहन एव इनका निर्यात बढ़ाने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि देश मे उपलब्ध खालो व चमडो के निर्यात व्यापार मे वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जाय। "निर्यात नीति प्रस्ताव" मे यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत मे अनेक खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है तथा इनके उत्पादन मे वृद्धि एव निर्यात से देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इन खनिज पदार्थो मे कच्चा लोहा, मैगनीज, क्रोम, बाक्साइट, अभ्रक, सिलीमेनाइट, कैडमियम, क्यानाइट, फ्लोरापार, आदि उल्लेखनीय है। इनमे से लोहा, मैगनीज व अभ्रक के निर्यात मे वृद्धि की काफी सम्भावनाएँ उपलब्ध है। ऐसा इस प्रस्ताव से स्पष्ट किया गया।

निर्यात नीति प्रस्ताव मे यह भी स्पष्ट किया गया कि नई इकाइयो को लाइसेन्स देते समय अथवा पुरानी इकाइयो की उत्पादन क्षमता के विस्तार की अनुमति देते समय इनकी निर्यात क्षमता को भी ध्यान मे रखा जाएगा। इन छोटी औद्योगिक इकाइयो तथा हस्तकला की वस्तुओ के निर्माताओ को उत्पादन बढ़ाने हेतु सभी प्रकार की सम्भव सहायता दी जाएगी, जो निर्यात हेतु उत्पादन क्रिया मे सलग्न है। उक्त प्रस्ताव मे यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि क्वालिटी-नियन्त्रण एव लदान पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी दायित्वो को सरकार और कठोरता पूर्वक करेगी।

भारत से सूती वस्त्रो का पर्याप्त मात्रा मे निर्यात किया जाता है। इस निर्यात नीति प्रस्ताव मे वस्त्र उद्योगो मे सलग्न इकाइयो के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। किन्तु इनमे से सभी इकाइयो का आधुनिकीकरण सम्भव नहीं है। पहले तो उन इकाइयो के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया जो पर्याप्त मात्रा मे निर्यात करने मे समर्थ हो। उक्त प्रस्ताव मे इन इकाइयो के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया तथा यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि आवश्यक हुआ तो अवश्यक साज-सज्जा के आयात द्वारा भी इनका आधुनिकीकरण किया जाएगा।

चुने हुए उद्योगो को निर्यात के बदले आयात लाइसेन्स प्रदान करने, नकद अनुदान देने, उत्पादन करो, प्रशुल्क दरो व रेल भाडे मे छूट देने तथा रियायती ब्याज दर पर निर्यातकर्ताओ

को साख उपलब्ध कराने की नीतियों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में भी जारी रखी गयी। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि जुलाई 1965 में 'विपणन विकास कोष' की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य निर्यातको को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। परन्तु इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति इस योजना काल में ही हो सकी। 1971-72 में उक्त कोष से निर्यातको को 4 करोड़ रुपये की साख उपलब्ध करायी गयी थी। 1972-73 में साख की यह राशि बढ़कर 62 करोड़ हो गयी। विभिन्न निर्यात सम्बर्द्धन परिषदों एवं संस्थाओं को सरकारी बजट से अनुदान देने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लागू कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात हेतु क्षतिपूर्क सहायता का भी प्रावधान किया गया था। 1971-72 में प्रशुल्क तथा उत्पादन करों में छूट के अन्तर्गत सरकार ने 36 करोड़ रुपये व्यय किये, जबकि 1972-73 में इन सुविधाओं पर 47 करोड़ रुपये व्यय किये गये।¹

1973 में निर्यात क्षेत्रों से सम्बद्ध उद्योगों के उत्पादन, अतिरिक्त सृजन तथा विदेशों में बाजार के विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर अधिक गम्भीरता पूर्वक ध्यान देने हेतु वाणिज्य मन्त्रालय में "निर्यात उत्पादन विभाग" की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त निर्यात व्यापार से सम्बद्ध इकाइयों की पूँजीगत वस्तुओं के आयात हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटारे हेतु औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को सीधा अधिकार दे दिया गया। इस सचिवालय की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर पूँजीगत वस्तुएँ आयात करने हेतु विदेशी विनमय के सामुदायिक आवंटन हेतु की गई, जो अपने उत्पादन का एक भाग निर्यात करती हैं।

इस योजना काल में विशुद्ध निर्यात आय में वृद्धि हेतु ऊँची कीमत वाली वस्तुओं का आयात बढ़ाने के भी प्रयास किये गये। इस्पात का उत्पादन देश में कम होने के कारण अत्यधिक मात्रा में आयात करने की आवश्यकता थी। 1973 जून में यह निर्णय लिया गया कि आयातित इस्पात केवल उन निर्यात अनुबन्धों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जिनका निर्यात (f o b) मूल्य इस्पात के आयात (c i f) मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक होगा। अर्ध निर्मित खालों के स्थान पर तैयार किये गये कपड़े को प्रोत्साहन देने हेतु अगस्त 1973 में खालों के निर्यात की मात्रा सीमित कर दी गई। इसके साथ ही चमड़ा उद्योग को उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने हेतु सम्बद्ध इकाइयों की उत्पादन क्षमता में विस्तार हेतु लाइसेन्स प्रक्रिया को और सरल बनाया गया।

¹ Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 1973-74, P-231

मनुष्य द्वारा निर्मित अर्थात् कृत्रिम रेशे, मिश्रित धागो एवं कुछ विशेष प्रकार के सूती धागो के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इन प्रतिबन्धों का प्रयोजन तैयार वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देना था। जूट की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु 1973 में गलीचों के काम में आने वाले जूट के सामान पर मौजूदा निर्यात कर में कमी की गई। 1973 अगस्त में टाट पर भी विद्यमान निर्यात कर में कमी की गई। परन्तु बोरियो पर विद्यमान निर्यात कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। बाद में मार्च 1974 में जूट की वस्तुओं के विश्व भर में मूल्य बढ़ जाने पर कार्पेट बैकिंग एवं टाट पर नवम्बर 1972 से पूर्व विद्यमान दरों से पुनः निर्यात कर लगा दिये गये, जबकि जूट की बोरियो पर फिर से निर्यात कर अगस्त 1973 में विद्यमान दर से लगा दिया गया।

पँचवी योजना काल में निर्यात नीति :-

पँचवी पंचवर्षीय योजना काल में निर्यातों में 35 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस निर्यात नीति के अन्तर्गत इस वृद्धि के लक्ष्य के पीछे यह भावना निहित थी कि विश्व के बाजारों में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अधिकाधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करते हुए देश आर्थिक विकास कर सके। भारत सरकार ने छ उद्योगों के लिए निर्यात का आवश्यक अनुपात बढ़ा दिया, क्योंकि इन उद्योगों की निर्यात क्षमता अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। ये उद्योग हैं — इन्जीनियरिंग उपकरण (file), ढले हुए हस्तचालित औजार (Hand tools)। अभी तक इन उद्योगों के लिए उत्पादन का न्यूनतम 5 प्रतिशत अंश निर्यात करना जरूरी था परन्तु अब यह सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई। अब तक निर्यात के लिए आवश्यक लक्ष्य पूरा करने पर आयात अधिकार में श्रेणीकृत कटौती का प्रावधान था। परन्तु अब जो इकाइयों उत्पादन के 10 प्रतिशत से कम निर्यात करेगी उनके आयात कोटे में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

इसके अलावा कुछ गैर परम्परागत निर्यात के सन्दर्भ में निर्यातकों को कच्चे माल व पूर्णों के सामान्य आयात अधिकार के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिक आयात कोटा दिया जाएगा। ये अधिकार इन उद्योगों के सन्दर्भ में दिये जाने का प्रवधान है—इन्जीनियरिंग वस्तुएँ, रासायनिक पदार्थ एवं सम्बद्ध उत्पादन, चमड़ा एवं कपड़े की वस्तुएँ, खेल सामान, हस्तकलाएँ, सूती वस्त्र एवं तैयार कपड़े। इस प्रकार इस पंचवर्षीय योजना काल में अपनायी जाने वाली निर्यात नीति को देश के भीतर एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया गया।

1976-77 एव 77-78 के लिए निर्यात नीति .- देश के निर्यात व्यापार में 1975-76 में आशातीत वृद्धि होने के पश्चात् भी व्यापार का घाटा बढ़ गया। इस वर्ष में वास्तविक निर्यात 3,9416 करोड़ रुपये का हुआ था जो कि लक्ष्य से कहीं अधिक था। परन्तु इसी वर्ष के आयातों में वृद्धि निर्यातों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से हुई। 1974-75 में व्यापार का घाटा 1,182.95 करोड़ रुपये का था जो कि 1975-76 में बढ़कर 1,216.2 करोड़ रुपये का हो गया। इस प्रवृत्ति को देखते हुए 1976-77 में व्यापार घाटे की स्थिति से निपटने हेतु निर्यातों में और अधिक वृद्धि करने का निश्चय किया गया। भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए 1976-77 तथा 1977-78 के दो वर्षों के लिए अपनी निर्यात नीति का निर्माण किया। इस नीति के अनुसार 1976-77 में 600 करोड़ रुपये से 700 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त निर्यात तथा 1977-78 में इससे भी अधिक राशि के निर्यातों का प्रवधान रखा गया।

इस नीति के अन्तर्गत निर्यात का विकास करने और उसमें विविधता लाने के प्रयासों को गतिशील करने के लिए, कई उपाय किये गये। इन प्रयासों में निर्यात के लिए वित्तीय सहायता, परिवहन सुविधाएँ, बजार अनुसंधान प्रशिक्षण, सस्थागत प्रबन्धनों को युक्ति सगत बनाना, सयुक्त राष्ट्र सघ के अभिकरणों और मित्र देशों से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना सम्मिलित था। इसके अलावा निर्यात में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा देना, आयात पुर्नभरण, दुर्लभ कच्चा माल प्राथमिकता से देना, कुछ दशाओं में रियायती कीमतों पर भी माल का निर्यात करना, रेल भाड़े में रियायत, आयात और उत्पादन शुल्कों की वापसी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणालियों के अनुरूप अन्य सामान्य और विशिष्ट सहायता देना, आदि सुविधाएँ भी सम्मिलित की गईं। इस वर्ष की निर्यात नीति में निर्यात व्यापार को बैंकों से ऋण देने के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया। निर्यातकर्ताओं के व्यापारी बैंकों से लदान पूर्व एव लदान के बाद रियायती ब्याज पर अग्रिम धन लेने की सुविधा दी गई। विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता का सामना करने, देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था में निहित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने, देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था में निहित प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रभावहीन करने और विपणन क्षमता का विकास करने के लिए कुछ चुनी हुई गैर परम्परागत औद्योगिक वस्तुओं को नगद सहायता चालू रखी गयी तथा निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाओं वाले चुने हुए मामलों में पूरक सहायता देना भी जारी रखा गया।

निर्यात सस्थान स्कीम को विस्तृत रूप से सशोधित किया गया तथा इसे और अधिक निर्यातवर्धक बनाया गया। इस नये स्कीम को 1976-77 की आयात नीति के साथ ही घोषित किया गया।

इन्जीनियरिंग, रसायन और अन्य उद्योगों को निर्यात माल बनाने के लिए देश में उपलब्ध आवश्यक कच्चा माल प्राथमिकता के आधार पर देने की व्यवस्था की गई। आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कच्चे माल का आयात करने का भी निर्यात नीति में प्रावधान रखा गया।

भारत सरकार ने 1976-77 की इस नई लाइसेन्स नीति की घोषणा में 100 प्रतिशत निर्यातवर्धक उद्योगों को महत्व दिया। इन इकाइयों को अपने सम्पूर्ण उत्पादन को बिना सरकार की क्षतिपूर्ति सहायता पर निर्भर रहते हुए प्रतियोगिता के आधार पर बेचने की छूट दी गई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। आयात कर मुक्त कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति सम्बन्धित सुविधाओं के अलावा सरकार ने कई अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने की घोषणा की। निर्यात इकाइयों को बजार की स्थिति के अनुसार उत्पादन की विविधता के लिए सुविधाएँ देने का भी प्रावधान रखा गया।

1976-77 में भारत के लाभ की स्थिति में आ जाने का प्रथम कारण तो आयात स्थिति में कुछ कठोर दृष्टिकोण रहा (जिसमें लाइसेन्स कम किए गये और रोके भी गये)। दूसरा कारण यह था कि 1976-77 में अधिकांश निर्यातित वस्तुओं के इकाई मूल्य में वृद्धि का लाभ भी प्राप्त हुआ, क्योंकि विश्व के विकसित औद्योगिक देशों में व्याप्त अवरोधक स्थिति समाप्त हो गयी थी। परन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि भारत को विदेशी खाद्यान्न का आयात करने में जिस बड़े खाते का भुगतान करना पड़ता था वह प्रायः बन्द हो गया। अतएव इस लाभ का श्रेय देश में खाद्यान्न की वृद्धि को दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि सरकारी उद्योगों में वर्षों से चली आ रही गतिरोध की अवस्था में परिवर्तन हुआ अर्थात् इन्जीनियरिंग सामान, लोहा, इस्पात, चमड़ा खली और कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्यात अधिक हुआ जो परम्परागत वस्तुओं के निर्यात से अधिक कही जा सकती है।

1977-78 की निर्यात नीति के सम्बन्ध में सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह नीति घरेलू माँग की पूर्ति करने तथा आयात का भुगतान अपने ही ससाधनों द्वारा कर, आत्मनिर्भर बनने में सतुलन स्थापित करने की होगी। 1977-78 में सरकार ने निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने की घोषणा इस मत से की, कि अनिश्चितकालीन विदेशी सहायता से मुक्ति पाने के लिए तथा उत्तरोत्तर एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली दुनिया में आत्मनिर्भर बनने के लिए निर्यात में वृद्धि करना ही एक मात्र उपाय है। इस वर्ष सरकार ने इन्जीनियरिंग के सामानों को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को प्रत्येक तरह की सहायता देने का प्रयास किया। इस वर्ष विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन के लिए 303 करोड़ रुपये रखे गये, जबकि 1975-76 में मात्र 160 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था थी। विगत वर्ष में निर्यात में हुई इस अतिरिक्त लाभ को

दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सकता है कि आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक अनुशासन और निर्यात नीति इन सबका प्रयोग उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। आजादी से इस वर्ष तक के 25 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी से भी अधिक हो गयी, जो कि सुखद प्रगति कहा जाएगा।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात नीति —

इस योजना काल (1980-85) में भारत के कुल निर्यातो का मूल्य लगभग 41,078 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। इस योजना काल में निर्यात नीति को इस प्रकार समायोजित किया गया कि एक तो देश को अधिकतम विदेशी विनमय प्राप्त हो सके, तो दूसरी ओर इस योजना के प्रमुख उद्देश्य में वृद्धि एवं अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति में योगदान मिल सके। इसी कारण आम लोगों के उपयोग की वस्तुएँ उदाहरणार्थ, चाय, सब्जी, दाल, तिलहन, आदि के निर्यात की अनुमति तभी दी जाएगी जब इनकी दशा में पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध हो। देश से टेक्नोलॉजी के निर्यात हेतु प्रयास, निर्यातकों को निर्यात सम्बर्द्धन परिषदों के माध्यम से सहायता देने, इनको मिलने वाली वर्तमान सुविधाएँ जारी रखने, निर्यातित होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार एवं लागत में कमी करने का प्रयास, परम्परागत निर्यात को बढ़ाने हेतु नये बाजार की खोज एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रयास, आदि का प्रावधान इस योजना काल में किया गया।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भू0पू0 वाणिज्य सचिव पी0सी0 एलेक्जेन्डर की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने जनवरी 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया कि वर्तमान में इन्जीनियरिंग की वस्तुएँ, रसायनो व सम्बद्ध वस्तुएँ, खेल के समान परिवर्तित कुछ पदार्थों, मछली व इससे बने पदार्थों, बगीचों, हस्तकला की वस्तुएँ, प्लास्टिक की वस्तुएँ, चमड़े से बनी वस्तुएँ, आदि के निर्यात पर नकदी सहायता दी जाय। 1979-80 से 1981-82 तक के तीन वर्षों के लिए अनेक पदार्थों के निर्यात पर नकद सहायता देने की व्यवस्था की गई। अनेक वस्तुओं के लिए नकद सहायता की दरें 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच निर्धारित की गई। निर्यात अनुदानों की राशि 1977-78 में 363 करोड़ रुपये थी जो 78-79 में 434 करोड़ रुपये हो गयी।¹

निर्यात नीति पर टण्डन समिति — श्री प्रकाश टण्डन की अध्यक्षता में सरकार ने निर्यात नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से 13 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1980 के

¹ बरला अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पृ0 428 एवं 429

दशक में निर्यात नीति से सम्बन्धित अपनी अन्तरिम रिपोर्ट मई 1980 में प्रस्तुत की।¹ समिति ने यह सुझाव दिया कि 1990-91 तक कुल निर्यात 17,986 करोड़ रुपये हो जाना चाहिए जबकि 1980-81 के लिए अनुमान 7000 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार समिति ने इस अवधि में 10 प्रतिशत वार्षिक दर से निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाया। समिति के अनुसार इसके लिए यह आवश्यक है कि एक “निर्यात जन्य विकास नीति” (Export oriented growth strategy) हो। समिति ने भी मत प्रकट किया कि निर्यात सम्बर्धन के ऐसे रास्ते अपनाये जाने चाहिए जिससे विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 तक कम से कम 1 प्रतिशत हो जाये। इस दृष्टि से समिति ने निम्न सुझाव दिये —

- 1 पर राष्ट्रीय निगमों (Transnational Corporations) को, भारत के लिए पंचवर्षीय निर्यात योजना, जो लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित हो, तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- 2 समिति ने ‘निर्यात जन्य आयात नीति’ के लिए सुझाव दिया तथा यह मत व्यक्त किया कि निर्यात-बाजार में पूर्ति के प्रयास को पूरा करने के लिए निर्यात घरों को ऐसी वस्तुओं के आयात की सुविधा दी जानी चाहिए जिनका आयात स्वीकृत न हो।
- 3 औद्योगिक इकाइयों तथा MRTP कंपनियों में लाइसेंस क्षमता को बिना ध्यान दिये हुए, निर्यात उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- 4 MRTP के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करने की लाइसेंस की व्यवस्था ‘निर्यात उत्पादन’ के सम्बन्ध में लागू किया जाना चाहिए।
- 5 ऐसे भारतीय व्यापार घर जो निर्यात घरों में से बने हों उन्हें MRTP के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए।
- 6 समिति ने यह सुझाव दिया कि बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पत्ति सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी जानी चाहिए।
- 7 समिति ने यह भी सुझाव दिया कि शत प्रतिशत निर्यात उत्पादन के आधार पर कंपनियों या औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लाइसेंस 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

¹ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मन्थली रिमि्यू अप्रैल, 1982 पर आधारित।

- 8 निर्यात उद्योगों को नवीनतम टेक्नोलॉजी के आयात की सुविधा दी जानी चाहिए ।
- 9 ऐसे उद्योग जो तीन वर्षों की अवधि में अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात किये हों, उन्हें पूँजीगत वस्तुओं के प्रशुल्क मुक्त आयात की सुविधा दी जानी चाहिए ।
- 10 समिति ने यह भी सुझाव दिया कि निर्यात जन्य उद्योगों के सम्बन्ध में परोक्ष कर ढाँचे में सुधार किया जाना चाहिए, जिससे वे कच्चा माल तथा मध्यम वस्तुएँ, बिना उत्पादन शुल्क के प्राप्त कर सकें ।
- 11 ऐसी कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में, जो निर्यात से सम्बन्धित हों, उत्पादन की योजना अलग से बनायी जानी चाहिए तथा इस योजना में राज्यों को गम्भीरता पूर्वक भाग लेना चाहिए । 'निर्यात जन्य फसलों' को बैंकों के माध्यम से आसान ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए ।

इस योजना काल में निर्यात नीति को अधिक युक्ति सगत एवं विकास परक बनाया गया।¹ इस अवधि की नीति में —

- 1 सर्वथा नये मदों (इंजीनियरी, तैयार कपड़े, दस्तकारी का सामान, हीरे—जवाहरात आदि) के निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि का निश्चय किया गया ।
- 2 निर्यातकों को सम्बन्धित उद्योग सम्बन्धी माल को आयात करने की छूट दी गई ।
- 3 निर्यात करने वाली इकाईयों को टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण करने की सुविधाएँ दी गई ।
- 4 निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ।
- 5 निर्यात वित्त के लिए निर्यात—आयात बैंक की स्थापना की गई ।

इन सब कदमों का लाभ यह हुआ कि पाँच वर्षों में निर्यातों में 76 प्रतिशत अर्थात् लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात नीति —

इसके पूर्व वाली योजना काल में आयात एवं निर्यात के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, निर्यातों का कुल योग 41,078 करोड़ रुपये की अपेक्षा केवल 33,000 करोड़ रुपये ही रहा, जिसके परिणामस्वरूप भारत को गम्भीर भुगतान सन्तुलन के संकट का सामना करना पड़ा।¹

¹ डा० जी०सी० सिंघई, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पृष्ठ 475

इस वर्ष यह भी अनुभव किया गया कि 1965-85 के दो दशकों की अवधि में भारत को केवल कुछ ही वस्तुओं (इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायानों, जवाहरात, तैयार पोशाकों, चमड़े की वस्तुओं तथा मछली से बने पदार्थों) के निर्यात में मात्रात्मक दृष्टि से सफलता मिल पायी थी। इसके फलस्वरूप अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती। इसीलिए सातवी योजना अवधि (1985-90) में निर्यातों का विविधीकरण करना आवश्यक समझा गया।

इस योजना के अर्न्तगत निर्यातों की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा गया जो पूर्व योजना की अपेक्षा कम होने पर भी व्यवहारिक था ऐसा अनुमान था कि उक्त वस्तुओं के निर्यात से इस योजना काल में अतिरिक्त विदेशी विनमय का 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होने की आशा थी। यह भी महसूस हुआ कि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यातों में वृद्धि के लक्ष्य कृषि जन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह से धातुओं तथा अन्य कुछ वस्तुओं के निर्यातों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करना सम्भव था। जबकि चाय, मसालों, सूती वस्त्र आदि के निर्यात में बढ़ोत्तरी की प्रबल सम्भावनाएँ विद्यमान थी। परन्तु पोशाकों तथा जूट की वस्तुओं के सन्दर्भ में भारत को अन्य देशों से स्पर्धा करनी पड़ी। इस योजना काल में निर्यात नीति को एक बार में घोषणा न करके तीन-तीन वर्षों के लिए दो बार में किया गया।

1985-88 की निर्यात नीति — इस योजना काल में पहली बार तीन वर्ष के लिए वाणिज्य मन्त्री द्वारा नयी निर्यात नीति की घोषणा की गई। वस्तुतः यह नीति 1984 के अन्त में व्यापार नीति समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनो में निहित सिफारिशों पर आधारित थी।² इस निर्यात नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें निहित थी—

- 1 निर्यात हेतु उत्पादन करने वाले उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक मशीनों की 201 मदों को खुले सामान्य लाइसेन्स श्रेणी में रखा गया।
- 2 निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देकर निर्यातों में अधिकाधिक वृद्धि करने का प्रयत्न करना।
- 3 निर्यात हेतु उत्पादन करने वाली इकाईयों के निष्पादन को आकलित करने हेतु आयात-निर्यात पास बुक प्रणाली लागू की गई। इसके आधार पर कच्चे माल का प्रशुल्क मुक्त आयात किया गया।
- 4 निर्यातों से सम्बन्धित माल के उत्पादन में तकनीकों को आधुनिकतम बनाना।

¹ Seventh five year plan (1985-90) Vol- I- P P- 65-68

² Economic Survey] 1988-89

- 5 ऐसी लघु इकाईयो तथा निगमो (निर्यात गृहो) के लिए निर्यात की न्यूनतम सीमा बढ़ा दी गई जो उदारतापूर्ण आयात नीति का लाभ उठाना चाहते थे।

इस नीति के फलस्वरूप हमारे निर्यातोन्मुखी उद्योगों की स्पर्द्धा क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी। इस नीति के फलस्वरूप हमारे उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

- 1 निर्यातो की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- 2 निर्यात (एव आयातो) का रिकार्ड रखने के लिए पास बुक की व्यवस्था की जाय।
- 3 5 से 10 करोड़ रुपये या अधिक के माल निर्यात करने वाली इकाइयों को अपना टेलीफोन एक्सचेंज आयात करने दिया जाएगा।
- 4 एक करोड़ रुपये या उससे अधिक रकम के वार्षिक निर्यात करने वाली इकाइयों को तकनीकी आयात करने की छूट दी जाएगी।

उपर्युक्त सब व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अधिकाधिक माल निर्यात करने वाली इकाईयों को टेक्नोलॉजी, मशीनें, पूर्जें, कच्चा माल, तथा वित्त सम्बन्धी सभी सुविधाओं की उपलब्धि में प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है।¹ इन सब सुविधाओं द्वारा देश के निर्यातो में आशातीत वृद्धि होने की आशा की गई।

वर्ष 1988-91 की तीन वर्षीय निर्यात नीति — अप्रैल 1988 से मार्च 1991 तक की अवधि के लिए त्रिवर्षीय निर्यात नीति 30 मार्च, 1988 को सरकार द्वारा निर्यात सम्बर्द्धन के प्राथमिक व्यूह रचना के एक भाग के रूप में किया गया। इस नीति के उद्देश्य का विवरण देते हुए वाणिज्य मन्त्री ने यह कहा कि आयात-निर्यात का नियन्त्रण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और निर्यात के लिए विकास को बढ़ावा देना चाहिए।² ओ0जी0एल0 तालिका के विस्तार का निर्माण सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, ताकि गैर जरूरी आयात न किया जाय। मंत्री महोदय के अनुसार केवल उन्ही वस्तुओं को आज्ञा प्रदान किया जाएगा जो कि घरेलू उत्पादन और देश के लिए जरूरी है।

इस तीन वर्षीय निर्यात नीति को सरकार ने क्रमबद्ध ढंग से निर्यात प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहनो में गुणात्मक-सुधारत्मक निर्यात

¹ डा0 जी0सी0 सिंघई, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पृष्ठ 476

² इकोनोमिक टाइम्स, मार्च, 31, 1988, नई दिल्ली

सम्बर्धन को नयी गति प्रदान करना था। इसमें आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया। इस नीति के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं—

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने की दृष्टि से ऐसे उद्यमी निर्यातकों को, जो अपने उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत निर्यात करते हैं। (न्यूनतम सीमा 1 करोड़ तथा इकाइयों के लिए 10 करोड़ रुपये) को निर्यात उत्पादन के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात की छूट होगी, भले ही इसका उत्पादन देश में हो रहा है।
- 2 निर्यात प्रोत्साहन को नयी प्रेरणा देना तथा इसके लिए प्रेरणाओं की गुणवत्ता व उनके प्रशासन में सुधार करना।
- 3 सरकार ने निर्यातों पर से नियंत्रण कम किये तथा निर्यात सूची में से 26 मदों को सरकारी क्षेत्र से मुक्त कर दिया।
- 4 अग्रिम लाइसेंस योजना को जो कुछ उत्पादों तक सीमित थी, ऐसे सब उत्पादों पर लागू कर दिया गया, जो दो विभिन्न इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से द्विस्तरीय ढंग से उत्पादित किये जाते हैं तथा इन दोनों इकाइयों को निर्यात का संयुक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया हो।
- 5 निर्यात वृद्धि के लिए Export House तथा Trading House की योजना को संशोधित कर दिया गया। इसका दर्जा प्राप्त करने के लिए विदेशी विनमय प्राप्त करने की निर्धारित शर्त रखी गई, जो कमश 2 करोड़ तथा 10 करोड़ है। इन सदनों की कुछ वस्तुओं के अलावा अन्य सब वस्तुओं के निर्यात की छूट होगी।
- 6 लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें Export House और Trading House का दर्जा देते समय अन्य उद्योगों की तुलना में दूना भार दिया जाएगा, तथा इन्हें आयात करने की विस्तृत छूट दी जाएगी।
- 7 नीति एवं विधियों को सरल एवं युक्ति सगत बनाया जाएगा।
- 8 निर्यात लाइसेन्स नीति को सरल बनाया गया तथा इनकी अवधि को बढ़ाया गया।
- 9 स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण निर्यात की अच्छी सम्भावना को देखते हुए इनकी निर्यात को उचित प्रोत्साहन दिया गया।
- 10 इस निर्यात नीति में अप्रत्यक्ष निर्यातकों की भूमिका को स्वीकार किया गया, अर्थात् जो अन्तिम निर्यात हेतु कच्चे माल तथा साधनों की पूर्ति करते हैं तथा इन्हें अनुमानित

निर्यातक (Deemed Exporters) का दर्जा दिया गया। इन्हें उन सब लाभों की पात्रता होगी जो वास्तविक निर्यातों को प्राप्त होते हैं। इससे घरेलू उत्पादन की क्षमता का न केवल पूर्ण उपयोग होगा वरन् विदेशी विनमय की भी बचत होगी।

- 11 इस नीति को भी कार्यान्वित किया गया कि व्यापार मन्त्रालय के अन्तर्गत राज्यों की राजधानी में निर्यात नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायें, जो इसकी निगरानी रखें कि उदर एव रियायती आयातों के फलस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों और व्यापार एव निर्यात सबर्धन एजेन्सी को शामिल कर समन्वय समितियाँ गठित की गई हैं जो निर्यात सम्बन्धी नीति एवं समस्याओं का अध्ययन कर निर्यात सम्बर्द्धन के उपाय सुझा सकें। भारी व्यापार घाटे को देखते हुए लक्ष्य यह है कि निर्यात में अधिकाधिक वृद्धि की जा सके और घाटे को कम किया जा सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में आयात-निर्यात नीति –

वाणिज्य मन्त्री श्री पी० चिदम्बरम ने 31 मार्च, 1992 को पहली बार पांच वर्षों के लिए देश की आयात-निर्यात नीति की घोषणा की। यह नीति 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी हो गयी।¹

दरअसल आयात-निर्यात व्यापार नीति देश के व्यापार नीति का अभिन्न अंग होती है और चूँकि हमारे आर्थिक सुधारों की दिशा स्पष्ट है इसलिए इस आयात-निर्यात की दिशा भी बहुत स्पष्ट है। न्यूनतम प्रतिबन्ध, व्यापार में अधिक स्वतंत्रता और प्राशसनिक नियंत्रणों में कमी इसके मूल मंत्र हैं। इस आयात-निर्यात नीति में आयात और निर्यात के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का निषेध किया गया है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं का आयात-निर्यात में कुछ प्रतिबन्धों के साथ छूट दी गयी। खाद्य तेलों, खाद्यान्नों, पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों व कुछ अन्य वस्तुओं का आयात सरकारी एजेंसियों के द्वारा करने की घोषणा की गई। कुल मिलाकर यह है कि इस आयात नीति में तीन वस्तुओं के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 71 वस्तुओं के आयात को सीमित किया गया तथा 7 वस्तुओं के आयात को सरकारी संस्थाओं द्वारा ही आयात की अनुमति दी गई।

इस आयात-निर्यात नीति (1992-97) में आयात के लिए जो निषेधात्मक सूची बनाई गई उसमें किसी भी पशु की चर्बी से बना तेल, पशु रैनेट और हाथी दाँत (बिना बना हुआ) को सम्मिलित किया गया। जिन वस्तुओं पर कुछ प्रतिबन्ध के साथ आयात की छूट दी गयी, उनमें

¹ प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक वर्ष 1993-94 पृष्ठ 93

इलेक्ट्रानिक, दूरसंचार का सामान, घड़ियाँ, अल्कोहल या मदिरा के सान्द्रण, केसर, दालचीनी, आदि भी है। इस आयात-निर्यात नीति में लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता के आयात की अनुमति तभी दी जाएगी जब आयात के मूल्य के दोगुने के बराबर निर्यात किया जाएगा। फिर भी इस आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, खेलकूद की सामग्री, कैमरे, आदि को विशेष उपभोक्ताओं के लिए ही लाइसेंस द्वारा ही आयात की अनुमति दी जाएगी। होटल, खेल संस्थाओं व पर्यटन उद्योग को भी यह विशेष सुविधाएँ दी गईं।

इस तरह से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की निषेधात्मक सूची भी काफी छोटी कर दी गई। मात्र सात वस्तुओं के निर्यात पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया गया। जिसमें सभी प्रकार के जंगली जीव, उनके भाग और उत्पाद, विदेशी पक्षी, जिन प्रजातियों के वश सकट में हैं उनके निर्यात, गौमास, मानव अस्थिपिंड, मछली को छोड़कर किसी पशु मूल की चर्बी या तेल और लकड़ी या उसके लट्ठे का निर्यात प्रतिबन्धित कर दिया गया।

इसी तरह से 62 वस्तुओं के निर्यात पर विभिन्न सीमाएँ और नियंत्रण लगाये गये। इनमें अस्थिपूर्ण, मवेशी, ऊँट, गधे, हाथ से बने रेशम के धागे, विविध प्रकार के चमड़े, छोड़े खासकर काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी प्रजाति के छोड़े और खच्चर, कई प्रकार के रसायन, खनिज, राक फास्फेट आदि सम्मिलित हैं।

इस आयात-निर्यात नीति के आधीन 10 वस्तुओं का निर्यात सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही किया जा सकेगा। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद, मक्खन, गोद रेसिन, माइका बेस्ट, खनिज अयस्क और सान्द्र, प्याज, दूध का पाउडर तथा घी सम्मिलित हैं।

इस पंचवर्षीय आयात-निर्यात नीति में पूँजीगत माल के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, साथ ही पुराने पूँजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई जिनमें से कुछ मामलों में लाइसेंस लेना आवश्यक होगा, तथा अब निर्यात बढ़ावा देने के लिये ई0पी0सी0जी योजना के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले पूँजीगत माल पर भी दो प्रकार की रियायतें दी गईं, जो निर्यात की अवधि और मात्रा पर निर्भर होगी। बाद में 1993-94 से इसमें एक रियायत समाप्त कर दी गई।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि 1947 में बने आयात निर्यात (नियंत्रण) कानून के स्थान पर सरकार शीघ्र ही एक और विधेयक लायेगी, जिसका नाम विदेशी व्यापार (विकास और नियमन) विधेयक 1992 होगा। जिसमें नई आयात नीति के साथ उसके अन्तर्गत बनाए जाने वाले सारे नियम सम्मिलित किये जाएंगे। इस प्रकार का विधेयक जुलाई 1992 में संसद ने

प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे ससद ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पंचवर्षीय आयात-निर्यात नीति के तदनुरूप ही सरकार ने अपने वार्षिक बजटों (1992-93, 93-94) में अनेक आयात निर्यात से सम्बन्धित उदारीकरण के उपायों की घोषणा की।

1993-94 की आयात-निर्यात नीति में सशोधन — सरकार ने आयात निर्यात (1992-97)

की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा 31 मार्च, 1993 को की। 31 मार्च, 1992 को अगले 5 वर्षों के लिए घोषित आयात-निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाते हुए इसमें कृषि क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ लगाने पर और छूट देने तथा बैंक और अन्य सेवा क्षेत्रों के लिए कई नयी योजनाएँ प्रारम्भ करने की घोषणा की। इस नीति में किये गये महत्वपूर्ण सशोधनों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है

1. **निर्यात क्षेत्र का विस्तार** — इस सशोधन के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निषेधात्मक सूची में शामिल 334 वस्तुओं में से 144 वस्तुओं को निर्यात योग्य वस्तुओं की सूची में सम्मिलित कर लिया, जिनके निर्यात पर पहले रोक लगी हुई थी। अब इनके निर्यात के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी। निर्यात प्रयासों में राज्यों को शामिल करने के लिए एक केन्द्रीय योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया जिनमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान किया गया।

2. **निर्यातोन्मुखी इकाइयों को लाभ** — सशोधित आयात-निर्यात नीति के अनुसार अब कृषि मत्स्य, पशुपालन, मुर्गीपालन, बागवानी, रेशम उद्योग तथा फूलों का व्यापार करने वाली इकाइयों को भी अपने उत्पादों का 50 प्रतिशत तक निर्यात करने पर वही सुविधाएँ तथा रियायतें मिलेंगी जो अन्य औद्योगिक इकाइयों को शत-प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत तक निर्यात करने पर मिलती है। ऐसी इकाइयाँ अब अपने शेष 50 प्रतिशत उत्पादों को घरेलू बाजार में बेच सकेंगी जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए यह सीमा 25 प्रतिशत तक ही है।

3. **झरोखों की समाप्ति** — वर्तमान में अन्य क्षेत्रों के लिए लागू EPCG योजना (Export Promotion Capital Goods Schemes) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दर को सशोधित आयात-निर्यात नीति में खुला रखा गया, तथा 25 प्रतिशत आयात शुल्क वाला दूसरा झरोखा अब समाप्त कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे यह कारण बताया गया कि 1993-94 के केन्द्रीय बजट में पूँजीगत सामान पर सामान्य प्रशुल्क में कमी के कारण ई0पी0सी0जी0 योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत आयात शुल्क से कोई अतिरिक्त लाभ उपलब्ध नहीं रह गया था।

4. पूँजीगत माल की परिभाषा का विस्तार – इस सशोधित नीति के अन्तर्गत पूँजीगत सामान की परिभाषा को भी बदल दिया गया, तथा उसमें कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यों में काम आने वाले सामान को भी सम्मिलित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी पूँजीगत सामान को रियायती दर पर आयात करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में काम आने वाले उपकरणों और सामान को अब निषिद्ध सूची से हटा दिया गया, ताकि एक ओर उनका निर्माण किया जा सके और दूसरी ओर इकाइयों ऐसे सामान का अपने काम के लिए आसानी से आयात भी कर सकें। इस सूची में मछलियों और मूर्गियों का भोजन, खाद्य मोम, अगूरों के बचाव के लिए उन पर लपेटा जाने वाला कागज आदि शामिल हैं। उस समय उम्मीद कि गई कि कृषि क्षेत्र के लिए घोषित इन रियायतों के फलस्वरूप कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

5. बैंक गारण्टी में उदारता – EPCG योजना के अन्तर्गत एक आयातकर्ता को उपलब्ध कराने वाली बैंक गारण्टी की आवश्यकताओं को सशोधित नीति के तहत उदार बना दिया गया तथा बैंक गारण्टी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया।

6 सेवा क्षेत्र के लिए पूँजीगत सामान निर्यात प्रोत्साहन योजना – सशोधित आयात-निर्यात नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सेवा का लाभ उठाने के लिए एक नई योजना लागू करना है। इस योजना को पूँजीगत माल निर्यात सम्बर्द्धन योजना का नाम दिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वास्तुविद, पत्रकार, इन्जीनियर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, कलाकार, अर्थशास्त्री वर्ग के लोग 15 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर उपकरणों का आयात कर सकेंगे। इस योजना का लाभ होटल, रेस्तरा चलाने वाले तथा ट्रेवल एजेंट भी उठा सकेंगे। उनका निर्यात दायित्व अर्जित विदेशी मुद्रा के रूप में देखा जाएगा। चाहे यह मुद्रा घरेलू सेवाओं से अर्जित की जाये अथवा विदेशी सेवा से। इस योजना के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो जाती है कि उन्हें अब विनिर्मित क्षेत्र के बराबर स्तर दिया जा रहा है।

7. अन्य सुविधाएं – जिन निर्यातकों ने रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने से पूर्व निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली थी। किन्तु 1 मार्च, 1993 के पूर्व उन्होंने अपने शुल्क मुक्त आयात लाइसेन्स का उपयोग नहीं किया था। उन्हें इसकी हानि उठानी पड़ी। अब इस सशोधित नीति के तहत ऐसे निर्यातकों की इस हानि को दूर करने के लिए यह निश्चित किया

गया कि उन्हें इनके अप्रयोगिक आयात लाइसेन्सों की 8 प्रतिशत के बराबर राशि नगद रूप में दी जाएगी।

पुनः उन निर्यातकों के लिए जिन्होंने अपने निर्यात 1 मार्च, 1992 तक पूरे कर दिए थे, तथा जिन्होंने 27 फरवरी 1993 तक अपनी एक्जिम स्क्रिप्ट्स का विनमय नहीं किया था, उन्हें उन एक्जिम स्क्रिप्ट्स को उत्सर्जन करने का एक और अवसर दिया जाएगा तथा वे उन पर 20 प्रतिशत प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं।

1992-97 की आयात-निर्यात नीति में पुनः सशोधन – निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापारिक नीति के अन्तर्गत आयात निर्यात नीति (1992-97) को और अधिक उदार बनाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में 1 अप्रैल, 1994 को घोषित आयात-निर्यात नीति में विशेष आयात लाइसेन्सों के क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसके तहत उपभोक्ता सामान के आयात की भी अनुमति प्रदान की गयी।¹ और उन लाइसेन्सों के तहत आयातित उपभोक्ता सामान की सूची को भी व्यापक बनाया गया। इस नीति के अन्तर्गत किए गये कुछ अन्य सशोधन हैं—सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस श्रेणी का प्रारम्भ, आयात की जाने वाली पुरानी मशीनरी की आयु सीमा की समाप्ति, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में व्यापार क्षेत्र का विस्तार आदि। उनसे सम्बन्धित सक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं—

- 1 ई0पी0सी0जी0 लाइसेन्स देने के अधिकार का विकेंद्रीकरण।
- 2 विकलांग लोगों को कुछ विशिष्ट मदों में मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति।
- 3 'सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस' नामक एक नयी श्रेणी की स्थापना व उसकी सदस्यता के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण।
- 4 आग्रिम राशि आदेश की सुविधा का विस्तार, जैसे स्पेशल इम्परेस्ट लाइसेन्स, एडवान्स इण्टरमीडिएट लाइसेन्स आदि में।
- 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ई0पी0सी0जी0) का सरलीकरण तथा निर्यात बाध्यता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तृतीय पक्ष को निर्यात की अनुमति।
- 6 DEEC पुस्तिका में वर्णित अर्हताओं की समाप्ति।
- 7 इलेक्ट्रानिक उद्योगों के तैयार उत्पादकों के लिए आयात की नकारात्मक सूची में काट-छाट।

¹ प्रतियोगिता सम्राट – मई 9195, दीवान पब्लिकेशन (प्रा0) लि0 नई दिल्ली, पृष्ठ 8

8 शुल्क मुक्ति स्कीम के अन्तर्गत की जानी वाली कार्यवाही का सरलीकरण।

इसके अतिरिक्त आयात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के साथ-साथ सीमा शुल्को में भारी कटौती की गई। पूँजीगत सामान के आयात पर लगने वाले शुल्को पर भारी कटौती की गई। निर्यात को बढ़ावा देने व विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि के उद्देश्य से अब चालू खाते में रुपये को पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया गया है।

आयात-निर्यात नीति (1992-97) में वर्ष 1995 का सशोधन — 1992-97 की आयात निर्यात नीति में 1993-94, 1994-95 व 1995-96 में पुनः सशोधन किये गये।¹ 1995-96 के लिए किये गये सशोधन की घोषणा 31 मार्च, 1995 को की गई। 1 अप्रैल, 1995 से प्रभावी इन सशोधनों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है —

- 1 1 अप्रैल, 1995 से 'बोर्ड आफ ट्रेड' का पुनर्गठन किया गया। 25 सदस्यीय इस बोर्ड में निजी क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र की कंपनियों व बैंको के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।
- 2 निर्यातकों को दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता के लिये निर्यात राशि की वास्तविक वसूली की शर्त समाप्त कर दी गयी।
- 3 उपहारों के आयातों के लिये कस्टम क्लियरेंस परमिट की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी।
- 4 आयातों के ऋणात्मक सूची में कुछ और कटौती की गयी। नयी सूची में तीन वस्तुओं का आयात निषिद्ध, 65 का नियन्त्रण, तथा 7 का केवल सरकारी संस्थाओं के माध्यम से Canalised होगा।
- 5 EPCG लाइसेंस धारकों को की गयी आपूर्ति को डीमंड एक्पोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया।
- 6 विशेष आयात लाइसेंस (SIL) के तहत आयात की जाने वाली उपभोग वस्तुओं की सूची का विस्तार किया गया। SIL सूची में शामिल वस्तुओं को OGL में हस्तांतरित किया गया, जबकि 39 नई वस्तुएं इसमें शामिल कर दी गईं।
7. निर्यातानुमुखी इकाईयों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र के मामले में नीति को विवेकीकृत किया गया है।

¹ प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक वर्ष 1996-97 पृष्ठ 108

- 8 इस ससोधित नीति मे निर्यात सम्बर्धन पूँजीगत सामान योजन का विस्तार किया गया तथा मर्चेन्ट एक्सपोर्टर्स व सेवाओ की आपूर्ति करने वालो को भी इसके लाभ उपलब्ध किए गये।
- 9 मूल्य सम्बर्धन के पश्चात् पुर्ननिर्यात की जाने वाली वस्तुओ के मामले मे अग्रिम कस्टम क्लीयरेंस परमिट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब एक बाण्ड/गारण्टी भरकर ही ऐसी वस्तुओ का आयात किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे मामलो मे निर्यात के समय मूल्य सम्बर्धन कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।
- 10 आयात-निर्यात की प्रक्रिया त्वरित गति से निपटाने के उद्देश्य से चुनीन्दा श्रेणीयो के आयातको व निर्यातको के लिए एक ग्रीन चैनल प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।
- 11 विदेशो मे सयुक्त उपक्रम स्थापित करने या पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाइयों स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रो का निपटान अब अकेले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाएगा।
- 12 EPCG योजना के तहत अब वस्तुओ व सेवाओ मे भेद सामाप्त कर दिया गया। ताकि सभी प्रकार की सेवाओ के निर्यातक इस योजना का लाभ उठा सके।
- 13 पडोसी राष्ट्रो के साथ व्यापार के मामले मे निर्देश जारी करने का अधिकार विदेशी व्यापार के महानिदेशक को होगा। श्रीलका से आयात की जाने वाली वस्तुओ के 18 प्रशुल्क मामले मे रियायती दरे घोषित की गई।
- 14 खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के तहत स्वतन्त्र रुप से आयात की जाने वाली वस्तुओ की सूची का विस्तार किया गया, तथा अभी तक कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओ व पूँजीगत वस्तुओ के अतिरिक्त इस सूची मे 43 उपभोग वस्तुएँ सम्मिलित थी। नई नीति मे इन्हे बढाकर 75 कर दिया गया।
- 15 मूल्य आधारित व मात्रा आधारित आग्रिम लाइसेन्स योजना का भी विस्तार किया गया।
- 16 पूँजीगत वस्तुओ को मरम्मत, जॉच प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन आदि कार्य सुगमता से विदेश भेजा जा सकेगा। इसके लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नही होगी।
- 17 निर्यात की लगभग 3100 वस्तुओ के लिए इनपुट आउटपुट मानक अभी तक उपलब्ध थे, इन्हे बढाकर अब 4200 वस्तुओ से भी अधिक के लिए उपलब्ध किया गया।

- 18 नई नीति में निजी क्षेत्र को वेयर हाउसेज खोलने की अनुमति दी गई, जिससे आयातकों और निर्यातकों की सहूलियत बढ़ेगी। इससे डियूटी के भुगतान के बिना सामान का भण्डारण किया जा सकता है और केवल क्लीयरेंस के समय डियूटी का भुगतान कर उन्हें घरेलू खपत के लिए निकाला जा सकता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि इस एक्जिम नीति में आयातों को काफी उदार बनाया गया तथा ऐसे आयातकों को अधिक राहतें प्रदान की गईं जो अपने उत्पादन का निर्यात करते हैं।

नवीं पंचवर्षीय योजना काल में आयात-निर्यात नीति –

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 को नवी पंचवर्षीय योजना में आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक मजबूत करते हुए उदारीकरण, पारदर्शिता और सरलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तेज आर्थिक विकास का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उसी से रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं और आमदनी का स्तर भी बढ़ता है। इस आयात निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- 1 आवश्यक कच्चा माल, कलपुर्जों उपभोग व पूजीगत वस्तुओं की उपलब्धि निश्चित करना ताकि उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक सवृद्धि की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
- 2 उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर अच्छी किस्म की वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- 3 बढ़ते हुए विश्व बाजार से लाभ उठाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन व गत्यात्मकता लाना।
- 4 भारतीय कृषि उद्योग व सेवाओं की तकनीकी क्षमता व दक्षता में वृद्धि लाकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि लाना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना तथा विश्व मान्य क्वालिटी उत्पादों का उत्पादन प्रोत्साहित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस नीति में जो कदम उठाए गये हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न लिखित हैं –

- 1 इस आयात निर्यात नीति में साफ्टवेयर व हार्डवेयर निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये गये। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादक केवल 50 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात कर सकते हैं और 50 प्रतिशत उत्पादन की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में बिक्री कर सकते हैं।

2 कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में काम कर रही निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के लिए घरेलू बिक्री की अनिवार्य शर्तों में ढील दी गई। ये इकाइयाँ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत तक बेच सकती हैं।

3 प्रतिबन्धित सूची को काफी कम कर दिया गया। सरकार ने 542 मदों के आयात को प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया जिसमें 150 ऐसे मद शामिल किए गये, जिनका आयात अब विशेष आयात लाइसेन्सों के माध्यम से किया जा सकेगा। 60 मदों को विशेष आयात लाइसेन्सों की श्रेणी से हटा कर खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के वर्ग में रखा गया। 5 मदों पर पर्यावरण सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध लगाये गये।

4 इस नीति में कार्य प्रणाली को पारदर्शी और कम विवेकाधीन बनाने के प्रयास इस बात को ध्यान में रखते हुए किये गए, कि नियमों और कार्य प्रणाली को सरल बनाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ – एडवांस लाइसेन्स के अधीन निर्यात बाध्यता, लाइसेन्स के आधीन निर्यात बाध्यता और लाइसेन्स की वैधता की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है।

5 आयात-निर्यात नीति 1997-2002 में पूँजीगत वस्तुओं की निर्यात प्रोत्साहन योजना में संशोधन किए गए। पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क 13 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया। इस योजना काल में 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक के आयातों को बिना शुल्क दिए मगवाने की अनुमति दी गई। परन्तु कुछ निर्यात बाध्यता की शर्तें रखी गईं। कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के निर्यातों के लिए पूँजीगत वस्तुओं को 5 करोड़ रुपये तक बिना आयात शुल्क दिए मगवाने की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के अधीन सेवा उद्योगों जैसे अस्पताल, वायुयान द्वारा माल ढुलाई, होटल व अन्य पर्यटन सम्बन्धित सेवाओं को भी शून्य शुल्क का लाभ दिया गया।

6 स्वर्ण आभूषण व जवाहरात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इस नीति में उन एजेसियों की संख्या में वृद्धि की गयी जो स्वर्ण के भण्डार रख सकती हैं। एजेसियों की संख्या में वृद्धि होने से निर्यातकों को स्वर्ण की आपूर्ति ज्यादा आसानी से और अधिक मात्रा में हो सकेगी, जिससे आभूषण निर्माण में कोई व्यवधान नहीं होगा।

7 वैल्यू वेस्टेड एडवांस लाइसेन्स तथा पुरानी पास बुक योजनाओं के स्थान पर एक नई ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक योजना शुरू की गई। जिसमें इन दोनों योजनाओं के अच्छे तत्वों का समावेश है और जिसे लागू करने प्रशासनिक रूप से अधिक आसान है। यह योजना अधिक

पारदर्शी होने के कारण लाइसेंसिंग या सीमा शुल्क अधिकारी इसका मनमाने ढंग से प्रयोग भी नहीं कर सकते। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में किये गये औसत निर्यात मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर आयात करने की छूट दी गई। इस छूट की वजह से निर्यातक बिना आयात शुल्क दिए आयात कर सकेगे।

8 आयात निर्यात नीति 1997-2002 की नीति में निर्यात गृहों की न्यूनतम सीमा को दुगुना कर दिया गया। इस नीति के अनुसार, निर्यात गृह का दर्जा पाने के लिए निर्यातक को पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कम से कम 20 करोड़ रुपये मूल्य का अथवा पिछले वर्ष 30 करोड़ रुपये मूल्य का, निर्यात करना आवश्यक है, जबकि पहले में सीमाएँ क्रमशः 10 करोड़ रुपये तथा 15 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार व्यापार गृहों के लिए इन न्यूनतम सीमाओं को बढ़ाकर क्रमशः 100 करोड़ व 150 करोड़ रुपये कर दिया गया। स्टार व्यापार गृहों के लिए नई सीमाएँ क्रमशः 500 करोड़ रुपये तथा 750 करोड़ रुपये तय की गईं। सुपर स्टार व्यापार गृहों के लिए न्यूनतम सीमाओं को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये तथा 2,250 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आयात निर्यात नीति में वर्ष 1998-99 का संशोधन .- आयात-निर्यात नीति 1997-2000 में 13 अप्रैल, 1998 को कुछ आवश्यक संशोधन किए गये। इस संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

- 1 आयातों और निर्यातों के लिए निजी आबद्ध गोदामों की स्थापना की अनुमति दे दी गई।
- 2 कुछ और मदों को ऋणात्मक व प्रतिबन्धात्मक सूची से हटा कर खुले सामान्य लाइसेन्स में रखा गया। 1 अप्रैल, 1996 से 6,161 मदें ऐसी थीं जिनका मुफ्त आयात किया जा सकता था, 1 अप्रैल, 1997 को इनकी संख्या बढ़ कर 6,649 हो गई। 31 दिसम्बर 1997 को जारी एक विज्ञप्ति के द्वारा 128 मदों को आयात प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया गया।
- 3 उपभोग के लिए निर्यात किए जाने वाले तिलहनो तथा खाद्य तेलों के निर्यात पर अब कोई मात्रात्मक प्रतिबन्ध नहीं होगा और न ही लाइसेन्स लेने की कोई आवश्यकता होगी।
- 4 पूँजीगत वस्तुओं की निर्यात प्रोत्साहन योजना के आधीन कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए बिना आयात शुल्क दिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात की न्यूनतम सीमा को 5 करोड़ रुपये से कम करके 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग, चमड़ा, हीरे व जवाहरात, खेल का सामान और खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्रों के लिए इस न्यूनतम सीमा को 20 करोड़ रुपये से कम करके 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। साफ्टवेयर क्षेत्र के लिए न्यूनतम सीमा मात्र 10 लाख रुपये रखी गयी।

1 अप्रैल, 1997 को भुगतान शेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभी 2,714 मदों पर आयात प्रतिबन्ध लगे हुए थे। विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य होने के नाते भारत को ये प्रतिबन्ध एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हटाना था। 1 अप्रैल, 1997 से लेकर अगले 6 वर्षों के बीच इन प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाना था। भारत में यह काम तीन चरणों में अर्थात् पहले तीन वर्षों में पुनः 2 वर्षों में तथा अन्त में आखिरी एक वर्ष में किए जाने का निश्चय किया गया, किन्तु यह कार्य समय से पूर्व ही कर लिया गया।

1999–2000 के आयात–निर्यात की नई सशोधित नीति .— पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति 1997–2002 में वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लिए सशोधित आयात–निर्यात नीति (एग्जिम पॉलिसी) की घोषणा तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री राम कृष्ण हेगड़े द्वारा 31 मार्च 1999 को नई दिल्ली में की गई। निर्यातकों को और रियाते प्रदान करते हुए नई एग्जिम नीति को अधिक उदार बनाया गया। प्रतिबन्धित सूची में भारी कटौती करते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) की शर्तों को पूरा करने का प्रयास भी इसमें किया गया। इस नयी नीति के तहत आयातों को और अधिक उदार बनाते हुए प्रतिबन्ध सूची में से 894 उत्पादों को मुक्त आयात लाइसेन्स (OGL) के तहत तथा 414 अन्य को विशेष आयात लाइसेन्स (SIL) वाली सूची में ले आया गया।¹ मुक्त आयात सूची में लाए गये अधिकांश उत्पाद कृषि उत्पाद तथा शेष मुख्यतः उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के उत्पाद हैं। प्रतिबन्धित सूची में से कुल 1308 उत्पादों को ओ0जी0एल0/एस0आई0एल0 के तहत ले आने के पश्चात् अब केवल 667 उत्पाद ही प्रतिबन्धित सूची में रह गये। विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गये वायदे के तहत भारत को सन् 2003 तक आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त करने थे, किन्तु इस गति से यह लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही प्राप्त किया जा सका।

निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रों को जुलाई 1999 से मुक्त व्यापार क्षेत्र में बदल दिया गया। एफ0टी0जेड0 की इकाईयों को कोई भी निर्माण अथवा व्यापार गतिविधियों को करने की छूट होगी और किसी पूर्व निश्चित मूल्य सवर्धन, निर्यात प्रतिबद्धता, निवेश–उत्पादन मानदण्डों आदि से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा।²

¹ प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक वर्ष 1999–2000 पृष्ठ 117

² यूथ कम्पिटिशन टाइम्स, प्लानर – 1 समान्य जानकारी, 12 चर्चलेन इलाहाबाद पृष्ठ 55

प्रणाली और प्रक्रिया को सख्त करने के लिए दो मुख्य कदम उठाये गये हैं –

- 1 निर्यातको और महानिदेशक, विदेशी व्यापार के बीच मेलजोल कम करने के लिए वार्षिक अग्रिम लाइसेन्स लागू किया गया। इस सुविधा से शुल्क मुक्त आयात और लचीला बना दिया जाएगा। ये लाइसेन्स, बिना किसी न्यूनतम मूल्य सवर्धन के जारी किये जाएंगे।
- 2 अग्रिम लाइसेन्स जारी करने के लिए दिल्ली में पायलट आधार पर प्रपत्र इलेक्ट्रानिक रूप से भर कर भेजने की सुविधा शुरू की गयी। इससे निर्यातको को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रपत्र भरने और ई-मेल के जरिए उत्तर प्राप्त करने की सुविधा होगी। इस सुविधा को धीरे-धीरे अन्य सभी बन्दरगाहों पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी।

इस प्रकार इस नीति के मुख्यतः तीन तथ्य प्रकट होकर सामने आते हैं –

पहला, भारत सरकार व्यापार नीति को WTO मापदंडों के निरन्तर अनुरूप बनाने के लिए वचनबद्ध है। नीति के स्वरूप और व्यवहार को उदार बनाना और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अधिक आसान, पारदर्शी और उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप बनाना।

दूसरा, विशिष्ट निर्यात सम्बर्द्धन योजनाओं के मामले में भारत सरकार किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, बशर्ते कि वह इन योजनाओं की उपयोगिता और वैधता के बारे में सन्तुष्ट हो।

तीसरा, कम्प्यूटर आधारित प्रक्रियाएँ जैसे EEI के बढ़ते उपयोग से वियमट एजेसियों की भूमिका कम की जाएगी और निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन में सरकार व्यापारिक समुदाय पर अधिक विश्वास रखेगी।

सशोधित नीति के तहत निर्यात गृह, ट्रेडिंग हाऊस अथवा स्टार एव सुपर स्टार ट्रेडिंग हाऊस के दर्जे के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को तीन गुना भराश प्रदान किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्हें सामान्य निर्यातको के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात या विदेशी मुद्रा अर्जन सीमा का सिर्फ एक तिहाई ही हासिल करने पर निर्यात गृह का दर्जा मिल जाएगा। सेवा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया। सेवा निर्यात गृह के दर्जे के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट को वस्तु व्यापार की इकाईयों के लिए निर्धारित लिमिट से एक तिहाई रखा गया। इस सशोधित एक्जिम नीति के महत्वपूर्ण बिन्दू निम्नवत हैं –

- 1 प्रतिबन्धित सूची से 894 वस्तुएँ OGL सूची में तथा 414 वस्तुएँ SIL सूची में स्थानान्तरित, प्रतिबन्धित सूची में केवल 667 वस्तुओं को रखा गया।

- 2 बन्दरगाहों पर लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
- 3 रसायन, प्लास्टिक व टेक्सटाइल क्षेत्र में EPCG योजना के तहत थ्रेशोल्ड मात्रा में भारी कमी की गयी।
- 4 EPCG व अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत निर्यात दायित्वों की पूर्ति हेतु समय सीमा में ढील दी गई।
- 5 सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा।
- 6 रूस को सभी निर्यात के मामले में 100 प्रतिशत के स्थान पर 33 प्रतिशत मूल्य सम्बर्द्धन की घोषणा।
- 7 विशेष श्रेणियों के निर्यातकों के लिए ग्रीन कार्ड तथा गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था।
- 8 जुलाई 1999 से निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रों EPZs का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (ETZs) के रूप में स्थानान्तरण की व्यवस्था।
- 9 प्रीशिपमेन्ट व पोस्ट शिपमेन्ट निर्यात ऋणों के मामले में ब्याज में 2 प्रतिशत की विशेष रियायत समाप्त करने की घोषणा।

निर्यात सम्बर्द्धन पूँजीगत सामान (EPCG) योजना के तहत जीरो ड्यूटी पर पूँजीगत सामान के आयात के न्यूनतम सीमा को रसायन, प्लास्टिक व टेक्सटाइल क्षेत्र के मामले में बीस करोड़ रुपये से घटकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत निर्यातकों को आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये निर्यात दायित्व की समय सीमा में 24 महीने की ढील दी गई। अग्रिम निर्यात लाइसेन्स धारकों को भी अपने निर्यात दायित्वों के पूर्ति के लिए 18 माह की ढील प्रदान की गई।

ड्यूटी एटाइटलमेन्ट पास बुक (DEPB) योजना व शुल्क मुक्त योजना का लाभ उठाने के लिए बन्दरगाहों की सूची में कुछ और भी बन्दरगाह शामिल कर दिये गये हैं। सीमा शुल्क के मामले में निर्यातकों के विवाद को तत्काल निपटाने के लिए बन्दरगाहों पर लोकपाल की नियुक्ति की बात सशोधित नीति में कही गई है। इसकी शुरुआत बम्बई से की जाएगी। जो निर्यातक अपने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग (न्यूनतम 1 करोड़ रुपये) निर्यात करते हैं उन्हें ग्रीन कार्ड प्रदान करने की बात सशोधित नीति में कही गई है। इस प्रकार लगातार तीन वर्षों तक निर्यात गृह/ट्रेडिंग हाऊस/स्वर या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाऊस का दर्जा रखने वाली ईकाइयों को "गोल्डन स्टेटस प्रमाण-पत्र" देने की बात इसमें शामिल है। यह

प्रमाण पत्र हासिल करने वाली ईकाइयों को सभी सुविधाएँ व रियायतें आगे भी मिलती रहेगी भले ही उनका निर्यात प्रदर्शन आगे खराब हो जाये ।

तमाम आशाओं के विपरीत इस नीति में निर्यातकों के लिए कोई कर माफी योजना का प्रावधान नहीं किया गया, और न ही 1999–2000 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य तय किया गया। प्री शिपमेंट व पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋणों पर 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर को भी 31 मार्च 1999 से आगे बढ़ाने से मना कर दिया गया। ऐसे निर्यात ऋणों के लिए 1998–99 में 2 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गयी थी। जिसे 31 मार्च, 1999 के बाद से समाप्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में 1 प्रतिशत बिन्दु की कटौती कर दिये जाने के कारण उपर्युक्त निर्यात ऋणों पर 1 अप्रैल, 1999 से निर्यातकों को 10 प्रतिशत ब्याज देनी होगी। लेकिन विदेशी मुद्रा, के लिए जाने वाले ऋणों को लिवॉर दर से जोड़ा जायेगा। 2000–2001 के बजट में आयात शुल्क की दर कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु उस पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है।

दसवीं पंचवर्षीय आयात-निर्यात नीति (2002–07) — अगले पाँच वर्षों (1 अप्रैल, 2002 से मार्च 2007) के लिए नयी आयात-निर्यात नीति 31 मार्च, 2002 को घोषित की गयी। इस नई नीति में आयात पर कुछ उत्पादों को छोड़कर ज्यादातर से मात्रात्मक पाबन्दियाँ हटाने की बात कही गयी है। कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति की घोषणा करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मुरासोली मारन ने कहा कि अतिरिक्त गेहूँ चावल, फल एवं सब्जियाँ सरीखे उत्पादों के निर्यात के लिए ढुलाई सुविधा मुहैया करायी जाएगी। इससे खेती से सम्बन्धित गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण होगा। उन्होंने इसे “खेती से बन्दरगाह तक” नाम दिया। इस नीति में अगले पाँच साल के दौरान देश के कुल निर्यात को 8 अरब डालर तक पहुँचाने के उम्मीद भरे लक्ष्य को हासिल करने और विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को मौजूदा 0.67 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिए नए प्रावधानों एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गयी है।

नई नीति में लघु उद्योगों, हस्तशिल्प, विशेष आर्थिक जोन (SEZ) और निर्यात समूहों से निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएँ और प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। नई नीति में निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। निर्यात विकास दर के लिए 11.9 फीसदी सालाना का लक्ष्य घोषित किया गया है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखने के साथ ही निर्यात सबधी प्रक्रियागत प्रावधानों की सरलता के जरिये निर्यात लागत में कमी करने के कदमों की घोषणा

की गई है। घरेलू क्षेत्र से एस0ई0जेड0 में जो माल जाएगा, उसे निर्यात माना जाएगा। एस0ई0जेड0 को सार्वजनिक सेवाओं के तहत लाया जाएगा।

मारन ने कहा कि कृषि क्षेत्र की आय में होने वाली बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की कायापलट करने में सक्षम है। व्यापार दर का कृषि क्षेत्र के पक्ष में एक फीसदी हस्तांतरण का सीधा अर्थ है इस क्षेत्र के पक्ष में 8,500 करोड़ रुपये का विशाल प्रवाह और इस राशि से पैदा होने वाली मांग अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में सक्षम है। इसे देखते हुए सरकार ने नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यात पर (केवल प्याज, जूट और नाइजरसीड के अलावा कुछ रसायन व लौह अयस्क जैसे गैर-कृषि उत्पादों को छोड़कर) मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा की है। 20 कृषि निर्यात जोन स्थापित होने से कृषि निर्यात में भारी बढ़ोत्तरी होगी। कृषि क्षेत्र के लिए ढाचागत सुविधाएं और क्रेडिट बढ़ाने के साथ ही ढुलाई में सहायता देने की घोषणा की गई है। यह सहायता प्रसस्कृत फलों, सब्जियों, पोल्ट्री व डेयरी उत्पादों और गेहूँ व चावल उत्पादों के निर्यात के लिए होगी। भारतीय खाद्य निगम के गेहूँ व चावल के स्टॉक से निर्यात करने के लिए ढुलाई सहायता देने की भी घोषणा की गई है। मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति से भारत इन उत्पादों के सतत निर्यातकों के रूप में अपना बाजार स्थापित कर सकेगा।

निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर मारन ने कहा कि ड्यूटी एनटाइटिलमेंट पासबुक (डी0ई0पी0बी0), एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ई0पी0सी0जी0) व अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को बनाए रखा गया है। डी0ई0पी0बी0 के तहत अधिकांश उत्पादों की दरों में मूल्य सीमा को हटाए रखा गया है। एडवांस लाइसेंस योजना के प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है। कप्लीटली बिल्ट यूनिट अथवा सी0के0डी0एस0के0डी0 के लिए समान डी0ई0पी0बी0 दरें निर्धारित की गई हैं।

एक्जिम नीति में औद्योगिक क्लस्टर (समूहों) को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है। फिलहाल इसका लाभ पानीपत, लुधियाना और तिरुपुर को मिलेगा। इनके अलावा खूर्जा से पॉटरी निर्यात बढ़ाने के लिए एक अध्ययन कराने की घोषणा भी की गई है। इन क्लस्टरों में समान सुविधाएं विकसित करने वालों को निर्यात सवर्धन पूंजीगत माल स्कीम का लाभ देने की बात कही गई है। औद्योगिक सगठनों को मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव स्कीम (एम0आई0एस0) का लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प के साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग के निर्यात बढ़ाने के लिए भी ई0जी0सी0जी0 योजना, मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है।

रत्न एव आभूषण क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने लिए रफ हीरो के शून्य सीमा शुल्क दर पर बगैर लाइसेंस के आयात की सुविधा दी गई है। मूल्यवर्धन की शर्तों में काफी ढील दी गई है। हार्डवेयर क्षेत्र के प्रोत्साहन पैकेज में शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के सकारात्मक होने की शर्त को सालाना स्तर से बढ़ाकर पाँच साल कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात सर्ववर्धन पार्क में स्थित इकाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी समझौता एक में शामिल उत्पादों के निर्यात को उनके समस्त निर्यात दायित्व में शामिल मान लिया जाएगा। चमड़ा व कपड़ा क्षेत्र को भी प्रक्रियागत सहूलियतें उपलब्ध कराई गई हैं।

एक्जिम नीति में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के लिए प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। इसके तहत भारतीय बैंको को एसईजेड में ओवरसीज बैंकिंग यूनिट (ओबीयू) स्थापित करने की अनुमति दी गई है। बैंको के स्तर पर एक्सपोर्ट अर्निंग फारेन करेसी (ईईएफसी) खाते में निर्यात आय को 100 फीसदी तक बनाए रखने के साथ ही निर्यात आय को स्वदेश लाने की अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 360 दिन कर दिया गया है। दस्तावेजों की उपलब्धता को लेकर बैंक व निर्यातक अब सीधे ही मामले को तय करेंगे। उत्पाद वर्गीकरण के लिए केंद्रीय उत्पाद एव सीमा शुल्क बोर्ड और विदेश व्यापार महानिदेशालय नया समान कोड लागू करेंगे। निर्यात के एफओबी मूल्य पर तीन से सात फीसदी ईंधन को निःशुल्क आयात की सुविधा दी गई है।

नयी निर्यात-आयात नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार रहे —

- उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री द्वारा भूतपूर्व वाणिज्य सचिव पीपी प्रभु की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सस्तुतियों तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मध्यकालीन निर्यात स्ट्रेटजी (2002-2007) जिसको जनवरी 2002 में घोषित किया गया था कि रिपोर्ट को ध्यान में रखकर निर्यात-आयात नीति 2002-2007 तैयार की गयी है।
- विश्व व्यापार में वर्तमान 0.67 प्रतिशत के हिस्से को 2007 तक 1 प्रतिशत तक बढ़ाने या मूल्य रूप के दसवीं योजनावधि में वर्तमान 46 मिलियन डालर के निर्यात को 80 मिलियन डालर से ऊपर ले जाने के उद्देश्य से नयी निर्यात नीति में अनेक कदम उठाये गये हैं।
- कृषि क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहन करने पर अत्यधिक बल जिससे यह एक ओर कृषकों को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य दिला सके तथा दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में सृजित क्रयशक्ति बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पूर्ण मांग पैदा कर सके।

- 2001-02 की निर्यात-आयात नीति में वाणिज्य मंत्री ने आयात से परिमाणात्मक नियंत्रण की पूर्ण समाप्ति की घोषणा की थी, इस वर्ष की घोषित नीति में कुछ सवेदनशील वस्तु (जैसे जूट, प्याज, आदि) को छोड़कर सभी निर्यातों पर से सभी परिमाणात्मक नियंत्रणों को समाप्त करने की घोषणा की गयी।
- कृषि क्षेत्र से निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे हैं— (क) ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो प्रोडक्ट तथा एग्रो आधारित प्रसंस्करित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों पर बल, 20 ऐसे क्षेत्रों को स्वीकृति दी जा चुकी। (ख) ताजे तथा प्रसंस्करित फलों, सब्जियों, पोल्ट्री, डेयरी, गेहूँ तथा चावल के सम्बन्ध में यातायात व्यय के सम्बन्ध में सहायाता देने की व्यवस्था।
- बिना तरासे हुए हीरो के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं तथा उस पर लगने वाली सीमा शुल्क को शून्य करना।
- 2000 से ही चले आ रहे सेज (SEZ) से सम्बन्ध में यह कहा गया कि 4 वर्तमान EPZ को सेज में परिवर्तित कर दिया गया है तथा 13 नये सेज और खोल दिए गये हैं। नयी नीति में सेज को प्रोत्साहित करने के लिए (क) सेज क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों को आयकर से रियायत। (ख) घरेलू शुल्क क्षेत्र से सेज की आपूर्ति पर केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्ति (ग) डी0 टी0 ए0 से सेज के व्यवहारों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात का दर्जा देना। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था सेज क्षेत्र में ओवरसीज बैंकिंग इकाइयों को खोलने की अनुमति प्रदान करना तथा उन्हें सी0आर0आर0 तथा सी0एल0आर0 से मुक्ति प्रदान करना है।
- नये बजार खोजने की नीति के अन्तर्गत इस वर्ष सब सहारन अफ्रीका क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने की पहल की गयी है। पहले से चली आ रही लैटिन अमेरिकी देशों पर विशेष ध्यान देने की नीति एक ओर मार्च 2003 तक के लिए जारी रखी जायेगी 2001-02 वर्ष में लैटिन अमेरिकन देशों में हमारे निर्यात में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।
- 2000-2001 के दौरान अफ्रीकन क्षेत्र में होने वाला हमारा कुल व्यापार 33 बिलियन डालर का रहा जिसमें से निर्यात की मात्रा 18 बिलियन तथा आयात की मात्रा 15 बिलियन डालर थी। पहले चरण में 7 देशों पर केन्द्रित किया जायेगा, ये हैं नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मालीशस, केन्या, ईथोपिया, तन्जानिया तथा घना। इन क्षेत्रों में निर्यात

करने वाली इकाइयों को निर्यात घरों का दर्जा 15 करोड़ रुपये के निर्यात के स्थान पर 5 करोड़ रुपये के निर्यात पर ही प्राप्त होगा।

- निर्यात की दृष्टि से उत्कृष्ट शहरों को विशेष सुविधा प्रदान करने की घोषणा। होजरी के लिए तिरुपुर, ऊनी कम्बलो के लिए पानीपत, ऊनी वस्त्रों के लिए लुधियाना को निर्यात उत्कृष्ट शहर घोषित किया गया तथा उन्हें अनेक सुविधाएँ जैसे EPCG सकीम के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त होगी।¹

कुटीर तथा हस्तकला क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे वे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। घोषणा से अनुसार इन इकाइयों को (क) EPCG के अन्तर्गत आवश्यक औसत निर्यात के स्तर को कायम रखने की दशा से मुक्त कर दिया गया है तथा (ख) निर्यात घरों का दर्जा 15 करोड़ रुपये के स्थान पर 5 करोड़ रुपये के औसत निर्यात के स्तर पर ही प्राप्त होगा।

¹ प्रो० एस०एन० लाल, भारतीय अर्थव्यवस्था (संक्षिप्त रूपरेखा) शिव पब्लिशिंग हाउस – 2002 पृष्ठ 87

अध्याय चार

“विदेशी व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं की स्थापना”

गई वस्तुओ के बचे हुए स्टाक की बिक्री को भी शामिल किया जाता है, परन्तु उक्त समिति ने यह बताया कि सरकारी विभागों द्वारा सम्पादित व्यावहारिक गतिविधियों में अनेक दोष हैं, और इसी कारण राजकीय क्षेत्र में किये गये आयात व निर्यात का दायित्व एक विशिष्ट संगठन को ही दिया जाना चाहिए। समिति का सुझाव था कि सरकारी विभागों के खाद्यान्नों एवं उर्वरकों से सम्बद्ध व्यावसायिक गतिविधियों को वैधानिक रूप से स्थापित एक राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना तथा 1952 में इस विषय पर पुनः एक नई समिति की नियुक्ति कर दी। इस द्वितीय समिति ने भी सिद्धान्त रूप में राज्य व्यापार निगम की स्थापना के सुझाव का समर्थन किया तथा यह सुझाव दिया कि यह निगम एकाधिकारिक रूप में कार्य करने के साथ-साथ व्यावसायिक कार्य भी करे। देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार के समक्ष अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई, अन्य कार्यों के अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार को चुनी हुई वस्तुओं को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। 1955 में पहली बार वित्त मंत्री ने राजकीय व्यापार एजेंसी की धारणा का समर्थन किया। इस बीच अर्थशास्त्रियों ने यह भी सुझाव दिया कि अधिक आर्थिक एवं समाजिक समानता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए राजकीय व्यापार आरम्भ करना अत्यंत उपयोगी होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह भी रखा गया था कि भारत को यथा सम्भव विदेशी व्यापार का अधिकाधिक विस्तार करके अधिकतम विदेशी विनियम प्राप्त करना चाहिए, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे पूर्वी यूरोप के देशों के साथ अपने व्यावसायिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए। इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हेतु एक विशेष सरकारी व्यावसायिक एजेंसी की आवश्यकता थी। इस प्रकार द्वितीय योजना के आरम्भ से ही एक सार्वजनिक व्यापार एजेंसी की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण बन गया था।¹ अन्ततः 'राज्य व्यापार निगम' की स्थापना एक सरकारी संगठन के रूप में 18 मई, 1956 को एक करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से की गई। बाद में इसकी पूँजी 2 करोड़ कर दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में विदेशी व्यापार के ढाँचे में पाये जाने वाले दोषों को दूर करके विदेशी व्यापार में वृद्धि करना तथा साथ ही निर्यात में वृद्धि करना, उचित मूल्य में जरूरी वस्तुओं का आयात करना तथा ऐसे घरेलू व्यापार को देख-रेख करना था, जिससे विदेशी व्यापार में वृद्धि हो सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा 1 फरवरी, 1957 को निर्यात सम्बर्द्धन पर एक अन्य समिति का निर्माण किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 1957 को प्रस्तुत किया। समिति ने पहली बार निर्यात सम्बर्द्धन के प्रश्न पर विचार किया और चाय पर निर्यात चुगी खत्म करने का अनुमोदन किया, उत्पादकों के आन्तरिक उपभोग को कम

¹ डा० एस० एन० लाल, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, शिव पब्लिकेशन, पृष्ठ 202।

किया और दिउद्देश्यीय, बहुउद्देश्यीय व्यापार समझौते प्रस्तुत किया और निर्यात आय को आयकर से मुक्त किया। समिति ने निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना और विपणन विकास कोष के निर्माण का सुझाव दिया। समिति द्वारा दिये गये ज्यादातर अनुमोदनो को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विस्तृत रूप से व्यापार सम्बर्द्धन के लिए योजनाओ को शुरु कर दिया गया। व्यापार सम्बर्द्धन के बारे मे कई समितियों की स्थापना के अलावा सरकार द्वारा 50 वर्षो के दौरान कई व्यापार सम्बर्द्धन समितियों की स्थापना की गयी । ये समितियाँ विशिष्ट वस्तुओ के लिये आयात निर्यात सम्बर्द्धन पर ध्यान देती है। यह समिति केन्द्र सरकार की भूमिका को सक्रिय करने, विस्तृत करने और आयात निर्यात को सही रास्ता दिखाने से सम्बधित है । ताकि विदेशी व्यापार को बढ़ाया जा सके।

किरी भी देश के लिए विदेशी व्यापार द्वारा आर्थिक विकास के लिए, पूजीगत माल, तकनीक और उपभोक्ता माल को बड़ी मात्रा मे आयात करना आवश्यक है ताकि उससे विकास कार्यक्रम लागू किए जा सके। इसी प्रकार के आर्थिक आयात मे निर्यातको द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। चूँकि विस्तृत आयात के वित्त के लिए बडे निर्यातको की आवश्यकता है। निर्यात क्षेत्र के लगातार विकास के लिए आयात आवश्यकता की सुविधा और पूर्ण विदेशी विनमय प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव सहायता देना चाहिये। यह बढ़ रहे सेवा मूल्यो को प्राप्त करने मे सहायता करता है। सरकार निर्यात आयात और विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण के लिए विस्तृत शक्ति रखती है। निर्यात सम्बर्द्धन उपाय लगभग सभी विकासशील या विकसीत देशो द्वारा अपनाए जाते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग-अलग होते हैं। कोई भी ऐसा एक उपाय नहीं है जो कि सभी उद्देश्यो के लिए लिया जा सके।

हमारी सरकार ने विदेशी व्यापार के प्रोत्साहन के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये हैं। इसके अर्न्तगत निर्यात क्षेत्रो के सहायता के लिए कई सस्थाओ की स्थापना, निर्यात बाजार अनुसधान प्रशिक्षण, सस्थागत प्रतिबन्धो को युक्तिसंगत बनाना, संयुक्त राष्ट्र सघ के अभिकरणो और मित्र देशो से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तकनीकी सेवाए प्रदान करना, विदेशो मे संयुक्त उद्योगो की स्थापना करना और निर्यात सम्बर्द्धन को सहायता देना आदि। सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए प्रयासो से विदेशी व्यापार की सहायता के लिए विभिन्न सस्थाओ की स्थापना की गई। इनमे से मुख्य सस्थाओ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. राज्य व्यापार निगम :-

भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 18 मई, 1956 को "राज्य व्यापार निगम" का पजीकरण पूर्ण रूप से एक सरकारी सस्था के रूप में किया गया एवं इसकी प्रारम्भिक प्रदत्त पूजी 1 करोड़ रुपये रखी गयी। आगे चलकर इसकी अधिकृत पूजी 5 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूजी 2 करोड़ रुपये कर दी गई। राज्य व्यापार निगम का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यातों का क्षेत्र विस्तृत करना, आवश्यक वस्तुओं के आयात की व्यवस्था करना है। यह निगम बहुधा कुछ वस्तुओं के न्यूनतम मूल्यों की प्रतिभूति देने तथा तटस्थ भण्डार के निर्माण के कार्य भी करता है। निर्यात के क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम चालू बाजारों के विस्तार के साथ-साथ नये बाजार की खोज हेतु भी प्रयत्नशील है। इस निगम की एक प्रमुख उपलब्धि यह भी है कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हुए व्यापार में आशा से अधिक वृद्धि हुई है। जहाँ 1955-56 में इन देशों के साथ हमारा व्यापार अत्यन्त सीमित था वही 1973-74 तक निर्यात का लगभग एक चौथाई केवल इन्हीं देशों को निर्यात किया जाने लगा। इसी प्रकार आयात का लगभग 20 प्रतिशत भाग इन देशों से प्राप्त किया जाने लगा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे व्यापार में विगत वर्षों में 20 से 25 गुनी वृद्धि हुई है। इस दिशा में प्राप्त सफलता में राज्य व्यापार निगम की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि निगम को ही इन देशों से किये जाने वाले व्यापार के एकाधिकार प्राप्त हैं।

किन्तु इतने पर भी राज्य व्यापार निगम देश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए कोई भी वस्तु कही भी खरीदने को स्वतन्त्र है। इसी प्रकार निगम को किसी भी उत्पादक वस्तु लेकर कही भी निर्यात करने की छूट है। आयात व निर्यात के अतिरिक्त निगम उद्योगपतियों व व्यापारियों को वित्त की उपलब्धि, क्वालिटी-नियन्त्रण, जहाजों में माल के लदान एवं दुर्लभ कच्चे माल की खरीद व वितरण की सेवाएँ अर्पित करता है। विदेशी उपभोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करवाना एवं इनकी पूर्ति करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना भी निगम का एक प्रमुख उद्देश्य है।

व्यवसायिक दृष्टिकोण एवं लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हुए भी राज्य व्यापार निगम भारतीय उद्योगों का विश्व बाजारों की स्थिति से अवगत कराता है, तथा समय-समय पर उनका मार्ग दर्शन करता है। निगम ऐसी वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रत्यक्ष रूप से पूजी का विनियोग करता है जिनके निर्यात की सम्भावनाएँ काफी अधिक हैं। इसी प्रकार एक निश्चित

बाजार की प्रतिभूति देने वाले विदेशी व्यापारी को निगम द्वारा समुचित सहायात प्रदान की जाती है।

यह निगम पूर्ण रूप से एक विपणन संस्था है। विपणन से सम्बद्ध विशिष्ट समस्याओं के विश्लेषण एवं उन पर सतत रूप से मार्गदर्शन हेतु निगम के कार्यक्रम को वस्तुओं के आधार पर छ विभागों में विभाजित किया गया है—1 इन्जीनियरिंग की वस्तुएँ, 2 रेलवे वैगन साज-सज्जा, 3 रसायन दवाइयों एवं नमक, 4 जूते बाल व बालों से निर्मित वस्तुएँ श्वकर, कपड़ा, तैयार कपड़े, आदि उपभोग वस्तुएँ, 5 फल, फलों के रस, चावल एवं दालें तथा 6 सीमेन्ट। इन विपणन डिवीजन की सहायतार्थ, परामर्शदाता एवं सेवा डिवीजन बनाए गये हैं। राज्य व्यापार निगम ने 18 देशों में अपनी शाखाएँ तथा विश्व के लगभग सभी देशों में अपने सम्पर्क सूत्र स्थापित किए हुए हैं। यह निगम देश के उद्योगों तथा विदेशी आयात व निर्यातकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है। राज्य व्यापार निगम जहाँ विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण करके भारतीय उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को निर्यात बढ़ाने हेतु मार्ग दर्शन करता है। वही विदेशी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य एवं उचित समय पर निर्दिष्ट क्वालिटी की वस्तुएँ उपलब्ध कराने का आश्वासन देता है।

आज के संदर्भ में राज्य व्यापार निगम के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं —

- (i) निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात व निर्यात करना विशेष रूप से उन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करना जहाँ विदेशी व्यापार पूर्ण सरकारी नियन्त्रण में है।
- (ii) सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक हित के पोषण हेतु निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात-निर्यात या आन्तरिक वितरण की विशेष व्यवस्था करना।
- (iii) सरकार के आदेशानुसार देश में पर्याप्त पूर्ति वाली (दुर्लभ) वस्तुओं के आयात अथवा आन्तरिक वितरण की व्यवस्था करके मूल्यों में स्थिरता लाना तथा देश में वितरण व्यवस्था ठोस करना।
- (iv) परम्परागत वस्तुओं के निर्यात हेतु नए बाजारों का विकास करना तथा निर्यात व्यापार के विविधीकरण हेतु नई वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना।

इनके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम देश के आयातों व निर्यातों की प्रवृत्ति पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखता है, तथा देश के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को आयातों सुविधाएँ एवं निर्यात सम्बर्द्धन हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करता है।

राज्य व्यापार निगम लघु एवं मध्य श्रेणी के लोक उद्यमों के बीच निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट भूमिका अदा करती है। वस्तुओं के आयात के निर्माण के द्वारा सरकार लाभ का प्रबन्ध करती है। इन नीतियों के द्वारा मिले लाभ की सहायता से सरकार एक नई नीति कार्यक्रम चला रही है। वस्तुओं के निर्यात में जो बेचने में कठिनाई महसूस होती है, उससे वित्तीय घाटा सहना पड़ता है। सरकार के द्वारा ब्रिकी में राज्य व्यापार निगम का मार्ग दर्शन किया जाता है। बेचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं का आयात जैसे कि सुपाडी, कालीमिर्च, नारियल आदि का आयात राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है। जब इन वस्तुओं का आयात निगम द्वारा किया जाता है तब इन वस्तुओं पर उपस्थित बड़े लाभ का एक भाग निगम के पास होता है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव स्वीकार करने के लिए राज्य व्यापार निगम जागृत हो गया है। निर्यात स्तर बनाए रखने के लिए मजबूत और अच्छी चीजों का निर्यात करना होगा। इसके द्वारा कई प्रगति कार्य किये गये हैं, आने वाले वर्षों के लिए दीर्घकालीन व्यूह रचना की जा रही है। आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ भारतीय उत्पादों के गुणों के विकास लाने में निगम उच्च महत्व प्रदान करता है। निगम बाजार अनुसंधान सूचना और बिक्री सम्बर्द्धन के उच्च महत्व से भी सम्बन्धित है। न्यूनतम दाम पर घरेलू बाजार में आयातित वस्तुओं की उपभोग की उपस्थिति में राज्य व्यापार निगम का योगदान कम महत्व नहीं रखता।

राज्य व्यापार निगम के कार्यों का विस्तार होने के साथ-साथ इसके प्रशासन में विकेन्द्रीकरण किया गया तथा आज निगम की निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ विशिष्ट क्षेत्रों में आयात व निर्यात क्षेत्र में कार्यरत हैं —

- (i) परियोजना एवं साज-सज्जा निगम
- (ii) भारतीय काजू निगम
- (iii) हस्तकला एवं हथकरघा निगम
- (iv) खनिज एवं धातु व्यापार निगम
- (v) केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम
- (vi) चाय व्यापार निगम
- (vii) निर्यात विकास कोष

¹ सार्वजनिक कार्य करने पर समिति/40 वॉ घोषणा (चौथा लोक सभा)

(1) परियोजना एव साज-सज्जा निगम इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम की एक सहायक एजेन्सी के रूप में 1971 में की गई थी। इस नई संस्था के प्रारम्भिक चरण में इन्जीनियरिंग एव रेलवे सामग्री के व्यापार के अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम के इन्जीनियरिंग डिवीजनो को काम सौंपा गया। इस निगम का प्रमुख उद्देश्य इन्जीनियरिंग की वस्तुओं, औद्योगिक एव रेल सम्बन्धी साज-सज्जा के निर्यात में वृद्धि करना है।

(11) भारतीय काजू निगम इस निगम की स्थापना भी राज्य व्यापार निगम की एक सहायक इकाई के रूप में 1970 में की गई थी। यह निगम कच्ची काजू का आयात करके उचित मूल्य पर काजू निर्यात करने वाली इकाईयों को परिनिर्माण हेतु उपलब्ध कराता है। भारतीय वस्तुओं के प्रचार हेतु निगम ने पेरिस एव न्यूयॉर्क में अपने कार्यालय स्थापित किये हैं।

(111) हस्तकला एव हथकरघा निर्यात निगम हस्तकला एव हथकरघा निर्यात निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम के पूर्णतः स्वीकृति शाखा के रूप में वर्ष 1964 में किया गया। किन्तु इस पर नियन्त्रण वस्त्र मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण विभाग का है। इसकी स्थापना हस्तकला की वस्तुओं हथकरघों के वस्त्रों, तैयार वस्त्रों एव ऊनी स्वेटरों व जर्सीयों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किया गया। इसके दो प्रमुख कार्य हैं—

पहला, निर्यात सम्बर्द्धन और व्यापार विकास तथा दूसरा, बाहर भारतीय दस्तकारी का अच्छा प्रभाव बनाना। शिल्प और हथकरघा के अन्तर्गत ऊन, ऊनी गलीचे और सिले-सिलाए वस्त्रों के सम्बन्ध में निगम इन उत्पादकों के निर्यात को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह विदेशों में उपभोक्ता के माँग का भी अध्ययन करती है और भारत के दस्तकारी पर विशिष्ट महत्व के साथ नए उत्पादों के प्रवेश का भी अध्ययन करती है। यह सलाह के माध्यम से व्यापार की सहायता करती है और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने से साथ बाहरी मेले व प्रदर्शनियों में भाग लेना सुनिश्चित करती है।

(iv) केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम — यह उद्योग निगम जो एस0एस0ई0सी0 की पूर्णतः स्वीकृति शाखा है, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई। इस निगम का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योग और शिल्प के उत्पादन का भारत और समुद्र पार देशों में बिक्री करना और घरेलू उद्योग के विकास में भी सहायता करना है।

(v) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (MMTC) — देश में उपलब्ध खनिज पदार्थों एव कच्ची धातु के निर्यात हेतु अप्रैल 1963 में इस निगम की स्थापना किया गया। इस निगम की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये एव प्रदत्त पूंजी 2 करोड़ रुपये की है। निगम के प्रमुख निर्यातों में

कच्चा लोहा, कच्चे मैंगनीज, फेरो मैंगनीज तथा कोयला को सम्मिलित किया गया है। इन सब वस्तुओं के निर्यातों से काफी मात्रा में विदेशी विनमय प्राप्त किया गया। इस निगम के आयतों में नॉन फ़ैरस धातुओं का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पिछले दशकों में अनेक बाजारों का विकास किया है। इसके निर्यातों में 3/4 भाग से अधिक केवल कच्चे लोहे के रूप में है। यूरोप व जापान के बाजारों में निगम ने भारतीय कच्चे लोहे के निर्यात-व्यापार में काफी वृद्धि की है। यूरोपीय देशों को निगम 11-12 लाख टन कच्चे लोहे का निर्यात करता है। इसी प्रकार जापान को भी काफी मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि विगत 3-4 वर्षों में विश्व के बाजारों में कच्चे लोहे के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई और इसका पूरा लाभ भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम को प्राप्त हुआ है। निर्यात की गई धातुओं व खनिज के मूल्यों में वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ खनिज व धातु व्यापार निगम को आयातित खनिजों व धातुओं के लिए भी पिछले 3-4 वर्षों में काफी ऊँची कीमत चुकानी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप निगम का आयात-बिल पिछले वर्षों में काफी बढ़ गया है।

(vi) चाय व्यापार निगम — चाय व्यापार निगम की स्थापना 1970 में भारतीय सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम की शाखा के रूप में किया गया। इसके प्रमुख कार्य भारतीय चाय के लिए साम्य बाजार खोजना, घरेलू उपभोग चाय रियासत का प्रबन्ध, चाय का भण्डारण और अन्य व्यवस्थाओं की स्थापना जो चाय उद्योग के लिए लाभकारी है। चाय के खरीदादारी में भी यह सहायता करती है।

(vii) निर्यात विकास कोष — निर्यात का आधार और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम ने निर्यात विकास कोष की स्थापना की। इस कोष द्वारा छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या इनकी उत्पादन क्षमता में विस्तार हेतु सहायता दी जायेगी, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले निर्यातों में से आधे लघु औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त किये जाते हैं। इन इकाइयों को निगम द्वारा कच्चे माल की पूर्ति, तकनीक परामर्श आदि सेवाओं के अतिरिक्त क्वालिटी नियन्त्रण, भण्डारण, लदान व्यवस्था, निर्यात विपणन एवं प्रलेख की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जिसमें यह कोष राज्य व्यापार निगम की सहायता करता है। राज्य व्यापार निगम के विभिन्न देशों में स्थित कार्यालय भारत की परम्परागत एवं गैर परम्परागत वस्तुओं का विदेशी बाजारों में प्रचार करके इनके निर्यात हेतु अनुबन्ध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। निर्यात में वृद्धि करने हेतु निगम अन्य देशों में विद्यमान बड़े-बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सम्पर्क

स्थापित करता है। हाल ही में एक समीक्षक समिति ने राज्य व्यापार निगम के प्रशासन एवं गतिविधियों में गत्यात्मकता (Dynamism) लाने हेतु कुछ सुझाव दिए हैं। निगम ने विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हेतु विशेषज्ञों से परामर्श एवं निजी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिष्ठानों से सहयोग प्राप्त करना भी प्रारम्भ कर दिया है।

2. वाणिज्य मन्त्रालय .—

इस मन्त्रालय के अधीन सबसे ऊपर वाणिज्य विभाग है। विदेश व्यापार नीति के प्रोत्साहन और देश के विदेशी व्यापार के नियमन को सही दिशा देने का उत्तरदायित्व प्राथमिक सरकारी संगठन को है। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीतियों के सम्मान में पुनर्संगठन के विभिन्न कार्य विदेशी व्यापार, राज्य व्यापार निर्यात सम्बर्द्धन, निर्यात उद्योग, निर्यात योजनाएँ, सूचना सेवाएँ और सस्थागत सहायता जो वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं, निम्नवत हैं—

(i) संगठन और सस्थाएँ इनके अन्तर्गत निम्न आते हैं —

- (अ) स्वतन्त्र व्यापार मण्डल।
- (ब) निर्यात साख गारण्टी निगम।
- (स) आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक का कार्यालय।
- (द) भारत का व्यापार मेला अधिकरण।
- (य) निर्यात निरीक्षण समिति।

(ii) सेवा सहायता सस्थाएँ — इसके अन्तर्गत निम्न आते हैं —

- (अ) निर्यात-आयात बैंक।
- (ब) भारतीय पैकेजिंग सस्थान।
- (स) निर्यात सम्बर्द्धन समिति।
- (द) भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान।
- (य) व्यापार विकास प्राधिकरण।

(iii) विदेश व्यापार विभाग — विदेशी व्यापार विभाग निम्न से सम्बन्धित कार्यों को देखता है —

- (अ) सभी बाह्य व्यापारिक पहलुओ जिसके अन्तर्गत व्यापारिक सौदा और समझौता, व्यापारिक शिष्टमण्डल, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल, व्यापारिक सहकारिता, व्यापारिक सम्बर्द्धन और देश के बाहर भारतीय औद्योगिक समुदाय के ब्याज का सरक्षण।
- (ब) आयात-निर्यात व्यापार नीति और भारत के व्यापारिक ब्याज का नियन्त्रण।
- (iv) निगमे और परिषदे — इसके अन्तर्गत निम्न निगमे व परिषदे आते हैं—
- (अ) कॉफी परिषद।
- (ब) चाय परिषद।
- (स) तम्बाकू परिषद।
- (द) रबर परिषद।
- (य) कृषि और कार्मिक खाद्य उत्पाद।
- (र) निर्यात विकास अधिकरण का समुद्री उत्पाद।
- (ल) भारत का चाय व्यापार निगम।
- (v) विदेशी व्यापार नीति विभाग :- विदेशी व्यापार नीति विभाग के प्रमुख कार्य निम्न हैं—
- (अ) अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतो को कार्यान्वित करना।
- (ब) विभिन्न पहलुओ पर विचार करना जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बन्धित हैं तथा जिसके अन्तर्गत तटकर तथा तटकर विहीन रुकावट आती है।
- (स) विदेशी वाणिज्यिक नीति का सूत्रीकरण।
- (द) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना जो कि वाणिज्यिक नीति से जुडा हुआ है जैसे, स्कैप, ई0सी0ए0, गैट अब डब्लू0टी0ओ0 और ई0ई0सी0।
- (vi) निर्यात उद्योग और उत्पाद विभाग :- यह विभाग निम्न के लिए उत्तरदायी है—
- (अ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पादे।
- (ब) समुद्री उत्पादे।
- (स) पूर्व के देशो के उत्पाद का विशिष्ट निर्यात लेकिन जूट उत्पाद और हथकरघा को वर्जित करके।

- (द) वस्तुएँ, उत्पाद, परियोजनाएँ, सलाहकारी सेवाएँ उत्पादन और अर्ध उत्पादन करने वाला, कृषि उत्पाद विधि 1973 के प्रतिष्ठा में निर्यात उत्पादन का विकास और बढ़ावा।
- (य) निर्मित उत्पाद जैसे कि अभियान्त्रिक सामान, रसायन, प्लास्टिक सामान, चमड़े का सामान, इत्यादि।
- (vi) राज्य व्यापारिक विभाग — वाणिज्य मन्त्रालय के इस विभाग का कार्य निम्न है —
- (अ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम और इसकी शाखाओं के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना।
- (ब) राज्य व्यापार से सम्बन्ध बनाना और संगठन जो कि उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गये हैं उनकी उन्नति ज्ञात करना।
- (viii) अन्य क्रियाशील क्षेत्र कुछ विशिष्ट क्रियाओं के अलावा जो अन्य क्षेत्र इसके अन्तर्गत आते हैं, वे हैं —
- (अ) तटकर आयोग से सम्बन्धित बचा हुआ कार्य जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चुगी तटकर सार्वजनिक कार्यालय के अन्तर्गत आता है।
- (ब) वाणिज्य मन्त्रालय सलाहकारी परिषद, सेवा संगठन, निर्यात सम्बर्द्धन अभिकर्ता का कार्यालय, राज्य व्यापार निगम, वस्तु परिषद और निर्यात के द्वारा सहायता किया जाता है।
- (स) निर्यात प्रयास और सही दिशा के लिए योजना एवं कार्यक्रम
- (द) घरेलू उपभोग के अलावा फसल रोपड़ के विकास का उत्पादन और वितरण जैसे कि चाय, काफी रबर, और इलायड़ी।
- (य) घरेलू उपभोग के लिए प्रगति और वितरण तथा चाय और काफी का निर्यात।

3. नीति सलाहकारी समिति :-

प्रशासनिक सुधार आयोग की सस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिये जून 1971 में नीति सलाहकारी समिति की स्थापना हुयी। यह समिति शीघ्र ही दीर्घकालीन नीति के मुख्य बिन्दुओं पर विचार करने लगी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं —

- (अ) व्यापार विकास प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक।

(ब) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रमुख।

(स) वाणिज्य विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव।

(द) वाणिज्य मन्त्रालय में एक उप सचिव।

(य) वाणिज्य मन्त्रालय का वित्तीय सलाहकार।

(र) वाणिज्य मन्त्रालय में निदेशक।

(ल) भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान का महानिदेशक।

(व) आयात और निर्यात का मुख्य नियंत्रक।

4. भारतीय पैकेजिंग सस्थान :-

भारतीय विदेश व्यापार सस्थान के परामर्श को आधार बनाते हुए 1966 में भारतीय पैकेजिंग सस्थान का सृजन पैकेजिंग के स्तर के विकास के द्वारा निर्यात करने के लिये किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के पैकेजिंग में प्रयोग किये गये उपकरण और उपाय ऐसे होने चाहिए कि निर्यात किए जाने वाले सामान का सुगमतापूर्वक स्थानान्तरण हो सके। पैकेजिंग के स्तर में आयी हुयी कमियों की उपस्थिति और सुविधापूर्वक स्थानान्तरण के लिये पैकेजिंग के मुख्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करने के साथ इस सस्थान के प्रमुख कार्य निम्न हैं -

(क) सुविधाजनक पैकेजिंग की आवश्यकता के लिये प्रोत्साहित करना।

(ख) पैकेजिंग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

(ग) निर्यात पैकेजिंग के लिये श्रम को केन्द्रित करना।

(घ) पैकेजिंग उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पर अनुसंधान प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

(ङ) पैकेजिंग उद्योग के क्षेत्र में निर्यात विकास के साथ-साथ चलना।

भारतीय पैकेजिंग सस्थान ने भारत में पैकेजिंग मशीन उद्योग की संरचना का अध्ययन किया। 1992-93 के दौरान पैकेजिंग में तीन महीने का प्रमाण-पत्र कोर्स में 17 विदेशी तथा 10 भारतीयों द्वारा भाग लिया गया। वर्ष के दौरान 4 योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत किये गये जिसमें 110 लोगों ने हिस्सा लिया। सस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओं में अप्रैल-नवम्बर 1992 के मध्य 4000 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश में

पैकेजिंग के अच्छे सम्बर्द्धन के लिए एक पुरस्कार चालू किया गया। 'पैक मशीन' नामक यह पुरस्कार कला, पैकिंग उद्योग के लिए मशीन उत्पादन में दक्षता के लिये दिया जाता है।¹

भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने पैकेजिंग के मानक में, विशेष तौर से निर्यात के लिये उपयुक्त सुधार करने के कोशिशों की सफलता का प्रयास जारी रखे। वर्ष 1994-95 की समयावधि में उपरोक्त संस्थान ने 20 विकास परियोजनाएँ पूरी की, जिसमें प्रसस्कृत खाद्य उपाय, फूलों की मढ़ाई, मास एवं कुक्कुट पालन, अफीम, प्लास्टिक प्रसस्करण, मशीनरी और लघु उद्योग शामिल हैं।

5. भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान .—

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना 1964 में की गयी। इस संस्थान की स्थापना सामाजिक पजीकरण अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में हुआ। यह संस्थान, प्रधान प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रलिखित चार प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति में सलग्न है—

- (अ) निर्यात विपणन अनुसंधान, सामग्री क्षेत्र तथा समुद्रपार बाजार सर्वेक्षण का पथप्रदर्शन करना।
- (ब) वर्तमान निर्यात विपणन तकनीक में श्रमिक वर्गीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (स) सूचना के अनुसंधान एवं बाजार विषयक अध्ययन का विस्तार करना।
- (द) निर्यात व्यापार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिये अनुसंधान करना।

विगत दो दशकों के समयावधि में उपरोक्त संस्थान सभी विकासशील राष्ट्रों में अपनी तरह का एक अद्वितीय संस्थान बन गया है। इस संस्थान ने अपनी पहचान एवं अस्तित्व को प्रतिभाषित करते हुए, तीसरे विश्व के देशों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रमुख स्थान बना लिया है, तथा इस संस्थान की सेवाओं से अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान यथा— अकटाड, गैट अब W T O, युनिडो स्कैप और आईटीसी आदि लाभान्वित हो रहे हैं। यह संस्थान त्रैमासिक समाचार—पत्र "फॉरेन ट्रेड रिव्यू" के माध्यम से अपनी सूचनाओं का प्रचार—प्रसार निर्वाध गति से कर रहा है। निर्यात व्यापार से सम्बन्धित अन्य अनुसंधान तथा इसके परितः अध्ययन के सूचना

¹ वार्षिक रिपोर्ट, 1992-93, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ — 40

को भी प्रसारित कर रहा है। इस संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र “फॉरेन ट्रेड बुलेटिन” नये विकास के सूचनाओं का विस्तार पूर्वक प्रसार कर रहा है।

अप्रैल-दिसम्बर 1992 के अवधि में 50 विद्यार्थियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया एवं 30 छात्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर कार्यक्रम पूर्ण किया। 129 व्यक्तियों ने निर्यात विपणन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। इसके अतिरिक्त 24 सम्पादकीय विकास कार्यक्रम, सरकारी कर्मचारी के लिए विशेष कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट के लिये कार्यक्रम अप्रैल से दिसम्बर 92 तक आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के क्षेत्रों में उपरोक्त संस्थान तीन आधारभूत कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। —

- (अ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम।
- (ब) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम।
- (स) निर्यात विपणन में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम।

अप्रैल-दिसम्बर 1994 की समयावधि में 52 व्यक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 43 प्रत्याशियों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 30 अभ्यर्थियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कार्याकारी कार्यक्रम (ई0एम0आई0टी0) में भाग लिया तथा 169 अभ्यर्थियों ने निर्यात विपणन (साध्य) पाठ्यक्रमों में भाग लिया। वर्ष 1993-1994 के दौरान संस्थान ने कई अनुसंधान कार्य पूरे किये जिनमें सम्मिलित हैं पश्चिम यूरोप एवं जापान में प्रिय खाद्यों पर बाजार सर्वेक्षण, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तथा इण्डोनेशिया में तकनीक के अन्तरण पर भारतीय संयुक्त उद्यमों का अनुभव और निर्यात के लिये चुनिन्दा उत्पादकों के प्रोफाइल।¹

6. भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन संगठन :-

भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन संगठन (आई0टी0पी0ओ0) की स्थापना विगत काल में सृजित ट्रेड फेयर आथरिटी आफ इण्डिया तथा ट्रेड डेवलपमेंट अथारिटी का विलय करने के बाद कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक जनवरी 1992 को की गयी। उपरोक्त संस्थान भारत में तथा विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों, व्यापारियों की बैठक, व्यापार प्रतिनिधि

¹ वार्षिक रिपोर्ट-1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृष्ठ-42।

मडलो के आदान-प्रदान, उत्पादन विकास कार्यक्रमो आदि का संचालन करके व्यापार वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाता है ।

आई0टी0पी0ओ0 का कार्य लाभ आर्जित करना नहीं है, अपितु भारतीय निर्यातको को विदेशी बाजारों में प्रवेश की सुविधाजनक स्थिति को सुनिश्चित करना एकमात्र लक्ष्य है। आई0टी0पी0ओ0 डोमेस्टिक मेलों का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में समय-समय पर व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, सम्पर्क वृद्धि कार्यक्रमों तथा व्याख्यानो के उपयुक्त माध्यमों से विदेशों को यह जानकारी प्रदान करता है कि भारतीय सामान विदेशों के अत्याधुनिक वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा में तभी सक्षम हो सकता है, जब निर्यातक अपने सामानों में गुणात्मक परिवर्तन कर उचित मूल्य का निर्धारण कर उसे प्रतिस्पर्धी बनाए। इसके अलावा आई0टी0पी0ओ0 व्यापार वृद्धि के लिए व्यक्तिगत सस्थाओं को "प्रगति मैदान" को एक व्यापार स्थल के रूप में किराए पर प्रदान करता है, जिससे एक छत के नीचे सभी उच्चस्तरीय सामान एकत्रित होकर आवश्यकता एवं उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। आई0टी0पी0ओ0 ने अपने पाँच कार्यालय विदेशों में खोले हैं तथा अनेक क्षेत्रीय कार्यालय भारत के महानगरों में स्थित हैं। निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन का एक मुख्य स्रोत है इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह के सस्थाओं को भारत सरकार और अधिक स्व-अर्जित बनाये तथा इनके कार्यक्रमों का अत्याधिक विस्तार करे।

'भारतीय व्यापार प्रोन्नति सगठन' एक सेवा सस्था है तथा इसकी व्यापार उद्योग और भारत सरकार के साथ विश्वासपूर्ण तथा समय-समय पर वार्तालाप जारी रहता है यह अपेक्षाकृत कम प्रचारित-प्रासारित बाजारों में प्रवेश करके, नई मदों के निर्यात वृद्धि के लिए, मेलों में सम्मिलित होने के लिये सूचना प्रदान कर एवं सेवाएँ उपलब्ध कराके तथा उन्नत व्यापार सेवाएँ एकत्र करके उनके प्रसार के माध्यम से उद्योग को अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

1991-92 के दौरान पूर्ण टी0एफ0ए0आई0 ने 38 बाहरी व्यापार मेलों और प्रदर्शनी में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इनमें से 21 सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेला, 15 विशिष्ट वस्तु मेला, 2 भारतीय प्रदर्शनी थी। इन 38 कार्यक्रमों में 5 अमेरिकी क्षेत्र में हैं, 10 पश्चिमी यूरोप में, 6 पूर्वी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में, 11 वाना क्षेत्र में। इन मेलों पर भारतीय कम्पनी द्वारा सूचित किये गये तत्कालीन व्यापार की मात्रा 435 46 करोड़ रुपये थी तथा सौदे के अन्तर्गत 949 49 करोड़ रुपये था। 1992-93 के लिये आई0टी0पी0ओ0 के बजटीय कार्य में 35 कार्यक्रम निर्धारित थे। सरकारी अनुदान पर आभार कम करने के लिये 1992-93 की समयावधि में मूल्य सुधार तथा स्व-वित्त आधार पर 8 और मेलों को सगठित करने का फैसला लिया गया। अक्टूबर

1992 तक 27 मेले लगाये गये। इन मेलो के माध्यम से हुए व्यापार की मात्रा 279 93 करोड रुपये तथा सौदा 611 53 करोड रुपया रहा।

भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन सगठन ने वर्ष 1994-95 की समयावधि मे विदेशो मे 33 मेलो तथा प्रदर्शनी कार्यक्रमो का आयोजन किया। इन 33 मेलो से 15 साधारण अन्तर्राष्ट्रीय मेले 13 विशेष वस्तु मेले तथा 4 अन्य भारतीय प्रदर्शनियो थी। इस साल के समयावधि मे आई0टी0पी0ओ0 ने दक्षिण अफ्रीकी शहर जोहन्सवर्ग मे प्रथम बार पूर्ण भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जिसमे 160 नियमित देशो ने भाग लिया। आई0टी0पी0ओ0 ने इजराइल की राजधानी तेलअविव मे इन्टरनेशनल माडर्न लिविंग प्रदर्शनी मे भागीदारी का आयोजन भी किया। व्यापारियो की बैठको, सम्पर्क वृद्धि कार्यक्रमो और विदेशी क्रेता प्रतिनिधिमडलो के कार्यक्रमो का प्रायोजन भी किया गया। फरवरी, 1995 मे यागोन, म्यामार मे एक अन्य भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिसम्बर 1994 तक 26 मेलो मे भागीदारी की गयी। भारतीय कम्पनियो द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इन मेलो मे दिसम्बर 94 तक उन्होने 796 करोड रुपये का व्यापार किया। इनमे 106 3 करोड के अनुमानित व्यय पर 214 करोड के दो पुष्टि आदेश भी शामिल है।

7. सलाहकारी परिषद .—

इस परिषद के अन्तर्गत दो समितियो है जो निम्नलिखित है—

(अ) व्यापार के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति — व्यापार के लिये केन्द्रीय सलाहकारी समिति दो सलाहकारी अनुभागो व्यापार पर आयात-निर्यात के सलाहकारी समिति तथा व्यापार बोर्ड (15 फरवरी 1978 से प्रभावी है) के सम्मेलन से निर्मित हुआ है। वाणिज्य मन्त्री सलाहकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। समिति अग्रलिखित विषयो पर सरकार को परामर्श देती है—

- (1) निर्यात और आयात नियन्त्रण का कार्यान्वयन।
- (2) निर्यात तथा आयात नीति एवं कार्यक्रम।
- (3) निर्यात उत्पादन का सगठन और प्रसार।
- (4) व्यापारिक सेवाओ का सगठन और विकास।

सलाहकारी समिति सरकार को परामर्श देती है नीतियो मे अनिवार्य परिस्थिति के निर्धारण को प्रभावित करता है, एवं कार्यक्रम प्रोत्साहन, आयात-निर्यात प्रक्रिया तथा सेवा निर्यात के विभिन्न क्षेत्रो मे सहायता करता है।

(ब) क्षेत्रीय आयात-निर्यात सलाहकारी समिति — भारत में कुल 4 क्षेत्रीय समितियाँ हैं जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए जुलाई 1968 में स्थापित किया गया तथा वे अग्रलिखित विषयों से सम्बन्धित हैं—

- (i) आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण सगठन का सार्वजनिक सम्बन्ध और कार्यक्रम के नियमों के प्रोन्नति के विषयों में परामर्श प्रदान करना और व्यापार एवं उद्योग से सम्बन्धित अन्य सरकारी विभाग।
- (ii) आयात-निर्यात को निर्विघ्न बनाना, जहाजी परिवहन साख बीमा तथा निर्यात निरीक्षण की बाधाओं के बारे में विचार करना और उसकी उन्नत के लिए उपाय सुझाना।
- (iii) आयात-निर्यात के नियमों के क्रियान्वयन में आयी बाधाओं पर विचार करना तथा नकद सहायता को चुकाने के लिए उपाय बताना।

8. भारतीय निर्यात सगठन का सघ —

देश के विभिन्न भागों में स्थित निर्यात वृद्धि एजेंट का कार्यालय एक शीर्ष समुदाय भारतीय निर्यात का सघ है। जिसे 1965 में निर्मित किया गया और इसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित है। अनेक सगठनों एवं संस्थाओं के द्वारा निर्यात सम्बर्द्धन क्रियाकलापों के क्रमिक एवं परिशिष्ट कार्य किया जाता है। जैसे निर्यात सम्बर्द्धन समिति, वस्तु परिषद तथा अन्य विशिष्ट अभिकर्ता कार्यालय। यह प्राथमिक श्रम सगठन के रूप में कार्य करता है एवं निर्यात भवन को आशिक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्र के अन्तर्गत निर्यात सम्बर्द्धन सघ केन्द्रीय अभिकर्ता कार्यालय का कार्य करता है। इसके सदस्य संस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान निर्यात सम्बर्द्धन समिति के अतिरिक्त वस्तु परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग के कार्यालय आते हैं। यह विदेशी बाजार में निर्यात से सम्बन्धित सूचनाओं की रिक्तता को व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जोड़ता है। इस सघ के प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित हैं —

- (क) निर्यातक और निर्यात सगठन के लाभ के लिए सामान्य सेवाएँ प्रदान करना तथा निर्यात सम्बर्द्धन क्षेत्र में साधारणतया कार्य करना।
- (ख) चढ़ा देना, सदस्य होना तथा अन्य किसी सगठन से सम्बन्ध बनाना।
- (ग) निर्यात व्यापार के विकास को प्रोत्साहन देना।

- (घ) नियमित पत्र प्रकाशन, सूचनाये और व्याख्यान का प्रबन्ध करना, सवाद और वार्तालाप करना।
- (ङ) प्रचार करना और सगठित व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियो मे सम्मिलित होना।
- (च) व्यापार का कार्यालय खोलना, आकर्षक व्यवसायिक केन्द्र के प्रतिनिधि को नियुक्त करना, भारत या विदेशो मे अभिकर्त्ता से पत्र व्यवहार करना।
- (छ) निर्यात सम्बर्द्धन क्रियाकलापो का क्रमिक विकास करना।
- (ज) विदेशी व्यापार के विषय मे उत्पन्न होने वाले विवाद को दूर करना।
- (झ) अध्ययन दल एव व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को बाहर भेजना तथा बाहर से प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित करना।
- (ञ) केन्द्रीय और राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्राधिकरण एव अन्य क्षेत्रीय समुदायो को निर्यात व्यापार से सम्बन्धित सभी मामलो मे सलाह देना।

सम्पूर्ण निर्यात समुदाय की आवश्यकताओ की योजना बनाना एव सभी समुदाय के लिए बहुत अच्छा बाजार उपलब्ध करना। सभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एव बाजार सूचनाये एकत्रित करना तथा इसके सदस्यो मे वितरित करने मे भी सहायता प्रदान करता है। विशेष देशो मे व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को भेजना तथा विदेशी प्रतिनिधिमण्डल को आमन्त्रित करना। यह विकास और निर्यात घरो की आवश्यकता और सूचना सस्थाओ को आश्वासन प्रदान करता है, जो निर्यात-व्यापार बढ़ाने मे मुख्य भूमिका अदा करते है।

9. निर्यात वृद्धि समिति तथा वस्तु बोर्ड :-

देश मे अनेक निर्यात वृद्धि समिति तथा वस्तु सगठन की स्थापना हुई है। विशेष वस्तु समुदाय के निर्यात के वृद्धि मे सहायता की दृष्टि से इस समिति का निर्माण हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रमुख है -

- (1) निर्यात सम्बर्द्धन समिति - अनेक उत्पादो को लेते हुए 19 निर्यात सम्बर्द्धन समितियों हैं। 12 निर्यात सम्बर्द्धन समितियों वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन हैं तथा 7 अन्य हथकरघा मन्त्रालय के अन्तर्गत है। यह समिति अभियान्त्रिक माल, चमड़ा-निर्माणकर्ता, चमड़े की वार्निश लगाना, खेलकूद सामान, शुद्ध-शिल्क, हथकरघा आधारित रसायन, काजू समुद्रपार निर्माण योजना, रुई, वस्त्र, रेयान-वस्त्र, ऊन और ऊनी गलीचे के निर्यात सम्बर्द्धन प्रभावो को देखते है। ये समितियों लाभ न बनाने वाली कम्पनियों है। ये निर्यात सम्बर्द्धन समितियों सरकार और

निर्यातको के मध्य एक आपसी सम्बन्ध बनाती है तथा निर्यात समुदाय के सामने आयी बाधाओं की सूचना सरकारी अधिकारियों को देती है। सभी निर्यातक जो विशेष वस्तु उत्पाद के अन्तर्गत आते हैं, इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों से समिति का चढ़ा, शुल्क सेवाएँ तथा विशेष निम्न चढ़ा, शुल्क, छोटे उद्योगों से लिया जाता है। समिति के सदस्य निर्वाचन के माध्यम से एक कार्य समिति का चुनाव करते हैं तथा कार्य समिति अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों का चयन करती है। उत्पाद के निर्यात से सम्बन्धित सभी नीति तथा समस्याओं का समाधान कार्य समिति के द्वारा होता है एवं आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं। सरकारी नियमानुसार समिति के अन्तर्गत केवल रजिस्टर्ड निर्यातक ही निर्यात के लिये सहायता की माँग कर सकते हैं। समिति के प्रमुख कार्य अग्रलिखित हैं।

- (क) निर्यात उत्पाद के लिए और आयात किये गये कच्चे माल की पूर्ति के लिये स्वदेशी व्यवस्था करना।
- (ख) बाहर के बाजारों के व्यापार प्रतिनिधि मंडल एवं अध्ययन दल को बुलाना।
- (ग) समुद्रपार क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा प्रतिदिन बाजार स्थिति की सूचना प्रदान करना तथा समिति के सदस्यों को परामर्श देना।
- (घ) निर्यात की सुविधा के लिये निर्यात बाजार उपलब्ध कराना एवं वस्तु की पहचान करना।
- (ङ) निर्यात वित्त, बैंकिंग, बीमा, तथा संयुक्त जोखिम पर सदस्यों को सलाह देना।
- (च) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में परामर्श देना।
- (छ) सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये निर्यात सहायता योजनाओं को कार्यान्वित करने एवं व्याख्या करने में निर्यातकों की सहायता करना।
- (ज) निर्यात सहायता प्राधिकरण के शीघ्र प्रदर्शन की व्यवस्था करना।
- (झ) पहचाने गये वस्तु पर बाजार निरीक्षण करना, एवं बाजार गुप्तचर प्रदान करना।
- (म) निर्यात किये जाने वाले सामान को जहाज में लाने से पहले निरीक्षण एवं शुल्क-नियन्त्रण पर निर्यात-निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।
- (ट) भावी ग्राहकों से सम्बन्ध बनाना ताकि भारतीय उत्पाद में उनकी रुचि बढ़ायी जा सके।
- (ठ) स्थानान्तरण समस्या को हल करने के लिए सदस्यों की सहायता करना।

- (ड) चुने हुए समूह को सगठित एवं प्रदर्शित करना ।
- (ढ) चुने हुए उत्पादों के लिए भारत एवं विदेश में अधिक प्रचार करना ।
- (ण) विशेषीकृति व्यापार मेले तथा बाहर के प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

समिति ने विदेशों में अपने कुछ कार्यालय खोले हैं। समिति के कार्यक्रम सही औद्योगिक छाया की योजना बनाना एवं अभियान्त्रिक माल के प्रकाशन के लिये व्यवस्था करना है।

(ii) वस्तु बोर्ड - भारत सरकार ने 9 वस्तु परिषदों की स्थापना की है, जो वाणिज्य मन्त्रालय के आधीन हैं। ये भारत के व्यापारिक उत्पादन की देख-रेख करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चाय, काफी, रबड़, नारियल का जटा, तम्बाकू आते हैं। ये परिषद इन उत्पादों के सभी प्रकार के विकास एवं समस्याओं के लिये उत्तरदायी हैं। यह परिषद उगाने वाले कृषकों के आर्थिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के उत्पाद गुण का विकास एवं उनके लाभ एवं अच्छी कीमत में सहायता प्रदान करना है। ये परिषद निम्नलिखित हैं -

(क) काफी बोर्ड - काफी बोर्ड की स्थापना 1942 में कहवा अधिनियम के अन्तर्गत इसके निर्यात उद्योगों एवं सम्वर्धन के विकास के लिए किया गया। अधिक उत्पाद, बजार और निर्यात सम्वर्द्धन एवं निकाय के माध्यम से काफी उद्योग के विकास का कार्य दिया गया है। यह कॉफी के बारे में सूचना एकत्रित करती है, जिससे निर्यात किया जा सके। यह केन्द्रीय अनुसंधान (ICR) के माध्यम से नमूनों को एकत्रित करता है जिससे निर्यात में सुविधा हो सके और नमूने सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाय ।

(ख) तम्बाकू परिषद - तम्बाकू परिषद की स्थापना 1976 में भारत सरकार के द्वारा आन्ध्र प्रदेश के गुटूर जिले में हुआ था। बोर्ड का कार्य अमेरिकी तम्बाकू के विकास और उत्पादन पर नियन्त्रण, भारत एवं विदेशों दोनों में अमेरिकी तम्बाकू बाजार पर निगाह रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि कृषक सही मूल्य पा रहे हैं कि नहीं। विभिन्न रोपाईयों को उचित स्तर प्रदान करना, उपलब्ध बाजार का विकास तथा नये बाजार खोजना, सहायता करना तथा आर्थिक अनुसंधान और तकनीक को बढ़ावा देना, ताकि उद्योगों के निर्यात विकास में बहुमुखी प्रगति संभव हो सके।

(ग) भारतीय हथकरघा बोर्ड - इस बोर्ड के अन्तर्गत दो हथकरघा तकनीक संस्थान हैं 1 सेलम में तथा 2 वाराणसी में हैं। इसके अन्तर्गत त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर छात्रों को बोर्ड द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। परिषद के

अन्तर्गत 7 बुनाई केन्द्र जो बम्बई, इन्दौर, वाराणसी, कोलकता, मगलूर, बंगलौर, और चेन्नई में हैं। ये छपाई, रगाई तथा बुनाई के क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को तकनीक सहायता प्रदान करती हैं तथा अर्थिक कठिनाईयों दूर करती हैं और विदेशी भंडारों के माध्यम से उद्योगों को सहायता देते हैं।

(घ) **रबड़ बोर्ड** — रबड़ परिषद की स्थापना भारतीय सरकार ने 1954 में रबड़ के विकास के लिये किया गया। रबड़ उद्योग के सभी बिन्दुओं पर परिषद सरकार को सलाह देती है। जैसे कि रबड़ नियन्त्रण पर विचार, बाजार प्राप्ति। रबड़ कृषक के बीच संगठन में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो रही है। इसमें एक रबड़ अनुसंधान संस्थान भी है, जिसमें सभी औजारों से सुसज्जित प्रयोगशाला है।

(ङ) **केन्द्रीय रेशम बोर्ड** — इस बोर्ड की स्थापना रेशम अधिनियम के अन्तर्गत 1949 में हुआ। यह परिषद कृषि उद्योग, वार्षिक योजना को प्रभावी बनाना तथा निर्यात उद्देश्य एवं उत्पाद की प्राप्ति, अनुसंधान के संगठन, प्रशिक्षण, बीज उत्पाद एवं कच्चे रेशमी धागे के आयात-निर्यात के विकास का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्यालय मुम्बई में स्थित है।

(च) **इलायची बोर्ड** — भारत सरकार ने 1965 में इलायची अधिनियम के तहत इलायची बोर्ड की स्थापना केरल प्रान्त के एर्नाकुलम् नगर में किया गया। परिषद को दिये गये विशेष कार्यों के अन्तर्गत इलायची कृषकों के बीच सहकारिता, इलायची उगाने वालों के प्रतिफल की वापसी सुनिश्चित करना एवं उद्योग में व्यस्त मजदूर के लिये उचित मजदूरी की व्यवस्था का विकास करना, इलायची की खेती के लिये आर्थिक सहायता देना, उसका क्षेत्र विस्तार करना, इलायची के बिक्री और निर्यात पर नियन्त्रण रखना, दाम को प्रभावित करना, इलायची परीक्षण में प्रशिक्षण एवं उत्पाद के स्तर को बनाये रखना, भारत एवं विदेशों में इलायची के बाजार का विकास एवं तकनीकी आर्थिक अनुसंधान, वैज्ञानिक मदद या प्रोत्साहन देना। मसाले के निर्यात इलायची परिषद, एवं मसाला निर्यात सम्बर्द्धन समिति। ये सभी 1986 में मसाला परिषद के नाम से अभिहित नये संगठन में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

(छ) **चाय बोर्ड** — 1955 में भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम के अन्तर्गत इसकी स्थापना की गयी। चाय परिषद विभिन्न देशों के चाय समिति से लगातार सम्पर्क बनाये हैं, जैसे कि यू0एस0ए0 कनाडा, जर्मनी एवं आयरलैण्ड से। विदेशी चाय आयातक कम्पनी, चाय पैकर्स, एवं इसके विक्रेता की एक सूची बोर्ड बनाता है एवं चाय व्यापार के लाभ के लिए विदेशी बाजार से सम्बन्धित समाचार की भी सूची बनाता है।

(ज) **नारियल की जटा बोर्ड** — नारियल जटा परिषद की स्थापना 1959 में इसके विकास के लिये जटा उद्योग कानून के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा किया गया। यह परिषद अनुसंधान, निरीक्षण, नये नारियल के जटा की स्थापना का विकास एवं बुनाई के विशेषज्ञों को व्यस्त रखता है, एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। नारियल की जटा अनुसंधान संस्थान त्रिवेन्द्रम में है और वही पर राष्ट्रीय नारियल जटा प्रशिक्षण केन्द्र भी है।

(झ) **भारतीय शिल्प बोर्ड** — इस बोर्ड के चार कला केन्द्र हैं, जो मुंबई, कोलकत्ता, बंगलौर और नई दिल्ली में हैं। यह राज्य सरकार को योजना बनाने तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देती है। परिषद नये कलाओं का विकास करती है, जिसमें व्यापार मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना, चलचित्र का उत्पादन, सिली हुयी छोटी पुस्तक और अन्य सम्बर्द्धन उपाय हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

10. कृषि और उन्नत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण .—

उन्नत खाद्य निर्यात सम्बर्द्धन समिति की जगह 13 फरवरी 1986 को कृषि और उन्नत खाद्य-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना हुयी। इसके अन्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार, उद्योग एवं व्यापार अनुसंधान संस्थान के मन्त्रालय से सम्बद्ध प्रतिनिधि आते हैं। प्राधिकरण का कार्य बागवानी उत्पाद, पशु उत्पाद, उन्नत भोज्य वस्तु, मिठाई उत्पाद, एवं कृषि आधारित वस्तुओं के निर्यात का विकास करना है। यह प्राधिकरण गुण एवं पैकिंग में विकास के द्वारा कृषि उत्पाद के मूल्य को गतिमान करने में सहायता करती है।

11. सेवा सहायता संगठन —

उद्योग और व्यापार की सहायता हेतु अनेक संस्थाओं और संगठनों की स्थापना हुयी है। जो निर्यात प्रबन्ध से विवर्गीय के विकास में सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए बाजार अनुसंधान, निर्यात, साख बीमा, निर्यात प्रचार, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी का गठन, पैकिंग की गुणवत्ता में सुधार इत्यादि। सम्बन्धित प्रमुख संस्थाएँ अग्रलिखित हैं —

(i) **आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण संस्थान** :— उपरोक्त संगठन आयात एवं निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय के नाम से जाना जाता है। सरकार के आयात-निर्यात नीति के निर्वाह के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसकी उप शाखाएँ लगभग सभी राज्यों में तथा ये शाखाएँ भारतीय व्यापार वृद्धि प्रयत्न को आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं। निर्यात वृद्धि कार्यालय जो मुंबई, कोलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, नागपुर और पुणे में हैं जो क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य

नियन्त्रक एव उपमुख्य नियन्त्रक के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करता है।

(ii) व्यापारिक सूचना और सांख्यिकी सामान्य निदेशालय — वाणिज्यिक सूचना एव सांख्यिकीय के सामान्य निदेशालय का मुख्य उत्तरदायित्व, अन्तर्राष्ट्रीय और सहायक व्यापारिक आँकड़ा एकत्रित करना एव विभिन्न प्रकार की व्यापारिक सूचनाएँ प्रदान करना है। यह कोलकता में स्थित है। निदेशालय भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के मध्य व्यापारिक विवाद के व्यवस्था में भी सहायता करता है। इस विभाग का कार्य निम्न बिन्दुओं से दर्शाया जा सकता है —

- (क) भारतीय और विदेशी व्यवसायिक संस्था के बीच वाणिज्यिक विवाद में उदारता स्थापित करने के उद्देश्य से मध्यस्थता करना।
- (ख) कोलकता स्थित वाणिज्यिक पुस्तकालय की रक्षा करना।
- (ग) भारत और विदेशी व्यापारिक संस्था के लिये हिसाब रखना।
- (घ) व्यापारिक भूमिका।
- (ङ) सरकार और व्यापार द्वारा आवश्यक वाणिज्यिक सूचनाओं को एकत्रित करना और प्रदान करना।
- (च) विदेशों में भारतीय सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिनिधि से प्राप्त सूचना का प्रकाशन करना।
- (छ) “डाइरेक्टरी आफ एक्सपोर्ट्स आफ इण्डियन प्रोडक्ट एण्ड मैन्युफैक्चरर” का प्रकाशन करना।
- (ज) साप्ताहिक “इंडियन ट्रेड जर्नल” का प्रकाशन करना।

(iii) पचायत से विवाद के निर्णय की भारतीय समिति .— पचायत से विवाद के निर्णय की भारतीय समिति की स्थापना 1965 में हुई। विदेशी व्यापार में भारत के प्रभाव को ध्यान में रखकर विवाद की मित्रतापूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये इस समिति की स्थापना हुई। इस समिति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

- (क) इसके निर्वाचक सदस्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विवाद में पचायत द्वारा निर्णय की व्यवस्था करना।

- (ख) यह समिति, व्यापारियों, निर्यात सम्बर्द्धन समिति के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत, वाणिज्य और व्यापार सगठन का कार्यालय के तहत विवाद और पचायत से झगड़े का निर्णय की समस्या के बारे में विचार करने के लिये लगातार बैठक करता है।
- (ग) विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में वाणिज्यिक पचायत से विवाद के निर्णय के विचारों का विस्तार और प्रसिद्धि प्रदान करना।
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पचायत से झगड़े के निर्णय के मामले के सम्बन्ध में पचायती समुदाय और अन्तर्राष्ट्रीय सगठन से सहायता माँगना।
- (ङ) पचायत से झगड़े का निर्णय जैसे काम करने के व्यक्तियों के जूरी की रक्षा करना।

12 निर्यात निरीक्षण समिति .—

भारतीय निर्माण और उत्पाद गुण के लगातार विकास के अनुरूप बाहरी आयातकों को विश्वास प्रदान करना तथा भारतीय निर्यातकों के लिये भारत सरकार ने निर्यात (गुण-नियन्त्रण एवं निरीक्षण) कानून 1963 में लागू किया। इस कानून के अन्तर्गत भारत का "निर्यात निरीक्षण समिति" की स्थापना की गयी। समिति आवश्यक गुण नियन्त्रण के प्रकाशन की व्यवस्था करती है। समिति निर्माण कर्ता को उनके उत्पाद के गुण स्तर बनाये रखने के लिये सभी वस्तुओं के गुण नियन्त्रण क्रिया के विस्तार का निश्चय किया गया है। इसके अन्तर्गत दो विशेषज्ञों की समिति का निर्माण हुआ है, एक प्रशासन से सम्बन्धित और दूसरा तकनीकी मामलों से सम्बन्धित है। ये समितियाँ आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के समिति को उनके अध्यक्ष की तरह सहायता करती हैं। समिति ने आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अन्तर्गत एक सगठन का निर्माण किया जो देश में गुण-नियन्त्रण और निरीक्षण के आवश्यक विस्तार के अन्तर्गत किसी वस्तु का आयात करने के लिये प्रमाणित करता है। समिति विभिन्न क्षेत्रों में, अभियांत्रिक, चमड़ा, जूट उत्पाद मछली, काजू और रसायन के लिये विशेषज्ञ समिति का निर्माण किया तथा अच्छा प्रशासन, अनिवार्य गुण-नियन्त्रण और जाँच योजनाओं को परामर्श देने के लिये निरीक्षण अभिकर्ता कार्यालय का भी स्थापना किया गया।

नवीन निर्यातकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जाँच-पड़ताल समिति या अन्य अभिकर्ता कार्यालय से विवर्गीय को बहुमूल्य क्रिया-कलाप प्रदान करते हैं। चेन्नई के निर्यात जाँच-पड़ताल एजेंट कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र में सुविधायें प्रदान की गयी हैं। इसके अन्तर्गत

मुम्बई, कोलकता, कोचीन, दिल्ली, चेन्नई, के गुण नियन्त्रण एव जॉच-पडताल निदेशक को निर्यात जॉच-पडताल अभिकर्ता कार्यालय के द्वारा निर्यात में शामिल किये गये विभिन्न वस्तुओं पर आकास्मिक निरीक्षण के लिये उपयुक्त आधार प्रदान किया गया है। 39 निजी निरीक्षण-कार्यालय के अधीन, 10 सरकार द्वारा प्रमाणित अभिकर्ता कार्यालयों के द्वारा इनके कार्यों को जोड़ा जाता है। वर्तमान में तीन जॉच-पडताल नियम हैं। उदाहरणस्वरूप – बाहर भेजे गये माल के जॉच पडताल की प्रक्रिया, गुण-नियन्त्रण विधि एव स्व-प्रमाणित योजनाएँ। अवैध निर्यात को कठोर सजा देने के लिये कानून में पुनः संशोधन किया गया है।

13. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण :-

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1970 में समुद्री उत्पाद निर्यात सम्बर्द्धन समिति की स्थापना की। जिसने सितम्बर 1972 में समुद्री उत्पाद के निर्यात विकास में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करना प्रारम्भ किया। यह प्राधिकरण न्यायधिक नियम, सुरक्षा और नियन्त्रण के माध्यम से उद्योग के स्वस्थ विकास में सहायता सुनिश्चित करती है। प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नवत हैं –

- (क) बाजार सम्बर्द्धन क्रिया-कलाप, विभिन्न देशों के माग में उत्पादक के प्रकार पर सूचना, विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता के लिये सहायता प्रदान करते हुए समुद्र पार समुद्री उत्पाद के बाजार का विकास करना।
- (ख) उद्योग के लिये छोटी मात्रा में आवश्यक कुछ जरूरी वस्तुओं का आयात और व्यापार पूछ-तॉछ, निर्यात-सम्बर्द्धन, बाजार गुप्तचर के सम्बन्ध में अन्य तरह की सेवाएँ और सहायता प्रदान करना।
- (ग) मछली पकड़ने वालों का पंजीकरण, क्रमिक यन्त्र स्वस्थ विकास के सम्बर्द्धन की दृष्टि से निर्यात और समुद्री उत्पाद उद्योग से सम्बन्धित चीजों का भण्डारण करना।
- (घ) समुद्र के किनारे एव गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास, समुद्र के किनारे एव गहरे समुद्र, मत्स्य उद्योग का संरक्षण और व्यवस्था करना।
- (ङ) वित्तीय और अन्य सहायताएँ प्रदान करना, सहायता कोष एव अनुदान के विस्तार के लिये अभिकर्ता के कार्यालय की तरह कार्य करना जैसा सरकार द्वारा सौंपा गया है।

- (च) समुद्री उत्पाद के निर्यात का नियन्त्रण करना।
- (छ) ऐसे और उपाय जो निर्यात उद्योग में प्रमुख हैं।
- (ज) मछली पकड़ने और बाजार के विशिष्ट सन्दर्भ में निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

14 आयात-निर्यात बैंक —

भारत का आयात-निर्यात बैंक 1-1-1982 को निर्यातकों की समस्याओं के समाधान सुनिश्चित करने के लिये, पूँजीगत माल एवं निर्यात योजना को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिए, संयुक्त कार्य एवं निर्यात की तकनीक सेवाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकिंग, खरीददार साख का विस्तार और उच्च घरेलू एवं समुद्र पार बाजारों के साख, निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं वित्तीय कार्यों के लिये ससाधनों को गति प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया। यह भारतीय सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था है। आयात-निर्यात बैंक, निर्यात सम्बर्द्धन की आवश्यकता के प्रबन्ध के लिये एवं वित्तीय मजबूती की आवश्यकता की पहचान के लिये है। विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात की उन्नति के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना चाहिए। आयात निर्यात बैंक, भारतीय उद्योग विकास के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त शाखा के क्रिया-कलापों के द्वारा ऋण देने का उत्तरदायित्व लेती है। वर्तमान में भारतीय आयात निर्यात बैंक कुछ ऋण देने का कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अन्तर्गत ऋण देने की व्यवस्था की गयी है। ये कार्यक्रम निम्नवत् हैं—

- (क) उधार देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक एवं विदेश सरकार तथा वित्तीय संस्थान।
- (ख) समुद्र पार निर्यातक।
- (ग) कमी की पूर्ति करने वाले का साख।
- (घ) भारतीय निर्यातक।
- (ङ) भारतीय बैंक जैसी मध्यस्थता।
- (च) जमानत अनुग्रह।
- (छ) खरीददार साख।
- (ज) पुनः छूट व्यवस्था।
- (झ) जहाज पर माल लादने से पूर्व वित्त।

15. निर्यात साख और जमानत निगम .—

जुलाई 1957 से “निर्यात जोखिम और बीमा निगम” नाम से निर्यात साख एव जमानत निगम प्रारम्भ किया गया। जनवरी 1964 में निर्यात साख के क्षेत्र में इसके क्रिया-कलापों के विस्तार के उद्देश्य से निर्यात जोखिम और बीमा-निगम को निर्यात साख और जमानत निगम में परिवर्तन कर दिया गया। निगम का मुख्य कार्य विभिन्न स्तर पर निर्यात व्यापार में जोखिम उठाना है। निगम जहाज पर माल लादने से पूर्व और माल लादने के उपरान्त उधार के लिये बैंक जमानत सुविधा के द्वारा आवश्यक वित्तीय मदद प्राप्त करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। इसके आरम्भ होने से निगम कई उधार प्रदान करने की योजनाएँ बनायी हैं। ये योजनाएँ अग्रलिखित हैं —

- (i) पैकेजिंग उधार, जमानत, जहाज पर माल लादने के बाद निर्यात उधार, निर्यात वित्तीय जमानत (जहाज पर माल लादने से पहले) और निर्यात क्रिया-कलाप जमानत।
- (ii) यह निर्यातकों को भुगतान न करने के विभिन्न योजनाओं द्वारा राजनीतिक एवं वाणिज्यिक जोखिम से बचाता है।
- (iii) निर्यात साख और जमानत निगम अपने सेवा क्षेत्र का और विस्तार किया है।

निगम की नयी योजनाएँ निम्न हैं —

- (क) सेवा (राजनीतिक जोखिम) नीति।
- (ख) विनिमय अस्थिरता नीति।
- (ग) भारतीय बैंक के द्वारा बाहरी योजनाओं के सम्पादन में भारतीय ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा उधार प्राप्त करने के लिए निर्यात-वित्त (समुद्र पार उधार देने का कार्य) जमानत की योजना।
- (घ) सेवा (विस्तृत जोखिम) नीति।

निर्यात साख और जमानत निगम बिना किसी शका के अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा निर्यातकों और वाणिज्यिक बैंकों को फलदायक सेवाएँ प्रदान करती है। भारत के निर्यात में उपरोक्त सस्था की भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है।

16 निर्यात सदन योजना —

निर्यात के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने के फलस्वरूप सरकार ने मुख्य व्यवसायिक फर्मों को निर्यात सदनों के रूप में मान्यता देने की योजना लागू की। इसके अन्तर्गत इन सदनों को निर्यात क्षेत्र में विशेष सुविधाएँ एवं रियायतें दी जाती हैं। 1985-88 की नयी आयात — निर्यात नीति में निर्यात में भारी वृद्धि करने के उद्देश्य से उन निर्यात सदनों को व्यापारिक प्रतिष्ठान का दर्जा देने की बात कही गयी है। जिन्होंने निर्यात बढ़ाने की क्षमता दिखायी थी तथा जिसके पास गुणात्मक नियन्त्रण के लिए आवश्यक तकनीकी साधन हैं। 1988-91 की आयात निर्यात नीति में निर्यात सदन एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान की पात्रता के नियमों में संशोधन कर दिया गया है तथा इन्हें अधिक प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। अब इनकी पात्रता हेतु वास्तविक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को आधारभूत शर्त माना गया है। जिसके अनुसार 2 करोड़ एवं 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने वाली संस्थाओं को क्रमशः निर्यात सदन एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान की पात्रता होगी तथा केवल कुछ वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं के निर्यात को इनकी पात्रता में शामिल किया जाएगा।

17. विपणन विकास कोष :-

निर्यात प्रयासों में सहायता के लिए जुलाई 1963 में भारत सरकार द्वारा एक विपणन विकास कोष की स्थापना की गई। यह कोष निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और अन्य निर्यात संगठनों को अनुदान देता है ताकि वे निर्यातों का विकास कर सकें। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का खर्च उठा सकें और विदेशी मण्डियों में भारतीय वस्तुओं के लिए परियोजनाएँ चला सकें।

18. व्यापार विकास संस्था :-

भारत सरकार ने निर्यात व्यापार में वृद्धि के लिए सन 1971 में व्यापार विकास संस्था की स्थापना की। जिसका मुख्य कार्य निर्यात सम्बर्द्धन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना है तथा उन्हें आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करना है। संस्था ने भारत तथा अन्य देशों में व्यापार मेलों का आयोजन कर भारत के व्यापार में सहयोग दिया है।

19. मुक्त व्यापार क्षेत्र :-

भारत सरकार द्वारा काण्डला, शांताकुज तथा दमदम में मुक्त बाजार क्षेत्र बनाये गये हैं, जिनमें केवल निर्यात के लिए माल बनाने वाली औद्योगिक इकाईयों को अनेक प्रकार की

रियायते दी जाती है, और उन्हें निर्यातों से सम्बन्धित माल के आयात पर कोई कर नहीं पड़ता। ऐसे चार और क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु में स्थापित किये गये हैं।

20 प्रचार अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेला :-

विदेशों में भारतीय वस्तुओं का प्रचार करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रदर्शन संचालनालय की स्थापना की गयी। समय-समय पर आयोजित मेलों ने भी निर्यात बढ़ाने में सहायता दी है, क्योंकि इनमें भारतीय वस्तुओं का विदेशों में प्रदर्शन किया जाता है। भारत सरकार ने 1978 में मास्को में सबसे बड़ा भारतीय व्यापार मेला आयोजित किया। इस मेले का उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशों में निर्यात बढ़ाना था क्योंकि इन देशों के साथ सरकारी सगठनों द्वारा व्यापार करने के बावजूद इन देशों में निर्यात से वृद्धि की काफी सम्भावना थी। भारत सरकार द्वारा निरन्तर इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिससे हमारी वस्तुओं को न केवल नये बाजार प्राप्त हुए हैं वरन् हमारे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

21 निर्यात साख एवं प्रत्याभूति निगम -

भारत सरकार ने 1964 में निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम की स्थापना की जिसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना तथा निर्यात व्यापार के जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना है।

22. राज्य सरकार की भूमिका -

निर्यात की पूर्ति प्रदान करने की दृष्टिकोण से देश के निर्यात सम्बर्द्धन में राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपने औद्योगिक निदेशालयों द्वारा निर्यात सम्बर्द्धन का निर्माण करती है। उनके विभिन्न राज्यों से उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को सक्रिय करने के लिए कुछ सरकारों ने निर्यात सम्बर्द्धन परिषद और निर्यात समिति का निर्माण किया है। राज्य द्वारा लघु और मध्य स्तर के उद्योगों के निर्यात के संचालन के विकास और बढ़ावे के कार्यक्रम के अलावा, अलग राज्य निर्यात समिति का निर्माण राज्य क्षेत्रीय अभिकर्ता कार्यालय की तरह किया गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वाणिज्यिक क्रिया कलाप करती है। मुख्य मन्त्री या सम्बन्धित राज्यों के उद्योग मन्त्री के सभापतित्व के अन्तर्गत कुछ राज्यों में निर्यात सम्बर्द्धन सलाहकारी समिति की स्थापना की गयी है।

23 विदेश मे भारत का वाणिज्यिक प्रतिनिधि –

संस्थागत व्यवस्था जो देश के अन्तर्गत विकास और मजबूती में लगा हुआ है, वह विदेश में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान में संस्थागत ढाँचे का यह भाग 65 व्यापार दूतकर्म और वाणिज्यिक विभाग समुद्र पार बाजार में चला रहा है। प्रतिनिधि विदेशी देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक नीति के सूत्रीकरण से सरकार को सहायता प्रदान करती है। वे सरकार के आँख और कान की तरह काम करते हैं। सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक शर्तों और देश के विकास में इनका अधिकार पत्र महत्वपूर्ण है। वे भारतीय व्यापार प्रतिनिधि को सुविधाएँ प्रदान करती हैं, और निर्यातकों को विदेशी देशों में जाने में सहायता करती हैं और अन्य देशों से आयातित माल के नमूने प्राप्त करने में सहायता करती हैं। जो भारत से निर्यात और निर्मित किया जाता है। वे व्यापारिक मेले और प्रदर्शनियों के सगठन में भी सहायता करती हैं।

24. विश्व व्यापार सगठन .—

व्यापार और तटकर की विश्वस्तर पर एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने के लिए सन् 1947 में गैर व्यापार, तटकर और मुक्त व्यापार की संधि पर स्वीकृति हुई थी। गैट की परिधि बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ विस्तृत होती गई। सन् 1995 में गैट के स्थान पर विश्व व्यापार सगठन (W T O) की स्थापना हुई। दुनिया के स्तर पर विभिन्न देशों के बीच व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि, उत्पादित वस्तुओं की बहुलता और जटिलता, अत्यन्त विकसित और जटिल प्रविधि, संचार क्रांति के कारण सिमटते समय और दूरी के सन्दर्भ में व्यापार तटकर, करो में छूट और मुक्त तथा नियन्त्रित व्यापार के लिए दुनिया के स्तर पर सर्वमान्य नियमों का होना एक सभ्य संसार के लिए अनिवार्य है। इस कारण विश्व व्यापार जैसे सगठनों की उपादेयता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

गैट (GATT) अब (W T O) के दिनों से ही अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपीय संघ के देश मुख्य रूप से पाँच बातों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक को विकासशील देशों में भी लागू करने, विदेशी पूँजी निवेश और व्यापार की शर्तों के पारस्परिक रिश्तों, विश्व स्तर पर खुली प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशों में अपनी उत्पादित वस्तुओं और बाजार के संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों की समाप्ति, बीमा के क्षेत्र में विकासशील देशों में विकसित देशों की बीमा, कम्पनियों के बिना

रोक-टोक प्रवेश तथा सरकारी नीतियों की पारदर्शिता पर जोर देते रहे हैं। सिंगापुर के विश्व व्यापार सगठन सम्मेलन में भी विकसित देश इनको स्वीकृत कराना चाहते थे।¹

विकासोन्मुख देशों के पास कच्चा माल और सस्ता श्रम है। इसी कारण पहले कोरिया, ताइवान, मैक्सिको, ब्राजील, हांगकांग और सिंगापुर में विदेशी पूंजीनिवेश विशाल पैमाने पर हुआ। इसके बाद इसकी शुरुआत चीन, फिलीपीन्स, थाइलैण्ड, मलेशिया और इण्डोनेशिया में हुई। अब इसकी शुरुआत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ्रीका के कुछ देशों में हुई है। इन देशों को आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी और टेक्नालॉजी की आवश्यकता है।

भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो० वी० रामचन्द्रैया के अनुसार नये बाजार ढूँढने में यह सगठन ही हमारी मदद करेगा। 1995-96 में 4,475 अरब डालर के कुल विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी केवल 0.65 प्रतिशत है। पहले हमारी भागीदारी एक प्रतिशत तक हुआ करती थी। लेकिन अब यह काफी घट गयी है।²

25 आर्थिक उदारीकरण के पश्चात निर्यातोन्मुख इकाइयाँ तथा निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र योजनाएँ .-

आर्थिक उदारीकरण की नीति सरकार ने जब से अपनायी है, तब से निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र योजनाओं को और अधिक उदार बना दिया है। इन इकाइयों में कृषि, बागवानी, मछली पालन, कुक्कुट पालन तथा पशुपालन को भी सम्मिलित कर दिया गया है। निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रों की इकाइयाँ निर्यात व्यापार और स्टार ट्रेडिंग गृहों के माध्यम से भी निर्यात कर सकती हैं, इन इकाइयों में शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।

(i) **निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र (Export Processing Zones EPZs)** – जिसका नाम अब Special Economics Zones हो गया है, विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों को एक प्रभावशाली यन्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना है। ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकें। भारत में ऐसे 8 निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं जिनमें हाल ही में निजी क्षेत्र में सूरत में सचिन औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित

¹ राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) लखनऊ 28 दिसम्बर 1996 पृष्ठ 3।

² राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) लखनऊ 28 दिसम्बर 1996 पृष्ठ 2।

निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे 7 क्षेत्र काण्डला (गुजरात), साताक्रुज (मुम्बई) फाहटा (पश्चिम बंगाल) नोएडा (उत्तर प्रदेश) कोचीन (केरल) चेन्नई (तमिलनाडू) तथा विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित है। साताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात ससाधन क्षेत्र विशिष्ट रूप से इलेक्ट्रानिक सामान तथा रत्न और आभूषणों के लिए है। जबकि अन्य क्षेत्र सभी प्रकार के उत्पादों के लिए है।

निर्यात सम्वर्द्धन हेतु आधारित सरचना सुदृढ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र में दो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स स्थापित करने की अनुमति दिसम्बर 1994 में प्रदान की। इनमें से एक मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा दूसरा सूरत (गुजरात) में स्थापित किया जाना था, सूरत के निर्यात प्रोसेसिंग केन्द्र ने 1995 से कार्य आरम्भ कर दिया है। दोनों ही निर्यात प्रोसेसिंग केन्द्र में मुख्यत रत्नों एवं आभूषणों से सम्बन्धित इकाईयाँ स्थापित होगी।

देश में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के 7 निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रों के निष्पादन में विगत वर्षों में निरन्तर सुधार हुआ है, तथा इन क्षेत्रों से किया गया निर्यात 1997-98 में 4810 करोड रुपये था। निर्यात निष्पादन में 1997-98 के दौरान साताक्रुज निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र अग्रणी रहा है। दूसरा स्थान चेन्नई स्थित EPZ का है। वर्ष 1999-2000 के लिए इन 7 निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रों से निर्यात-लक्ष्य 6500 करोड रुपये निर्धारित किया गया है। जिसमें साताक्रुज का सार्वधिक लक्ष्य 3950 करोड रुपये रहा।

(ii) निर्यात विकास केन्द्र — निम्न निर्यात विकास केन्द्रों की भी स्थापना की गयी है —

- 1 तिरुपुर — हौजरी एवं बुनाई उद्योग।
- 2 मुरादाबाद — ब्रासवेयर हैण्डीक्राफ्ट।
- 3 लुधियाना — भारी मशीनरी तथा होजरी।
- 4 सूरत — रत्न और आभूषण।
- 5 पानीपत — हथकरघा।
- 6 अलेप्पी — नारियल के रेशे और इसमें निर्मित सामान।
- 7 जलान्धर — खेल का सामान।
- 8 भागलपुर — बुनाई।
- 9 अम्बाला — वैज्ञानिक उपकरण।

- 10 आगरा – चमड़ा फुटवियर।
- 11 राजकोट – इजनपम्प।
- 12 काचीपुरम – रेशम।
- 13 रानीपत – चमड़ा।
- 14 अलीगढ़ – पीतल के ताले।
- 15 वापी (अक्लेश्वर) – रसायन।
- 16 विशाखापट्टनम – मछली उत्पाद।
- 17 शिवाकाशी – माचिस।
- 18 बटाला – मशीन उपकरण।
- 19 सेलम – हस्त उपकरण।
- 20 जामनगर – ब्रासपार्ट्स।
- 21 नागपुर – हस्तउपकरण।
- 22 खुर्जा – मिट्टी के बरतन।
- 23 मेरठ – खेल के सामान।

(iii) निर्यातोन्मुख ईकाईयों (Export Oriented Unit EDU) :- सरकार ने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के पूरक के रूप में 1981 से शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाईयों की एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों द्वारा निर्यातों के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने हेतु इन इकाईयों को मशीन, कच्चा माल, उपकरण तथा शुल्क मुक्त उपभोग वस्तुओं के आयात की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। निर्यात-आयात नीति (1997-2002) के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र को वरीयता देते हुए निर्यात घरानों तथा ट्रेडिंग हाऊसों आदि की योग्यता निर्धारित करते समय कृषि निर्यात को दुगुना भार देने का निर्णय लिया गया। यदि फलों, सब्जियों फूलों तथा बागवानी उत्पादों का निर्यात कुल निर्यात के 10 प्रतिशत के बराबर होता है, तो 1 प्रतिशत इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए विशेष आयात लाइसेंस सुविधा दी जायेगी। कृषि तथा सम्बन्धित वस्तुओं से जुड़ी निर्यातोन्मुखी इकाईयों तथा निर्यात सम्बद्ध क्षेत्रों को अपना 50 प्रतिशत उत्पाद घरेलू बाजार (DTA) में बेचने की अनुमति होगी। EOUs तथा EPZs में

स्थित इकाईयों के लिये करावकाश की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। EOUs को डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सब कान्ट्रेक्टिंग की अनुमति भी दे दी गई।

देश में दिसम्बर 1997 के अन्त में ऐसी 1140 निर्यातोन्मुखी इकाईयाँ कार्यरत थीं। अन्तिम आकाडो के अनुसार 1997-98 में इन इकाईयों से 10500 करोड़ रुपये मूल्य का सामान निर्यात किया गया। इस प्रकार EOU तथा EPZ दोनों को मिलाकर निर्यात 1996-97 में 13054 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997-98 में 15310 करोड़ हो गया।

(iv) निर्यात सम्वर्धन पार्क — देश का पहला निर्यात सबर्द्धन औद्योगिक पार्क जो जयपुर के निकट सीतापुर में स्थित है, का औपचारिक उदघाटन केन्द्रिय वाणिज्य मन्त्री ने 22 मार्च 1997 को किया। 365 एकड़ में फैले इस औद्योगिक पार्क का विकास राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम (RIICO) द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से किया गया है। इसमें सम्पूर्ण व्यय 47.15 करोड़ रुपये आया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि निर्यात सबर्द्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिये भारत सरकार कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

राजस्थान में ही भिवाड़ी में एक अन्य निर्यात सबर्द्धन औद्योगिक पार्क को स्थापित करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में पहला निर्यात सबर्द्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोयडा के कसाना में स्थापित करने का निर्णय किया है। इसकी स्थापना का दायित्व राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC) को सौंपा गया है।

(v) निर्यात गृह, व्यापार गृह तथा स्टार ट्रेडिंग गृह — इन गृहों की स्थापना का उद्देश्य पहले से स्थापित निर्यातकों तथा बड़े निर्यात गृहों की बाजार क्षमता में वृद्धि करना है, वे पजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च बना है, उन्हें निर्यात व्यापार गृह अथवा स्टार ट्रेडिंग गृह का स्तर प्रदान किया जाता है इनके लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम औसत शुद्ध निर्यात आय अर्जन करना आवश्यक होता है। इन इकाईयों को सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त लाभ स्वीकृत किये जाते हैं।

देश में 31 दिसम्बर, 1998 तक 6 सुपर स्टार ट्रेडिंग गृह तथा 37 स्टार ट्रेडिंग गृह 366 मान्य व्यापार गृह तथा 1804 मान्य निर्यात गृह कार्यरत थे। इन निर्यात गृहों का कुल निर्यात

1996-97 में 86524 करोड़ रुपये था जो 1997-98 के दौरान अप्रैल से दिसम्बर 1997 में 42453 करोड़ रुपये रहा।

(vi) कृषि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs for agriculture) — हाल के वर्षों में निर्यात में कृषि के बढ़ते योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर में 50 करोड़ रुपये की लागत से 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र केवल कृषि के लिए स्थापित करने का निर्णय किया है।

अध्याय पाँच

“क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता एवं विदेशी व्यापार”

अध्याय – 5

क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता एवं विदेशी व्यापार

व्यापार सहकारिता एक बहुआयामी सकल्पना होती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के समझौते और सगठनों को शामिल किया जाता है। यह व्यापारिक और गैर-व्यापारिक दोनों होता है। यह द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनों प्रकार का होता है। इसको अत्यन्त महत्वाकांक्षी सहयोग के लिए तथा अत्यन्त महत्वहीन सहयोग के लिए दोनों प्रकार से सहयोग में लाया जाता है।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् और समाजवादी बाजार व्यवस्था के अंत के बाद विश्व आर्थिक परिदृश्य में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को अपने नये सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वे अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत पिछले कुछ वर्षों में अनेक साझा बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आए हैं। आज वर्तमान समय में पूरे विश्व में अब सैनिक शक्ति का स्थान आर्थिक सम्पन्नता लेती जा रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व की अगुवाई वही देश कर रहा है या भविष्य करेगा, जिसकी आर्थिक सम्पन्नता सुदृढ़ होगी। “वर्तमान परिस्थिति में किसी भी देश में आर्थिक मजबूती का विषय काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक आर्थिक बम हो गया है। इसीलिए आज यदि कोई देश आर्थिक रूप से विपन्न हो गया है तो उसको बरबाद करने के लिए किसी बम या हथियार की जरूरत नहीं रह गई है, वह तो स्वयं अपने से बरबाद है।¹

आज वर्तमान माहौल में हमें इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा तथा भारत को निर्यात लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य को सामने रखकर ही अपनी व्यापार रणनीति तैयार करनी चाहिए। विशाल कुशल मानव शक्ति भारत की प्रमुख आर्थिक ताकत है। भारत के कुशल कर्मियों को विकसित देशों में आने-जाने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

¹ कॉनिकल, मार्च 1996, कॉनिकल बुक्स (208) शिवलोक हाउस-1, कलपुरा कामर्शियल कम्प्लेक्स, नयी दिल्ली-15 (पृष्ठ-10)।

गतिविधियों का क्रियान्वयन करते समय हमें इस व्यापार की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए भारत को अब गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय उत्पादों को धीरे-धीरे विकसित देशों की ओर से गैर शुल्क व्यापार अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक कारण, सुरक्षा मानक, पर्यावरण मानक और पैकेजिंग स्तर जैसे मुद्दे उठाये जा रहे हैं।

आजकल विश्व में काफी बैरियर टूट रहे हैं और विभिन्न देश अपने पूर्वाग्रह तोड़कर आपस में परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक लाभ की भावना और गरीबी उन्मूलन सहित, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के दायित्व ने व्यापारिक गुटों और साझा बाजारों के गठन को मजबूर कर दिया है। इन व्यापारिक गुटों ने कुछ हद तक व्यापारवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन ऐसे गुट और समूह आज वर्तमान समय की जरूरत बन गए हैं। इस अवधारणा के तहत आयात को विभिन्न बदेशों एवं शुल्कों से मुक्त रखना तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, आर्थिक व्यापार सहयोग का आधार बिन्दु है, जिससे एक देश के सस्ते उत्पाद का लाभ दूसरे देश को मिलता है।

“विश्व व्यापार में अधिकतम हिस्सा समेटने तथा एशिया पसिफिक कोऑपरेशन (एपेक) तथा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) जैसे अति शक्तिशाली व्यापार सगठनों के उभरने के साथ ही साथ यूरॉपियन कम्युनिटी (ई० सी०) तथा एशियाई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत को विश्व बाजारों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यापार रणनीतियों का गंभीरता के साथ पुनरावलोकन करना चाहिए।¹

सार्क व्यापार के देशों ने सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेजमेंट (सप्ता) की स्थापना करके सदस्य देशों के मध्य ही निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अन्य व्यापार सहकारिता प्रकोष्ठ भी तेजी से उभर रहे हैं। सार्क देशों को आपसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। भारत ने एशियन से बातचीत के द्वारा साझेदार का स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए भारत को अगले दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7

¹ दैनिक जागरण, वाराणसी — 30 अप्रैल, 1996, पृष्ठ 8

से 8 प्रतिशत बनाए रखना होगा। निम्न प्रकार के आर्थिक सहयोग क्षेत्रीय व्यापार सहकारिता के अतर्गत आते हैं -

- (I) मुक्त व्यापार क्षेत्र उदाहरणार्थ लैटिन अमेरिकी एकता सगठन।
- (II) आर्थिक संध जैसे भविष्य का यूरोप आर्थिक समुदाय।
- (III) द्विपक्षीय व्यापार समझौता उदाहरणार्थ अमेरिका कनाडा का स्वैप समझौता।
- (IV) तकनीक एवं अन्य गैर व्यापारिक सहकारिता सहयोग उदाहरणार्थ - सार्क, ओईसीडी।
- (V) बहुपक्षीय व्यापार समझौते उदाहरणस्वरूप गैट अब डब्लूटीओ।
- (VI) सीमा संध उदाहरणस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय।
- (VII) मौद्रिक समझौते जैसे - यूरोपीय भुगतान संध।

अन्य प्रकार के कई सहयोग, जो दो राष्ट्रों के बीच आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उसे व्यापारिक सहयोग के अतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे सयुक्त निवेश कार्यक्रम इत्यादि।

इस सहयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप व्यापारिक समझौता होता है। इसका मुख्य कार्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना तथा मुक्त व्यापार में विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ सहयोग प्रदान करना होता है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन लागतों के आधार पर होना चाहिए राजनीति के आधार पर नहीं।

कुछ वस्तुएँ प्राकृतिक देन होती हैं, जिनका उत्पादन दूसरे जगह संभव नहीं होता। पेट्रोल जो तथा अन्य पदार्थ कि पेट्रोल से संबन्धित कुछ देशों में मिलती हैं जबकि कुछ देशों में नहीं मिलती। कृषि योग्य भूमि प्रत्येक देश में हर जगह उपलब्ध होती है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कृषि वस्तुएँ किसी खास स्थान पर ही उत्पादित हो सकती हैं जैसे- चाय, काफी, काजू, एवं गर्म मसाला इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति ने कुछ खास स्थानों को अधिकतम भंडारों से पूरित किया है। अगर उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होता है तो निश्चित रूप से उत्पादन लागत कम होती है तथा उत्पादन अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप उपयोग एवं समाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। जैसे लोहे और स्टील के उत्पादन के दो प्रमुख अवयव होते हैं - लौह खनिज और कोयला।

दोनों काफी भारी होते हैं तथा इनकी परिवहन लागत बहुत अधिक होती है। इस लिए स्टील के कारखानों को उसी स्थान लगाना चाहिए, जहाँ इनमें से कम से कम एक साधन नजदीक ही उपलब्ध होता हो।

प्रत्येक राज्यो के बीच सौहार्द एव आपसी भाईचारा तथा विश्वास का अत्यंत अभाव है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक व्यापार में आत्मनिर्भर होना चाहता है। कुछ व्यापार में तो वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने उसे वह वस्तु प्रदान किया ही नहीं है, जैसे बहुत से देशों में कोयला, पेट्रोल आदि वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उस देश को विवश होकर इनका आयात करना पड़ता है। अन्य दूसरे व्यापार में आत्मनिर्भर होने के लिए कितने सारे उपाय करने पड़ते हैं। इनकी लागत अधिक होती है, विदेशी निर्भरता बढ़ती है, जबकि इसी लागत को घटाने के लिए इन कारखानों को लगाया जाता है। आत्मनिर्भरता की यह कोशिश विदेशी व्यापार को बढ़ाने से रोकते हैं। कई बार कोई देश किसी अन्य देश से दुश्मनी के कारण आयात नहीं करना चाहता, जिससे स्वतंत्र व्यापार नहीं हो पाता है — परिणामस्वरूप साधनों का उचित बँटवारा विश्वस्तर पर नहीं हो पाता है।

भारत में लौह खनिज झारखण्ड राज्य के सिंहभूमि जिले में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है — कोयला बंगाल तथा उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है जैसे — रानीगंज, झरिया, इत्यादि।

अगर स्टील मिले इनके बीच में लगाई जाती है और अन्य बातें समान रहती हैं, जैसे—मशीन की गुणवत्ता, कारीगरों की कुशलता, कार्य स्थल की विशेषता इत्यादि तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादन लागत काफी कम आती है। इसी प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन का आधार उसकी उत्पादन लागत होनी चाहिए।

पूरे विश्व स्तर पर साधनों के उचित आवंटन का आधार स्वतंत्र व्यापार ही हो सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु यदि स्वतंत्र रूप से देशों के बीच खरीदी व बेची जाएगी तो उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर वह न्यूनतम लागतों पर उत्पादित हो। इस प्रकार विश्व में उत्पादन में वृद्धि होती है। उपभोग एवं समाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। सम्पूर्ण विश्व छोटी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं में बँटा हुआ है जिन्हें हम राज्य कहते हैं। प्रत्येक राज्य एक संप्रभु संस्था है जो विशिष्ट भौगोलिक व्यापार का स्वामी होता है।

क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के दो प्रमुख रूप होते हैं :— मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सीमा संघ देश दोनों में कुछ देश मिलकर आपस में मुक्त व्यापार करते हैं। इस संगठन में शामिल सदस्य देश तथा अन्य देश गैर सदस्य देश होते हैं। सदस्य देश आपस में व्यापार प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन गैर सदस्य देशों पर प्रतिबंध (सीमा संघ में एक साथ तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र में अलग) लगाते हैं। जहाँ पर सदस्य देशों के बीच आपस में व्यापार बढ़ता है वही पर गैर सदस्य देशों से कम होता है। सदस्य देशों से प्राथमिकता के आधार पर व्यापार किया जाता है। व्यापार

सृजन प्रभाव धनात्मक तथा अपवर्जन प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि सृजन प्रभाव अपवर्जन प्रभाव से ज्यादा होता है, तो उक्त सगठन लाभदायक होता है, अन्यथा ये सगठन हानिकारक भी हो सकता है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र ऐसे देशों में लाभदायक होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं अथवा विकास के असमान स्तर पर होता है या औद्योगिक रूप में विकसित हो, ताकि प्रतियोगिता के कारण औद्योगिक और तकनीकी विकास बढ़ सके। आर्थिक शक्ति समान होने पर लाभों का उचित वितरण होता है। इसलिए यूरोपीय समुदाय सफल है लेकिन अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी और भारतीय उपमहाद्वीपीय सगठन सफल नहीं हो पा रहे हैं।

व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभ है — बाजार का विस्तार इस समय पूरा विश्व लगभग 200 छोटे-बड़े देशों में बँटा हुआ है। कुछ देश अत्यन्त ही छोटे हैं जहाँ पर आत्मनिर्भरता का प्रश्न ही नहीं है। मांग की कमी के कारण उस देश में बड़े प्रकार के उद्योग पनप ही नहीं पा रहे हैं। जापान जैसा विकसित राष्ट्र व्यापार के न होने पर आज विकसित नहीं हो पाता है जापान में जितने बड़े उद्योग लगे हैं ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में वे वहाँ पर पनप ही नहीं सकते थे, अगर जापान उन वस्तुओं का निर्यात न कर रहा होता, क्योंकि वहाँ पर मूल निवासियों की संख्या अत्यन्त कम है जिसके कारण बाजार संकुचित है और बाजार के अभाव में किसी वस्तु के बनाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जापान ने लोहे और स्टील के उद्योगों को विकसित किया है जबकि उसके वहाँ न तो लौह खनिज हैं न ही कोयला। वह दोनों का ही भारत और इंग्लैंड से आयात करता है। इसी प्रकार भारत में पर्याप्त मात्रा में तेल भंडार न होने पर भी तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं।

आसियान के गैर विकसित राष्ट्रों के सगठन की सफलता और जापान आदि जैसे देशों की इसमें शामिल होने की इच्छा और हाल ही में गठित किया गया उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार, सहकारिता इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में किसी देश को बिना किसी व्यापार गुट में शामिल हुए व्यापार करना निश्चित रूप से अलाभकारी हो सकता है। सगठन की शक्ति, सौदेबाजी की क्षमता तथा व्यापार प्रसार शक्ति के कारण भविष्य में व्यापार सगठन ही विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी कायम रख सकते हैं। अन्य देश इनमें शामिल हो सकते हैं या विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी में काफी कमी के शिकार हो सकते हैं। विश्व व्यापार में भारत का गिरता हिस्सा इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

व्यापार के माध्यम से बाजार का विस्तार होता है। बड़े पैमाने के उद्योग लगाये जाते हैं। श्रम विभाजन की संभावना बढ़ती है। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागतों में और कमी

आती है। व्यापार कम लागतो का परिणाम ही नहीं कारण भी है। इसके माध्यम से खोजे बढ़ती है, नई-नई खोजों का प्रसार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन उपभोग और सामाजिक कल्याण बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन होता है। इसके अभाव में जीवन स्तर में तथा उपभोग स्तर में गिरावट आती है। व्यापार के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि इसको प्रतिबन्धित होना चाहिए। जितना व्यापार प्रतिबन्धित होता है, उतनी ही व्यापार में कमी आती है और मानव समुदाय के लिए उतना ही जीवन अधिक कठिन हो जाता है।

मुक्त व्यापार विश्व स्तर पर कल्पनातीत है। मुक्त व्यापार के अभाव में संपूर्ण मानव समुदाय को भारी लागत चुकानी पड़ती है। विश्व इतने धड़ो, प्रजातियों, राजनैतिक व्यवस्थाओं में बट चुका है कि मुक्त व्यापार की संभावना नहीं के बराबर है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर अगर मुक्त व्यापार दो देशों के बीच (द्विपक्षीय) अथवा कुछ देशों के बीच (क्षेत्रीय व्यापार संगठन) होता है तो व्यापार जनित लाभों का कुछ सीमा तक फायदा उठाया जा सकता है। विश्व स्तर पर व्यापार को मुक्त नहीं किया जा सकता तो एक सीमित क्षेत्र में मुक्त व्यापार के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल देशों (छोटे-बड़े) की सफलता निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है। विश्व व्यापार में इनकी बढ़ती साझेदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन दोनों का आपसी व्यापार बढ़ा है।

“एशिया” प्रशांत व्यापार के विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्थाओं में समानता नहीं है। सफल देशों ने बृहत आर्थिक नितियों तथा कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करके निर्यात में वृद्धि की है। इससे बचत और निवेश की दरों में बढ़ोतरी हुई, सरकार एवं व्यापार में भागीदारी बढ़ी तथा विकास प्रक्रिया तेज हुई है। भारत कई स्तरों पर व्यापार एवं निवेश के प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। व्यापार ही अपने आप में इस प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है, बल्कि विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा मानव संशोधन विकास इसका उद्देश्य है, और इनकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। व्यापार बढ़ने से गरीबी और रोजगार तथा विकास के सामाजिक पक्षों से निटने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं।¹

व्यापारिक गुट तेजी से उभर कर अस्तित्व में आए हैं और अन्य गुटों के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। व्यापारिक गुटों में भी प्रतिस्पर्द्धा की भावना तेजी से बढ़ रही है।

¹ राष्ट्रीय सहारा, दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ, 31 मई, 1996, पृष्ठ-7

इसी आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा की कोख से यूरोपीय सघ, नाफ्टा, कोमेसा, ओपेक, आसियान, सार्क, सफ्टा इत्यादि व्यारिक एव आर्थिक गुट उभर कर सामने आये है।

1 यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार (EEC or ECM)

सम्पूर्ण विश्व मे यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनो विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लडे गए। दोनो विश्व युद्धो मे अधिकतम क्षति यूरोप को उठानी पडी। फिर भी आज यूरोप, आर्थिक राजनीतिक शक्ति के शिखर पर विद्यमान है। यूरोप मे राजनितिक और आर्थिक एकता के अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए है। यूरोप का इतिहास भारी उथल-पुथल का इतिहास रहा है। फिर भी यूरोप का इतिहास जहाँ एक तरफ एकीकरण और शक्ति के प्रयासो से भरपूर है वही पर दूसरी तरफ विघटन और शीत युद्ध भी यूरोपीय समुदाय के इतिहास का मुख्य आधार रहा है। 1928 मे ब्रा और फ्रासीसी राजनीतिक, अर्थशास्त्री ज्या मोने ने सबसे पहले एकीकृत यूरोप का विचार सबके समक्ष रखा। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद 1946 मे विन्सटन चर्चिल ने यूरोपीय एकता का आदोलन शुरू किया। 1947 मे पूर्वी यूरोप के एकीकरण की शुरुआत तब हुई जब सोवियत सघ, हंगरी, वल्गारिया, रूमानिया, पोलैड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, फ्रास और इटली के साम्यवादी प्रतिनिधि वरसा मे इकट्ठे हुए और एक कामिन्फार्म खोलने का निश्चय किया गया। 1958 मे क्षेत्रीय सहयोग के कई छोटे-मोटे प्रयास करने के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म हुआ। स्थापना के समय इसमे छ सदस्य थे — नीदरलैण्ड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रास, पश्चिमी जर्मनी तथा इटली। आर्थिक एव राजनीतिक कूटनीतिक के लिए इस सगठन का निर्माण किया गया। इस सस्था के माध्यम से 1962 मे एक साझा बाजार की स्थापना हुई। 1968 मे मुक्त व्यापार तथा समान व्यापारिक नीति को अपनाया गया। इस समय एक समान कृषि नीति की भी घोषणा की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय सगठन के चार प्रमुख घटक होते है —

- (क) न्याय सभा
- (ख) विकास परिषद
- (ग) महा सभा
- (घ) विकास आयोग

आधुनिक युग मे यूरोप आर्थिक समुदाय की विश्व व्यापार मे 21.8 प्रतिशत भागीदारी है जबकि सयुक्त राज्य अमेरिका 12.9 प्रतिशत तथा जापान 7.2 प्रतिशत के मुकाबले मे ज्यादा है। यूरोपीय समुदाय देशो की प्रति व्यक्ति आय तथा उपयोग का स्तर काफी ऊँचा रहा है। इस समय सबसे अधिक स्वर्ण भंडार 24 प्रतिशत यूरोपीय सुदाय के पास है। इन सभी देशो का

संपूर्ण घरेलू उत्पादन 5,110 मिलियन डालर है जो कि अमेरिका के संपूर्ण घरेलू उत्पाद से नहीं के बराबर कम है तथा शीघ्र ही इसकी अमेरिका से आगे निकल जाने की संभावना है। ये सब देश पूँजी प्रधान देश हैं तथा उद्योग एवं तकनीक दोनों ही व्यापार में काफी विकसित अवस्था में हैं। खासकर मशीनें तथा उपभोग की दर भी यहाँ पर तकनीकी विकास की दुनिया में बहुत ही आगे हैं। अर्ध विकसित देशों को खासकर एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ बहुत नजदीकी संबंध हैं, इसलिए आधिकांशतः एशियाई और अफ्रीकी देश इनके उपनिवेश के रूप में रह चुके हैं। आधुनिक युग में यह संगठन निश्चित रूप में सबके सामने बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आएगी।

वर्तमान युग में यूरोपीय समुदाय एक सीमा संधि है जबकि भविष्य में इसको आर्थिक संधि बनाने पर जोर दिया गया। मुक्त व्यापार संधि, सीमा संधि तथा आर्थिक संधि में मुख्यतः अंतर पाया जाता है।

- (क) **मुक्त व्यापार संधि** .— आपस में सदस्य देश मुक्त व्यापार अन्य देशों से अपनी-अपनी अलग व्यापार नीति के आधार पर व्यापार करते हैं।
- (ख) **सीमा संधि** — सदस्य देशों के मुक्त व्यापार, गैर सदस्यों से समान व्यापारिक नीति पर सभी देश बराबर प्रशुल्क दरों अथवा छूटों का इस्तेमाल अन्य सभी देशों के लिए किया जाता है।
- (ग) **आर्थिक संधि** .— सदस्य देशों की सभी आर्थिक नीतियाँ (औद्योगिक, मौद्रिक, व्यापारिक तथा राजकोषीय) एक ही प्रकार की होती हैं और एक साथ बनायी जाती हैं। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक हाथ में केन्द्रित होता है राजनीतिक व्यवस्था भले ही अलग-अलग इकाईयों पर होती है। उदाहरण स्वरूप रूस का गणराज्य रहा।

आर्थिक संधि की परिकल्पना तभी सफल हो सकती है जब किसी राष्ट्र के राजनयिक अपने नीतिनिर्धारक अधिकारों को किसी अन्य संस्था अथवा राष्ट्र के हाथ में सौंपने को तैयार होते हैं। प्रायः व्यवहार में ऐसा दुष्कर माना जाता है किन्तु यूरोपीय समुदाय इसे साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। 1 जनवरी 1994 को मौद्रिक संस्थान की स्थापना की गई जो इन देशों की नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सुझाव देता है। ताकि धीरे-धीरे इन देशों की नीतियाँ एक प्रकार की हो जाएँ और पूर्ण संधि की स्थापना करते समय किसी देश को गंभीर समस्याओं का सामना न करना पड़े। पहले ऐसे सदस्यों को ही आर्थिक संधि का सदस्य बनाना चाहिए जिस देश में —

(क) बजट तथा व्यापार घाटा दोनों कम हो।

(ख) मुद्रा स्फीति की दर कम हो।

धीरे-धीरे अन्य देशों में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। 1981 में भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच में एक नया व्यापार समझौता हुआ, जिसे व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग समझौता कहा जाता है। 1982 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत के अंदर वाणिज्य कार्यालय खोला। भारत के अत्यधिक अनुरोध करने पर 1987 में यूरोपीय समुदाय भारत के साथ औद्योगिक सहकारिता के विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा जिसके अंतर्गत दोनों विभिन्न औद्योगिक व्यापार में आपस में मिल-जुल कर कार्य करने के लिए एक सस्थागत कार्य क्षेत्र का निर्माण किया। निम्नलिखित छ क्षेत्रों में इस प्रकार का सहयोग व्यापार क्षेत्र स्थापित है—

- (1) वाणिज्य सूचना केन्द्र
- (II) वाणिज्य प्रबन्धक शैक्षिक केन्द्र
- (III) गुणवत्ता नियमन और नियंत्रण केन्द्र
- (IV) तकनीकी सूचना केन्द्र
- (V) ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र नागपुर (दिल्ली में भी एक शाखा है)
- (VI) टेलीकम्युनेकेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना केन्द्र

उपर्युक्त सभी सस्थाओं को भारत में औद्योगिक विकास की गति एवं गुणवत्ता नियंत्रण के विशिष्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है। तत्पश्चात् भारत से यूरोपीय समुदाय का व्यापार अपेक्षित मात्रा और लक्ष्य तक नहीं पहुँचा है। 1992-93 में भारत से यूरोपीय समुदाय को कुल निर्यात 32,351 करोड़ रुपये का हुआ था जो संपूर्ण निर्यात का 60.3 प्रतिशत है। कुल आयात 35,147 करोड़ रुपये का हुआ जो संपूर्ण आयात का 55.3 प्रतिशत है। इस व्यापार में भारत के निर्यात वृद्धि की अनंत संभावनाएँ मौजूद हैं।

आर्थिक नीतियों के अतिरिक्त यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब अन्य व्यापार में भी एकीकरण पर जोर दे रहा है। मास्ट्रिख संधि में जो अन्य एकीकरण के उपाय सुझाए गए हैं, ये निम्नलिखित हैं—

(A) प्रतिरक्षा एवं विदेश नीति

- (B) सामाजिक नीतियाँ
- (C) यूरोपीय ससद
- (D) राजनीतिक सघ

(A) प्रतिरक्षा एव विदेश नीति — इन सभी राष्ट्रों से व्यापारिक ही नहीं, गैर व्यापारिक (राजनीतिक, सामाजिक सुरक्षा सबधी) सबध भी एक ही तरह से होना चाहिए जिसमे सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हो। (अभी आधे राष्ट्र इस बात से सहमत नहीं हैं) तथा इन सभी देशों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। नाटो सधि पश्चिमी सुरक्षा सघ के साथ-साथ चलनी चाहिए या नाटो को ही पूर्ण सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया जाय। ब्रिटेन, इटली, हालैंड और पुर्तगाल नाटो को चलाने के पक्ष में हैं तथा बाकी सभी देश पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। अगर ये सुझाव लागू हो जाती है तो यूरोप में आंतरिक सीमाएँ समाप्त हो जाएगी।

1980 के आरम्भिक काल के दौरान में भारत ने उदारवादी नीतियों को अपनाया तथा 1980 से 1989 तक भारत सरकार ने काफी मात्रा में नीतिगत परिवर्तन किये। 1989-90 के दौरान बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल रही। 1991 में पुन भारत सरकार ने उन उठाए गए कदमों को ज्यादा मजबूती के साथ प्रारम्भ किया। इस समय भारत काफी हद तक बाजारी शक्तियों पर आधारित आर्थिक नीतियों में विश्वास करता है। नकारात्मक सूची मृतप्राय अवस्था में पहुँच चुका है, और रुपया पूर्ण परिवर्तनीय हो गया है। तटकर की दरों में गिरावट आई है। विदेशी पूँजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तथा निर्यात छूटों में गिरावट आई है, और चैनलबद्ध आयात निर्यात घट गया है। निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों में काफी बड़ी संख्या में भारत में धीरे-धीरे आ रही है। जिसके आने से भारत तथा यूरोपीय समुदाय के संबंधों में कोई अडचन प्रतीत नहीं होती है।

यूरोपीय समुदाय में कुछ नीतिगत परिवर्तन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अधिक सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाईं। यूरोपीय समुदाय ने 1975 में अफ्रीकी देशों को सर्वप्रिय राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को मिलने वाली प्राथमिकताएँ लगभग समाप्त हो गई हैं। 1975 में लोम अधिवेशन होने पर इसके अंतर्गत जो निर्णय लिए गए थे उन सभी का अर्द्धविकसित देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

साठ के दशक में भारत को यूरोपीय समुदाय की शक्ति न पहचान पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा, वहीं पर दूसरी तरफ सत्तर के दशक में परिस्थितिजन्य कारणों से भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। भारत साम्यवादी-समाजवादी घटकों के ज्यादा करीब रहा है और भारत की नीतियाँ काफी प्रतिबधित नीतियाँ रही, इसीलिए भारत को यूरोपीय समुदाय से अधिक लाभ की आशा करना व्यर्थ है।

(B) सामाजिक नीतियाँ — यूरोपीय संघ हर देश के नागरिकों को एक तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराने, अमीर-गरीब की दूरी को कम करने एक प्रकार की यूरोपीय नागरिकता, न्यूनतम आय सबधी कानूनों को बनाने इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए एक संघ की स्थापना करना चाहता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यूरोप एक देश हो सकता है और सभी राष्ट्र इसके प्रांत। यह संघीय ढांचा एक तरह से अमेरिकी संघीय ढांचे के रूप में हो सकता है।

(C) यूरोपीय संसद — समस्त देशों को मिलाकर 518 सदस्यों वाली एक संसद होनी चाहिए। इस संसद को राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सहयोग से यूरोपीय संघ के नीति निर्धारण का कार्य करना चाहिए। अभी तक ब्रिटेन और डेनमार्क इस सूझाव का विरोध कर रहे हैं।

(D) राजनीतिक संघ — यूरोपीय संघ आर्थिक ही नहीं राजनीतिक व्यापार में भी सभी देशों को मिलाकर कार्य करने की ओर अग्रसर करने के लिए एक राजनीतिक संघ की स्थापना करना चाहता है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक सुरक्षा, इत्यादि सभी पर एक ही कानून बनाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

1958-59 में इस समुदाय के बनने पर भारत ने उसे कोई महत्व नहीं दिया था। भारत इस समुदाय को नाटो संधि का राजनीतिक और सामाजिक संगठन मानता रहा है। जिस समय 1961 में ब्रिटेन इस समुदाय की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रार्थना किया उस समय भी भारत ने इसको इतना महत्व नहीं दिया था। भारत अपने पूंजीगत आयातों के लिए अन्य बाजार खोजता रहा। सौभाग्य से 1973 में ब्रिटेन इस समुदाय का सदस्य बन गया, उस समय भारत भी इस समुदाय के निकट आया और भारत तथा यूरोपीय समुदाय में व्यापार सबधी एक दीर्घकालीन समझौता हुआ, जिसको भारतीय यूरोपीय आर्थिक समुदाय का व्यापारिक सहयोग समझौता कहा जाता है। यह समझौता मुख्यतः दो उद्देश्यों के लिए किया गया है—

(A) उत्पादन वैविध्यीकरण

(B) व्यापार विस्तार

इस समझौते के अंतर्गत भारत से यूरोपीय समुदाय के व्यापार को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए सोचा गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से किया गया पहला व्यापार समझौता था। 1974 में भारत सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दिया, जिसमें मानव अधिकार का हनन हुआ और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिर गई। पेट्रोल का दाम बढ़ जाने से भारत के पेट्रोल का आयात बिल बढ़ गया तथा यूरोपीय समुदाय से पूँजी और उद्योग का आयात न बढ़ सका। और ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से भारत को तात्कालिक लाभ नहीं मिल पाया। 1981 में यूनान ने इसकी सदस्यता ग्रहण किया। 1986 में स्पेन तथा पुर्तगाल ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लिया। 1990 में पूर्वी जर्मनी के पश्चिमी जर्मनी में विलय हो जाने के बाद अपने आप पूर्वी जर्मनी इस समुदाय का सदस्य बन गया। 1 जनवरी, 1995 के पूर्व यूरोपीय समुदाय में 12 राष्ट्र थे। 1991 में मास्ट्रिच सम्मेलन में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के भविष्य को लेकर विचार किया गया तथा बारहों देश ने मिलकर मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए। इसको मास्ट्रिच संधि के नाम से जाना जाता है।

1 जनवरी, 1973 को ब्रिटेन, डेनमार्क व आयरलैंड को समुदाय की सदस्यता प्राप्त हो गई बाद में ग्रीस, स्पेन व पुर्तगाल को मिलाकर इस समुदाय की सदस्य संख्या 12 हो गई। 1 जनवरी, 1995 को आस्ट्रिया, फिनलैंड तथा स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए, अतः इसकी संख्या बढ़ कर 15 हो गई। आज यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है। पश्चिमी यूरोप में मजबूत आर्थिक शक्ति बनने के पश्चात् अब यूरोपीय संघ की पूर्वी यूरोप में विस्तार करने की योजना है। 12-13 दिसम्बर, 1997 को लक्जेंबर्ग में सम्पन्न हुए शिखर सम्मेलन में पूर्वी यूरोप के पाँच राष्ट्रों को यूरोपीय संघ में सन् 2000 से 2006 तक शामिल करने का प्रस्ताव किया गया, ये राष्ट्र हैं— चैक गणराज्य, पोलैंड, हंगरी, एस्टोनिया तथा स्लोवेनिया, इनके अतिरिक्त साइप्रस को भी संघ में शामिल करने के लिए आमन्त्रित करने को चुना गया है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। 1 जनवरी, 2001 से 15 सदस्यीय यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का दायित्व स्वीडन को 6 माह के लिए फ्रांस से प्राप्त हुआ है। 15 देशों का यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन 7-11 दिसम्बर, 2000 को फ्रांस में नाइस (NICE) में सम्पन्न हुआ। निकट भविष्य में यूरोपीय संघ के प्रस्तावित विस्तार के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मामलों में सरचनात्मक सुधार इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख विचारणीय मुद्दों में शामिल थे। इस सन्दर्भ में उन 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया जो संघ की सदस्यता प्राप्त करने के दावेदार हैं। इनमें टर्की, साइप्रस व माल्टा के अतिरिक्त पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र भी शामिल हैं। 7 दिसम्बर, 2000 को शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन, सदस्य राष्ट्रों ने मौलिक अधिकारों के यूरोपीय

चार्टर (European Charter of Fundamental Rights) को स्वीकार किया। सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी न होने के कारण इसका कोई तात्कालिक प्रभाव होने की सम्भावना नहीं है। सम्मलेन में एक यूरोपीयन रैपिड एक्शन फोर्स के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया।

उल्लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत यूरोपीय सघ में आयुक्तों (मन्त्रीयों) की कुल संख्या 20 होती है, तथा छोटे-बड़े सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा कम से कम एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, इटली व ब्रिटेन द्वारा 2-2 आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। जनवरी 2003 से नए सदस्य का प्रवेश आरम्भ होने के पश्चात् सन् 2004 या 2005 तक यूरोपीय सघ की सदस्यता संभवतः 27 हो जाएगी। उस स्थिति में सघ के 20 आयुक्तों (मन्त्री) का मनोनयन व सदस्य राष्ट्रों में मताधिकार (Voting Right) का वितरण किन फार्मूला से हो तथा भावी यूरोपीय पार्लियामेंट का आकार व संरचना क्या हो, आदि मुद्दे इस सम्मेलन में विचार के प्रमुख मुद्दे थे। इन मामलों में सघ के मौजूदा सदस्य राष्ट्रों में से किसी को भी अपना कोटा कम करने हेतु तैयार न होने के कारण परिचर्चा तीन दिन की जगह पाँच दिन तक चली।

मौजूदा व्यवस्था के तहत यूरोपीय सघ के कुल 82 मतों में से चार बड़े राष्ट्रों के पास 10-10 मत हैं, जबकि लक्जेंबर्ग के पास मतों की संख्या 3 ही है। सघ की क्वालिफाइड मैजोरिटी वोटिंग (Qualified Majority Voting) की व्यवस्था के तहत कोई भी नया नियम बनाने के लिए कम से कम 67 मतों का समर्थन आवश्यक होता है, किन्तु राष्ट्रीय महत्व के 20 प्रतिशत मुद्दों पर निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाता है, करारोपण, सुरक्षा, परिवहन, बजटीय परिवर्तन व सन्धि में संशोधन जैसे राष्ट्रीय महत्व के इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीटो का अधिकार सभी सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त है। मताधिकार के बँटवारे व यूरोपीय आयुक्तों की नियुक्ति के मामलों पर लम्बी कशमकश के बाद अन्ततः 1 दिसम्बर, 2000 को इन मामलों पर सन्धि हो सकी, जबकि पूर्व में सम्मेलन 9 दिसम्बर, 2000 तक के लिए निर्धारित था। 'नाइस सन्धि' (Nice Treaty) नाम की इस सन्धि के विस्तृत यूरोपीय सघ में चार बड़े राष्ट्रों (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन व इटली), विशेषतः जर्मनी की स्थिति और मजबूत होगी, जबकि बेल्जियम, पुर्तगाल, लक्जेंबर्ग व आस्ट्रिया जैसे छोटे राष्ट्रों की शक्ति सघ में अपेक्षाकृत कम हो जाएगी।

'नाइस सन्धि' के तहत यूरोपीय सघ के राष्ट्र इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि जनवरी 2003 के बाद नए सदस्यों के शामिल होने के साथ यूरोपीय संसद की सदस्य संख्या 626 के मौजूदा स्तर से क्रमशः बढ़ती जाएगी तथा यह अन्ततः 728 तक हो सकेगी। विस्तृत यूरोपीय संसद में जर्मन के यूरो सांसदों (Euro MPs) की संख्या पूर्वतः 99 ही बनी रहेगी,

जबकि फ्रांस, इटली व ब्रिटेन की सीटों की संख्या 87-87 से घटकर 72-72 ही रह जाएगी। संसद में स्पेन की सीटें भी 64 से घटकर 50 रह जाएगी, जबकि पोलैण्ड व नीदरलैंड्स की सीटें भी 50-50 रह जाएगी।

यूरोपीय संघ में कुल मतों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ मत संरचना में परिवर्तन का निर्णय भी शिखर सम्मेलन में लिया गया है। नाइस संधि के अनुसार विस्तृत यूरोपीय संघ में चारों बड़े राष्ट्रों के मतों की संख्या 10-10 से बढ़कर 29-29 हो जाएगी, जबकि स्पेन के मतों की संख्या 8 से बढ़कर 27 होगी। नई मत संरचना में नीदरलैंड्स के मतों की संख्या 13 तथा ग्रीस, हंगरी, पुर्तगाल व बेल्जियम के मतों की संख्या 12-12 होगी।

अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार के लिए 15 सदस्यीय यूरोपीय संघ (EU) का एक दिवसीय आपात शिखर सम्मेलन 19 अक्टूबर, 2001 को बेल्जियम में घेंट (Ghent) में सम्पन्न हुआ। अफगानिस्तान में की जा रही अमरीकी कार्यवाही का पूर्ण समर्थन प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से इस सम्मेलन में लिया गया।

2. आसियान :-

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के बाद पूरे विश्व में उथल-पुथल मच गई। पूरा विश्व दो दल साम्यवाद तथा पूंजीवाद में बँट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ही दक्षिण-पूर्व एशिया के पूरे समुचे व्यापार को अपने प्रभाव में शामिल कराने के लिए उत्सुक रहे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आखड़े में दक्षिण पूर्व एशिया का समूचा व्यापार दोनों महाशक्तियों का केन्द्र बिन्दु बना रहा। व्यापार जाहाँ एक तरफ प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण था वहीं पर दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर तथा दक्षिण दो राज्यों में वियतनाम का विभाजन होने से लाओस, बर्मा, कंबोडिया आदि देशों में उग्रवादी एवं लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच संघर्ष तथा महाशक्तियों द्वारा अपनी नीतियाँ जबरजस्ती थोपने से व्याकुल होकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के नये स्वतंत्र राष्ट्रों ने आपस में संगठित होने का निश्चय किया।

इन सभी देशों के आर्थिक विकास की अदम्य महत्वकांक्षा ने इनके भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं के होने के बावजूद आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की प्रेरणा प्रदान किया और अंत में 1967 में इन सभी देशों ने एक अलग गुट बनाने की घोषणा करके संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरू में प्रत्येक राष्ट्र इस संगठन की सफलता को सदिग्ध रूप में देख रहे थे, लेकिन 29 वर्षों के बाद आज यह संगठन पूरी सफलता के साथ आगे की

और बढ़ रहा है। इन सभी राष्ट्रों की अलग-अलग तथा एक साथ दोनों ही तरह से आर्थिक विकास दर अन्य सभी दक्षिण एशिया के देशों से काफी ज्यादा है। इस सगठन की सफलता को देखते हुए आज एशिया का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र जापान भी इसके साथ सहयोग कर रहा है, और इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है।

आसियान एक व्यापार सगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 में थाइलैंड राष्ट्र के बैंकाक शहर में यह समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते पर ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स और थाइलैंड देशों ने हस्ताक्षर किए। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सभी राष्ट्र एक दूसरे के बहुत करीब लेकिन आर्थिक शक्ति, जनसंख्या, राजनीतिक व्यवस्था, और औद्योगिक विकास की दृष्टिकोण से काफी अलग हैं। इन देशों के बीच में जो आर्थिक समानता रही है, वह अल्प विकास, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग का स्तर के रूप में रही।

आयोजन समिति — इस बैठक को प्रायः दो महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। साधारणतया इसमें आयोजनकर्ता देश का विदेश मंत्री तथा अन्य देशों के राजदूत शामिल होते जाते हैं। कभी-कभी विदेश मंत्री के स्थान पर वित्तमंत्री शामिल हो जाते हैं। प्रत्येक देश में साल में एक बैठक आयोजित किया जाता है। सचिवालय से कोई मुद्दा उठाए जाने के बाद इस बैठक को उस पर विचार करने के लिए बुलाई जाती है।

सगठन — आसियान सगठन का संचालन कई उच्चस्तरीय बैठकों, सभाओं और सचिवालयों के माध्यम से किया जाता है।

मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन — आसियान के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक प्रतिवर्ष बुलाई जाती है। प्रत्येक देश इस सभा का आयोजन करता है। विदेश मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्रियों की बैठक भी प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। विदेश मंत्रियों की बैठक नीति से संबंधित निर्णय लेने के लिए और सामान्य सदभाव के कारण बुलाई जाती है। वित्तमंत्री आपस में मिलकर आसियान के दिशा-निर्देश को तय करते हैं। मन्त्रीस्तरीय बैठक उन निर्णयों पर विचार करती है, जो अन्य सहायक समितियाँ इनके सामने प्रस्तुत करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जाती है। अगर कोई मुद्दा नहीं है, तो इस बैठक को सदभाव के लिए ही आयोजित किया जाता है।

शीर्ष सभा — अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इस बैठक को बुलाया जाता है। सभी देशों के सदस्य राष्ट्रध्यक्ष इस बैठक में भाग लेते हैं। इसकी बैठक समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाती

है। फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली शहर में इसकी प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। उसके तुरंत बाद शीघ्र ही अगस्त 1977 में मलेशिया की राजधानी क्वालामपुर में दूसरी बैठक सम्पन्न हुई। दस वर्ष के बाद दिसम्बर 1987 में फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में तीसरी बैठक सम्पन्न हुई। सामान्य तौर पर यह बैठक किसी विशेष अवसर पर ही बुलाई जाती है। सामान्य कामकाज करने के लिए मंत्रीस्तरीय बैठक ही शक्ति सम्पन्न होता है।

सलाहकार समितियाँ — आर्थिक सहकारिता की दृष्टिकोण से आसियान ने पाँच सलाहकार समितियों का निर्माण किया है—

- (1) मुद्रा एवं बैंकिंग समिति।
- (2) कृषि, खाद्यान्न एवं वन्य संपत्ति समिति।
- (3) खनिज, धातु एवं ऊर्जा समिति।
- (4) परिवहन एवं संचार समिति।
- (5) व्यापार एवं पर्यटन समिति।

इसके तीन अतिरिक्त उप समितियाँ हैं—

- (A) संस्कृति एवं सूचना समिति।
- (B) विज्ञान एवं तकनीकी समिति।
- (C) सामाजिक विकास समिति।

उपरोक्त सभी समितियाँ अपने व्यापारों में सहयोग एवं सहकारिता के विभिन्न उपायों पर विचार एवं शोध कार्य करती हैं। सहायक संस्थाओं, संगठनों और कार्य समूहों द्वारा इन समितियों की मदद की जाती है। जब ये समितियाँ किसी निर्णय पर पहुँच जाती हैं, उसके बाद सचिवालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। बाद में उन निर्णयों पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

आसियान समूह ने विदेशों से अपने संबंधों में सद्भाव एवं व्यापार बढ़ाने के लिए 10 विदेशी राजधानियों आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना कार्यालय खोल रखा है। आसियान द्वारा इन कार्यालयों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं जो हमेशा इन देशों और संगठनों से संपर्क बनाए रखते हैं जिसे हम आसियान का प्रवक्ता कहते हैं।

सचिवालय — 1976 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्य स्थाई सचिवालय स्थापित किया गया। इस सचिवालय का प्रमुख कार्य समन्वय एवं सहयोग करना है। प्रत्येक राष्ट्र की राजधानी में अलग-अलग सचिवालय हैं, जो समय-समय पर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिवालय को भेजते हैं। मुख्य सचिवालय सभी रिपोर्टों को क्रमबद्ध करके उचित कार्यवाही करने हेतु आयोजन समिति को भेजती है। इस सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता है। प्रमुख सचिव के चयन के लिए अंग्रेजी वर्णाक्षरों के आधार पर देशों के नामों को रखा जाता है। प्रत्येक देश क्रमशः अपने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करता है जो तीन वर्ष तक इस सचिवालय को देखता है।

बैंकाक समझौते के प्रमुख उद्देश्य —

- (A) व्यापारिक शांति, स्थिरता को कायम रखने का हर संभव प्रयत्न करना। इसका आधार कानून का राज्य है। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र का समुचित आदर करते हुए न्यायपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना।
- (B) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यापारों में सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रदान करके विकास की ओर अग्रसर होना।
- (C) कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में नई तकनीकों का आदान-प्रदान करना। व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाना। परिवहन तथा संचार साधनों के विकास के साथ-साथ अपनी आपसी संबंधों को बढ़ाना। आर्थिक हस्तान्तरणों तथा सहयोग को बढ़ावा देना जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर और उपभोग स्तर में वृद्धि हो सके।
- (D) इस व्यापार (दक्षिण पूर्व एशिया) में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना। इन सभी के लिए सदस्य राष्ट्रों को मिलजुलकर समानता और संप्रभुता अक्षुण्ण रखते हुए कार्य करना।
- (E) अन्य देशों तथा संगठनों के साथ जो विश्व में शांति, न्याय व्यवस्था तथा आर्थिक विकास में विश्वास रखते हैं, उनके संबंधों में लगातार वृद्धि किया जाना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त राजनीतिक संगठन होने के कारण आसियान में कुछ सैन्य समझौता किया गया। 1967 में आसियान की प्रथम शीर्ष बैठक सपन्न हुई। इसके बाद आम सहमति के आधार पर तीन विशिष्ट क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए।

- (1) शांति और सहकारिता — इसके अतर्गत एक ऐसा अनुच्छेद बनाया गया जिनमें एक दूसरे की स्वतंत्रता और संप्रभुता कायम रखना, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सभी विवादों का निपटारा करना और एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वायदा सभी पाँच राष्ट्रों ने किया।
- (2) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यापारों में विशिष्ट कार्यक्रम — इन सब की सदस्यता के लिए पालन करना एक अनिवार्य शर्त है, राजनीतिक स्थिरता, शांति व्यापार की स्थापना, सामाजिक न्याय, और जीवन स्तर में सुधार के आवश्यक उपाय प्रत्येक राष्ट्र को मानना अनिवार्य है। प्राकृतिक विपदाओं के समय आवश्यक सहयोग, आर्थिक विकास करने हेतु ससाधन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता सबंधी निर्देश देना।
- (3) व्यापारिक सहयोग :— सभी सदस्य देश आपस में एक दूसरे को विशिष्ट प्राथमिकताएँ प्रदान करते हैं, जिसके अतर्गत 1976 में 71 वस्तुओं का चुनाव किया गया जिनमें एक दूसरे को तटकर की विशेष छूट प्रदान की गई। 1 जनवरी 1978 को वस्तुओं और तटकर की दरों के बारे में वास्तविक निर्णय लिए गए, उसके फलस्वरूप इस प्रकार की वस्तुओं की सूची निरंतर बढ़ रही है जिसके अतर्गत आपसी व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से तटकरों तथा अन्य व्यापार प्रतिबंधों पर विशेष छूट प्रदान करते हैं। 1992 से लगभग 10,000 वस्तुएँ इस प्रकार की रही जिसमें सभी देश आपस में 20 से 30% तक तटकर पर छूटे प्रदान कर रहे हैं। आसियान देशों के आंतरिक व्यापार के केवल 50% व्यापार को ही तटकर छूटे हासिल हैं। इन देशों की आयात-निर्यात व्यापार की अधिकांशतः मुख्य वस्तुएँ 'अपवर्जन सूची' के अतर्गत आती हैं। दिसम्बर 1987 में एक शीर्ष सम्मेलन में यह पारित किया गया कि अपवर्जन सूची के अतर्गत कुल निर्यात वस्तुओं के 10% से अधिक पर 50% मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। सूची में कमी लाने के लिए इंडोनेशिया और फिलीपीन्स को सात वर्ष तथा अन्य देशों को पाँच वर्ष का समय दिया गया।

मनीला में अगस्त 1986 में आसियान देशों के आर्थिक सलाहकारों एवं वित्त मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड तथा फिलीपीन्स ने इसका कड़ा विरोध किया जिसके दो प्रमुख कारण रहे—

- (1) ये सभी देश एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करते हैं।

(2) इनकी तटकर दरो में काफी अतर है।

सिंगापुर और ब्रूनेई में तटकर नगण्य है जो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों के बीच की स्थिति में है। थाईलैंड और फिलीपीन्स के लिए शुरू के वर्षों में ऐसी परिस्थिति में तटकरों को समाप्त करना काफी घातक है जो इस प्रकार से इन देशों में आंतरिक व्यापार बढ़ा सकता है लेकिन सिंगापुर और ब्रूनेई दोनों के निर्यात काफी मात्रा में बढ़ सकता है, वहीं इनके आयातों के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि फिलीपीन्स और थाईलैंड के लिए इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें उनके आयात बढ़ सकते हैं तथा निर्यात स्थिर रह सकते हैं। मलेशिया एवं इंडोनेशिया को भी अधिक लाभ होने की आशा नहीं रही, इसी कारण से आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने की संभावना नहीं है।

इनका आंतरिक व्यापार इनके विश्व व्यापार का 10% से भी कम है। वास्तव में ये सारे देश एक ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, न कि पूरक वस्तुओं का। इनका मुख्य उद्देश्य संगठित होकर सौदेबाजी में अपनी शक्ति बढ़ाना है भविष्य में इसको आर्थिक गुट के रूप में ही कार्य करते रहने की संभावना है।

आसियान के अन्य अवयव

कृषि व्यापार — 1981 में शोध प्रशिक्षण तथा व्यापार के मुख्य उद्देश्य को लेकर आसियान ने कृषि विकास एवं आयोजन केन्द्र की स्थापना की है। अक्टूबर 1983 में एक मत्स्य निगम की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, तथा आसियान वानिकी कॉंग्रेस की स्थापना भी अक्टूबर 1983 में ही की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य वन संरक्षण तथा इमारती लकड़ी के निर्यात प्रोत्साहन करना है। 1988 में आसियान ने वित्त के क्षेत्र में भी एक इन्श्योरेन्स निगम की स्थापना की। 1983 में ऊर्जा सिकट को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा सहकारिता के संदर्भ में एक समिति गठित की जिसके अंतर्गत कोयला विकास, पेट्रोल का बटवारा और 9 सहकारी पेट्रोल शोधन परियोजनाओं पर कार्य किया गया तथा आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर आपस में पेट्रोल बॉटने पर आम सहमति हुई। तकनीकी शोध, शिक्षा, सामाजिक विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के संबंध में आसियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आसियान संस्था नियमित रूप से निम्न प्रकाशन करती है —

- (1) विभिन्न सूचनाएँ समय-समय पर।
- (2) आयोजन समिति की वार्षिक रिपोर्ट।
- (3) आसियान समाचार-पत्र (द्वैमासिक)।

(4) विज्ञान और तकनीकी जनरल (वर्ष में दो बार)।

वर्तमान में आसियान – 23-24 जुलाई 1993 को आसियान की 26 वीं द्विदिवसीय मंत्रीस्तरीय बैठक में आसियान देशों की विदेश व्यापार बढ़ाए जाने के लिए काफी निर्णय लिया गया। आसियान देशों को यह पूर्ण विश्वास है कि अगर चीन से उचित व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का व्यापार 1 से 15% तक बढ़ जाने की संभावना है। भारत के साथ विचार-विमर्श की जो एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है, वह न केवल आसियान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आसियान के अन्य देशों से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसके लिए भी प्रेरणादायक है। आसियान देशों ने अन्य व्यापारिक सहयोगियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जिनमें जापान, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने अपनी व्यापारिक नीति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि वह दुनिया के प्रत्येक देश से आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंधों को बढ़ाना पसंद करते हैं लेकिन उनका पूर्ण विश्वास है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है और आसियान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्व प्रदान कर सकता है।

आसियान व्यापारिक फोरम – 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित आसियान की कुल जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है, जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार है। प्रशांत और हिंद महासागर के संधि स्थल पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष महत्व का है।

आसियान व्यापारिक फोरम औपचारिक रूप से 24 जुलाई 1997 को बैंकाक में कायम किया गया जिसमें आसियान के 6 सदस्य देश ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ सलाहकार और परामर्श साझीदार के रूप में अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय समुदाय, जापान तथा दक्षिण कोरिया सम्मिलित हुए। 28 जुलाई 1995 को आसियान ने वियतनाम को भी अपनी सदस्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या 7 हो गई है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के शेष तीन देशों— कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार को शामिल करने की योजना है।¹ प्रत्येक सदस्य देश

¹ क्रानिकल, मई 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, 208 शिवलोक हाउस-1, नई दिल्ली-110015 पृष्ठ 102

की राजधानी में एक राष्ट्रीय आसियान सचिवालय होता है, जिसका प्रमुख एक सचिव होता है तथा आसियान का केन्द्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है।

भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण इस व्यापार का आर्थिक सगठन तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आसियान के देशों का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 15 दिसम्बर 1995 को थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में सपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने 'मुक्त व्यापार' की स्थापना में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। मुक्त व्यापार की स्थापना के लिए सन् 2003 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आसियान देश चाहते हैं कि इसकी शुरुआत निर्धारित वर्ष से पहले ही हो जाए। मुक्त व्यापार की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 1992 में रखा गया। उस समय आसियान ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 15 वर्ष का समय रखा था, लेकिन भारत एवं चीन के तरह तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था तथा दूसरे व्यापार गुटों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए लक्ष्य में कटौती कर दी गई। बैंकाक घोषणा के अनुसार मुक्त व्यापार की स्थापना की दिशा में पहले कदम के रूप में 1 जनवरी 1996 तक और गैर-व्यापारिक अवरोध हटा दिया गये।

आसियान का सदस्य देश सिंगापुर तो विश्व के विकसित देशों में सम्मिलित हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों का भी इस सगठन के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। भारत भी इसी श्रेणी में आता है वह आसियान की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। हाल ही में आसियान द्वारा भारत को आसियान के सम्मेलनों एवं बैठकों में पूर्ण वार्ता सहभागी बनाए जाने की घोषणा से इस दिशा में एक उपयुक्त कदम कहा जा सकता है। आसियान के साथ भारत का सहयोग सबंध कायम हो जाने से दोनों पक्ष एक-दूसरे के विभिन्न क्षेत्र एवं उद्योग व्यापार के अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं तथा साथ ही आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व्यापार में परस्पर सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। एक तरफ भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, वहीं पर दूसरी तरफ आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते पारस्परिक सहयोग में वृद्धि भी हो सकती है।¹

फरवरी 1976 में बाली सभा में भारत ने आसियान के प्रस्तावों (शांति व्यापार, स्वतंत्रता तथा हस्तक्षेपरहित संप्रभुता, समता) का न केवल स्वागत किया है बल्कि उसे पूरा करने का वायदा भी किया है। सितम्बर 1983 में आसियान देशों की कम्पूचिया स्वतंत्रता अपील पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र-संघ में आसियान देशों का साथ दिया।

¹ कानिकल, मार्च 1996 कानिकल पब्लिकेशन प्रा० लि०, 208 शिवलोक हाउस-1, नई दिल्ली-110015 पृष्ठ- 11।

वर्तमान समय में भारत आसियान की सदस्यता ग्रहण करने के लिए काफी उत्सुक है, लेकिन निकट भविष्य में भारत की इच्छा पूर्ति हो पाएगी, ऐसा नहीं लगता। हाल ही में आसियान के सदस्य देशों द्वारा लिए गए एक निर्णय को इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम माना जा सकता है कि भारत को आसियान के सम्मेलनों एवं बैठकों में पूर्ण-वार्ता सहभागी बनाया गया। भारत के लिए आसियान की सदस्यता आर्थिक एवं सामरिक दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री सीमा मलक्का जल डमरूमध्य तक फैला है, जिसे पश्चिम और पूर्वी एशिया की आर्थिक शक्तियों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि) के बीच व्यापार की जीवन रेखा कहा जा सकता है। आसियान के सदस्य देशों ने आर्थिक व्यापार में काफी प्रगति की है। इनमें से सिंगापुर तो अब विश्व के विकसित देशों में शामिल हो गया है। भारत का आसियान के लगभग सभी देशों के साथ अच्छा व्यवहारिक और मैत्री संबंध है तथा इनमें से कुछ देशों ने भारत में अपने संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद से थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में वृद्धि भी की है।

मशीनरी तथा यातायात उपकरणों का आयात आसियान के देशों में कुल आयात का 32 प्रतिशत भाग पूरा करता है तथा भारत में यह मात्र 14 प्रतिशत है। इधर कुछ वर्षों में भारत में इस क्षेत्र के आयात में कमी आई है। आसियान के देश इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य सदस्य देश मशीनरी तथा यातायात उपकरणों का निर्यात भी भारत से अधिक करते हैं। भारत को ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में आसियान के देशों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भारत की दृष्टि से यह सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है।

आसियान के देशों से सहयोग स्थापित करने के लिए भारत को निम्नलिखित दिशाओं में प्रयास करना चाहिए—

- (1) औद्योगिक मजदूरी की दर आसियान के देशों में भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह भारत को आसियान के देशों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है।
- (2) सबसे पहले मुद्रास्फीति पर भारत को नियंत्रण रखना चाहिए। 1980 से 1993 के बीच भारत में मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 87 प्रतिशत के करीब रही है आसियान के देशों की मुद्रास्फीति 22 तथा 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना में यह बहुत अधिक है। मूल्य में स्थायित्व तथा कम मुद्रास्फीति निर्यातकों को आगे पहुँचा देता है।

- (3) अतः सरचना सुविधाओं के क्षेत्र में भी भारत आसियान के देशों की तुलना में बहुत पीछे है। बिजली, यातायात तथा दूरसंचार के व्यापार में भारत आसियान के देशों की तुलना में पीछे है। 1992 में भारत में दूरभाष की सुविधा प्रति हजार 8 व्यक्ति को उपलब्ध थी, जबकि ये सुविधा सिंगापुर प्रति हजार 415 व्यक्ति, मलेशिया में प्रति हजार 112 व्यक्ति तथा थाईलैंड में 31 था। किन्तु अब भारत में भी इसका प्रतिशत तेजी से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

भारत में सीमा शुल्क संबंधी प्रतिबंध भी आसियान देशों की तुलना में अधिक हैं। इसके अतिरिक्त भारत को व्यापार संबंधी जटिलताओं को भी कम करना चाहिए। आसियान के साथ भारत का सहयोग संबंध कायम होने से इन देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग का जहाँ मार्ग प्रशस्त हो सकता है, वही दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के साथ उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में अपने अनुभवों के आदान प्रदान से लाभान्वित भी हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत को उसके अत्यंत समीप दक्षिण-पूर्व एशिया में एक उन्नत विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, जहाँ पर निश्चित ही भारतीय उत्पादों की पर्याप्त माँग हो सकती है।

वर्तमान में सदस्य देशों ने भारत को आसियान के साथ औपचारिक बात-चीत के भागीदार बनने पर बल दिया है। जो पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए समूह के सदस्य बनने में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यापार विस्तार की दृष्टिकोण से आसियान की सदस्यता प्राप्त करना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे एक दशक से दक्षिण पूर्व एशिया की वृद्धि दर दो अंकों में रही है तथा अगले शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व व्यापार में आधा भागीदारी इन देशों की हो जाने की संभावना है। "भारत आकार में किसी भी एशियाई देश से बड़ा है लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय इन देशों की तुलना में बहुत ही कम है। आसियान के सर्वाधिक धनी देश सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय 19,850 अमेरिकी डालर है जो भारत की प्रति व्यक्ति आय 300 अमेरिकी डालर से छियासठ गुना अधिक है। अगर फिलीपीन्स को अपवाद में रखा जाता है तो भारत में जी० डी० पी० की वृद्धि दर भी आसियान देशों की तुलना में बहुत कम है।¹ आसियान देशों की तुलना में भारत कम औद्योगिकीकृत देश है।

¹ प्रतियोगिता सम्राट—नवम्बर 1995, दीवान पब्लिकेशन प्रा० लि०, कामर्शियल कामप्लेक्स, नई दिल्ली—110015, पृष्ठ 29।

आसियान देशों को बाह्य व्यापार से अधिक आय होता है। वर्ष 1993 में सिंगापुर में जी0 डी0 पी0 का 169 प्रतिशत भाग निर्यात द्वारा पूरा किया गया, जबकि भारत का वर्ष 1993 में मात्र 11 प्रतिशत ही रहा।

ज्ञातव्य है कि आसियान ने 23 जुलाई, 1996 को भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्रदान कर दिया। भारत के साथ-साथ चीन और रूस को भी आसियान के क्षेत्रीय मंच में पूर्ण वार्ताकार सहभागी का दर्जा प्रदान किया गया। अमेरिका को पहले से ही यह दर्जा प्राप्त है। भौगोलिक स्थिति में अन्तर के कारण भारत को आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया जा सकता, भारत दक्षिण एशिया में स्थित राष्ट्र है, जबकि आसियान दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र को परमाणु हथियार रहित क्षेत्र बनाने सम्बन्धी ASEAN राष्ट्रों की दिसम्बर 1995 में सम्पन्न संधि को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से 'दक्षिण-पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित जोन' (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone-SEANWFZ) आयोग का गठन 24 जुलाई, 1999 को सिंगापुर में किया गया तथा सिंगापुर को ही पहला अध्यक्ष बनाया गया।

दक्षिण-पूर्व एशिया परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र (SEANWFZ) संधि में शामिल राष्ट्र अग्रलिखित कार्य न करने के लिए वचनबद्ध हैं।

- (1) परमाणु शस्त्रों का विकास, निर्माण व किसी भी अन्य तरीके से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास,
- (2) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में परमाणु शस्त्र की तैनाती तथा इनका परिवहन,
- (3) परमाणु शस्त्रों का परीक्षण अथवा इनका इस्तेमाल,

10 सदस्यीय आसियान अभी तक तीन गैर-आसियान सदस्यों (चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान) के साथ ही नियमित शिखर बैठक करता है। आसियान के साथ शिखर बैठक में सम्मिलित होने को भारत लगातार प्रयासरत रहा है, किन्तु इसमें वांछित सफलता उसे अब ही प्राप्त हो सकी है। ब्रुनेई में बादर सेरी बेगावान (Bandar Seri Begawan) में नवम्बर 2001 में सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत भारत व आसियान की शिखर बैठक 'आसियान +1' के प्रारूप पर होगी। 'आसियान +3' (आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र + चीन, द कोरिया व जापान) को 'आसियान +4' में बदलने का निर्णय इसमें नहीं लिया गया है।

इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि 'आसियान +3' पूर्वी एशिया उन्मुखी है।

उल्लेखनीय है कि भारत अभी तक आसियान का वार्ता भागीदार (Dialogue Partner) होने के साथ-साथ 'आसियान रीजनल फोरम' (ARF) का सदस्य रहा है। भारत के साथ आसियान के सम्बन्धों को यही तक सीमित रखने का मलेशिया पक्षधर रहा है तथा मलेशियाई विरोध के चलते ही आसियान +4 के विचार को सगठन के सिंगापुर शिखर सम्मेलन में अस्वीकार कर दिया गया था। मलेशिया ने अब बादर सेरी बेगावान में आसियान +1 के विचार का समर्थन किया है।

11 सितम्बर, 2001 की घटना के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद का मुद्दा इस शिखर सम्मेलन में भी छाया रहा, किन्तु आतंकवाद को किसी भी धर्म या जाति से जोड़ने के प्रयासों की कड़ी निन्दा इसमें की गई। अफगानिस्तान में अमरीकी सैन्य कार्यवाही के मामले में एक ओर इण्डोनेशिया व मलेशिया जैसे राष्ट्रों (जो अमरीकी कार्यवाही के विरोधी रहे हैं) तथा दूसरी ओर फिलीपींस व थाइलैण्ड जैसे राष्ट्रों (जो अमरीकी कार्यवाही के समर्थक रहे हैं) की मौजूदगी के कारण इसका कोई उल्लेख घोषणा-पत्र में नहीं किया गया, किन्तु हाल ही के 'ऐपेक घोषणा-पत्र' की तर्ज पर सभी प्रकार के आतंकवाद की घोर निन्दा इसमें की गई। सभी प्रकार के आतंकवाद की निन्दा करते हुए इसे विश्व शान्ति व स्थिरता के लिए गम्भीर खतरा इसमें बताया गया है तथा इसके विरुद्ध कड़े कदमों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

3. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस अर्थात् सार्क) :-

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सगठन आसियान जब 80 के दशक के दौरान सफलता की ओर अग्रसर होने लगा, तब एशिया के देशों में भी इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि अगर एशिया के सभी देश सगठित होकर विश्व के आर्थिक समुदाय में उभर जाए तो उनका महत्त्व और लाभ दोनों बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के मुख्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 55 वर्ष पूर्व एक ही देश के अभिन्न अंग रहे हैं। ये व्यापारिक, भौगोलिक रूप से ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी आपस में बहुत करीब हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका इत्यादि इन देशों की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाएँ एक ही हैं, और प्राचीन विशाल भारत से इनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ रहा है। एक देश से दूसरे देश के बीच नागरिकों का आवागमन

उसी प्रकार रहता है जैसे— एक राष्ट्र के प्रांतों में होता है। नेपाल को छोड़कर सभी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। (नेपाल सदैव संप्रभु स्वतंत्र देश रहा है।)

विश्व की आबादी का चौथाई (23.2%) भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र एक बहुत बड़ा बाजार है। खनिज एवं कृषि व्यापार की दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जूट और चाय के क्षेत्र में विश्व निर्यात में इस व्यापार का हिस्सा 97% और 91% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के 33% भू-भाग पर स्थित है। जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से यहाँ पर विश्व के औसत की दुगुनी जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी नीचे है तथा यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीकी देशों के मुकाबले कम है।

आर्थिक विकास की अनन्त सभावनाएँ इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने अगस्त 1981 में एक व्यापारिक गुट के गठन का प्रस्ताव किया। अन्य देशों से सहमति प्राप्त हो जाने के बाद अगस्त 1983 में जियाउर रहमान ने एक राजनीतिक संगठन के रूप में सार्क के गठन की शुरुआत की जिसमें इन देशों के ढाँचागत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के बारे में विचार किया गया। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर० वेङ्कटरमन ने एक पत्र के माध्यम से इस संगठन के गठन का स्वागत किया। बहुत सारे व्यवधानों को समाप्त करने के पश्चात् 1983 में व्यापार सहयोग के लिए सात देश (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव) सहमत हुए, जिसके परिणामस्वरूप सार्क का गठन हुआ। ये सभी देश कुछ क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुए जो निम्नवत हैं —

- (1) तकनीकी अध्ययन हेतु व्यापारिक प्रयोगशालाओं का निर्माण।
- (2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमिनारों का आयोजन।
- (3) सांस्कृतिक उत्सवों में एक दूसरे देश के नागरिकों को आवागमन की छूट।
- (4) शोध तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग।
- (5) विशेषज्ञों का आवागमन।
- (6) अन्य वे क्षेत्र जिनमें सहयोग की पारस्परिक सहमति प्राप्त हो।

इसके बाद इन सभी देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का इरादा बनाया। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति ने ढाका में 7-8 दिसम्बर,

1985 को सातों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सभा में सार्क का गठन किया गया है। जिसका अपना घोषणा-पत्र है, सगठन है, उद्देश्य है, अनुच्छेद है।

सगठन — इस सगठन का क्रियाकलाप देखने के लिए कई अलग-अलग प्रकार की सस्थाएँ तथा व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। सभी राष्ट्राध्यक्षों को मिलाकर एक शीर्ष सभा होती है। शीर्ष सभा इन सभी सस्थाओं तथा व्यक्तियों के क्रियाकलाप की उत्तरदायी होती है। बारी-बारी से प्रत्येक देश में इस सभा की बैठक बुलाई जाती है। जिस देश में यह सभा बुलाई जाती है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष ही सार्क का अध्यक्ष होता है। शीर्ष सभा में राष्ट्राध्यक्ष को स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। सार्क समझौते के अनुसार इस बैठक को प्रति वर्ष बुलाई जानी चाहिए। 5वाँ सम्मेलन दो वर्षों बाद बुलाया गया था। चार्टर के अनुसार किसी भी शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह सभा स्थगित कर दी जाती है। लेकिन एक बार केवल बांग्लादेश, मारीशस, श्रीलंका तथा पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योंकि भूटान नरेश किसी कारण से इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके तथा भारत ने सोचा कि अब यह शिखर सम्मेलन स्वतः स्थगित हो जाएगा (चार्टर के अनुसार) इसलिए भारत भी सम्मेलन में नहीं गया। तत्कालीन अध्यक्ष गयूम ने इस सम्मेलन को स्थगित न करके सार्क की प्रतिष्ठा को कायम रखी।

उद्देश्य — 1985 में गठित किया गया सार्क के अनुच्छेद प्रथम में इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- (1) इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक प्रगति की दर तीव्र करना एवं सांस्कृतिक विरासत कायम रखना।
- (2) इस क्षेत्र के निवासियों में सद्भाव, आपसी विश्वास एवं एक दूसरे की सहायता का भाव विकसित करना।
- (3) आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना।
- (4) अन्य विकासशील देशों से सद्भावपूर्ण मैत्री संबंध विकसित करना।
- (5) अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर और संगठनों में एक दूसरे का सहयोग करना।
- (6) दक्षिण एशिया के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- (7) दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना।

- (8) अन्य अंतर्राष्ट्रीय सगठनों, जो इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं का सहयोग करना।

सिद्धांत – चार्टर के अनुच्छेद दो के अनुसार सार्क के सिद्धांत –

- (1) वर्तमान समझौता किसी देश के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के साथ असंगत होने पर त्याज्य होना।
- (2) सार्क के देशों में सहयोग का आधार संप्रभुता की रक्षा करना, समता, भौगोलिक व्यापार की सुरक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता और एक दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप न करना।
- (3) वर्तमान समझौता किसी और बहुपक्षीय समझौते का स्थानापन्न नहीं है। यदि कोई समझौता पहले हो चुका है, तो यह समझौता उसके अतिरिक्त तथा पूरक होगा।

सचिवालय – सार्क का मुख्य सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमाडू में स्थित है। विभिन्न देशों के अंदर अलग-अलग सचिवालय कार्य करते हैं। लेकिन इनके समन्वय का कार्य केन्द्रीय सचिवालय का होता है। सार्क द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न इकाइयों स्थापित की गईं। जिनका व्यय, तकनीकी रख-रखाव एवं प्रबंध मिल-जुल कर किया जाता है। सचिवालय में सभी प्रकार के सार्क कार्यक्रमों का लेखा-जोखा रखा जाता है। शुरुआत में सार्क ने केवल नौ क्षेत्रों में ही सहयोग के लिए अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया।

12-13 दिसम्बर, 1992 को सातवाँ सम्मेलन हुआ, लेकिन भारत के शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण उनको स्थगित कर दिया गया। 10-11 अप्रैल 1993 को पुनः इसका आयोजन ढाका में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बांग्लादेश की राष्ट्रपति बेगम खालिदा जिया ने की। इस सम्मेलन और इसके पूर्व के सम्मेलनों में निम्न विषयों पर आम सहमति बनी और निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए।

ऊर्जा एवं साधनों का विकास – ऊर्जा के साधनों का विकास दक्षिण देशों की सहकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इन सभी क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा की बहुत संभावनाएँ हैं फिर भी पेट्रोल इन सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। 1985 में सबसे पहले पाकिस्तान में ऊर्जा के पुनर्नवीनीकरण वाले स्रोतों के संदर्भ में विशेषज्ञों की एक कार्य समिति का आयोजन किया। इसके दो केन्द्र (पहला-नई दिल्ली 1986 तथा दूसरा- इस्लामाबाद 1986) खोला गया। सौर ऊर्जा और वायोगैस के विकास के लिए पुनः एक विशेषज्ञ दल 1985 में दिल्ली में ही गठित

किया गया। 1985 में ऊर्जा संरक्षण पर विशेषज्ञों के एक दल की बैठक पुणे में बुलाई गई तथा प्रत्येक देश में ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ केन्द्रों की स्थापना की गई। प्रति वर्ष एक बैठक बुलाए जाने पर विचार किया गया, लेकिन इस विषय पर कोई सर्वमान्य निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका।

प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग, पर्यावरण, संरक्षण – दक्षिण देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण तथा आवास संबंधी काफी संभावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991 को दक्षिण आवास वर्ष तथा 1992 को 'पर्यावरण वर्ष' मनाने की घोषणा की गई। पर्यावरण के संदर्भ में तथा प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में प्रत्येक देश का स्वयं का उत्तरदायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वन संपदा का उचित संरक्षण नहीं हो पाने की दशा में बाढ़, सूखा, भूमि क्षरण तथा कटाव की समस्या पूरे क्षेत्र की होती है। इसी क्रम में पर्यावरण पर समुचित जानकारी देने के लिए अलग-अलग स्थान पर संभाएँ, सेमिनार तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

कृषि विकास :— विश्व की लगभग चौथाई जनसंख्या कृषि क्षेत्र में निवास करती है। कृषि विकास तथा क्षेत्रीय स्तर पर कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इन सभी देशों में अधिकांशतः जनसंख्या, कृषि पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आधारित है। कृषि तकनीक प्रसार सेवाएँ तथा तकनीकी सेवाओं के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें काफी विस्तार हो सकता है। भूटान में आलू केन्द्र, बांग्लादेश में चावल केन्द्र इत्यादि के साथ-साथ हैदराबाद में ग्रामीण विकास केन्द्र, करनाल में बाजार भूमि सुधार केन्द्र, नेपाल में कृषि मौसम सूचना केन्द्र, मैसूर में खाद्यान्न तकनीक पर विशेषज्ञों का कार्य समूह (1985) इत्यादि काफी कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान में कृषि विकास काफी अधिक हुआ है। भारत कृषि पदार्थों का निर्यातक देश है। बांग्लादेश तथा नेपाल में कृषि विकास का स्तर बहुत नीचे है और दोनों खाद्यान्नों का आयात करते हैं।

शिक्षा और मानव संसाधन विकास – शिक्षा और मानव संसाधन विकास दक्षिण देशों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती हैं। भारत औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने में काफी समर्थ हैं। भारत ने कई क्षेत्रों में जैसे— जर्मप्लाज्म के रखरखाव, जेनोर्टक कन्जरवेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा तथा अन्य औद्योगिक और तकनीकी व्यापारों और प्रशिक्षण केन्द्रों के चलाने का सुझाव दिया, जिसका अन्य सदस्य देशों ने स्वागत किया है। इन सभी देशों ने जीन बैंक के संगठन

की योजना पर सहमति व्यक्त की है। माले शिखर सम्मेलन में आठ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मादक पदार्थों की तस्करी — नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी इस क्षेत्र की गंभीर समस्या है। इन देशों में विभाजन रेखा कृत्रिम है और एक देश से दूसरे देश में जाना काफी आसान है। सामान्य तौर पर तस्कर एक देश से दूसरे देश में भाग जाता है। इस गंभीर समस्या को रोकने के लिए प्रत्यर्पण संधि की व्यवस्था की गई है। यदि कथित अपराधी किसी दूसरे देश में चला गया है, तो वह देश जहाँ उसने अपराध किया है, उक्त अपराधी की पहचान के लिए सारी जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर राजनीतिक कारणों से उक्त अपराधी का प्रत्यर्पण सम्भव नहीं है। शुरुआत में इस समझौते के तहत मादक द्रव्यों के तस्करों को ही इस कानून के अन्तर्गत रखने का विचार किया गया, बाद में शस्त्र विक्रेताओं, आतंकवादियों और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों को भी इस कानून के तहत दंडित करने का प्राविधान किया गया।

अन्य कई क्षेत्रों में भी दक्षिण समझौते को लागू किया गया है— उदाहरणार्थ, सभी देशों के सासद और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश किसी भी देश में वीजा और पासपोर्ट के बिना यात्रा कर सकते हैं। यही सुविधा राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों के प्रधानों और आश्रितों को भी प्रदान की गयी है। लघु, कुटीर और क्षेत्रीय उद्योग के विकास के लिए विशिष्ट सुविधाओं के अलावा एक क्षेत्रीय कोष की स्थापना पर सहमति हो गयी है। लेकिन यह कोष कार्य रूप में अभी परिणित नहीं हो पाया है। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई कोष पर भी अभी तक सहमति होने के बावजूद कोई रूप रेखा नहीं बन पाई है।

निम्न स्तरीय जीवन — दक्षिण देशों के सामने निम्न स्तर का जीवन एक गंभीर समस्या है। महानगरों और शहरों में रहने वाले बड़ी संख्या में बेरोजगारों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर काफी निम्न स्तर का है। शहरी आबादी में एक तिहाई से अधिक लोगों के पास रहने के लिए उपयुक्त मकान और आवास नहीं है। शहरियों में से लगभग 40 प्रतिशत को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। शहरों में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। स्वस्थ सम्बन्धी सुविधाओं का भी अभाव है।

वर्तमान समय में विश्व की लगभग आधी आबादी शहरों में बसी है। विश्व के बड़े-बड़े शहरों में प्रति सप्ताह एक करोड़ व्यक्ति की दर से शहरी जनसंख्या बढ़ रही है। शहरी विकास के लिए उचित सामाजिक व तकनीकी जानकारी का अभाव है। इन क्षेत्रों के महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रगति से बढ़ रही है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों की जनसंख्या एक करोड़ पार कर चुकी है। कराची और ढाका की जनसंख्या भी लगभग एक

करोड़ के आस-पास है। शहरों की ओर बढ़ते प्रवास की तीव्र अभिलाषा के चलते आवास, स्वास्थ्य महामारियों की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।¹ इस क्षेत्र में दक्षेस देश मिलकर कुछ ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं और गाँव में समाजिक कल्याण के कार्यक्रमों की योजनाएँ चलाई जा सकती हैं जिससे गाँव से पलायन और शहरों में अनुचित प्रवास को रोका जा सकता है।

10-11 अप्रैल, 1993 को ढाका में दक्षेस सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा साफ्टा रहा अर्थात् दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इस शिखर सम्मेलन में 'साफ्टा' को आम सहमति के आधार पर गठित किया गया। 2 नवम्बर, 1992 को दक्षेस देशों की आर्थिक सहयोग समिति की बैठक में साफ्टा के गठन के लिए उससे सम्बन्धित सभी आवश्यक महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया। भारत इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र या सीमा सघ बनाने का इच्छुक था। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर सहमत नहीं हुआ। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि भारत विकसित, औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्र के कारण अन्य सभी देशों पर हावी हो सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान ने यह सुझाव दिया कि पहले आपस में प्राथमिकता के आधार पर व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय दक्षेस देशों का सम्पूर्ण विश्व में व्यापार में 22% व्यापार का अंशदान है। इन देशों में आन्तरिक व्यापार की मात्रा और भी कम है। अन्य दक्षेस देशों से भारत का निर्यात इसके कुल निर्यातों का मात्र 3% है। सबसे पहले इन सभी देशों में आपस में व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिसके लिए शुल्कों और तटकरों में विशेष रियायतों की व्यवस्था होनी चाहिए। शुल्कों की रियायत प्रदान करने के लिए वस्तुओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए।

(1) वे वस्तुएँ, जिनमें तटकरों और प्रशुल्कों में रियायतें प्रदान की जायें।

(2) वे वस्तुएँ, जिनमें तटकरों और प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त किया जायें।

(3) वे वस्तुएँ, जिनमें निर्यातों के लिए एक निश्चित रूप रेखा तैयार की जायें।

पाकिस्तान के विरोध के कारण साफ्टा की सहमति के पश्चात् भी इसका क्रियान्वयन टाल दिया गया। वास्तव में इस क्षेत्रीय घटक में कोई भी महत्वाकांक्षी समझौता होना सम्भव नहीं हो पा रहा है। कुछ तो आर्थिक कारणों से तथा कुछ अधिकांश देश प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की समस्या से ग्रस्त हैं और मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से ये देश संप्रभुता और आर्थिक नीतियों के निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत भावुक हैं। छोटी-छोटी बातों पर इन देशों में

¹ राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र लखनऊ 31 मई, 1996 पृष्ठ 7

राजनीतिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। इस लिए इन क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारिता के और व्यापार सहकारिता की कम महत्वाकांक्षी योजना ही सफल हो सकती है— उदाहरणार्थ सयुक्त उपक्रम, सूचनाओं का आदान-प्रदान, क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी स्थानान्तरण, सयुक्त शोध और विकास कार्यक्रम, सयुक्त विनियोजन केन्द्र और भुगतान समझौते। इस क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है और भविष्य में हो भी सकता है।

दक्षिण देश अभी तक एक आर्थिक गुट के रूप में विकसित नहीं हो पाये हैं। ये सभी देश एक ही प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनके सामाजिक पहलू एक ही प्रकार के हैं। सांस्कृतिक एकता इस क्षेत्र को एक सूत्र में बाँधने के लिए काफी है, और भौगोलिक रूप से मालदीव और श्रीलंका को छोड़कर इनमें प्राकृतिक विभाजन की रेखा नहीं है, पर आपसी मतभेदों और पूर्वाग्रहों के कारण इसमें महत्वपूर्ण सहयोग की सम्भावना नहीं दिखलाई पड़ती है। जैसे—कोई भी देश किसी दूसरे देश के अन्दरूनी मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बाद भी ढाका दक्षिण सम्मेलन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने आयोध्या कांड के मामले को उठाया, जो भारत का आन्तरिक मसला था। दक्षिण देशों के चार्टर में द्विपक्षीय मसलों को उठाने की इजाजत नहीं है। वही पाकिस्तान हमेशा से दक्षिण में कश्मीर में आत्मनिर्णय और जनमत संग्रह करवाने जैसी बात करता है। इस राजनीतिक विरोधाभास की दशा में आर्थिक सहयोग और सहकारिता का हो पाना असम्भव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है। इस क्षेत्र में व्यापार की सम्भावनाएँ अनन्त होने के बावजूद सफलता की सम्भावना क्षीण है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सघ (दक्षिण) देशों के बीच आपसी व्यापार को अधिक खुला और सरल बनाने के लिहाज से मई 1997 के माले में हुई बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दक्षिण देशों नेपाल, भुटान, बंगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ भारत के व्यापार में बढ़ोत्तरी एक अहम पहलू है, क्योंकि इन देशों के साथ व्यापार करने में भारतीय निर्यातकों को परिवहन लागत कम होगी, जबकि यूरोपीय देशों के साथ व्यवसाय भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत का करीब 30 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय सघ के 15 देशों के साथ होता है जबकि दक्षिण देशों के साथ व्यापार मात्र तीन प्रतिशत ही है। मई 1997 के माले शिखर सम्मेलन में लिए गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं —

- (1) दक्षिण एशिया को 2001 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया।
- (2) समाज में महिलाओं और महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान पर अधिक जोर दिया गया। 2000-2010 के दशक को बच्चों के अधिकारों के दक्षिण दशक के रूप में

मनाया जायेगा। दक्षेस, महिलाओं और बच्चों के व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा। दक्षेस के कार्यकलापों में दूरवर्ती शिक्षण शामिल किया जायेगा। खुले विश्वविद्यालयों और दूरवर्ती शिक्षण संस्थानों को खुले विश्वविद्यालयों के सकाया के निर्माण की सम्भावनाओं के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जायेगा।

- (3) दक्षेस के व्यवसायिक संगठनों और स्वैच्छिक समूहों के मध्य सहयोग सर्धित करने के उद्देश्य से दक्षेस मान्यता प्राप्त निकायों की एक नयी श्रेणी के सृजन के बारे में सहमति हुई।
- (4) दक्षेस के दूरगामी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करना।
- (5) पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पर जैव विविधता संरक्षण और वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने सम्बन्धी नियम तैयार करना। पर्यावरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दक्षेस के पर्यावरण मंत्री साल में एक बार बैठक किया करेंगे।
- (6) इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए दक्षेस के वित्त और योजना मंत्री की तीसरी बैठक का शीघ्र आयोजन। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने में लक्ष्य समूहों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- (7) 1997 दक्षेस सहभागी शासन वर्ष के रूप में नामित किया गया।
- (8) दक्षेस सचिवालय के माध्यम से उपक्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के मई 97 शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र के सात राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने एक स्वर से यूरोपीय समुदाय के तरह से आर्थिक सहयोग बढ़ाने, सन् दो हजार तक मुक्त व्यापार की सुविधाओं का लक्ष्य पूरा करने तथा गरीबी, अशिक्षा एवं पिछड़ापन दूर करने के लिए संयुक्त प्रयासों का सकल्प व्यक्त किया।

मई 1997 के माले बैठक में भारत के प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के कहा कि विभिन्न क्षेत्र पूरे विश्व में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। दक्षिण एशिया को भी अपनी विशिष्ट और गतिशील पहचान बनानी चाहिए। शताब्दियों से हमारा इतिहास और संस्कृति एक रही हैं। कालान्तर में हमने विशिष्ट परिपूरक अर्थव्यवस्था कायम रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिलों में जानते हैं कि दक्षिण एशिया अपने आप में

एक समुदाय है यह एक बन्धन है जो हमें इस क्षेत्रों की भावी अपार सभावनाओं को प्राप्त करने के लिए साथ रखेगा।

गुजराल ने कहा था कि विश्व में आज दक्षिण एशिया को अपना यथोचित स्थान बनाना प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। ऐसा इस क्षेत्र के लोगों, यहाँ के उद्योगों, कौशल और कृतित्व के अनुरूप होना चाहिए। इस दिशा में हमें आपस में व्यापारिक प्राथमिकता देने के कार्यक्रम को तेज करते हुए न केवल शताब्दी के अंत तक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा बल्कि दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन की भूमिका तैयार करनी होगी। प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से वादा किया था कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में सीमा शुल्क घटाने के फलस्वरूप दक्षिण के सदस्य देशों में भारत को बढ़ने वाले निर्यात को सीमित रखने के लिए किसी तरह के प्रतिबन्धात्मक कदम नहीं उठाये जायेंगे और अपील की थी कि शुल्कों में रियायतें बढ़ाई जायें और इस सूची में सभी वस्तुएँ लाने की कोशिश की जाय। उन्होंने कहा था कि भारत ने काफी हद तक शुल्क तथा अन्य प्रकार के अवरोध हटा दिए हैं और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रखेगा। हमारी कोशिश है कि बूढ़ की तरह शुरू हुए हमारे प्रयास मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में बाढ़ का रूप धारण कर लें।¹ इसके लिए व्यापक रूप से आयात-निर्यात शुल्क घटाने शुरू करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दक्षिण देशों का आर्थिक सहयोग अब निर्यात-आयात तक सीमित नहीं रहकर पूँजी निवेश प्रोत्साहन, प्रतिबन्धात्मक नीतियों को समाप्त करने, दोहरी कर प्रणाली रद्द करने, उत्पादन मानकों में सुधार एवं समानता और व्यापारिक विवाद सुलझाने के तंत्र तक पहुँच गया है।

सन् बीस सौ बीस में दक्षिण एशिया क्षेत्र समग्र विकास का निर्धारण करके और उसे साकार करने के विभिन्न चरण और नीतियाँ बनाने का निर्देश देकर नौवा शिखर सम्मेलन सुनहरे भविष्य की ओर यात्रा में मील का पत्थर बन सकता है। अगली शताब्दी एशियाई शताब्दी होने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। एशिया का भाग्य पहले ही उद्घोषित किया जा चुका है। विश्व उत्पाद में एशिया का अंश जो 1820 में 60 प्रतिशत से घटकर 1950 में मात्र 20 प्रतिशत रह गया था। सन् बीस सौ बीस में दोबारा बढ़कर 60 प्रतिशत हो जायेगा। दक्षिण एशिया का यह विहगम स्वरूप हम सिर्फ सतत समूहिक प्रयास, प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के श्रेष्ठतम अर्थवेत्ताओं ने एशिया को भविष्य का महाद्वीप की सज़ा दी है।

¹ हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, नई दिल्ली, 13 मई, 1997, पृष्ठ-11।

भारतीय वाणिज्य एव उद्योग मंडल महासघ (फिक्की) के अध्यक्ष श्री ए० एस० कासलीवास ने कहा कि दक्षेस देशों में आपसी व्यापार बढ़ाने के बारे में भावनाएँ तो अच्छी हैं लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हो पा रही है। दक्षेस प्रयास मात्र तीन प्रतिशत तक ही सीमित है जो यह सिद्ध करता है कि पिछले 4-5 वर्षों में हुई प्रगति की गति बहुत ही धीमी है।

उल्लेखनीय है कि दक्षेस का 11वाँ शिखर सम्मेलन 5-6 जनवरी, 2002 को काठमाडू में सम्पन्न हुआ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान व मालदीव के शासनाध्यक्षों का यह सम्मेलन मूलतः नवम्बर 1999 में प्रस्तावित था, किन्तु पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार का जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तख्ता पलटे जाने से वहाँ सैन्य सरकार होने के कारण यह सम्मेलन उस समय नहीं हो सका (भारत सरकार ने सैन्य सरकार के साथ शिखर बैठक में भागीदारी से तब इनकार कर दिया था)। भारत एवं पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बने रहने के कारण दक्षेस का यह शिखर सम्मेलन टलता ही रहा।

तालिका-5 1

दक्षेस शिखर सम्मेलन कब और कहाँ

क्रमांक	वर्ष	आयोजन स्थल
1	1985	ढाका (बांग्लादेश)
2	1986	नई दिल्ली (भारत)
3	1987	काठमाडू (नेपाल)
4	1988	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)
5	1990	माले (मालदीव)
6	1991	कोलम्बो (श्रीलंका)
7	1993	ढाका (बांग्लादेश)
8	1995	नई दिल्ली (भारत)
9	1997	माले (मालदीव)
10	1998	कोलम्बो (श्रीलंका)
11	2002	काठमाडू (नेपाल)
12	2003	पाकिस्तान (प्रस्तावित) नोट - भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ न जाने की घोषणा से यहाँ यह सम्मेलन होना संदिग्ध।

इस सम्मेलन का आयोजन अन्ततः ऐसे समय में हुआ, जब भारत एवं पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों में गम्भीर तनाव की स्थिति चरम अवस्था में है। भारतीय संसद पर 13 दिसम्बर 2001 के आतंकी हमले व इसके लिए उत्तरदायी आतंकवादियों के विरुद्ध पाकिस्तान के उदासीन रवैये के परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काठमाडू रवाना

होने से पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था, कि शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता वह नहीं करेंगे।

दक्षेस के विगत 10 शिखर सम्मेलनों की भँति यह ग्यारहवाँ शिखर सम्मेलन भी मूलतः तीन दिन का निर्धारित था, किन्तु खराब मौसम के कारण पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के समय से न पहुँच पाने के कारण 4 जनवरी, 2002 को सम्मेलन का उद्घाटन न हो सका। श्री मुशर्रफ बीजिंग होते हुए काठमाडू आये थे। दक्षेस चार्टर के अनुसार सभी सातों शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में ही इसके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सम्भव है। 5 जनवरी, 2002 को सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर सातों राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष उपस्थित थे।

‘नरेश वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय सभागार’ में सम्पन्न उद्घाटन समारोह को सभी उपस्थित शासनाध्यक्षों ने सम्बोधित किया। आतंकवाद का मुद्दा ही इन सभी सम्बोधनों में हावी रहा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस मंच से जहाँ 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका में हुए आतंकी हमले की कड़ी भर्त्सना की वही भारतीय ससद पर 13 दिसम्बर, 2001 के हमले का कोई उल्लेख अपने सम्बोधन में नहीं किया। उद्घाटन समारोह में ही दक्षेस की निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रिका कुमारतुंग ने अपना यह पद नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा को औपचारिक रूप से सौंप दिया।

सम्मेलन की समाप्ति पर जारी 11 पृष्ठों के 56 सूत्रीय ‘काठमाडू घोषणा पत्र’ में भी आतंकवाद के खात्मे के प्रति प्रतिबद्धता सभी सात शासनाध्यक्षों ने व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1373 (इसे 11 सितम्बर, 2001 की आतंकी घटना के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था) के प्रति अपना पूर्ण समर्थन इन शासनाध्यक्षों ने व्यक्त किया है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों व सन्धियों के अनुरूप वृहद् कार्य योजना तैयार करने पर इसमें बल दिया गया है।

आर्थिक सहयोग पर भी समान रूप से बल देते हुए क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाकर इसका लाभ प्राप्त करने के लिए दक्षेस घोषणा-पत्र में कहा गया है। इसके लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) का मसौदा-2002 के अन्त तक तैयार करने को इसमें कहा गया है। दक्षेस का आगामी 12वाँ शिखर सम्मेलन 2003 में पाकिस्तान में सम्पन्न होगा। दक्षेस राष्ट्रों के सूचना मंत्रियों का तीन दिवसीय सम्मेलन 7-9 मार्च, 2002 को इस्लामाबाद में सम्पन्न हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया।

4 साफ्टा —

भारत सहित दक्षिण एशिया के सात देशों में साफ्टा अर्थात् 'दक्षिण एशियाई वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता' को लागू कर दिया गया है। सबसे पहले साफ्टा का प्रस्ताव श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास ने 1991 में हुए छठे दक्षिण शिखर सम्मेलन (कोलम्बो) के दौरान किया तथा उसके बाद ढाका में सम्पन्न सातवें दक्षिण शिखर सम्मेलन अप्रैल 1993 के दौरान उस पर हस्ताक्षर किया गया। 4 दिसम्बर, 1995 में दक्षिण एशिया का पहला क्षेत्रीय व्यापारिक गुट अस्तित्व में आ गया। इस संगठन से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और भारत को विशेष रियायतें ही उपलब्ध नहीं हो सकती बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों के जवाब में एक करारी पहल भी सिद्ध हो सकता है। साफ्टा के अन्तर्गत जो उत्पाद आते हैं उनके तटकर में कम से कम दस प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। दो देश तटकर में कटौती का प्रतिशत आपस में परस्पर विचार-विमर्श करके तय कर सकते हैं।

भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को न्यूनतम विकसित देश घोषित करने के उपरान्त ये व्यवस्था की गई है कि ये देश दक्षिण देशों से आयात पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। साफ्टा के अन्तर्गत आने वाले देशों ने अभी तक केवल 226 वस्तुओं को ही शुल्क रियायत देने की सहमति प्रकट की है। इस व्यापारिक गुट में 106 वस्तुओं पर शुल्क रियायत देकर भारत इनमें से अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। जबकि इस सन्दर्भ में श्रीलंका ने 31 वस्तुओं, बांग्लादेश ने 12, मालदीव ने 17, भूटान ने 7, और पाकिस्तान ने 35 वस्तुओं की सूची जारी की है। लगभग 12 अरब आबादी वाले इन देशों के बीच आपसी व्यापार कुल विश्व व्यापार का मात्र 3 प्रतिशत (9300 करोड़ डॉलर) है।¹

इन सभी देशों के बीच आने वाली विभिन्न बाधाओं की वजह से ऐसा है, लेकिन साफ्टा के वजह से ये बाधाएँ अब टूटती नजर आ रही हैं। ये सभी देश औद्योगिक उत्पादों को विकसित देशों से आयात करते हैं, जो कि यही औद्योगिक उत्पाद क्षेत्र के अन्य पड़ोसी देशों से काफी सस्ते में आयात किया जा सकता है।

¹ क्रानिकल मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, 208, शिवलोक हाउस-1, नई दिल्ली 110015 पृष्ठ-12।

साफ्टा के लागू होने के साथ ही दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक व व्यापार सहयोग के एक नये युग की शुरुआत हो रही है। यदि इस क्षेत्र के सभी देश आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जिसके बल पर विकसित देश भी दक्षिण-एशिया का लोहा मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

दक्षेस देशों के वाणिज्य एवं व्यापार मन्त्रियों का प्रथम सम्मेलन नयी दिल्ली में 9 जनवरी, 1996 को सम्पन्न हुआ, जिसमें साफ्टा को प्रभावशाली बनाने का संकल्प लिया गया ताकि सन् 2000 तक या अधिक से अधिक 2005 से पूर्व तक इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इस सम्मेलन में साफ्टा को पूरी तरह से लागू करने और व्यापार उदारीकरण पर अन्तरसरकारी दल की बैठक मार्च, 1996 में श्रीलंका में बुलाने का निश्चय किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के अनुसार “दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता (साफ्टा) से दक्षेस देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार को बल मिलेगा। ऐसी कई आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाएँ हैं जिनका कार्यान्वयन क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर ही सम्भव है। दक्षेस देशों के बीच आर्थिक सहयोग से सभी सदस्यों को लाभ मिलने वाला है।¹ इससे किसी भी देश को नुकसान नहीं होगा।

आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार में जानकारी और सूचनाओं के आदान-प्रदान में दूरी सबसे बड़ी बाधा साफ्टा के देशों के बीच रही है। विकसित देशों ने पर्यावरण, श्रमिक मानक और मानवाधिकार जैसे नये संरक्षणवादी तरीके अपनाने शुरू कर दिये हैं। ऐसी दशा में विकासशील देशों की मदद के लिए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे क्षेत्र की व्यापक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

सदस्य देशों को साफ्टा के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढ़ना चाहिये। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा की प्राप्ति तक इन नकारात्मक सूचियों में लगातार गिरावट आनी चाहिए। क्षेत्र में मुक्त व्यापार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। नकारात्मक सूची में दर्ज वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं का व्यापार वरीयता के आधार पर तय शुल्क अथवा गैर शुल्क दरों पर किया जाय।

दक्षेस क्षेत्र के सभी देशों में आम धारणा यही है कि अपने पड़ोसी देशों से ही आयात किया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार संवर्धन के लिए उचित नीतियाँ और उपाय करने चाहिए। आपसी व्यापार में बाधाओं का एक

¹ अमृत-प्रभात, इलाहाबाद 4 जनवरी 1996, पृष्ठ 11।

बार पता चल जाने से उनका निवारण किया जा सकता है। इससे निवेश कारोबार सयुक्त उद्यम और सेवाओं में वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। दक्षेस देशों को समय पर साफ्टा को क्रियान्वित करने के लिए भविष्य के लिए एजेडा तैयार करना चाहिए तथा विशिष्ट मुद्दों पर समझौता करना चाहिए।

क्षेत्रीय सहयोग से फायदा हो जाने के बावजूद गरीबी की स्थिति तथा क्षेत्रीय विषमता के कारण शुरू में दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग गति नहीं पकड़ पाया। विश्व के कुल व्यापार में दक्षेस देशों का व्यापार एक प्रतिशत भी नहीं है, जबकि इन देशों के कुल विदेशी व्यापार में से केवल तीन प्रतिशत व्यापार आपस में होता है।

बदलते आर्थिक परिवेश में व्यापार और उद्यम की नयी-नयी संभावनाएँ पैदा हो रही हैं तथा क्षेत्र के व्यवसायिक समुदाय का ध्यान तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहा है। साफ्टा के गठन के बाद नयी संभावनाओं के प्रति व्यापारिक क्षेत्र का रूप काफी उत्साहवर्धक रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव के अनुसार "दक्षेस के बीच व्यवसायियों की मुक्त आवाजाही, संचार और दूरसंचार सम्पर्कों में सुधार तथा आवागमन की सुविधा के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा क्षेत्र के लिए जरूरी आवश्यकताएँ हैं।"¹

5. उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) :-

12 अगस्त, 1992 को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लिए जब सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों ने मिलकर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की तो उस समय विश्व के आर्थिक समुदाय ने इसको एक नया गुट स्वीकार करते हुए इसके प्रभावों का विश्लेषण और लेखा जोखा तैयार करना शुरू कर दिया तथा बाद में इसी गुट का नाम नाफ्टा रखा गया।

17 नवम्बर, 1993 को अमेरिकी संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 1 जनवरी, 1994 से यह पूर्ण आस्तित्व में आ गया। नाफ्टा (नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट) अथवा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का संगठन है। नाफ्टा के घरेलू उत्पाद 6 खरब, 8 अरब डालर के बराबर हैं। इसकी जनसंख्या अटलांटिक क्षेत्र के यूरोपीय संघ के देशों की जनसंख्या से 2 करोड़ अधिक है। इस प्रकार यह आबादी की दृष्टि से यूरोपीय समुदाय से बड़ा है तथा अब विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया है।

¹ अमृत-प्रभात, दैनिक समाचार पत्र, इलाहाबाद, 9 जनवरी 1996, पृष्ठ 12।

कनाडा से 22 बिलियन डालर की वस्तुओं का आयात तथा 05 बिलियन डालर की वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके विपरीत कनाडा अमेरिका से 91 बिलियन अमेरिकी डालर की वस्तुओं का आयात और 85 बिलियन डालर की वस्तुओं का निर्यात करता है। अमेरिका के कुल आयात का 61 प्रतिशत सामान मैक्सिको से आता है और अमेरिका के कुल निर्यात में 72 प्रतिशत सामानों का निर्यात मैक्सिको को होता है।

नाफ्टा तीन देशों का एक व्यापारिक गुट है और इससे सभी सदस्य देशों को लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक फायदे में अमेरिका ही रहने वाला है। मैक्सिको जैसे देश में अमेरिका को काफी रियायत मिलने से व्यापक सभावनाओं वाला नया बाजार प्राप्त हुआ है। जिससे अमेरिका के निर्यात में वृद्धि हो सकती है रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था में नये रक्त संचार के साथ ही कारपोरेट क्षेत्र सबसे अधिक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। भारत की तरह मैक्सिको भी एक विकासशील देश है जहाँ काफी सस्ता श्रम उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप मैक्सिको में अमेरिकी पूँजी का प्रभाव बढ़ सकता है। जिससे वहाँ भी रोजगार के नये अवसरों का सृजन हो सकता है। कनाडा का आर्थिक भविष्य नाफ्टा के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे भी अमेरिका के साथ कनाडा का एक समझौता पहले से ही है, जिसके फलस्वरूप दोनों ही देशों को व्यापार में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी।

नाफ्टा के तहत हुए कुछ प्रमुख समझौते :-

- (1) तीनों देश एक-दूसरे के लिए लागू सभी व्यापार प्रतिबंध 10 वर्षों में पूरी तरह समाप्त कर देंगे।
- (2) अमेरिका, मैक्सिको को प्रतिवर्ष निर्यात होने वाले लगभग 25 करोड़ डालर (कुल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत) के वस्त्र एवं परिधानों पर सभी तरह के अकुश या नियंत्रण तत्काल प्रभाव से हटा देगा।
- (3) अमेरिका से कृषि जिनसे के आयात पर से मैक्सिको 10-15 वर्षों में आयात शुल्क समाप्त कर देगा।
- (4) सीमा शुल्क 15 वर्षों के लिए लागू होगा। मैक्सिको में उत्पादित वस्तुओं पर अमेरिका में सीमा शुल्क औसतन 4 प्रतिशत से कम होगा जबकि इसके विपरीत अमेरिकी वस्तुओं पर मैक्सिको में सीमा शुल्क औसतन 10 प्रतिशत होगा।

- (5) वित्तीय सेवाओं में मैक्सिको अपने वित्तीय बाजार अमेरिका और कनाडा के लिए खोल देगा तथा वहाँ की बीमा कंपनियों एवं बैंकों का पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयों स्थापित करने की अनुमति प्रदान करेगा।¹

जहाँ नाफ्टा से तीनों ही सदस्य देशों को लाभ हो सकता है वही पर दूसरी ओर लातिन अमेरिका के अन्य देशों, दक्षिण पूर्व एशिया के नव विकसित देशों, यूरोपीय समुदाय और भारत जैसे विकासशील देशों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। भारतीय निर्यात संगठन सघ ने 1996-2001 के लिए भारत की निर्यात रणनीति नामक प्रारूप में कहा है कि नाफ्टा दो विकसित देशों और एक विकासशील देश का समूह है जो वास्तव में अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मैक्सिको के सस्ते श्रम का मिश्रण है। 24 जनवरी, 1996 को भारतीय निर्यात संगठन सघ ने कहा है कि नाफ्टा के अस्तित्व में आने से भारत के व्यापार हितों पर सीधे खतरा पैदा हो सकता है। नाफ्टा विशेषकर कपड़ा क्षेत्र पर आधारित है। वही पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ कपड़ा क्षेत्र के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है, और कुल निर्यात में इसका हिस्सा लगभग एक-चौथाई है। इसीलिए नाफ्टा के प्रतिरूप कदम उठाने के भारतीय निर्यात संगठन सघ ने ऐसी नीति बनाने का सुझाव दिया है जिससे कनाडा और अमेरिका के साथ-साथ पुनर्खरीद और तीसरे देश को निर्यात करने की सुविधा दी जाय। इसके अतिरिक्त उत्तर अमेरिकी बाजार के लिए भारतीय निर्यातकों को सरकार की ओर से विशेष सहायता भी दी जानी चाहिए।

पहली बार इस व्यापार समझौते में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी मुक्त व्यापार में शामिल कर लिया गया। मैक्सिको श्रम बाहुल्य देश है तथा कनाडा में और अमेरिका में श्रम साधनों की कमी है। इन तीनों देशों की साझा सकल राष्ट्रीय आय कुल विश्व के राष्ट्रीय आय का एक तिहाई है और यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सकल राष्ट्रीय आय से अधिक है। क्षेत्रफल, खनिज और अन्य प्राकृतिक सुविधाओं की वजह से इस समूह का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और कनाडा खाद्यान्न का निर्यात करते हैं और मैक्सिको खाद्यान्न का आयात करता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से अमेरिका काफी विकसित है और मैक्सिको उद्योग और तकनीक का आयात करता है इसकी वजह से मैक्सिको को लाभ हो सकता है तथा अमेरिका को भी अपने निर्यातों को बढ़ाने में काफी सहायता मिल सकती है।

¹ क्रानिकल, मासिक पत्रिका, क्रानिकल प्रा0 लि0 200 शिव लोक हाउस-1, नई दिल्ली 110015, मार्च, 1996, पृष्ठ 12।

अमेरिका कनाडा और मैक्सिको का व्यापार विश्व के व्यापार का 18% है, जिसमें अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अमेरिका के कुल निर्यात में से 20% निर्यात कनाडा को किया जाता है। (लगभग 87 बिलियन डालर) मैक्सिको से 77% निर्यात अमेरिका को किया जाता है (कुल निर्यात 44 बिलियन डालर का अमेरिका को 33.7% बिलियन डालर)। इसी प्रकार कनाडा का 78% निर्यात अमेरिका को होता है (कुल निर्यात 135 बिलियन डालर में से 105 बिलियन डालर) कनाडा और मैक्सिको का आन्तरिक व्यापार बहुत सकुचित है जिसके बढ़ने की अधिक संभावना है। मैक्सिको में श्रमिकों का मूल्य अमेरिका की तुलना में काफी कम है, इसी कारण से मैक्सिको में अधिकांश वस्तुओं की उत्पादन कीमत बहुत कम आती है जिसकी वजह से मैक्सिको में औद्योगीकरण और रोजगार बढ़ सकता है।

6. कोमेसा :—

कोमेसा पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों का एक व्यापारिक संगठन है जिसका पूरा नाम दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका साझा बाजार है। 5 नवम्बर, 1993 को हस्ताक्षर करके युगांडा की राजधानी कम्पाला में इसकी स्थापना की गयी। कोमेसा के कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिसमें युगांडा, जाम्बिया, मेडागास्कर, दक्षिण-अफ्रीका, इरीट्रिया, साईचीलीस आदि देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य 320 मिलियन लोगों के लिए एक साझा बाजार की स्थापना करना है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 125 बिलियन डालर है।

शीतयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद अफ्रीकी देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलना कम हो गया तथा जो बाहरी देश अफ्रीकी देशों की मदद करते थे, वे ही अफ्रीकी देशों पर इस बात के लिए दबाव डालने लगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को उनके अनुकूल ढाल ले लेकिन अफ्रीकी देशों में ऐसी क्षमता बहुत कम रही है, जो बाहरी दबाव के अनुरूप अपने आर्थिक संरचना का विकास कर सकते हैं। इस लिए ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र के अफ्रीकी देशों को कोमेसा जैसी बाजार व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लेना पड़ा, ताकि उस क्षेत्र की पर्याप्त आर्थिक उन्नति हो सके।

7. हिंद महासागर तटीय देश :—

हिंद महासागर का तट तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। आज के इन तटीय देशों को आपस में स्थायी आर्थिक सम्बन्ध कायम करने

के प्रयत्न के पीछे एक लम्बा सिलसिला रहा है। पिछले चार-साढ़े चार हजार वर्षों से हिंद महासागर के तट पर बसे हुए देश और वहाँ के निवासी किसी न किसी रूप में, खासकर व्यापार के बहाने एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये देश जाति, संस्कृति, तथा धर्म की दृष्टि से काफी भिन्नता रखते हैं। इन सबसे बढ़कर इन देशों में आर्थिक असमानता है। एक तरफ जहाँ आस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय का औसत 15,000 डालर है, वहीं पर दूसरी तरफ मोजाम्बिक, तजानिया, मेडागास्कर, बंगलादेश जैसे गरीब अफ्रो-एशियाई देशों में इसका औसत काफी कम केवल 250 डालर है। इनमें एक तरफ जहाँ पर एक अरब से अधिक जनसंख्या वाला भारत है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे भी देश हैं, जिनकी जनसंख्या केवल 80 हजार है।

आर्थिक प्रगति में सहयोग के अलावा तटीय देशों का गुट गठित हो जाने से इसके द्वारा सदस्य देशों के द्विपक्षीय विवादों आतंरिक अशांति तथा देश की संप्रभुता व अखण्डता को पड़ोसी देशों के खतरे के मसलों को भी हल किया जा सकता है। अंतराष्ट्रीय क्षेत्रीय व्यापार गुटों की तगड़ी प्रतिस्पर्धा, तटीय देशों के गुट की सफलता को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वे गुट यह नहीं चाहते कि एशिया-अफ्रीका का एक बड़ा बाजार उनके हाथों से निकल जाय। तटीय देशों के गुट की सफलता इस बात पर निर्भर है, कि वह अंतराष्ट्रीय व्यापार गुटों में कितनी दक्षता के साथ पेश आता है। हिंद महासागर के तटीय देशों का व्यापार गुट का गठन इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के देश काफी पहले से अपना व्यापार गुट (साफ्टा) बनाने में जुटे हुए हैं। हिंद महासागर के तटीय देशों का व्यापार गुट यदि शीघ्र ही अमल में आ जाता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया के देशों के लिए सुखकर हो सकता है, बल्कि यह हिंद महासागर के समस्त तटवर्ती देशों के हित में हो सकता है, जिससे विश्व के इस बदलते दौर में सभी देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत एवं गतिशील करने का अवसर मिल सकता है।

आपस में इतनी भिन्नताओं के होने के बावजूद विश्व के बदलते परिदृश्य को देखते हुए इन सब तटीय देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक गुट बनाने की बात पिछले कई वर्षों से उठ रही है, लेकिन इधर एक बार फिर इसके गठन की मांग बड़ी तेजी से प्रबल हो उठी है। यदि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को ध्यान में रखकर इन सभी देशों का एक मुक्त व्यापार संगठन बन जाय, तो यह बीसवीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद बड़ी तेजी से क्षेत्रीय व्यापार गुटों का गठन किया गया है। नाफ्टा, यूरोपीय संघ, कोमेसा, ओपेक, आसियान आदि इसी आर्थिक

प्रतिस्पर्धा की कोख से बाहर निकले हैं। इन सबको देखते हुए हिंद महासागर के तटीय देशों का भी एक व्यापार गुट गठित करना जरूरी हो गया है, जिसमें कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से हो सके। हिंद महासागर के तट पर बसे एशिया और अफ्रीका के देशों की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या की एक तिहाई है। यह क्षेत्र खनिज ससाधनों के मामले में भी काफी समृद्ध है।

विश्व का दो तिहाई तेल भंडार, कुल यूरेनियम भंडार का 60 प्रतिशत, कुल सोने का 40 प्रतिशत तथा विश्व के कुल हीरे के भंडार का 98 प्रतिशत उपलब्ध है।¹ दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन से मुक्त हो जाने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति डा० नेल्सन मंडेला ने भी इस प्रकार का गुट बनाने की घोषणा किया और स्वयं भी काफी सक्रियता दिखाई। भारत, दक्षिण अफ्रीका, मारिशस, ओमान, आस्ट्रेलिया, केन्या तथा सिंगापुर, इस क्षेत्र के वे प्रमुख देश हैं, जो क्षेत्रीय व्यापार गुट के गठित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में नई दिल्ली में 14 दिसम्बर, 1995 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले देशों ने यह तय किया कि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के मार्ग में जो अवरोध हैं, उनकी पहचान करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाय। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं, फिक्की, सी० आई० आई० और एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दूरसंचार, कस्टम और व्यापार दस्तावेजीकरण, गैर चुगी बाधाएँ, समुद्री परिवहन और सम्बन्धित मामले, पर्यावरण और ऊर्जा के मामले पर विशेष ध्यान दिया जाय।

जून 1995 में आस्ट्रेलिया ने इस गुट के देशों की तीन दिवसीय बैठक पर्थ में आयोजित किया, जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उस बैठक में दो 'प्रयास-समूहों' की स्थापना की गई, जो सम्बन्धित देशों में व्यापारिक और शैक्षणिक वातावरण का माहौल तैयार करेगा, इस बैठक के आयोजित होने के पहले प्रस्तावित गुट के सात प्रमुख देश मार्च 1995 में पोर्ट लुइस में मिले और पारस्परिक व्यापार संभावनाओं और अडचनों के बारे में बातचीत की।

भारत के अनुरोध पर आस्ट्रेलिया उसे संबंधित खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, विशेष प्रकार के चिकित्सीय उत्पादों, रसायनिक उत्पादन, बैंकिंग, बीमा, साफ्टवेयर का विकास, प्रबन्धन, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा बचत तकनीक, वैज्ञानिक उपकरण तथा खनिज ससाधन के क्षेत्र में सहायता दे सकता है। भारत इस गुट में शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका की खनन

¹ क्रानिकल, मासिक पत्रिका, क्रानिकल प्रा० लि० 208 शिव लोक हाउस-1, नई दिल्ली 110015, मार्च, 1996, पृष्ठ 12।

कम्पनियो से उन अत्याधुनिक तकनीको को हासिल कर सकता है, जिनके द्वारा कोयले, हीरे तथा अन्य खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से खनन किया जा सके। वहाँ पर कुछ कम्पनियों ऐसी भी है जो अति आधुनिक तकनीक के जरिए कोयले को गैस में बदलती है। भारत इसमें भी लाभ उठा सकता है। भीतरी समुद्र में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर में दोनों की नौ सेना के बीच भी व्यापार स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। इसी तरह का सहयोग मारिशस, सिंगापुर तथा अन्य तटीय देशों के साथ भी संभव हो सकता है।

भारत वर्तमान परिस्थितियों में व्यापक और निवेश के मामले में इस गुट के सात प्रमुख देशों के बीच सहयोग की संभावनाएँ तेजी से तलाश रहा है। भारत ने अपना ध्यान इस गुट के कुछ देशों, विशेषकर आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त व्यापार नीति पर केन्द्रित कर रखा है। भारत और आस्ट्रेलिया प्राकृतिक तत्वों के विश्व के दस बड़े निर्यातकों में से दो हैं। उसी प्रकार आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व के दस प्रमुख लौह अयस्क के निर्यातकों में से तीन हैं। ये तीनों देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक जैसे उत्पादों के लिए संयुक्त बाजार की नीति पर अमल किया जाय, तथा इसके साथ ही वे प्रादेशिक व्यापार संस्थाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात भी कर सकें।

हिंद महासागर के तटीय देशों के गुट का प्रमुख लक्ष्य है आपसी व्यापार को गति प्रदान करना, संयुक्त बाजार, उदारीकरण, संयुक्त खरीद आदि पर सहयोग की बढौलत ही संभव है। इसके अतिरिक्त इस गुट के लिए अन्य विषय गौण हैं। एक दूसरे को व्यापार सुविधाएँ उपलब्ध कराकर व्यापार सम्बन्धी तथ्यों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, निवेश तथा तकनीक का आदान प्रदान किया जा सकता है। भारत ने भी इस प्रस्ताव पर बल दिया है कि इस गुट के सात प्रमुख देश संयुक्त बाजार, संयुक्त खरीद और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग करके क्षेत्रीय सहयोग को बढावा दे सकते हैं।

8. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) :-

1962 में तेल उत्पादक देशों ने इराक की राजधानी बगदाद में एक सम्मेलन में ओपेक की स्थापना का निर्णय लिया। तीन, अरब मुस्लिम देश इराक, कुवैत एवं सऊदी अरब, गैर-अरब मुस्लिम देश ईरान, दक्षिण अमेरिका। गैर अरब व गैर मुस्लिम देश वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक देश हैं ओपेक 13 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। विश्व तेल व्यापार का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग इन्हीं पाँच देशों के हिस्सा आता है। इस संगठन में बाद में निम्न देश शामिल हुए — अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, लीबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार ओपेक के सदस्य देशों की कुल संख्या 13 है। इस संगठन की सदस्यता ऐसे देश भी ग्रहण कर सकते हैं जो पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल निर्यात करते हैं और जिनका पूरा हित मूल रूप से संगठन के सदस्य देशों के हितों से मिलता जुलता है।

ओपेक (OPEC) का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन वेनेजुएला की राजधानी कराकस (Caracas) में 27-28 सितम्बर, 2000 को सम्पन्न हुआ। ओपेक के 40 वर्षों के इतिहास में यह दूसरा शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन 25 वर्षों के अन्तराल पर वेनेजुएलाई राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज (Hugo Chavez) के लम्बे प्रयासों के परिणामस्वरूप हुआ था।¹

गम्भीर पारस्परिक मतभेदों के परिणामस्वरूप ओपेक के सदस्य राष्ट्रों ने सम्मेलन में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए तेल मूल्यों को लाभदायक स्तर पर बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया। इसके लिए ईरान-इराक व इराक-कुवैत के आपसी मतभेदों तथा इराक के विरुद्ध आरोपित संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों को सऊदी अरब के समर्थन आदि विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करते हुए कराकस घोषणा पत्र में 'कार्टेल' की एकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई तथा निर्धन राष्ट्रों की सहायता का संकल्प लिया गया। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि तेल मूल्यों में वृद्धि के लिए ओपेक की नहीं बल्कि धनी राष्ट्रों की नीतियाँ उत्तरदायी हैं। तेल मूल्यों को घटाने के लिए पड़ रहे अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के परिप्रेक्ष्य में घोषणा-पत्र में कहा गया है कि पश्चिमी देशों की सरकारों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर आरोपित ऊँचे कर इन पदार्थों की ऊँची कीमतों का वास्तविक कारण है। कराकस सम्मेलन के मेजबान राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने आगे से प्रति 5 वर्ष के अन्तराल पर ओपेक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा इस सम्मेलन में की थी।

तेल उत्पादन कोटों में कटौती के साथ ही ओपेक की विएना बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निगरानी रखी जाएगी तथा इसके नीचे गिरने की स्थिति में रोकथाम की कार्यवाही तत्काल की जाएगी।

¹ प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक वर्ष 2002

9 पन्द्रह निर्गुट एव विकासशील देशों का समुह (समुह-15) :-

सन् 1989 में 'नाम' (NAM) के बेलग्रेड (युगोस्लाविया) में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नौवां शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ, उस दौरान इस सगठन की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। समुह-15 विश्व के 19 विकासशील देशों का एक सगठन है। समुह 15 का पुरा नाम है "सम्मिट लेबल ग्रुप फार साउथ-साउथ कंसल्टेशन एण्ड को-ऑपरेशन" (दक्षिण- दक्षिण सलाह और सहयोग के लिए शिखर समुह) है। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं - भारत, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, युगोस्लाविया, अर्जेंटीना, जमैका, पेरू, मिश्र, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सेनेगल, नाइजीरिया, वेनेजुएला, और अल्जीरिया।

वर्तमान समय में समुह-15 के सदस्य देशों में से अधिकांश देशों में आर्थिक सुधार चल रहा है। इसमें प्रशिक्षित मानव संसाधन, आबादी, बाजार और प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। इन देशों में मजदूरी सस्ती है, इसलिए विकसित देश उसी को मुद्रा बनाकर व्यापारिक बाधाएं खड़ी करना चाहते हैं तथा पर्यावरण, बाल मजदूरी और मानवाधिकार के बहाने भी उनके व्यापार में अड़चने खड़ी करते रहते हैं।

गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, विदेशी कर्ज जैसी चुनौतियों का मुकाबला विकासशील देश सिर्फ आपास में पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही कर सकते हैं। इसी लिए विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना नितान्त आवश्यक है। विकासशील देशों की सामूहिक ताकत से ही राष्ट्र विशेष भी मजबूत होता है। इसके लिए खुली क्षेत्रीयतावाद की नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता है, तथा इसी के अन्तर्गत विकासशील देशों के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ विश्व स्तर पर विकासशील देशों के साथ भी आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ विकसित और विकासशील देशों के बीच एक नयी लोकतांत्रिक भागीदारी कायम करना और आपसी विकास करने के लिए नयी परम्परा की शुरुआत की आवश्यकता है। जिसकी वजह से केवल समुह-15 के देशों का ही नहीं बल्कि सभी विकासशील देशों का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है।

इस सगठन के पाचवें शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने गरीबी, बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त किया। लेकिन इस प्रकार की चिन्ताओं को केवल सम्मेलनों तक रख छोड़ने से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती है, और केवल

अमीर देशों पर किसी प्रकार का तोहमत लगाकर ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं ढुंढा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी विकासशील और विकास की दौड़ में जो देश पिछड़ गये हैं, उन देशों को आपस में एकजुट होकर विकास के लिए स्वयं प्रायस करना चाहिये तथा अमीर और विकसित देशों पर से अपनी निर्भरता को भी कम करने की जरूरत है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने इसका समर्थन करते हुए पाचवे शिखर सम्मेलन में कहा कि "उत्पादन तथा सेवाओं के क्षेत्र में विकासशील देशों की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था में समानता के आधार पर जुड़ सकें और विकास व व्यापार के नये केन्द्र बिन्दु बन सकें।"

तालिका-5 2

जी-15 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ

शिखर सम्मेलन	आयोजन स्थल
प्रथम (1990)	क्वालालम्पुर (मलेशिया)
द्वितीय (1991)	कराकस (वेनेजुएला)
तृतीय (1992)	डकार (सेनेगल)
चतुर्थ (1994)	नई दिल्ली (भारत)
पाचवा (1995)	ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना)
छठा (1996)	हरारे (जिम्बाब्वे)
सप्तम (1997)	क्वालालम्पुर (मलेशिया)
आठवा (1998)	काहिरा (मिस्र)
नौवा (1999)	मोण्टेगो बे (जमैका)
दसवा (2000)	काहिरा (मिस्र)
ग्यारहवा (2001)	जकार्ता (इण्डोनेशिया)
बारहवा (2002)	वेनेजुएला (प्रस्तावित)

जी-15 सगठन में 19 सदस्य देश हैं, जिनमें अमरीकी महाद्वीप से मेक्सिको जमैका, कोलम्बिया, वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, चिली व अर्जेंटीना। अफ्रीकी महाद्वीप से सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, ईरान व कीनिया। एशिया महाद्वीप से भारत, मलेशिया, इण्डोनेशिया तथा श्रीलंका शामिल हैं। जी-15 सगठन के 19 देशों में ब्राजील तथा मेक्सिको को छोड़कर शेष सभी देश निर्गुट राष्ट्र हैं। सदस्य देशों द्वारा प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि जी-15 विकसित देशों के जी-7 के विरुद्ध खड़ा किया गया कोई सगठन नहीं है,

¹ क्रानिकल मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स ग्रा० लि०, 208, शिवलोक हाउस-1, नई दिल्ली 110015
पृ०-15

बल्कि विकासशील देशों के वृहत्तर संगठन जी-77 को और भी अधिक सार्थक बनाने का प्रयास है।¹

उल्लेखनीय है कि जी-15 के सदस्य राष्ट्र मिलकर विश्व की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत, विकासशील जगत् के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 43 प्रतिशत विकासशील देशों के कुल निर्यात व आयात के क्रमशः 25 व 22 प्रतिशत तथा तीसरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र के 34 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त रूप से इन देशों का सरल घरेलू उत्पाद लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तथा विदेशी व्यापार 500 अरब डॉलर का है।

जी-15 का ग्यारहवाँ शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 31 मई-1 जून, 2001 को सम्पन्न हुआ। गम्भीर राजनीतिक संकट एवं महाभियोग की कार्यवाही का समना कर रहे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान वाहिद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मेजबान राष्ट्रपति पर छाए राजनीतिक संकट से यह सम्मेलन अछूता नहीं रहा। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति कृष्णाकांत ने किया, जो इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद कम्बोडिया की सरकारी यात्रा पर रवाना हो गये।

जी-15 के ग्यारहवें शिखर सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियाँ एक शक्ति सम्पन्न आयोग के गठन के निर्णय तथा 'विकास हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर जकार्ता घोषणा-पत्र' को स्वीकार किया जाना रहा। जी-15 के आगामी (12वें) शिखर सम्मेलन के मेजबान वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चोवेज (Hugo Chavez) के आह्वान पर गठित किये जाने वाला प्रस्तावित आयोग समूह-15 के निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास करेगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर स्वीकार किया गया जकार्ता घोषणा-पत्र जी-15 का पहला सार्वभौमिक घोषणा-पत्र बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के परिणामस्वरूप विश्व में उत्पन्न हुए 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने के लिए समयबद्ध कार्य योजना के अभाव में अमीरी व गरीबी के बीच की खाई में और वृद्धि होगी। उच्च प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में भारत एवं मलेशिया द्वारा प्राप्त की गई श्रेष्ठता में समूह के सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी का आह्वान भी इसमें किया गया है।

¹ प्रतियोगिता दर्पण, अतिरक्तांक, वर्ष-2002

10. आठ विकसित देशों का समूह : [G-8] :-

प्रारम्भ में जी-7 विश्व के सात औद्योगिक रूप से विकसित गैर-समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमरीका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व जापान सम्मिलित थे। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात् रूस भी इस संगठन का 21 जून, 1997 को सदस्य बन गया, अतः अब इसे G-8 के नाम से जाना जाता है। G-8 का पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रम्बोनिलेट (Rambouillet) में नवम्बर 1975 में हुआ था, उस समय इसके अन्तर्गत पाँच प्रमुख औद्योगिक देश अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, 40 जर्मनी तथा जापान थे, 1976 में कनाडा तथा इटली को भी इसमें शामिल कर लिया। G-8 के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सम्पन्न होता है जिसमें विश्व की राजनीतिक समस्या तथा आर्थिक मुद्दों पर वार्ता की जाती है।

आठ औद्योगिक देशों के समूह जी-8 का 27वाँ तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन इटली के तटवर्ती शहर जेनोआ में 20-22 जुलाई, 2001 को सम्पन्न हुआ। पूँजीवाद विरोधियों के हिंसक प्रदर्शनों के साए में सम्पन्न इस सम्मेलन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इटली प्रशासन द्वारा की गई थी। अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक, इटली के राष्ट्रपति सिल्वियो बर्लुस्कोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री जीन श्रेतियो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जापान के प्रधानमंत्री जुनिशिरो कोइजुमी व जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के प्रधानमंत्री गार्ड बेरहोफस्टाड तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रोमनो प्रोदी अपने-अपने प्रतिनिधि मण्डलों के साथ इस सम्मेलन में उपस्थित थे।

निर्धन राष्ट्रों के ऋणग्रस्तता, भूमण्डलीकरण व विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी मुद्दे इस सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय रहे। अफ्रीका की निर्धनता इस सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय रही, अफ्रीका के विकास के लिए नई किस्म की भागीदारी का निर्णय सम्मेलन में किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पहल पर स्वीकृत की गई इस योजना के तहत जी-8 के नेता व्यक्तिगत तौर पर प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे जो अफ्रीकी नेताओं से मिलकर ठोस प्रावधान तैयार करेंगे। इस योजना को कनाडा में होने वाले जी-8 के आगामी शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी घोषणा-पत्र में विश्व व्यापार संगठन की नए दौर की वार्ता का स्वागत किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग से

सम्बन्धित क्योटो सन्धि पर अमरीका के साथ मतभेद बने रहने की बात भी घोषणा-पत्र में स्वीकार की गई है। अमरीका की प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली, जिसके लिए एबीएम सन्धि को त्यागने की धमकी अमरीका ने दी है, का घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समुह का अगला शिखर सम्मेलन 2002 में अल्बर्ट (कनाडा) के शहर में आयोजित करने का निर्णय जेनोआ सम्मेलन में किया गया, साथ ही यह भी तय किया गया कि कनाडा शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों के प्रतिनिधिमण्डलों में सदस्यों की संख्या 30-40 तक ही सीमित रहे, जेनेवा सम्मेलन में प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल में सैकड़ों सदस्य शामिल थे। सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधिमण्डल में सदस्यों की संख्या जहाँ 900 के आसपास थी, वहीं जर्मनी के प्रतिनिधिमण्डल में लगभग 600 सदस्य शामिल थे।

11. ओ0 ई0 सी0 डी0 :-

ओ0ई0सी0डी0 का पूरा नाम आर्थिक विकास व सहयोग सगठन है। पहले इसके सदस्यों की संख्या 24 थी लेकिन 1 जनवरी 1996 में विश्व के विकसित देशों की सूची में सिंगापुर के शामिल हो जाने की वजह से इसकी संख्या 25 हो गयी तथा इस सगठन का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है। ओ0 ई0 सी0 डी0 विश्व के सभी विकसित देशों का सगठन है। वर्तमान समय में उसके 29 सदस्य देश हैं। जिसमें आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक, हंगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान लक्जेंबर्ग, नीदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, टर्की यू0 के0 तथा यू0 एस0 ए0।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन बनाया गया। तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा प्रस्तावित सहायता अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में ओ0 ई0 सी0 डी0 का गठन किया गया, इसे मार्शल सहायता के नाम से भी जाना जाता रहा है। 1948 में पेरिस में आयोजित यूरोपीय देशों के एक सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर सहमति हुई तथा उसके बाद 1961 में इसका नाम बदलकर ओ0 ई0 सी0 डी0 रख दिया गया, क्योंकि तब तक इसमें गैर-यूरोपीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी शामिल हो गये थे। इस पुनर्गठित संस्था का उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक प्रगति में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना तथा लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करना है।

तालिका-53
विश्व में प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक गुट

क्र.सं.	गुट का नाम	सदस्य देश	उद्देश्य
1	अमेरिकी देशों का संगठन	उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के 35 देश इसके सदस्य हैं तथा एशिया, अफ्रिका और यूरोप में 25 देश पर्यवेक्षक हैं।	शांति व सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
2	निःशुल्क व्यापार सघ का अंतर-परिसघ	103 देशों (भारत नहीं) के 144 राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं।	व्यापार सघ आंदोलन का विकास करना।
3	निर्यात नियन्त्रण समन्वय समिति	अमेरिका, जापान, फ्रांस और जर्मनी सहित 17 सदस्य देशों तथा अन्य 8 समन्वयक देश।	सदस्य देशों के बीच सामरिक वस्तुओं एवं तकनीकी आँकड़ों के निर्यात पर नियन्त्रण रखना।
4	सीमा शुल्क सहयोग समिति	भारत और अमेरिका सहित 108 सदस्य देश।	सीमा - शुल्क विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना।
5	अरब आर्थिक एकता समिति	सोमालिया, सूडान, यू0ए0ई0, यमन, मिश्र, इराक, जार्डन, कुवैत, लीबिया, पी0एल0ओ0, सीरिया।	अरब देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देना (30 मई, 1964 से प्रभावी)।
6	बेनेलेक्स इकोनोमिक यूनियन	बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग।	आर्थिक सहयोग एवं एकीकरण को विकसित करना (1 नवम्बर, 1960 से प्रभावी)।
7.	इपटा	यूरोपीय निःशुल्क व्यापार सघ के सदस्य देश हैं - स्विटजरलैंड, नार्वे, आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क, पुर्तगाल, आइसलैंड।	निःशुल्क व्यापार के प्रसार का विस्तार करना (3 मई, 1960 से प्रभावी)।
8.	केन्द्रीय अमेरिकी सामान्य बाजार	निकारागुआ, होन्डुरास, एल-सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका।	केन्द्रीय अमेरिकी सामान्य बाजारों की स्थापना को बढ़ावा (3 जून 1961 से प्रभावी)।

9	केन्द्रीय अफ्रीकी सीमा शुल्क व आर्थिक सघ	कागो, चाड, कैमरून, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आदि।	केन्द्रीय अफ्रीकी सामान्य बाजारो को स्थापित करने पर बल (1 जनवरी, 1966 से प्रभावी)।
10	जी-77	भारत व पी0एल0ओ सहित 128 विकासशील देश।	आर्थिक सहयोग बढ़ाना।
11	दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क व सघ	बोत्सवाना, वेन्डा, बोयूथात्सवाना, किस्की, ट्रॉसकेई, लेसेथो, नामीबिया, द0 अफ्रीका, स्वाजिलैण्ड।	मुक्त व्यापार और सीमा - शुल्क में मामले में सहयोग।
12	इस्लामी सम्मेलन सगठन	विश्व में 47 मुस्लिम देश तथा फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन इसके सदस्य हैं।	इस्लामी सौहार्द तथा आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक सहयोग को बढ़ावा देना।
13	जगगर समिति	अमेरिका, जापान, इटली, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा सहित 25 सदस्य।	निर्यात नियन्त्रण प्रावधानों आदि के लिए दिशा निर्देश तैयार करना।
14	पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय	बेनिन, बुर्कीना, आइवरी कोस्ट, माली, मौरिटानिया, नाइजर, सेनेगल तथा पर्यवेक्षक के रूप में टोगो।	क्षेत्रीय आर्थिक विकास संवर्द्धन।
15	जी-24	भारत और पाकिस्तान सहित अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में 24 देश।	आई0एम0एफ0 के तहत सदस्य देशों का हित संवर्द्धन करना।
16	लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रणाली	दक्षिण अमेरिका के 26 देशों का सगठन।	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
17	पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय	पश्चिमी अफ्रीका के 16 देश।	क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
18.	दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन	मलावी, बोत्सवाना, लेसेथो, अंगोला, स्वाजिलैण्ड, नामीबिया, मोजाम्बिक, तजानिया, जाम्बिया, जिम्बावे।	क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

19	लैटिन अमेरीका एकता सगठन	ब्राजील, चिली, बोलिविया, अर्जेन्टीना, पेरागुवे, कोलम्बिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, युरुगवे, बेनेजुएला।	निशुल्क क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। यह सगठन 18 मार्च, 1981 से प्रभावी हुआ।
20	खाडी सहयोग समिति	स0अ0 अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर (6 सदस्य)।	आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सैन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का सम्वर्द्धन करना।
21	पूर्वी कैरिबियाई राज्यों का सगठन	एटीगुआ व बरबुडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मोटसेरात, सेटीकीट्स व नेविस, सेट लूसिया, सेट विसेट तथा ग्रेनाडिन।	आर्थिक, राजनीतिक व प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
22	एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग	अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, हांगकांग, द0 कोरिया, न्यूजीलैण्ड, ताइवान, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस।	प्रशांत बेसिन में व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करना।
23	अरब सहयोग समिति	मिश्र, इराक, यमन, जार्डन।	अरब के सामान्य बाजार को हर सम्भव तरीके से उन्नत करना, आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना।
24	जी-3	कोलम्बिया, मैक्सिको, बेनेजुएला	मशीनीकरण हेतु नीति समन्वय
25	दक्षिणी शकु सयुक्त मंडी	युरुगवे, ब्राजील, पेरागुवे, अर्जेन्टीना	क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग।
26	षट्कोणीय समूह	हंगरी, इटली, पोलैण्ड, आस्ट्रिया, चेक, यूगोस्लाविया (पूर्व), स्लोवाकिया।	एड्रीटिक एवं बाल्टिक सागर के मध्य स्थित क्षेत्रीय समूहों हेतु आर्थिक राजनीतिक समूह।
27	नाफटा	अमरीका, कनाडा, मैक्सिको	यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा जापान की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना।

28	एपेक	आस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, चीन, मेक्सिको, जापान, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, ब्रूनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैण्ड, पपुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चिली, पेरू, रूस तथा वियतनाम।	सन् 2020 तक एशिया प्रशान्त क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र होगा।
29	मर्कोसूर	ब्राजील, अर्जेन्टीना, पराग्वे व उरुग्वे।	स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना।
30	ओपेक	अल्जीरिया, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बनेजुएला।	तेल उत्पादन कोटे में कटौती, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निगरानी मूल्य गिरने की स्थिति में रोकथाम की कार्यवाही करना।
31	दक्षेस	भारत, पाकिस्तान, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव।	दक्षिण एशियाई वरियता व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत रियाती प्रशुल्को पर व्यापार करना।
32	पन्द्रह निगुर्ट एव विकास-शील देशों का समूह (जी-15)।	भारत, मेक्सिको, जमैका, बनेजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेन्टीना, सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बावे, मिश्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चिली, कीनिया, श्रीलंका, कोलम्बिया व ईरान।	विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
33	आर्थिक सहयोग एव विकास का सगठन (ओईसीडी)	आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक, हंगरी, कोरिया, मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्वीटजरलैण्ड, टर्की, यूके तथा यूएसए।	सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक एव सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों का समन्वय करना तथा उसके सदस्यों को विकासशील देशों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना।

34	ऐसेम	यूरोपीय सघ के 15 व एसियान के 7 देशों के साथ-साथ जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, को शामिल करते हुए एशिया के 10 देश।	एशियाई व यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य मुक्त व्यापार व वित्तीय सकट से निपटने हेतु सक्षम बनाने का प्रयास।
35	एशियाई क्लीयरिंग यूनियन	भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, व म्यांमार।	एशियाई देशों के चालू अन्तराष्ट्रीय लेन-देनों के लिए समाशोधन सुविधा उपलब्ध कराना।
36	आठ विकसित देशों का समूह (जी-8)	अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, तथा रूस।	विश्व की आर्थिक मुद्दों व राजनीतिक समस्याओं के लिए निराकरण का प्रयास।
37	आठ मुस्लिम विकासशील राष्ट्रों का समूह (डी-8)	टर्की, ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान व बांग्लादेश।	अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पारस्परिक सहयोग।
38	बीस औद्योगिक एवं विकासशील देशों का समूह (जी-20)	अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, द० कोरिया, टर्की तथा फिलिपिन्स।	मौजूदा विश्व वित्तीय सकट से निपटने के नये उपायों को तलाश करना।

12. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) :-

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को पूरा करने के लिए हाल ही के वर्षों में भारत सरकार ने लगभग सभी उत्पादों के आयात से परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा दिये हैं, इनमें अधिकांशतः उपभोक्ता उत्पाद हैं देश के भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए (तथा सम्भवतः स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी) यद्यपि भारत सरकार इन प्रतिबन्धों को शीघ्र ही हटाने के पक्ष में नहीं थी। किन्तु व्यापार के भागीदार विकसित देशों के दबाव के चलते भारत ने इन सभी उत्पादों के आयात पर से अप्रैल 2002 तक परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटाने को सहमत हो गया था। भारत ने इस आशय का एक समझौता यूरोपीय देशों के साथ किया था। किन्तु इस समय सीमा से असन्तुष्ट अमेरिका इस मामले को जुलाई 1997 में विश्व व्यापार संगठन में ले गया। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement

Body) के समक्ष भारत ने यह दलील पेश की कि देश के भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए। उन सभी उत्पादों (उस समय परिणामात्मक प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादों की संख्या 2714 थी) के आयात पर से प्रतिबन्धों की समाप्ति के लिए 6 वर्ष का समय उचित है। भारत की दलील को अस्वीकार करते हुए विवाद निपटान निकाय (DSB) ने 6 अप्रैल, 1999 को अमरीका के पक्ष में फैसला सुनाया। डी एस बी के इस फैसले के विरुद्ध भारत ने विश्व व्यापार संगठन के अपीली निकाय (Appellate Body) में अपील की, किन्तु अपीली निकाय ने 23 अगस्त, 1999 के अपने फैसले में विवाद निपटान निकाय के फैसले को बरकरार रखा। अपीली निकाय द्वारा भारत की अपील के ठुकराए जाने के पश्चात् विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय ने भारत को 22 सितम्बर, 1999 को यह निर्देश दिया कि वह इस मामले में अमरीका के साथ समझौता करे अन्यथा भारत से किये जाने वाले आयातों पर दण्डात्मक प्रशुल्क (Penal Tariffs) लगाने की उसे छूट होगी। इसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में भारत ने सभी 1429 उत्पादों के आयात पर से अप्रैल 2001 तक प्रतिबन्ध हटाने के लिए अमरीका से अपनी सहमति व्यक्त की थी।¹

अमरीका के साथ सम्पन्न ताजा समझौते के तहत भारत को 714 उत्पादों के आयात पर से प्रतिबन्ध 1 अप्रैल, 2000 तक हटाने थे, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने अपनी आयात निर्यात नीति 2000-2001 के अन्तर्गत कर दी थी, जबकि शेष 715 उत्पादों को 1 अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक आयात नियंत्रण से मुक्त कर दिया है नियंत्रण मुक्त किए गए 715 उत्पादों में से 300 उत्पादों को अति सवेदनशील बताया गया है जिनके आयात पर निगरानी रखने के लिए उच्चस्तरीय वार रूम (War Room) का गठन सरकार ने किया है।

तालिका-54

WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ		
सम्मेलन	वर्ष	स्थान
पहला	9-13 दिसम्बर, 1996	सिंगापुर
दूसरा	18-20 मई, 1998	जेनेवा
तीसरा	30 नवम्बर, 3 दिसम्बर, 1999	सिएटल
चौथा	9-14 नवम्बर, 2001	दोहा (कतर)
पाँचवाँ	2003	मेक्सिको (प्रस्तावित)

¹ प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2002 पृष्ठ 172।

WTO का चौथा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन -

दोहा (कतर) में 9-13 नवम्बर, 2001 को आयोजित विश्व व्यापार संगठन का चौथा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर सदस्य राष्ट्रों की सहमति के लिए एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा। अतः इसका समापन 14 नवम्बर, 2001 को हुआ, 142 सदस्य राष्ट्रों के वाणिज्य मंत्रियों के इस सम्मेलन में कृषि, सेवाओं व औद्योगिक उत्पादों के व्यापार के विस्तार एवं पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर नए सिरे से वार्ता का दौर प्रारम्भ करने की सहमति अन्ततः छठे दिन ही बन सकी। इसके एजेन्डे (दोहा डेवलपमेंट एजेन्डे) को स्वीकार किया जाना, विकासशील राष्ट्रों की बजाय यूरोपीय संघ एवं अमरीका के लिए ही अधिक लाभदायक माना जा रहा है। इस मामले में भारत की मुख्य आपत्ति चार सिंगापुर मुद्दों को लेकर थी। इनमें विदेशी निवेश (Foreign Investment) व प्रतिस्पर्धा नीति (Competition Policy) के सम्बन्ध में नए वैश्विक नियमों के निर्धारण, सरकारी परियोजनाओं के लिए सामान की खरीद में विदेशी कम्पनियों को अवसर प्रदान करने तथा व्यापारिक नियमों को सरल बनाने (Trade Facilitation) के मुद्दे शामिल थे। मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में स्वीकार किए गए दोहा घोषणा-पत्र को भारत ने अपनी मजूरी तभी प्रदान की जब सम्मेलन के अध्यक्ष शेख यूसुफ हुसैन कमाल (कतर के वाणिज्य, वित्त एवं आर्थिक मामलों के मंत्री) ने यह स्पष्ट घोषणा की कि उपर्युक्त चारों विवादित मुद्दों पर बातचीत सदस्य राष्ट्रों की सहमति हो जाने पर ही पॉचवे मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद शुरू होगी। दोहा डेवलपमेंट एजेन्डे पर बातचीत 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य यद्यपि घोषणा-पत्र में निर्धारित किया गया है, तथापि यह आम तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि यह 2007 से पहले पूरी नहीं हो सकेगी, यह बातचीत जनवरी 2002 से ही प्रारम्भ है।

सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में विकासशील राष्ट्रों को एक बड़ी सफलता जनस्वास्थ्य सम्बन्धी औषधियों के उत्पादन एवं अधिग्रहण के मामले में मिली है। एच0 आई0 वी0/एड्स, टी0बी0 व मलेरिया आदि रोगों से जनसामान्य की सुरक्षा के लिए औषधियों के उत्पादन के मामले में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) एवं पेटेंट सम्बन्धी नियम अब आड़े नहीं आ सकेंगे। इस मामले में दी गई छूट के परिणामस्वरूप कोई देश जनस्वास्थ्य के लिए पेटेंट शुल्क दवाओं का सस्ता उत्पादन करने के लिए किसी भी कम्पनी को लाइसेंस दे सकेगा। कृषि के क्षेत्र में डोमेस्टिक सपोर्ट तथा निर्यात सब्सिडी में कटौती का प्रस्ताव, दोहा घोषणा-पत्र में शामिल किए जाने से विकासशील राष्ट्रों के किसान लाभान्वित हो सकेंगे इससे भारत को भी लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि दोहा सम्मेलन में चीन व ताइवान को भी विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बना लिया गया है यह दोनों इस सगठन के क्रमशः 143 वे व 144 वे सदस्य हैं। WTO का आगामी पॉचवॉ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सन् 2003 में मेक्सिको में होगा।

दोहा घोषणा पत्र

दोहा घोषणा पत्र जिसमें एक मुख्य घोषणा 'ट्रिप्स' करार और जन स्वास्थ्य पर एक घोषणा तथा कार्यान्वयन सबद्ध मुद्दों और चिन्ताओं पर निर्णय शामिल है। विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यूटीओ) का भावी कार्यकरण प्रारम्भ करता है, और इसमें कृषि तथा सेवाओं वर्तमान बातचीत के लिए विस्तारण और समयसारणी तथा अन्य कार्य मुद्दों में बातचीत शामिल है।¹

कार्यान्वयन सबद्धी मुद्दे — नए एसपीएस और टीबीटी उपायों के अनुपालनार्थ दीर्घ समय सीमा (छ महीने की) "ट्रिप्स" करार के अधीन उल्लघन नहीं करने की शिकायतों पर दो वर्ष की छूट एक वर्ष के भीतर बैंक-टु-बैंक डपिंग-रोधी जाच और घोषित मूल्यों से सबन्धित जाच में सदस्यों द्वारा सहभाग और सहायता सहित कार्यान्वयन सबद्ध मुद्दों और चिन्ताओं पर निर्णय में कार्यान्वयन सबद्धी कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। घोषणा यह सहमति देती है कि अन्य सभी बकाया कार्यान्वयन सबद्धी मुद्दे कार्यकरण कार्यक्रम का अभिन्न अंग होंगे। जहाँ विशिष्ट वार्ताएँ अधिदेशित हैं वहाँ कार्यान्वयन सबद्धी सगठन मुद्दों पर उस अधिदेश के अधीन ध्यान दिया जायेगा और अन्य बकाया कार्यान्वयन सबद्धी मुद्दों पर विश्व व्यापार सगठन के सगठन निकायों, उपयुक्त कार्रवाई के लिए वर्ष 2002 के अंत तक व्यापार वार्ता समिति को रिपोर्ट करेंगे, द्वारा प्राथमिकता के मामले के रूप में ध्यान दिया जायेगा।

कृषि :- घोषणा विकासशील देशों के लिए बाजार पहुँच में काफी सुधारों, सभी किस्म की निर्यात सबद्धी आर्थिक सहायताओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की दृष्टि से कमी करने, और विकसित देशों द्वारा दिए जा रहे व्यापार विकृत करने वाले घरेलू समर्थन में काफी कमी करने के लिए लक्षित व्यापक वार्ताओं के लिए वचनबद्ध हैं। यह विकासशील देशों की व्यापार-भिन्न चिन्ताओं तथा खाद्य-सुरक्षा और ग्रामीण विकास सहित उनकी विकास सबद्धी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती हैं। विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार वार्ताओं का एक अभिन्न अंग होगा।

¹ आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001-2002

सेवाएँ – सेवाओं में व्यापार की परिषद द्वारा अपनाई गयी वार्ता सबधी दिशा निर्देश और कार्यविधियाँ “गैट्स” के उद्देश्यों के प्रति के दृष्टिगत सेवाओं में अनवरत वार्ता का आधार बनेगी। यह घोषणा देशजात व्यक्तियों के आवागमन सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कई प्रस्तावों को मानती है।

औद्योगिक टैरिफ – औद्योगिक टैरिफ के आधीन वार्ता का लक्ष्य टैरिफ शीर्ष, उच्च टैरिफ और टैरिफ वृद्धियों की कमी सहित, टैरिफ को कम करना अथवा यथा उपयुक्त हटाना तथा साथ ही विशेषकर विकासशील देशों को निर्यात की दिलचस्पी वाले उत्पादों पर टैरिफ-भिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। उत्पाद का सीमा क्षेत्र व्यापक और कमी करने की वचनबद्धताओं में पूर्ण अन्योन्यता से कम के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखने वाली वार्ताओं के पूर्ण अपवर्जन के बिना होगा।

“ट्रिप्स” – कार्यक्रम कार्यक्रम मंत्री-स्तरीय सम्मेलन के 5वें सत्र द्वारा शराब (वाइन) और स्पिरिट के लिए भौगोलिक संकेतों की अधिसूचना और पंजीकरण की एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना पर वार्ता अधिदेशित करता है। शराब (वाइन) और स्पिरिट के अतिरिक्त अन्य उत्पादों पर भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के उच्च स्तर के विस्तार से संबंधित मुद्दों “ट्रिप्स” करार और जैविक विविधता पर समझौता (सीबीडी) के बीच संबंधों की जांच, पारम्परिक ज्ञान और लोक साहित्य के संरक्षण और अन्य सगत नये घटना क्रमों पर “ट्रिप्स” परिषद द्वारा कार्यान्वयन सबधी मुद्दों के भाग के रूप में ध्यान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त “ट्रिप्स” और जन-स्वास्थ्य पर घोषणा दोहा सम्मेलन के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणामों में से एक थी। यह मानती है कि “ट्रिप्स” करार की जनस्वास्थ्य के संरक्षण और सभी के लिए दवाईयों तक पहुंच का संवर्धन करने के लिए डब्लू0टी0ओ0 सदस्यों के समर्थनकारी तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए और उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन नियम :- घोषणा अधिदेश बातों का लक्ष्य तथा सन्निधियों तथा प्रतिकारी उपायों पर करार के अंतर्गत, इन करारों की बुनियादी अवधारणा सिद्धांत तथा प्रभावीपन को सुरक्षित रखते हुए, नियमावलियों को स्पष्ट करने तथा सुधार करने का था तथा विकासशील देशों की जरूरतों पर गौर करना था। इसमें वार्ताएँ जिनमें क्षेत्रीय व्यापार करार पर प्रयोज्य मौजूदा विश्व व्यापार संगठन के उपबंधों (इन करारों के विकासात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए) के अधीन नियमावलियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना तथा उनमें सुधार करना था, शामिल थी। इसके अलावा वार्ताओं को विवाद निपटान समझौते के सुधारों तथा स्पष्टीकरण

पर अधिदेशित किया गया। इन विषयों पर विशेष क्रियान्वयन मुद्दों को संबोधित करना इन वार्ताओं का एक अटूट भाग होगा।

विशेष एव अन्तरीय व्यवहार (एस एण्ड डी) – वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए विशेष तथा अन्तरीय व्यवहार के सिद्धान्त पर पूर्ण विचार किया जायेगा। सभी विशेष एव अन्तरीय व्यवहार उपबन्धों को उन्हें मजबूत करने तथा उन्हें और सुस्पष्ट प्रभावी तथा परिचालित बनाने के उद्देश्य से इनकी समीक्षा करने पर भी सहमति हो गई है।

इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य – कार्यक्रम कार्यक्रम घोषणा करता है कि सदस्य पाँचवें मन्त्रीपक्षीय सत्र तक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारणों पर सीमाशुल्क नहीं लागू करने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखेंगे।

सिंगापुर मुद्दे – व्यापार एव निवेश, व्यापार एव प्रतियोगिता के मध्य पारस्परिक प्रभाव, सरकारी प्रबन्ध तथा व्यापार सुविधा में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे कार्यदल अध्ययन प्रक्रिया में उठाये जाने जारी रहेंगे। कार्यक्रम कार्यक्रम के अनुसार इन विषयों पर वार्ताएँ मन्त्रीपक्षीय सम्मेलन के बाद पाँचवें सत्र के बाद, वार्ताओं की जटिलताओं पर उस सत्र में, सुनिश्चित सहमति से किये गए निर्णयों के आधार पर की जायेगी।

पर्यावरण – व्यापार तथा वातावरण (मौजूदा विश्व व्यापार सगठन नियम तथा बहुपक्षीय पर्यावरणिक करार में निर्धारित विशेष व्यापार बाधकताओं के सबन्ध, विदेश मन्त्रालय तथा विश्व व्यापार सगठन के बीच नियमित सूचना विनियम के लिए प्रक्रियाएँ तथा पर्यावरणिक वस्तुओं तथा सेवाओं को टैरिफ तथा टैरिफ-भिन्न बैरियरों की कटौती/समाप्ति) के सीमित पहलुओं पर वार्ताओं को, बाजार पहुँच के मुद्दों, टी आर आई पी एस करार के प्रासंगिक उपबन्ध तथा लेबलिंग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापार तथा पर्यावरण पर समिति की इसकी कार्यसूची में सभी मद्दों पर कार्य करने के अनुदेशों के साथ, अधिदेशित किया गया है।

श्रम – घोषणा मान्यता देती है कि महत्वपूर्ण श्रम मानदंडों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन एक उचित मंच है।

कार्यदल – कार्यक्रम कार्यक्रम ने दो कार्यदलों को भी गठित किया है एक का कार्य विश्व व्यापार सगठन अधिदेश के भीतर व्यापार, ऋण तथा वित्त के बीच, विकासशील देशों की विदेशी ऋणग्रस्तता की समस्या के हल के लिए सुझाव देने के लिए बने सबन्ध की जांच करना और वित्तीय तथा आर्थिक अस्थायित्व के प्रभावों से बहुपक्षीय व्यापार तंत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्तीय नीतियों के सामंजस्य को मजबूत करना है। दूसरा कार्यदल

व्यापार तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के बीच सबध की जाच करेगा तथा विश्व व्यापार सगठन अधिदेश के भीतर विकासशील देशो की प्रौद्योगिकी के बढे हुए प्रवाह को सुकर बनायेगा।

कार्यकरण कार्यक्रम के अतर्गत वार्ताओ को 1 जनवरी 2005 के बाद निष्पादित नही किया जाना है (विवाद निपटान समझौता जो मई, 2003 के अत तक निष्पादिक किया जाना है, को सुधार तथा स्पष्ट करने पर वार्ता के सिवाय)। वार्ताओ के परिणाम के सचालन, निष्कर्ष तथा प्रवृत्त होने को एक एकल उपक्रम के भाग के रूप मे व्यवहृत किया जायेगा (सिवाय विवाद निपटान समझौते के) वार्ताओ का समगत् सचालन सामान्य परिषद के प्राधिकारी के अधीन एक व्यापार वार्ता समिति द्वारा पर्यवेक्षित किया जाना है।

13 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन—अंकटाड :-

सन् 1961 मे संयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा ने 1961-70 को विकास दशक (Development decade) घोषित किया तथा इसका मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित देशो की आय मे 5% प्रति वर्ष वृद्धि लाने का था। इस अहम मुद्दे को लेकर महासचिव से एक विश्व सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया गया, जुलाई 1962 मे काहिरा मे विकासशील देशो का एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन ने भी एक विश्व सम्मेलन की माँग की, इसी उद्देश्य को लेकर सघ के महासचिव के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् ने जेनेवा मे एक विश्व-व्यापार एवं विकास सम्मेलन बुलाया, जो 31 मार्च, 1964 से 16 जून, 1964 तक चला। इसमे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विश्वव्यापी नीति निर्धारित की गई तथा विकासशील देशो की विशेष आवश्यकताओ एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार सम्बन्धी समस्याओ के व्यवहारिक पहलुओ पर विचार किया गया। वास्तव मे इसी सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD-I) कहा जाता हैं।¹

ऐसा ही दूसरा सम्मेलन (UNCTAD-II) नई दिल्ली मे फरवरी-मार्च 1968 मे, तीसरा सम्मेलन (UNCTAD-III) अप्रैल-मई 1972 मे सेटियागो (चिली) मे, चौथा सम्मेलन (UNCTAD-IV) मई, 1976 मे नैरोबी (अफ्रीका) मे, पाँचवा सम्मेलन (UNCTAD-V) 7 मई, से 2 जून, 1979 तक मनीला (फिलीपीन्स) मे, छटा सम्मेलन (UNCTAD-VI) 6 जून से 03 जुलाई, 1983 तक बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में, सातवाँ सम्मेलन (UNCTAD-VII) 1987 मे जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में, आठवाँ (UNCTAD-VIII) 1992 मे कार्टेजिना डी इण्डियाज

¹ प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था - वर्ष 2002 पृष्ठ 113

(कोलम्बिया) में, नौवें सम्मेलन (UNCTAD-IX) 27 अप्रैल से 11 मई, 1996 तक दक्षिण अफ्रीका के मिडरैंड में तथा दसवें सम्मेलन (UNCTAD-X) 12-19 फरवरी, 2000 को बैकाक में सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का यह सम्मेलन एक स्थायी संगठन बन गया है, इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है। द0 अफ्रीका के एलेक इरविन अकटाड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चार वर्ष के अन्तराल में सामान्यतः इसका अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी सभी सभाओं में IMF को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है इसी कारण UNCTAD द्वारा पारित प्रस्तावों को IMF अपनी नीति निर्माण में प्रयुक्त करता है, अकटाड के सुझाव मात्र रचानात्मक होते हैं। जिन्हें पालन करने के लिए किसी भी राष्ट्र को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना।
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास से सम्बद्ध आवश्यक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना एवं नीति निर्धारित करना।
- (3) निर्धारित सिद्धान्तों एवं नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- (4) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद् को आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं के कार्यों के साथ तालमेल बैठाना।
- (5) व्यापार सम्बन्धी वार्ता के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।

‘अकटाड’ की सदस्यता व मताधिकार — संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेन्सी के रूप में अकटाड कार्य कर रहा है, जिसकी सदस्यता पूर्णरूपेण ऐच्छिक है। कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छानुसार ‘अकटाड’ की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा परित्याग कर सकता है।

अकटाड की कार्यप्रणाली पूर्णरूपेण प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है, प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, सामान्य महत्व के विवादों पर केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

अकटाड-X सम्मेलन — अकटाड का दसवाँ सत्र 12-19 फरवरी, 2000 को बैंकाक में सम्पन्न हुआ, थाईलैण्ड के डॉ० सुपाचाइ पानिचपकडी (Supachai Panitchapakdi) की अध्यक्षता में सम्पन्न अकटाड का यह सत्र विश्व व्यापार के मुद्दे पर विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के हितों के टकराव से ग्रसित रहा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केन्द्रीय उद्योग, एवं वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन ने किया।

अकटाड-X में भाग लेने वाले 146 देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत बैंकाक घोषणा-पत्र में कहा गया है कि विभिन्न देशों को अपने तौर पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के ठोस प्रयासों से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सभी देशों को विशेषतः अल्पविकसित देशों को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफल रहे, घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि भूमंडलीकरण के जरिए विकास को बढ़ावा देना है, तो इसका प्रबंधन भी सही तरीके से होना चाहिए, घोषणा-पत्र के अनुसार अल्पविकसित देशों को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़े बिना विश्व स्तर पर सन्तुलित और निरन्तर विकास की नींव नहीं डाली जा सकती। इसके लिए खुली एवं सीधी बहस के जरिए विवादित मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाना आवश्यक है, इससे सभी देशों के बुनियादी हितों की रक्षा हो सकेगी। घोषणा-पत्र में विश्व व्यापार संगठन के सिएटल सम्मेलन की विफलता के लिए विकासशील देशों के तीखे मतभेद एवं उनके अडियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया गया है।

14. एशियाई विकास बैंक :-

एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (Economic Commission for Asia & Far East- ECAFE) की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 में की गई थी। 1 जनवरी, 1967 को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया, बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। 2मई, 1996 को मनीला में सम्पन्न बैंक की 29वीं वार्षिक बैठक में जापान के श्री मित्सू सातो (Mitsu Sato) को अगले पाँच वर्ष के लिए बैंक का अध्यक्ष पुनः चुना गया था। उल्लेखनीय है कि ADB का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है। जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमरीका, एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में ADB की सदस्य संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

1974 में इसने एशियाई विकास कोष (Asian Development Found) की स्थापना की, इसका उद्देश्य एशियाई देशों को रियायती ब्याज दर पर उधार देना है। एशियाई विकास कोष (ADF) को सर्वाधिक ऋण अमरीका से प्राप्त होते हैं। भारत में इसने अपना आवासीय कार्यालय नई दिल्ली में खोला है, जिसने 10 दिसम्बर, 1993 से कार्य प्रारम्भ कर दिया, (ADB) की वार्षिक बैठक मई 2001 में हवाई द्वीप में होनोलूलू में सम्पन्न हुई।

15 आठ मुस्लिम विकासशील राष्ट्रों का समूह[D-8]:-

विश्व के आठ मुस्लिम विकासशील राष्ट्रों के समूह डी-8 का दूसरा शिखर सम्मेलन 1-2 मार्च, 1999 को बांग्लादेश में ढाका में सम्पन्न हुआ। 'डेवलपिंग-8' अर्थात् 'डी-8' नाम से इस समूह का गठन जून 1997 इस्ताबुल में आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस (OIC) के 8 बड़ी जनसंख्या वाले देशों ने किया था। इसमें शामिल देशों में टर्की, ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान व बांग्लादेश हैं। जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 80 करोड़ तथा विश्व व्यापार में संयुक्त भागीदारी लगभग 4 प्रतिशत है।

शैशवावस्था के दौर से गुजर रहे इस इस्लामिक संगठन के प्रति सदस्य राष्ट्रों की रुचि का अन्दाजा इससे लगता है कि मेजबान बांग्लादेश के अतिरिक्त केवल तीन अन्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ही मार्च 1999 के शिखर सम्मेलन में उपस्थित हुए इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉ० महाथिर मोहम्मद तथा टर्की के राष्ट्रपति सुलेमान डेमिरेल शामिल थे, शेष राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व निचले स्तर के नेताओं/अधिकारियों ने किया।

सम्मेलन में वैश्विक व्यापार प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया जिससे सम्पन्न व निर्धन, दोनों श्रेणियों के राष्ट्रों को समान लाभ प्राप्त हो सकें। पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधारों के आह्वान के साथ यह शिखर सम्मेलन 2 मार्च 1999 को समाप्त हुआ।

डी-8 का तीसरा शिखर सम्मेलन 25-26 फरवरी, 2001 के अन्तिम सप्ताह में काहिरा में सम्पन्न हुआ, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में पारस्परिक सहयोग के मुद्दों पर इस सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा हुई, सम्मेलन में कहा गया कि निर्धनता की समस्या यद्यपि प्राचीनतम समस्याओं में से एक है, तथापि पिछली शताब्दी में, विशेषतः विगत दशकों में हुए विकास ने इसे ऐसे स्तर पर ला दिया जो राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

16 अफ्रीकी सघ तथा अफ्रीकी आर्थिक समुदाय .—

यूरोपीय सघ (EU) की तर्ज पर अफ्रीकी महाद्वीप के राष्ट्रों के अफ्रीका सघ (African Union- AU) के गठन का प्रस्ताव अफ्रीकी एकता सगठन (Organisation of African Unity- OAU) के सितम्बर 1999 में सम्पन्न शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसके साथ ही अफ्रीकी आर्थिक समुदाय (African Economic Community- AEC) की स्थापना का निर्णय भी 53 सदस्यीय सगठन के इस शिखर सम्मेलन में लिया गया था। लीबियाई राष्ट्रपति गद्दाफी की पहल पर गठित किये जाने वाले अफ्रीकी सघ के लिए चार्टर को बाद में 11 जुलाई, 2000 को टोगो में लोम (Lome) में हुए शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया गया।

इस चार्टर के अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया था कि OAU के 53 सदस्यों में से कम से कम 36 सदस्य राष्ट्रों द्वारा विधिवत अनुमोदन (Ratification) के 30 दिनों के बाद अफ्रीकी सघ अस्तित्व में आ जाएगा। चार्टर (CAAU) का अनुमोदन करने वाले 35वें व 36वें राष्ट्र क्रमशः दक्षिणी अफ्रीका व नाइजीरिया थे। जिन्होंने क्रमशः 23 व 26 अप्रैल 2001 को इसे अनुमोदित किया था। इस प्रकार नाइजीरिया (अनुमोदन प्रदान करने वाला 36वाँ राष्ट्र) के अनुमोदन के 30 दिन बाद 26 मई 2001 से 'अफ्रीकी सघ' अस्तित्व में आ गया है। नवगठित अफ्रीकी सघ (AU) का पहला शिखर सम्मेलन 9-11 जुलाई 2001 को लुसाका (जाम्बिया) में सम्पन्न हुआ।

17. खाड़ी सहयोग परिषद् का शिखर सम्मेलन :—

छ सदस्यीय खाड़ी सहयोग परिषद् (Gulf Cooperation Council) का वार्षिक शिखर सम्मेलन 27-29 नवम्बर, 1999 को सऊदी अरब में रियाद (Riyadh) में सम्पन्न हुआ। खाड़ी क्षेत्र के तेल सम्पन्न छ राष्ट्रों—सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एवं संयुक्त अरब अमीरात के इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सऊदी अरब के शाह फरद ने सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सैन्य सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया ताकि क्षेत्र की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय 'मूड' एवं हितों पर निर्भर न रहे।

सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने आमतौर पर यह स्वीकार किया कि सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी छोटी हैं कि भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर में उभर रहे व्यापार ब्लॉकों से प्रतिस्पर्द्धाओं का सामना करने में वह अलग-अलग से सक्षम नहीं हैं। इन परिस्थितियों में

उभर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए समान प्रशुल्क व्यवस्था वाले खाड़ी देशों के एक साझा बाजार की स्थापना पर खाड़ी के नेताओं ने बल दिया। किन्तु समान प्रशुल्क संरचना पर उनमें आपस में सहमति न हो सकी। परिषद् के सदस्य राष्ट्रों में प्रशुल्क की सबसे ऊँची दरें सऊदी अरब में व सबसे नीची दरें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हैं।

उल्लेखनीय है कि 1981 में स्थापना के बाद से ही खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) सदस्य राष्ट्रों में एकीकृत प्रशुल्क व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रयत्नशील है।

18 बीस औद्योगिक एवं विकासशील देशों का समूह [G-20] :-

मौजूदा विश्व वित्तीय संकट से निपटने के लिए नए उपाय तलाशने के लिए विश्व के प्रमुख 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 15-16 दिसम्बर 1999 को जर्मनी में बर्लिन में सम्पन्न हुआ। 'जी-20' के नाम से इस अनौपचारिक मंच का गठन विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सितम्बर 1999 में वाशिंगटन में सम्पन्न वार्षिक बैठक के दौरान किया गया था। इसमें जी-8 के सात राष्ट्रों-अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली व जर्मनी के अतिरिक्त अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, द0 अफ्रीका, द0 कोरिया, टर्की तथा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहे देश (वर्तमान में फिनलैंड) को शामिल किया गया है।

कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन (Paul Martin) की अध्यक्षता में सम्पन्न (कनाडाई वित्त मंत्री को दो वर्ष के लिए जी-20 का अध्यक्ष बनाया गया है) दिसम्बर 1999 के सम्मेलन में वित्तीय क्षेत्र का नियमन व निगरानी, ऋणों का कुशल प्रबंधन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानक व सहिता चर्चा के मुख्य विषय रहे। सम्मेलन का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अमरीका की इस माँग के परिप्रेक्ष्य में किया गया था कि रुग्ण अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार ऋण देने के स्थान पर उसे आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। फ्रांस व जापान के वित्त मंत्रियों ने अमरीका की इस माँग का कड़ा विरोध किया। अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समुचित 'कुशन' (Cushion) स्थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी का सम्मेलन में आह्वान किया गया। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते नवम्बर 2001 में नई दिल्ली में होने वाले जी-20 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है।

19 'शघाई-5' तथा 'शघाई सहयोग सगठन' :-

मूलतः क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के समाधान के लिए 1996 में गठित 5 देशों के समूह 'शघाई-5' का औपचारिक रूपांतरण अब अपेक्षाकृत अधिक व्यापक 'शघाई सहयोग सगठन' (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) के रूप में हो गया है। नवगठित 'शघाई सहयोग सगठन' में शघाई-5 के पाँच सदस्यों—रूस, चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान व ताजिकिस्तान के अतिरिक्त छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान को भी संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सगठन का पहला शिखर सम्मेलन 14-15 जून 2001 को शघाई (चीन) में सम्पन्न हुआ। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने दो दिन के इस सम्मेलन में भाग लिया तथा इसके घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। ज्ञातव्य है कि उज्बेकिस्तान के अतिरिक्त पाकिस्तान भी 'शघाई-5' की सदस्यता प्राप्त करने को प्रयासरत रहा था। किन्तु उसे नए गठित हुए शघाई सहयोग सगठन में स्थान नहीं प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रूस व चीन की पहल पर 1996 में गठित शघाई-5 जहाँ सदस्य राष्ट्रों के सीमावर्ती विवादों को हल करने में मध्यस्थता करता रहा है। वही शघाई सहयोग सगठन का गठन मुख्यतः तीन समस्याओं— आतंकवाद (Terrorism), अलगाववाद (Separatism) व धार्मिक कट्टरवाद (Extremism) के विरुद्ध मिलकर कार्य करने के लिए किया गया है। तालिबान संरक्षित धार्मिक कट्टरवाद इन सभी राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। धार्मिक कट्टरवाद के अतिरिक्त आतंकवाद व अलगाववाद के फैलते जाल को क्षेत्रीय अखंडता व सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा सगठन के घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है।

सगठन के इस पहले शिखर सम्मेलन में 1972 की एटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि (ABM Treaty) का पुरजोर समर्थन करते हुए अमरीका की राष्ट्रीय मिसाइल सुरक्षा (NMD) परियोजना का कड़ा विरोध किया गया है।

20 बेनेलक्स [BENELUX] :-

यह बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स तथा लक्जमबर्ग का व्यापारिक सघ है। जिसकी स्थापना 1958 में परस्पर व्यापारिक सहयोग के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रूसेल्स (बेल्जियम) में है।

21 यूरोपीय मुक्त व्यापार सघ [EFTA].-

यूरोपीय मुक्त व्यापार सघ की स्थापना स्टॉकहोम में सात देशों द्वारा 3 मई, 1960 को की गई थी। ये सात देश थे— ब्रिटेन, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नार्वे, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन तथा पुर्तगाल। इसकी स्थाना ECC के पैटर्न पर ही की गई थी, तथा इसके उद्देश्य भी उसी के समान रखे गये थे। इन सात देशों को 'आऊटर सैविन' (Outer Seven) के नाम से जाना जाता था जो ECC के तत्कालीन छ सदस्य देशों से अलग थे। ECC के तत्कालीन छ सदस्य देशों को 'इनर सिक्स' (Inner Six) के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर व्यापार के लिए कस्टम ड्यूटी तथा अन्य करों में धीरे-धीरे कटौती करना है। 31 दिसम्बर, 1966 तक लगभग सभी टैरिफ समाप्त करके इसके मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। द्वितीय उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में एक बाजार की स्थापना करना था जो कि 1972 में ECC से समझौते के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा तीसरा उद्देश्य विश्व-व्यापार को बढ़ावा देना है। इस सघ का मुख्यालय जेनेवा में है।

22. भारत यूरोप शिखर बैठक :-

भारत एवं यूरोपीय सघ (EU) की पहली बैठक वर्ष 2000 में पुर्तगाल में लिस्बन में हुई थी। इस बैठक में पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के निर्णय लिए गये। इसी सदर्भ में भारत एवं यूरोपीय सघ की दूसरी शिखर बैठक 23 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली बैठक में भी इन सम्बन्धों के विस्तार की तत्परता दोनों पक्षों ने व्यक्त की। आर्थिक सहयोग सम्वर्द्धन के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान नई दिल्ली बैठक में की गई, उनमें वित्तीय सेवाओं, टेक्स्टाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा एवं विद्युत शामिल हैं। अगले पाँच वर्षों में दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक व्यापार के स्तर को 25 अरब यूरो से बढ़ाकर 50 अरब यूरो तक ले जाने का निर्णय इस शिखर बैठक में किया गया। भारत में 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की

सार्वभौमिक शिक्षा के 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 20 करोड़ यूरो के यूरोपीय सघ के अनुदान के लिए भी एक समझौते पर दोनो पक्षों में हस्ताक्षर हुए। एक अन्य हस्ताक्षरित समझौता विज्ञान एवं प्रद्यौगिकी क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित है।

शिखर बैठक की समाप्ति पर तीनो नेताओं (भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यूरोपीय सघ के अध्यक्ष गॉय वेहोफस्टाड व यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रोमानो प्रोदी) द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा-पत्र में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने तथा ऐसे सभी देशों, संगठनों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाने की माँग की गई है जो आतंकवादियों को समर्थन, प्रश्रय एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

23. यूरो · सामूहिक मुद्रा : —

विश्व के पटल पर बढ़ते आर्थिक एकीकरण अभियानों— नाफ्टा (उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार समझौता), साफ्टा (दक्षिण एशियाई वरीयता— व्यापार समझौता), एसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का सघ), सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन), आदि अनेक के प्रयासों ने क्षेत्रीय आर्थिक गुट की रणनीति को बढ़ावा दिया और इसी कड़ी में जुड़ गया एक और नाम — मास्ट्रिख संधि (Maastricht Treaty), 9-10 दिसम्बर, 1991 को यूरोप आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने मास्ट्रिख (नीदरलैण्ड्स) में आयोजित शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बाद यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकरण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए और यही मास्ट्रिख संधि यूरो करेंसी के उदय की बुनियाद बनी। 1 नवम्बर, 1993 से लागू इस मास्ट्रिख संधि ने राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय सघ (European Union) को जन्म दिया। मास्ट्रिख एवं यूरोपीय सघ की स्थापना के लिए याक डेलोर्स की योजना के परिणाम के रूप में ही आज विश्व पटल पर यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' ने दस्तक दी है।

यूरो जोन में भागीदारी: प्रमुख शर्तें :— मास्ट्रिख संधि के दस्तावेजों में यूरोप में मौद्रिक एवं आर्थिक एकीकरण एवं साझी मुद्रा 'यूरो' के प्रचलन के लिए चार प्रमुख शर्तों का उल्लेख किया गया .—

- 1 मुद्रा स्फीति की दर पर नियन्त्रण (उत्तम निष्पादन करने वाले पहले तीन देशों में प्रचलित मुद्रा स्फीति दर से मुद्रा स्फीति की दर का 15% से अधिक न होना)।

- 2 निम्न ब्याज दर (उत्तम निष्पादन करने वाले प्रथम तीन देशों की ब्याज दर की तुलना में 2% से अधिक न होना)।
- 3 सरकारी ऋण का GDP के 60% से अधिक न होना।
- 4 वार्षिक बजट घाटा GDP के 3% से अधिक न होना।

मास्टरिच संधि में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के देशों से उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' में अपनी भागीदारी दर्ज कर सकें। यूरोप के अब तक 12 राष्ट्रों ने यूरो में भागीदारी हेतु सभी आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा कर लिया है।

15 सदस्यीय यूरोपीय संघ (EU) के 12 राष्ट्रों में एकीकृत मुद्रा 'यूरो' (Euro) का चलन 1 जनवरी, 2002 से प्रारम्भ हो गया है इन राष्ट्रों में आस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस (यूनान), आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल व स्पेन शामिल हैं। यूरो के चलन वाले 12 राष्ट्रों के लगभग 30 करोड़ जनसंख्या वाले इस क्षेत्र को यूरोजोन (Eurozone) कहा गया है। यूरोपीय संघ के शेष तीन राष्ट्र जो फिलहाल यूरोजोन में शामिल नहीं हुए हैं, ब्रिटेन डेनमार्क व स्वीडन हैं। आगे चलकर इन राष्ट्रों को भी यूरोजोन में शामिल होने की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

यूरो (Euro) के चलन के साथ ही यूरोजोन राष्ट्रों की अपनी मुद्राएँ भी कुछ समय तक इन राष्ट्रों में चलन में बनी रहेगी, किन्तु जर्मन मार्क का चलन 31 दिसम्बर, 2001 को ही समाप्त हो गया है। नीदरलैंड्स में गिल्डर 28 जनवरी, 2002 तक, आयरलैंड में पुट 9 फरवरी, 2002 तक व फ्रांस में फ्रैंक 17 फरवरी, 2002 तक यूरो के साथ-साथ चलन में रहेंगे। यूरोजोन के शेष राष्ट्रों में उनकी पुरानी मुद्राएँ 28 फरवरी, 2002 तक चलन में रहेंगी तथा 1 मार्च, 2002 से अकेली यूरो ही इन सभी 12 राष्ट्रों में विधिग्राह्य मुद्रा (Legal /Tender) होगी। बन्द हुई यूरोपीय मुद्राओं को 1 जनवरी, 2012 तक बैंकों से यूरो में बदला जा सकेगा।

यूरो के करेसी नोट 5, 10, 20, 50, 100, 200, व 500 यूरो के मूल्य में छापे गए हैं। 5 यूरो से कम मूल्य का लेनदेन सिक्कों से ही किया जा सकेगा। यह सिक्के 1 व 2 यूरो के अतिरिक्त 1, 2, 5, 10, 20, व 50 सेंट (Cents) मूल्य में जारी किए गए हैं। 1 यूरो का मूल्य 100 सेंट के बराबर है। सिक्कों के एक ओर उनका मूल्य व दूसरी ओर सम्बन्धित राष्ट्र का राष्ट्रीय चिह्न मुद्रित किया गया है।

अब प्रश्न उठता है कि यूरोप के तीन अन्य देश ब्रिटेन, स्वीडन तथा डेनमार्क यूरोप की इस साझी मुद्रा में अपनी भागीदारी दर्ज करने में पीछे क्यों हट रहे हैं ? जहाँ तक ब्रिटेन का प्रश्न है वह राजनीतिक कारणों से इस भागीदारी से पीछे हटा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन अब तक यूरोप की वित्तीय एवं पूंजीगत गतिविधियों का केन्द्र रहा है, किन्तु जर्मनी के फ्रैंकफर्ट को यूरोप की साझी मुद्रा यूरो की राजधानी बनाना शायद ब्रिटेन को राजनीतिक बिन्दुओं पर स्वीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का पौण्ड अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक बाजार में अपनी सुदृढता आज भी बनाए हुए है, इसी कारण ब्रिटेन ने यूरो में भागीदारों को अपनी आर्थिक सम्प्रभुता के लिए हानिकारक माना और यूरो की छतरी (Umbrella of Euro) के नीचे आने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। विश्व मौद्रिक बाजार में यूरो का प्रचलन यूरोप के इन देशों को निकट भविष्य में यूरो की सम्प्रभुता स्वीकार करने के लिए किस सीमा तक विवश कर पायेगा, यह प्रश्न अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है।

अन्तराष्ट्रीय तरलता की समस्या यूरो एक सम्भावित समाधान :- विश्व पटल पर दिन-प्रतिदिन विषम होती अन्तराष्ट्रीय तरलता (International Liquidity) की समस्या अन्तराष्ट्रीय व्यापार के विविध विस्तार में अवरोध बनकर सामने आती रही है। अन्तराष्ट्रीय तरलता की समस्या के परिमाणत्मक पहलू के साथ-साथ इस समस्या का गुणात्मक पहलू भी विश्व मौद्रिक बाजार में एक अवरोधक घटक रहा है। इस गुणात्मक पहलू का सम्बन्ध रिजर्व के रूप में अमरीकी डॉलर और ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिंग के प्रयोग से है क्योंकि ये दोनों विश्व पटल पर लम्बे समय तक आधार मुद्राएँ रही हैं। यद्यपि यह स्थिति विगत कुछ समय से जापानी येन तथा जर्मन मार्क को भी प्राप्त हो गई थी। अन्तराष्ट्रीय तरलता के कुछ विशिष्ट देशों की मुद्रा के साथ बँधे रहने के कारण अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय व्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। इसी समस्या के सम्यक् समाधान की दिशा में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 1971 से विशेष आहरण अधिकार (SDR) की योजना, जिसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) के नाम से भी जाना जाता है, आरम्भ की गई। SDR के मूल्य निर्धारण में वर्ष 1991 के दौरान मुद्राओं की पिटारी (Basket of Currencies) में अमरीकी डॉलर (भार. 40%), जर्मन मार्क (भार. 21%), जापानी येन (भार. 17%), ब्रिटिश पाउण्ड (भार. 11%) तथा फ्रान्सीसी फ्रैंक (भार. 11%) को सम्मिलित किया गया। अमरीकी डॉलर का प्रभुत्व विशेष आहरण अधिकार (SDR) पर भी हावी है और इसी का परिणाम है— वर्तमान में अमरीका का IMF के पास सर्वाधिक कोटा। अन्तराष्ट्रीय विनिमय बाजारों में अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व और अन्य मुद्राओं की सापेक्षिक उपेक्षा ने यूरोप में मौद्रिक एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी और यूरोप के देश चल

पड़े, आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकृत मुद्रा 'यूरो' को अपनाने के लिए और वह भी इस आशा के साथ कि यूरो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में डॉलर की सम्प्रभुता को चुनौती देगा और अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। यूरोपीय मुद्राओं के साथ यूरो की विनमय दर निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों की बैठक 31 दिसम्बर 1998 को ब्रुसेल्स में सम्पन्न हुई, जिसमें इन मुद्राओं की विनमय दरें निम्नवत् निर्धारित की गयीं—

तालिका-5 5

यूरो की एक इकाई का विभिन्न मुद्राओं में मूल्य

जर्मन—मार्क	1 96
फ्रांसीसी—फ्रैंक	6 56
इटालियन—लीरा	1936 27
स्पेनिश—पेसेटा	166 39
डच—गिल्डर	2 20
बेल्जियम—फ्रैंक	40 34
आस्ट्रियन—शिलिंग	13 76
पुर्तगाली—एस्कुडो	200 48
फिनिश—मार्का	5 95
आयरिश—पाउंड	0 79
लक्जेंबर्ग—फ्रैंक	40 34

24. यूरोशियाई आर्थिक समुदाय का गठन :-

पूर्व सोवियत संघ से विघटित हुए 12 सदस्यीय 'स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल' (Commonwealth of Independent States- CIS) के पाँच सदस्य राष्ट्रों ने पारस्परिक आर्थिक-वाणिज्यिक सम्बन्धों में दृढ़ता के लिए यूरोशियाई आर्थिक समुदाय (Eurasian Economic Community-EEC) का गठन 31 मई, 1 जून, 2001 को बेलारूस की राजधानी मिंस्क (Minsk) में सीआईएस के शिखर सम्मेलन में किया है। इसमें रूस के अतिरिक्त वह चार राष्ट्र शामिल हैं जिनका झुकाव पश्चिम की बजाए रूस की ओर रहा है।

रूस के अतिरिक्त कजाखस्तान किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व बेलारूस की सदस्यता वाले इस समुदाय ने सर्वाधिक 4 मत रूस को आवंटित किए गए हैं, जबकि कजाखस्तान व बेलारूस को 2-2 मत तथा किर्गिस्तान व ताजिकिस्तान को 1-1 मत आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 10 मतों में रूस की मत शक्ति सर्वाधिक होने के बावजूद इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी निर्णय के लिए कम-से-कम तीन सदस्य राष्ट्रों की सहमति आवश्यक होगी। कजाखस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव, जिन्होंने इस परिषद् की

स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1994 में दिया था, को इस समुदाय का अध्यक्ष एक वर्ष के लिए बनाया गया है। इस समुदाय में वर्तमान में यद्यपि 5 राष्ट्र ही शामिल हैं, किन्तु शीघ्र ही आर्मेनिया के भी इसमें शामिल होने की सम्भावना है पश्चिमोन्मुखी मोल्दोवा का ससदीय चुनावों के पश्चात् रूस की ओर झुकाव बढ़ा है वह भी आगे चलकर इसमें शामिल हो सकता है।

25 एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) :-

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) तथा नाफ्टा (NAFTA) के पश्चात् अब 'एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग' (APEC) विश्व के एक बड़े व्यापारिक गुट के रूप में उभर रहा है। APEC की स्थापना नवम्बर 1989 में तत्कालीन आस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री बॉब हॉक की पहल पर हुई थी। बॉब हॉक ने एपेक को 'विश्व मामलों में एशिया-प्रशान्त की आवाज' (Voice for the Asia Pacific in World Affairs) कहा था। हिमालय से एन्डीज (Andes) तक व न्यूजीलैण्ड से कनाडा तक विस्तृत क्षेत्र में फैले विश्व की बड़ी व विस्तारोन्मुख अर्थ व्यवस्थाओं वाले प्रमुख राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इन देशों का संयुक्त व्यापार विश्व के कुल व्यापार का 40 प्रतिशत से भी अधिक है। EEC तथा NAFTA की भाँति APEC को भी एक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) के रूप में विकसित करने हेतु सदस्य राष्ट्र प्रयासशील हैं। जून 1992 में बैकाक की बैठक के बाद सिंगापुर में इसके सचिवालय की स्थापना की गई।

1998 में रूस, वियतनाम व पेरू को सदस्यता मिल जाने के बाद एपेक की सदस्य संख्या 21 हो गई है। इन 21 सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं — आस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, मेक्सिको, जापान, चीन, हांगकांग, ताइवान, द० कोरिया, इण्डोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपीन्स, सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, पपुआ, न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चीली, पेरू, रूस तथा वियतनाम। भारत को अभी इस संगठन का सदस्य नहीं बनाया गया है।

APEC का नौवाँ शिखर सम्मेलन 20-21 अक्टूबर, 2001 को शंघाई में सम्पन्न हुआ। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में अमरीका पर 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करने के साथ ही सभी प्रकार के आतंकवादी हमलों को रोकने व अपराधियों की धर-पकड़ के लिए हरसंभव प्रयास करने के प्रति जहाँ एकजुटता व्यक्त की गई वहीं अफगानिस्तान में अमरीकी सैन्य कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया।

दो दिन चले इस सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा इतना छाया रहा कि संगठन के अपने एजेडे विशिष्ट वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों पर ठोस चर्चा इसमें नहीं हो सकी। आर्थिक

मोर्चे पर, सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि वर्तमान में विश्व मदी के गम्भीर दौर से गुजर रहा है। मदी के इस दौर को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए शघाई घोषणा-पत्र में कहा गया है कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए ऐपेक के सदस्य राष्ट्रों न समुचित नीतियों अपनाई है। सरक्षणवाद (Protectionism) के विरुद्ध सघर्ष तथा विश्व व्यापार सगठन (WTO) के तहत वार्ता के नए दौर के प्रति प्रतिबद्धता की बात भी आर्थिक दृष्टि से सशक्त इस सगठन के शघाई घोषणा-पत्र में कही गई है।

तालिका-56

ऐपेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ

1993	सीटल (अमरीका)
1994	बोगोर (इण्डोनेशिया)
1995	ओसाका (जापान)
1996	सुविक पोर्ट (मनीला, फिलीपीन्स)
1997	वैकुवर (कनाडा)
1998	क्वालालम्पुर (मलेशिया)
1999	ऑकलैण्ड (न्यूजीलैण्ड)
2000	बादर सेरी बेगावान (ब्रूनेई)
2001	शघाई (चीन)

26. एशिया-यूरोप मीटिंग (ASEM) :-

यूरोपीय सघ (EU) के 15 तथा एसियान (Association of South-East Asian Nations- ASEAN) के 7 राष्ट्रों के साथ-साथ जापान, द0 कोरिया व चीन को शामिल करते हुए एशिया व यूरोप के 25 राष्ट्रों की बैठक ऐसेम (ASEM-Asia Europe Meeting) ने मोटे तौर पर दोनों महाद्वीपों के एक संयुक्त अनौपचारिक सगठन का ही रूप ले लिया है। इन 25 एशियाई व यूरोपीय राष्ट्रों की पहली शिखर बैठक मार्च 1996 के प्रथम सप्ताह में थाईलैण्ड की राजधानी बैंकाक में सम्पन्न हुई इसमें 10 एशियाई राष्ट्रों के अतिरिक्त यूरोप के 13 राष्ट्रों ने भी भाग लिया।

यूरोपीय राष्ट्र ASEM को APEC (Asia Pacific Economic Community) के परिप्रेक्ष्य में ही विकसित होते देखना चाहते हैं। APEC में जहाँ पूर्वी एशियाई देशों को प्रशान्त क्षेत्र के देशों-विशेषकर अमरीका, कनाडा, मेक्सिको व चिली, आदि के साथ एक आर्थिक गठबंधन में बाँधा गया है वहीं ASEM एशियाई देशों के साथ यूरोपीय देशों का आर्थिक गठबंधन है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारत को न तो APEC में ही अभी तक प्रवेश मिल सका है और न ही ASEM में। एशिया एवं यूरोप के राष्ट्रों की दूसरी शिखर

बैठक 'ऐसेम' 3-4 अप्रैल, 1998 को लन्दन में सम्पन्न हुई सम्मेलन की समाप्ति पर सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए घोषणा-पत्र में यूरोप ने एशियाई राष्ट्रों के उत्पादों के लिए अपने बाजार खुले रखने तथा किसी प्रकार की संरक्षणात्मक नीति न अपनाने का आश्वासन दिया है। वित्तीय संकट से निपटने हेतु पर्याप्त सहायता उपलब्ध करने को संक्षम बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक साधन सम्पन्न बनाने की मांग भी घोषणा-पत्र में दोहराई गई है।

ऐसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यद्यपि अनेक कदमों की बात लन्दन घोषणा-पत्र में कही गई है, किन्तु इसके विस्तार का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। एशियाई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की पुनर्संरचना के लिए आवश्यक प्रौद्योगिक सहायता उपलब्ध कराने को विश्व बैंक के तत्वावधान में एक 'ट्रस्ट फंड' की स्थापना थाईलैण्ड में एशिया-यूरोप एन्वायरनमेंटल टेक्नोलॉजी सेन्टर की स्थापना तथा मनी लाउडरिंग के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही की बात घोषणा-पत्र में कही गई है।

27. एशियाई क्लीयरिंग यूनियन -

एशियाई क्लीयरिंग यूनियन (ACU) की 25वीं बैठक 24-25 मई, 1996 को मुम्बई में सम्पन्न हुई। 1975 में स्थापित इस समाशोधन संघ (Clearing Union) का उद्देश्य एशियाई देशों के चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों के लिए समाशोधन सुविधा उपलब्ध कराना है। मूलतः इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों के व्यापार सम्बन्धी भुगतानों का स्थानीय मुद्राओं में निपटान करने के उद्देश्य से हुई थी, ताकि इनके सीमित विदेशी मुद्रा भण्डारों पर अधिक दबाव न पड़े। प्रारम्भ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका व ईरान ही इसके सदस्य थे, बाद में म्यांमार ने 1977 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। एशियाई क्लीयरिंग यूनियन का मुख्यालय तेहरान में है।

28. मर्कोसुर :-

1 जनवरी, 1995 से दक्षिण अमेरिका के चार राष्ट्रों— ब्राजील, आर्जेन्टीना, पराग्वे तथा उरुग्वे के बीच एक साझा बाजार (Common Market) 'मर्कोसुर' (Mercosur) प्रभावी हो गया है। (मर्कोसुर स्पेनिश नाम का शब्द संक्षेप है, जिसका अर्थ है दक्षिणी शंकु का साझा बाजार)। चारों राष्ट्रों की सरकारों ने दिसम्बर, 1994 में इस साझा बाजार की स्थापना का अनुमोदन कर दिया। इसके पश्चात् आर्जेन्टीना, ब्राजील, पराग्वे तथा उरुग्वे के राष्ट्रपतियों क्रमशः कार्लोस मेनम,

गयी थी। सैनेगल के डॉ० जैक्वेस डियोफ (Jacques Diouf) इस सगठन के महानिदेशक हैं। इसका प्रधान कार्यालय रोम (इटली) में है। इस सगठन के प्रमुखतः निम्नलिखित कार्य हैं—

- (i) विश्व में कृषि-उत्पादन की कमी की पूर्ति करना और उनकी निरन्तर पूर्ति करते रहना।
- (ii) भण्डारित अन्न को हानि पहुँचाने वाले कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के उपाय खोजना।
- (iii) बीमार पशुओं की देखभाल करना।
- (iv) प्रत्येक प्रकार की फसलों के अच्छे बीजों को उपलब्ध कराना।
- (v) रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना।
- (vi) पोषण-शक्ति में वृद्धि करना।
- (vii) कृषि-उत्पादन और वितरण में सुधार करना।

31. हिन्द महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग संघ—हिमतक्षेस : —

हिन्द महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों के बीच पारस्परिक आर्थिक सहयोग सवर्धन के उद्देश्य से एक सगठन 'हिन्द महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग सगठन' (Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation- IORARC) की औपचारिक स्थापना की घोषणा 5 मार्च, 1997 को मॉरिशस में पोर्टलुई में सस्थापक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई। इस सगठन की स्थापना के लिए भारत, द० अफ्रीका व आस्ट्रेलिया विगत लगभग दो वर्षों से प्रयासरत थे। यह संघ तीन महाद्वीपों—एशिया, अफ्रीका व आस्ट्रेलिया के लिए एक सेतु का कार्य करेगा।

अध्याय छः

“स्वतन्त्रता के पचास वर्षों के दौरान हमारा विदेशी व्यापार
तथा हाल के उदारीकरण कार्यक्रम एवं उनका प्रभाव”

अध्याय – 6

स्वतन्त्रता के पचास वर्षों के दौरान हमारा विदेशी व्यापार तथा हाल के उदारीकरण कार्यक्रम एवं उनका प्रभाव

हम इस अध्याय में देश के विदेशी व्यापार का अध्ययन इस बात को दृष्टिगत करते हुए करेंगे कि आजादी के पश्चात से विशेषतया देश में आर्थिक नियोजन के प्रारम्भ होने पर देश के विदेशी व्यापार में जो परिवर्तन आये, विदेशी व्यापार के परिणाम में जो वृद्धि हुई तथा व्यापार की दिशा में परिवर्तन के साथ उसके ढाँचे व स्वभाव में जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह वृद्धि व्यापार की मात्रा तथा मूल्य दोनों में ही हुई है, फिर भी इस वृद्धि को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले वर्षों में लगभग स्थिर ही रहा है। भारत का विदेशी व्यापार विश्व के लगभग सभी देशों के साथ है, और 7500 से भी अधिक वस्तुएँ लगभग 190 देशों को निर्यात की जाती हैं। जबकि 6000 से भी अधिक वस्तुएँ 140 देशों से आयात की जाती हैं। आजादी के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसे तालिका द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।

तालिका 6.1

आजादी के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार घाटा (करोड़ ₹ में)
1950-51	608	606	-2
1960-61	1122	642	-480
1970-71	1634	1535	-99
1980-81	12549	6711	-5838
1990-91	43375	32553	-10645
1991-92	47851	44041	-3810
1992-93	63375	53688	-9687
1993-94	73104	69751	-3350

1994-95	89971	82674	-7297
1995-96	122678	106353	-16325
1996-97	138920	118817	-20103
1997-98	154176	130101	-24075
1998-99	176099	141604	-34495
1999-2000	215236	159561	-55675
2000-2001	230873	203571	-27302
2001-2002 (अप्रैल- दिसम्बर)	181753	154445	-27308

भारत के विदेशी व्यापार के सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि योजना अवधि में केवल दो वर्षों को छोड़कर हमारा विदेशी व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल ही रहा है। केवल 1972-73 तथा 1976-77 में हमारा विदेशी व्यापार सन्तुलन क्रमशः 173 करोड़ व 68 करोड़ रुपये अनुकूल रहा है। विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ व्यापार सन्तुलन का यह घाटा भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। व्यापार सन्तुलन के घाटे पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार द्वारा आयात नियन्त्रण व निर्यात सम्बर्द्धन के अनेक उपाय किये गये हैं। किन्तु कतिपय कारणों से जिनमें प्रमुख रूप से खनिज तेल के बड़े आयात बिल के कारण इसमें विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। इन्हीं सब कारणों व निवारणों तथा व्यापार प्रगतियों का विश्लेषण हम निम्न बिन्दुओं के माध्यम से करेंगे।

आजादी के पश्चात योजना काल के प्रथम दशक में विदेशी व्यापार:-

भारत के विदेशी व्यापार का लम्बा इतिहास रहा है। 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत भी विश्व व्यापार का एक स्वतंत्र सदस्य बन गया। स्वतंत्रता के पूर्व देश में आयात और निर्यात की दृष्टि से जो नीतियाँ अपनायी जा रही थी, उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना था। लेकिन आजादी के पश्चात देश के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एवं जीवन स्तर की प्रगति बन गया।

भारत के वाणिज्यिक प्रधानता के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार निश्चित रूप से अनुकूल था, हमने निर्यात में आयात को बढ़ावा दिया। भारत निर्यात में वाणिज्यिक प्रधान था। इसलिए यूरोपियन देश एवं अन्य देश भारत के साथ ज्यादा व्यापार सम्बन्ध बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। व्यापार की यह स्थिति अंग्रेजों द्वारा देश पर पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण तक बनी रही।

किन्तु बाद में अंग्रेजों द्वारा अपनायी गयी स्वार्थपरता की नीतियों से यहाँ के उद्योग तितर-बितर हो गये।¹

अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने व पाकिस्तान के अलग हो जाने के पश्चात् से प्रथम आयोजन काल प्रारम्भ होने तक भारतीय विदेशी व्यापार में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए, किन्तु प्रथम योजना काल (1950-51) के प्रारम्भ होने पर विदेशी व्यापार नीति में कुछ परिवर्तन होने लगे। इस योजना काल के दौरान पहले वर्ष में 716 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात किया गया, एवं देश के विदेशी व्यापार की नीति में बड़े उद्योगों का विकास, निर्यात स्थानान्तरण और निर्यात रोकने वाले व्यवहार की प्रगति हुई। वर्ष 1953-54 के दौरान निर्यात का मूल्य अब तक जब से योजनाओं की घोषणा की गयी है, सबसे कम था। जिसके फलस्वरूप दूसरी योजना के दौरान आयात बहुत अधिक हो गये। वास्तव में पहली योजना के अन्त में उदार नीति के कारण आयात में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी योजना के मध्य में विदेश विनिमय स्रोत बहुत कम हो गये। वर्ष 1956 से 1961 तक निर्यात का वार्षिक औसत 606 करोड़ पर ही रुका रहा। इसलिए इस काल के दौरान बड़ी मुश्किल से ही कोई विकास हुआ।²

आजादी प्राप्ति के पश्चात् भारत में सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 1951 से प्रारम्भ हुए आर्थिक नियोजन के युग में विदेशी व्यापार के नये अध्याय का सूत्र पात हुआ। इस योजना में योजना आयोग ने विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में दो उद्देश्य निर्धारित किये। पहला निर्यात के उच्चतर स्तर को कायम रखना व केवल उन वस्तुओं का निर्यात करना जो राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो तथा द्वितीय उद्देश्य यह था, कि भुगतान शेष को देश के विदेशी विनिमय की जमा तक सीमित रखना। इस योजना के पाँचों वर्षों में व्यापार शेष भारत के प्रतिकूल रहा जिसका मुख्य कारण यह था, कि इस योजना काल में औद्योगीकरण के कारण विदेशों से भारी मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ा। इस अवधि में खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं का क्रमशः 595 करोड़ और 878 करोड़ रुपये का आयात हुआ, जबकि निर्यात के ढाँचे में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। वही 1956 से 1961 तक के द्वितीय योजना काल में जो मुख्य रूप से देश के औद्योगीकरण का योजना काल था, के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ा। साथ ही अनुरक्षण आयातों में भी काफी वृद्धि

1 कृष्ण बाल, कामार्सियल रिलेशन, विटविनइण्डिया एण्ड इंग्लैंड (1960-1757) लन्दन, 1924, पृष्ठ संख्या 208.

2 कालीपाड़ा देव, 'एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया' सुल्तान चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1978, पृष्ठ संख्या 3-8.

हुई। खाद्यान्न का आयात भी लगभग प्रथम योजना के समान ही हुआ। निम्न तालिका इस योजना कालो के प्रथम दशक में हमारे व्यापार की स्थिति को स्पष्ट करती है।

तालिका 62
आजादी के प्रथम दशक में विदेशी व्यापार
(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1950-51	650 3	646 8	-3 5
1951-52	962 9	730 1	-232 8
1952-53	633 0	601 9	-31 1
1953-54	591 8	536 7	-52 1
1954-55	989 7	596 6	-93 1
1955-56	773.1	640 3	-132 8
1956-57	1102 1	635 2	-406 9
1957-58	1233 2	594 2	-639 0
1958-59	1029 2	576 2	-453 0
1959-60	932 3	627 4	-304 9
कुल योग (1950-51 से 1959-60)	7947.3	5541.6	-2405.7

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजनाकाल के प्रथम दशक में कुल आयात 7,947 3 करोड़ रुपये का तथा कुल निर्यात 5541 6 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार इस दशक में -2405 7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यद्यपि सरकार ने इस व्यापार घाटा को रोकने के लिए 1957 में कठोर आयात नीति की घोषणा की किन्तु, व्यापार शेष की प्रतिकूलता को रोका नहीं जा सका।

आजादी के द्वितीय दशक में भारत का विदेशी व्यापार :-

आजादी के द्वितीय दशक में देश को अनेक सकट ग्रस्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सन् 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। जिसके कारण पूँजीगत वस्तुओं का बहुत अधिक आयात करना पड़ा। सन् 1965 का वर्ष देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे घातक वर्ष था। सम्भवतः ऐसा वर्ष किसी देश के इतिहास में सैकड़ों वर्ष में एक बार आता है। इस वर्ष केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण ही क्षति नहीं हुई, बल्कि देश का एक भाग बाढ़ तथा दूसरा भाग सूखा से तबाह हो गया। फलतः पूँजीगत वस्तुओं के साथ-साथ खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ा। 1964-65 में 1421 5 करोड़ रुपये का आयात किया गया। निर्यात की मात्रा जो 1963-64 में 802.3 करोड़ रुपये थी, घटकर 801 6 करोड़ रुपये हो गयी। देश के निर्यात से केवल 57.1 प्रतिशत आयातों का ही भुगतान कर सकते थे। इस वर्ष का विदेशी विनिमय

अल्पमत में था।¹ देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति को देखते हुए रुपये के अवमूल्यन का निर्णय लिया गया, और 6 जून, 1966 को रुपये का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। मुद्रा अवमूल्यन से आयात हतोत्साहित तथा निर्यात प्रोत्साहित होते हैं। परन्तु इसके बाद भी तत्काल कोई मुख्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि अधिक मूल्य ही चुकाना पड़ा, क्योंकि उस समय देश के आयातों की मांग बेरोकड़ थी। परिणाम स्वरूप 1966-67 के घाटे का रिकार्ड कायम हुआ, और व्यापारिक प्रतिकूल सन्तुलन 906 करोड़ रुपये पहुँच गया। हम अपने निर्यातों द्वारा केवल 55.6 प्रतिशत आयातों का ही भुगतान कर पा रहे थे। किन्तु अवमूल्यन ने धीरे-धीरे फल देना प्रारम्भ किया। आयातों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए एवं निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्य किये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के बाद पहली बार इस दशक में प्रारम्भ की गयी नीतियों के फलस्वरूप अगले कुछ वर्षों के लिए व्यापार सन्तुलन कुछ पक्ष में हुआ। इस दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है—

तालिका 63
60 के दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1960-61	1105	603	-475
1961-62	1006	668	-338
1962-63	1097	681	-416
1963-64	1245	802	-443
1964-65	1421	801	-620
1965-66	1350	783	-567
1966-67	1991	1086	-906
1967-68	2043	1255	-788
1968-69	1740	1367	-373
1969-70	1582	1413	-169
योग	14580	9,459	-5095
वार्षिक औसत	1458.0	945.9	509.5

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस दशक में निर्यात का वार्षिक औसत 945.9 करोड़ रुपये तथा आयात का वार्षिक औसत 1458 करोड़ रुपये रहा। इस प्रकार इस दशक का औसत

1 एम०सी० वैश्य एवं सुदामा सिंह, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अक्सफोर्ड एण्ड आई०वी०एच० क०प्र० लि०, नई दिल्ली, वर्ष 1991

वार्षिक घाटा 5095 करोड़ रुपये का था। उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि 1967-68 तक लगातार व्यापार प्रतिकूल था। इसके प्रमुख कारणों में पाकिस्तान तथा चीन का आक्रमण जिसकी वजह से रक्षा सामग्री का आयात करने से अर्थव्यवस्था को धक्का लगा तथा साथ ही भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना भी है। अवमूल्यन के पश्चात जहाँ निर्यातों में वृद्धि हुई वहीं अच्छी फसल के कारण खाद्यान्नों के आयातों में कमी हुई। फलस्वरूप प्रतिकूल व्यापार शेष जो वर्ष 1967-68 में 788 करोड़ रुपये का था वही 1968-69 में घटकर 373 करोड़ हो गया।

आजादी के तीसरे दशक में भारतीय विदेशी व्यापार—

इस दशक के दौरान हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। इन वर्षों में सरकार द्वारा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाये गये। जिसके परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता के बाद पहली बार वर्ष 1972-73 में देश का व्यापार शेष अनुकूल हुआ। किन्तु इस प्रवृत्ति को अगले वर्ष जारी नहीं रखा जा सका, क्योंकि इस वर्ष आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। तेल की कीमतों में वृद्धि जो अक्टूबर 1973 में प्रारम्भ हुई, ने दुनिया भर के आयातों एवं निर्यातों दोनों के मूल्यों पर भारी प्रभाव डाला। भारत भी इसका अपवाद नहीं रह सका। इन वर्षों के दौरान आयात मूल्य काफी ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। इसका मुख्य कारण देश का प्रधान आयात वस्तुएँ अर्थात् पेट्रोलियम, उर्वरकों एवं खाद्यान्नों के मूल्य में तीव्र वृद्धि थी। साथ ही देश के निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और वे पाँचवी योजना के प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष में बढ़ते ही गये। यह वृद्धि इतनी तीव्र थी कि 1976-77 तक निर्यात बढ़कर 5,146 करोड़ रुपये हो गया, और ये आयात से 68 करोड़ रुपये अधिक हो गया। अतः भारत के विदेशी व्यापार में दूसरी बार अतिरेक पैदा हो गया। इसका मुख्य कारण हमारी निर्यातोंमुख नीति थी। मछली, मछलियों से बनी वस्तुएँ, काफी, मूंगफली, सूती वस्त्र और हस्तशिल्पों के निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई। लौह एवं इस्पात के निर्यात में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1977-78 में जनता सरकार के समय आयात में उदारता की नीति अपनाने और निर्यात तेजी से समाप्त हो जाने के कारण भारत के विदेशी व्यापार में पुनः 621 करोड़ रुपये का भारी घाटा उत्पन्न हो गया। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों द्वारा पेट्रोलियम की कीमत में और अधिक वृद्धि कर देने के कारण हमारा आयात बिल जो 1978-79 में 6,814 करोड़ रुपये था बढ़कर 1979-80 में 8,908 करोड़ रुपये हो गया। इसके विरुद्ध निर्यात जो 1978-79 में 5,726 करोड़ था बढ़कर 1979-80 में केवल 6,459 करोड़ रुपये तक ही पहुँच सका, अर्थात् इनमें केवल 12.8% की ही वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप वर्ष 1979-80 में हमारा व्यापार घाटा 2,449 करोड़ रुपये

हो गया। अगले दशक के वर्ष 1980-81 में स्थिति और भी गम्भीर हो गयी और व्यापार घाटा 5,838 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुँच गया। इस दशक के विदेशी व्यापार की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है –

तालिका 64
70 के दशक में विदेशी व्यापार की स्थिति

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1970-71	1634	1535	-99
1971-72	1824	1608	-216
1972-73	1797	1970	+173
1973-74	2955	2523	-432
1974-75	4519	3329	-1190
1975-76	5266	4043	-1223
1976-77	5074	5142	+68
1977-78	6020	5408	-612
1978-79	6814	5726	-1088
1979-80	8908	6459	-2449
कुल योग	44710	377436	-6967
वार्षिक औसत	4471.0	3774.3	-696.7

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस दशक में कुल आयात 44710 करोड़ रुपये का और कुल निर्यात 37743 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार इस दशक के दो वर्षों में व्यापार शेष अनुकूल होने के बाद भी -6967 करोड़ रुपये प्रतिकूल रहा। कुल मिलाकर देखा जाय तो पहले व दूसरे दशक से अधिक ही व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। इस दशक में विदेशी व्यापार की प्रमुख बातें इस प्रकार थीं—

- 1 इस अवधि में भारत का कुल व्यापार 82,453 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें से आयात 44,710 करोड़ रुपये तथा निर्यात 37,743 करोड़ रुपये रहा। इस प्रकार इस अवधि में व्यापार शेष -6967 करोड़ रुपये रहा।
- 2 इस अवधि में औसत वार्षिक आयात 4,471 करोड़, निर्यात 3774.3 करोड़ तथा प्रतिकूल भुगतान शेष -696.7 करोड़ रुपये का रहा।
- 3 आयात में वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम, खाद्यान्न तथा उर्वरक में तीव्र वृद्धि के कारण हुई।
- 4 इस दशक के दौरान भारतीय निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

- 5 इस सम्पूर्ण दशक में वर्ष 1972-73 व 1976-77 में दो बार व्यापार शेष क्रमश 173 करोड़ व 68 करोड़ रुपये का अधिक देखने को मिला।

आजादी के चौथे दशक में भारतीय विदेशी व्यापार .—

पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों द्वारा पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि करने की वजह से हमारा आयात बिल जो 70 के दशक में बढ़ा, वह इस दशक में जारी रहा। इस दशक के शुरुआती वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान व्यापार घाटा क्रमश 5,802 करोड़ रुपये और 5448 करोड़ रुपये हो गया। इन वर्षों के आयात और निर्यात के आकड़ों की समीक्षा से पता चलता है, कि पेट्रोलियम तथा इससे सम्बन्धित पदार्थों का आयात जो 1980-81 में 5267 करोड़ रुपये था, गिरकर 1983-84 में 4830 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि एक तो तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिर रही थी, और दूसरे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, द्वारा रूक्ष तेल के देशीय उत्पाद को बढ़ाया गया, फिर भी 1983-84 में व्यापार घाटा 5,891 करोड़ रुपये था। इस स्थिति की व्याख्या इस बात से होती है कि विदेशी मुद्रा की जो बचत पेट्रोलियम के आयात में कमी के कारण हुई, वह आयात-उदारता की नीति अपनाने के कारण गैर पेट्रोलियम आयात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कट गई। इस दशक में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) के दौरान 14,986 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत आयात के विरुद्ध 9,051 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक निर्यात किया गया। इस योजना काल के दौरान 5,935 करोड़ रुपये का भारी औसत वार्षिक व्यापार घाटा व्यक्त हुआ और यह राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय रहा। इस दशक के विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है —

तालिका 65
80 के दशक में भारतीय विदेशी व्यापार
(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1980-81	12524	6711	-5813
1981-82	13608	7806	-5802
1982-83	14356	8908	-5448
1983-84	15763	9872	-5891
1984-85	18680	11959	-6721
1985-86	21164	11578	-9586
1986-87	22669	13315	-9354
1987-88	25692	16396	-9296
1988-89	34202	20647	-13555
1989-90	40642	28229	-12413
कुल योग	219300	135421	83879
वार्षिक औसत	21930 0	13542.1	8387 9

इस दशक में सातवी योजना वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान प्राप्त ऑकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस (इ) द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाने से जिसका बाद में जनता दल सरकार ने भी अनुमोदन किया, के परिणाम स्वरूप केवल इस योजना काल के दौरान वार्षिक आयात बढ़कर 28,874 करोड़ रुपये हो गये। परन्तु जिसकी तुलना में इन वर्षों में औसत वार्षिक निर्यात केवल 18,033 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक अभूतपूर्व घाटा पैदा हो गया। इतने भारी व्यापार घाटे के उत्पन्न होने के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 मिलियन डालर के ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ा। भारत सरकार को बढ़ते हुए आयात को रोकने के लिए आयात लाइसेन्सों की उदार नीति पर अकुश लगाना पड़ा।¹ इस दशक में विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं —

- 1 इस दशक में भारत का कुल व्यापार 354721 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें से आयात 2,19,300 करोड़ रुपये तथा निर्यात 1,35,421 करोड़ रुपये रहा। इस प्रकार इस अवधि में व्यापार शेष -83879 करोड़ रुपये रहा।
- 2 इस दशक में औसत वार्षिक आयात 21,930 करोड़ रुपये, निर्यात 13,542 करोड़ तथा प्रतिकूल भुगतान शेष का वार्षिक औसत -8387 करोड़ रुपये का रहा।
- 3 आयात में वृद्धि का कारण पेट्रोलियम व खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि का रुख जारी रहना तथा कांग्रेस (ई) व जनता दल सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाया जाना रहा।
- 4 इस दशक के दौरान भी भारतीय निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी रही।
- 5 इस दशक के वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक व्यापार शेष 13555 करोड़ रुपये प्रतिकूल रहा।
- 6 निर्यात में वृद्धि तो हुई पर आयात की तेज वृद्धि को यह पूरा नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप इस अवधि में व्यापार शेष खतरनाक ढंग से बहुत तेजी से बढ़ा।

¹ रुद्र दत्त एव के०पी०एम० सुन्दरम, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लि० रामनगर, नई दिल्ली, चौवीसवा संस्करण।

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात आजादी के पॉचवे दशक में विदेशी व्यापार -

इस दशक के शुरुआती वर्षों में विदेशी व्यापार घाटा 10,645 रुपये रहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास के कारण निर्यात बढ़कर 32553 करोड़ हो गये, अर्थात् इसमें 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु खाड़ी युद्ध के कारण सरकार आयातों को सीमित नहीं कर सकी, और ये भी बढ़कर 43,375 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुँच गये, अर्थात् इसमें 226 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार व्यापार शेष का घाटा 1990-91 में बढ़कर 10,645 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष के दौरान यू0एस0 डालरों के रूप में निर्यात में 15 प्रतिशत की कमी हुई और वे इस वर्ष में 18143 मिलियन डालर थे, परन्तु इन वर्षों में आयात संकुचन अधिक तीव्र था, और इसमें 194 प्रतिशत की गिरावट आयी। वर्ष 1990-91 में हमारे आयात 2,4075 मिलियन डालर से गिरकर 1991-92 में 19411 मिलियन डालर हो गये। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा 1991-92 में 1546 मिलियन डालर हो गया जबकि यह 1990-91 में 5932 मिलियन डालर था। इसके बाद भी सरकार ने नई व्यापार नीति में निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किये। उदाहरण के रूप में आयात स्क्रिप्स की इजाजत देना, नकद क्षतिपूर्ति आलम्बन और रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन। परन्तु ये सभी उपाय निर्यात को प्रोत्साहित करने में विफल रहे। सामान्य करेसी क्षेत्र में भी डालर के रूप में निर्यात में केवल 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में रुपया करेन्सी क्षेत्र में 1991-92 के दौरान निर्यात में 425 प्रतिशत की गिरावट आई। इसका मुख्य कारण सोवियत संघ में कठिन राजनीतिक स्थिति थी, जिसका परिणाम इसके विघटन के रूप में व्यक्त हुआ और जिसकी वजह से निर्यात में गिरावट आयी।

वर्ष 1992-93 के दरम्यान निर्यात में केवल 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई और निर्यात जो वर्ष 1991-92 में 1,7865 मिलियन डालर था बढ़कर केवल 1,837 मिलियन डालर ही हो पाया, परन्तु इसके विरुद्ध आयात में 127 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कहीं अधिक वृद्धि हुई। यह वर्ष 1991-92 में 19411 मिलियन डालर से बढ़कर 1992-93 में 2,188 मिलियन डालर हो गया। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा जो वर्ष 1991-92 में 1545 मिलियन डालर था बढ़कर 1992-93 में 3345 मिलियन डालर हो गया। इस बिगड़ती हुई व्यापार घाटे की परिस्थिति के कई कारण थे। पहला कारण तेल के आयात में 136 प्रतिशत की वृद्धि जो 5624 मिलियन डालर के उच्च स्तर पर पहुँच गया। दूसरा आयात संकुचन के उपायों को हटाने के कारण आयात में हुई वृद्धि। जिससे आयात बिल बढ़ गया। वर्ष 1993-94 के दौरान, निर्यात प्रोन्नति उपायों के परिणाम

स्वरूप निर्यात में 196 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 1992-93 में 1,8537 मिलियन डालर से बढ़कर 1993-94 में 2,2238 मिलियन डालर हो गया। यह अभिनन्दनीय है। आयात क्षेत्र में यह देखा गया कि आयात में केवल 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 1992-93 में 2,1882 मिलियन डालर से बढ़कर 1993-94 में 2,3306 मिलियन डालर हो गया। परिणाम स्वरूप घाटा 1068 मिलियन डालर रहा जबकी 1992-93 में यह 3345 मिलियन डालर था। वर्ष 94-95 में निर्यात तेजी से बढ़कर 2,6330 मिलियन डालर हो गये जबकि ये 1993-94 में 2,2238 मिलियन डालर थे। अतएव इनमें 183 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसके विरुद्ध आयात में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से 217 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल रूप में 1994-95 में आयात 2,8654 मिलियन डालर था, इसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा जो 1993-94 में 1068 मिलियन डालर था बढ़कर 1994-95 में 2324 मिलियन डालर हो गया, परन्तु विदेशी मुद्रा रिजर्व की स्थिति सुविधाजनक होने के कारण देश इस व्यापार घाटे को सहन करने की स्थिति में था। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 से प्रारम्भ होने के पश्चात के वर्षों में भारतीय विदेशी व्यापार की स्थिति निम्न तालिका 66 से स्पष्ट है—

तालिका 66
नब्बे के दशक से विदेशी व्यापार की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार सतुलन
1990-91	18143	24075	-5932
1991-92	17865	19411	-1546
1992-93	18537	21882	-3345
1993-94	22238	23306	-1068
1994-95	26330	28654	-2324
1995-96	31797	36678	-4881
1996-97	33470	39133	-5663
1997-98	35006	41484	-6478
1998-99	33218	42389	-9171
1999-2000	36822	49671	-12849
2000-2001	44560	50536	-5976
2001-2002(अ) अप्रैल-दिसम्बर	32572	38362	-5790

अ — अनन्तिम

स्रोत — आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001-2002 पेज S-79

इस दशक के शुरुआती वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 में व्यापार शेष 1546 करोड़ डालर से बढ़कर 3345 करोड़ डालर हो गया। यह वृद्धि अगले वर्ष जारी नहीं रह सका, जबकि हमारे आयात एवं निर्यात दोनों में वृद्धि हुई, किन्तु व्यापार शेष घाटा पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 1068 करोड़ डालर हो गया। इसके बाद के वर्षों में यह व्यापार शेष घाटा निरन्तर बढ़ता हुआ, वर्ष 1999-2000 में 12849 करोड़ डालर के उच्च बिन्दु पर पहुँच गया, तत्पश्चात् बाद के दो वर्षों में क्रमशः 2000-01 व 2001-02 में व्यापार शेष घाटे में पुनः थोड़ा सा नरमी का रुख आया और यह क्रमशः 5976 व 5790 करोड़ डालर रहा।

वर्ष 1989-90 से 1995-96 की 6 वर्षों की अवधि के लिए यह कहा जा सकता है, कि डालर के रूप में निर्यात की औसत वार्षिक दर 11.4 प्रतिशत रही और आयात की वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत रही। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि रुपये के रूप में निर्यात में 25.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि इन 6 वर्षों के दौरान हुई। परन्तु निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास का अधिकतर भाग दो चरणों में किये गये अवमूल्यन के प्रभाव का निराकरण करने में ही समाप्त हो गया, और आयात के मूल्य में वृद्धि बहुत हद तक अवमूल्यन के कारण ही हुई। जाहिर है कि अवमूल्यन एक अल्पकालीन उपाय है और यह हमारे लगातार चलते हुए व्यापार घाटे की समस्या का कोई स्थायी हल प्रस्तुत नहीं करता। जुलाई 1991 में किये गये रुपये के अवमूल्यन तथा 1993-1994 में रुपये को व्यापार खाते के अन्तर्गत तथा वर्ष 1994-1995 में चालू खाते के अन्तर्गत पूर्णरूप से परिवर्तनीय घोषित किये जाने से व्यापार सतुलन में सुधार हुआ, किन्तु बाद के वर्षों में यह पुनः बड़ी मात्रा में प्रतिकूल ही रहा। वर्ष 1960-1961, 1970-1971, 1980-1981 एवं 90 के दशक में भारत के आयातित व निर्यातित वस्तुओं के मदवाद आँकड़े तालिका सख्या 67 पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 1990-1991 में विदेशी व्यापार नीति में सुधार से पूर्व वर्षों में देश के निर्यातों का मूल्य कुल आयात बिल का औसतन 66.2 प्रतिशत था किन्तु 1997-1998 में 83.3 प्रतिशत हो गया, रुपये के सन्दर्भ में 1997-1998 के दौरान भारत के आयातों में वृद्धि 9.1 प्रतिशत रही, जबकि यह 1996-97 के दौरान 13.2 प्रतिशत थी।

वाणिज्य मंत्रालय ने सन् 2001 में 44.56 बिलियन डालर के निर्यात को बढ़ाकर 2006-07 में 80.48 बिलियन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान विदेशी व्यापार घाटा और भी अधिक हुआ होता, यदि आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति पूर्व वर्षों के समान हुई होती। सन्दर्भित वर्ष में तेल आयात बिल कम रहने के कारण आयातों में वृद्धि 4.2 प्रतिशत पर ही सीमित रही।

तालिका सख्या 67

निर्यात की मुख्य वस्तुएँ

(करोड रुपये मे)												
1.	कृषि और संबद्ध उत्पाद जिसमे से	1960-61	70-71	80-81	90-91	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01
	(i) काफी	284	487	2057	6317	13712	21138	24239	25419	26164	25016	28535
	(ii) चाय और मेट	7	25	214	252	1053	1503	1426	1696	1703	1435	1185
	(iii) खली	124	148	426	1070	975	1171	1037	1876	2302	1785	1976
	(iv) तम्बाकू	14	55	125	609	1798	2349	3495	3435	1912	1638	2045
	(v) काजू गिरी	16	33	141	263	255	447	757	1070	779	1009	871
	(vi) मसाले	19	57	140	447	1247	1237	1288	1407	1613	2461	1883
	(vii) चीनी और शीरा	17	39	11	239	612	794	1202	1410	1617	1767	1619
	(viii) कपास	30	29	40	38	62	506	1078	255	23	40	511
	(ix) घावल	12	14	165	846	140	204	1575	822	224	78	224
	(x) मछली तथा मछली से बनी वस्तुएँ	5	5	224	462	1206	4568	3172	3371	6201	3128	2943
	(xi) मांस और मास से बनी वस्तुएँ		31	217	960	3537	3381	4008	4487	4368	5125	6367
	(xii) फल सब्जियाँ और दाले (काजू, गिरी, और ससाधित फलों व जूसों के अतिरिक्त)	1	3	56	140	403	627	709	808	760	819	1470
	(xiii) विविध ससाधित खद्य पदार्थ (जिसमे ससाधित फल एवं जूस शामिल है)	6	12	80	216	606	802	828	1067	912	1247	1608
		1	4	36	213	282	745	974	528	550	668	1095
2.	अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमे से	52	164	414	1497	2538	3061	3185	3062	2976	3005	4139
	(i) अयस्क	-	16	18	35	22	27	25	40	44	42	64
	(ii) लौह अयस्क	17	117	303	1049	1297	1721	1706	1770	1600	1175	1634

3.	विवर्णित वस्तुएँ जिसमें से	291	772	3747	23736	64688	80219	88528	99824	111476	127532	160771
(i)	कपड़ा और उसमें बनी वस्तुएँ (हाथ से बने गलीचों के अतिरिक्त) जिसमें से	73	145	933	6832	19945	24149	27793	32109	35897	40178	49831
	सूती धागे तन्तुओं से बने वस्त्र आदि	65	142	408	2100	7014	8619	11082	12132	11669	13388	16030
(ii)	समी प्रकार के कपड़ा सामग्रियों के रडीमेड गारमेंट्स	1	29	550	4012	10305	12295	13324	14405	18698	20649	25478
	नारियल के रेशे और इससे निर्मित समान	6	13	17	48	173	210	217	255	313	200	221
(iii)	बड़े हुए धागे रहित जूट से निर्मित समान	135	190	330	298	473	621	552	694	595	544	933
(iv)	चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित समान	28	80	390	2600	5057	5790	5609	6061	6817	6890	8914
	चमड़ा फुटवियर चमड़े के यात्रा सामान और चमड़ा परिधान शामिल हैं											
(v)	हस्तशिल्प (हाथ से बुने गलीचे सहित) जिसमें से	11	73	952	6167	16730	20501	20110	3480	4372	5058	5097
	रत्न और आभूषण	1	45	618	5247	74131	17644	16872	19867	24839	32716	33734
(vi)	रसायन और संबद्ध उत्पाद	7	29	225	2111	7642	9849	11463	13692	14188	17389	22850
(vii)	मशीनरी, परिवहन एवं लोहा और इस्पात सहित धात्विक विनिर्माण	22	198	827	3872	10947	14578	17431	19528	18371	22251	31870
4.	खनिज, ईंधन और लुब्रिकेंट्स (कोयले सहित)	7	13	28	948	1610	1761	1832	1399	510	3399	8821
5.	अन्य	8	100	466	55	126	174	232	397	456	609	1305
	योग	642	1535	6711	32553	82674	106353	118817	130101	141604	159561	203571

आयात की मुख्य वस्तुएँ

		(करोड़ रुपये में)										
		1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1.	खाद्य पदार्थ और मुख्यतः खाद्य जीवित पशु (कच्चे काजू के अलावा) जिसमें से	214	242	380	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
	(i) अनाज और अनाज के उत्पाद	181	213	100	182	92	80	488	1083	973	961	90
2.	कच्चे माल और मध्यवर्ती विनिर्माण	527	889	9760	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
	(i) काजूगिरी (असंसाधित)	-	29	9	134	691	760	688	767	693	1198	962
	(ii) कच्चा रबर (कृत्रिम एवं पुनर्प्राप्त)	11	4	32	226	371	719	630	596	592	621	695
	(iii) रेशों जिसमें से	101	127	164	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
	a. कृत्रिम और पुनरुत्पादित रेशों (हस्त निर्मित रेशों)	-	9	97	56	444	502	423	465	282	184	275
	b. ऊन रेशा	1	15	43	182	351	486	581	600	466	492	458
	c. कपास	82	99	-	1	507	521	31	81	372	1254	1185
	d. जूट रेशा	8	0	1	20	62	48	76	51	92	139	84
	(iv) पेट्रोलियम तेल व लुब्रीकेन्ट	69	136	5264	10816	18613	25173	35629	30341	27064	54649	71497
	(v) पशु और वनस्पति तेल और वसा, जिसमें से	5	39	709	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
	a. खाद्य तेल	4	23	677	326	624	2260	2929	2765	7131	8046	6093
	(vi) उर्वरक और रासायनिक उत्पाद, जिसमें से	88	217	1490	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
	a. उर्वरक और उर्वरक सामग्री	13	86	818	1766	3304	5628	3235	3799	4179	5560	3034
	b. रासायनिक तत्व और यौगिक	39	68	358	2289	7344	9403	10382	1111	1662	1563	1542
	c. रंगाई क्षमता रंगाई और रंगाई की सामग्री	1	9	21	168	439	509	600	667	796	841	874

d.	विक्रितीय और औद्योगिक मोजीय उत्पाद	10	24	85	468	927	1358	1089	1447	1447	1616	1723
e.	प्लास्टिक सामग्री, पुनरुत्पादित सैल्यूलोस एव कृत्रिम राल	9	8	121	1095	1903	2687	2826	2574	2781	3118	2551
(vii)	लुगदी और अवशिष्ट कागज	7	12	18	458	635	921	823	1055	973	1106	1290
(viii)	कागज, गत्ता और उसके विनिर्माण	12	25	187	456	773	1583	1770	1866	1891	1938	2005
(ix)	अध्यात्मिक खनिज विनिर्माण जिसमे से	6	23	555	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	710	797
a	मोती, बहुमूल्य और अपमूल्य रत्न गढ़े अथवा अनगढ़े	1	25	417	3738	5116	7045	10384	12421	15827	23556	22101
(x)	लोह और इस्पात	123	147	852	2113	3653	4838	6866	5281	4956	3832	3569
(xi)	अलौह धातुएँ	47	119	477	1102	2954	3024	3925	3420	2823	2370	2462
3.	पूँजीगत वस्तुएँ	356	404	1910	10466	19990	28289	26868	28016	29220	25878	25281
(i)	धातुओं का विनिर्माण	23	9	90	302	648	930	1123	1209	1705	1755	1786
(ii)	चर विद्युतीय मशीनरी - मशीन औजार सहित उपस्कर और उपकरण	203	258	1089	4240	9236	14371	14801	15029	14459	17301	16915
(iii)	विद्युतीय मशीनरी, उपस्कर और उपकरण	57	70	260	1702	789	1292	1155	1406	1876	1897	2227
(iv)	परिवहन उपकरण	72	67	472	1670	3497	3697	5269	3907	2571	4925	4343
4.	अन्य (अवर्गीकृत)	25	99	499	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०	३० न०
5.	योग	1122	1634	12549	43198	89971	122678	138920	154176	176099	215236	230873

३० न० - उपलब्ध नहीं।

* वर्ष 1987-88 से आगे पूँजी वस्तुओं में परियोजना वस्तुएँ शामिल हैं।

** 1991-92 से आगे मद 3II तथा III में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ शामिल नहीं हैं।

स्रोत: आर्थिक समीक्षा, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार वर्ष 2001-02।

वर्ष 1998-99 में डालर मूल्य में भारत के निर्यातों में 370 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 1998-99 में निर्यात 33218 मिलियन डालर तथा आयात 42389 मिलियन डालर के हुए जिसके फलस्वरूप 1998-99 में व्यापार घाटा 9171 अरब डालर हो गया। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में व्यापार घाटा 12849 मिलियन डालर के उच्च स्तर तक पहुँच गया। वर्ष 1996-97 में भारत का पेट्रोलियम व तेल (POL) आयात बिल 10036 मिलियन डालर था, जो घटकर 1997-98 में 8217 मिलियन डालर रहा। इस वर्ष में तेल आयात बिल में यह कमी तेल की खपत में कमी के कारण नहीं बल्कि वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्य का नीचा रहना था। किन्तु चालू वर्ष में पुनः पेट्रोलियम आयात बिल काफी बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि विगत दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गये, इसके मद्दे नजर तेल पूल घाटे को कम करने के लिए घरेलू बाजार में भी इन पदार्थों के दामों में अत्यधिक वृद्धि करना पड़ा।

कच्चे पेट्रोलियम और उत्पादों के आयातों में वर्ष 1998-99 में 64 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2000-01 में 156 बिलियन अमरीकी डालर की तेज वृद्धि हुई, जिससे वर्ष 2000-01 में कुल आयातों में इन आयातों का हिस्सा बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया। जहाँ इस अवधि के दौरान घरेलू शोधन क्षमता में कुछ विस्तार हुआ है वही हाल के पिछले दिनों में इन आयातों में अधिकांश वृद्धि कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा उत्पादन में कमी लागू करने और कम आपूर्तियों के कारण कच्चे तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (यू०के०ब्रेट) फरवरी, 1999 के दौरान लगभग 10 अमरीकी डालर प्रति बैरल के स्तर से बढ़कर नवम्बर, 2000 के दौरान लगभग 33 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान कच्चे तेल का मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा आपूर्ति में कटौती करने के बावजूद सितम्बर, 2001 से कम हो गया। खराब होते हुए आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक ऊर्जा की घटती हुई माँग और 'ओपेक' तथा 'ओपेक' से भिन्न देशों के बीच आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति की कमी ने तेल के मूल्यों में इस वर्तमान मन्दी में योगदान दिया है। कच्चे तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य फरवरी, 2001 के दौरान प्रति बैरल 27 अमरीकी डालर से अधिक की तुलना में इस समय प्रति लगभग 19-20 अमरीकी डालर है। कच्चे तेल के मूल्य का ऐसा निम्न स्तर अगर बना रहा तो यह हमारे आयात बिल में स्वागत योग्य राहत प्रदान करेगा, व्यापार घाटे को रोकने और तेल पूल घाटे को कम करने में सहायता करेगा तथा इस क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तनों, अगर कोई हो, को आसान बनाने में भी सहायता करेगा।

वर्ष 1999-2000 में तीव्र आमूलचूल परिवर्तन प्रदर्शित करने के बाद, निर्यात वृद्धि वर्ष 2000-2001 में तेज हो गई। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी0जी0सी0आई0 एण्ड एस0) द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-2001 में निर्यात वृद्धि वर्ष 1999-2000 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि दर (अमरीकी डालर के मूल्य में) से लगभग दुगुनी हो गई। वृद्धि में अधिकांश योगदान निर्यातों में मात्रात्मक वृद्धि द्वारा किया गया था। निर्यातों में इस तेजी ने वर्ष 2000 में विश्व पण्य वस्तुओं के मूल्यों के सुधार और एशियाई सकट के बाद विश्व व्यापार के पुररुद्धार के साथ घट-बढ़ वाली वैश्विक माग प्रदर्शित की। निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित कई उपायों के अतिरिक्त, वस्त्रोद्योग, इंजीनियरी सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, रसायन, चमड़ा विनिर्माण, अयस्क और खनिज तथा पेट्रोलियम उत्पादों जैसे चयनित क्षेत्रों में पर्याप्त अभिलाभों ने भी निर्यातों को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। रुपए की विनिमय दर वर्ष 2000-2001 के दौरान वास्तविक प्रभावी रूप में अपेक्षातया स्थिर बनी रही, जिसने वैश्विक बाजारों में भारत के निर्यातों की काफी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने का प्रदर्शन किया।

दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को हुई दुखद घटना और अफगानिस्तान में उसके परिणाम ने वैश्विक व्यापार और वृद्धि की सभावनाओं के दृष्टिकोण को और उदासीन कर दिया है। वास्तविक प्रभावी मुद्रा के रूप में रुपए की हाल की बढ़ोत्तरी जैसे घरेलू कारक भी निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव डाल सकते हैं। वर्ष 2001-2002 में कृषि उत्पादन में उछाल के विनिर्माण में लगातार धीमेपन द्वारा प्रतिसतुलित होना संभावित है और इस प्रकार यह वर्ष के दौरान हमारे निर्यातों के समग्र आपूर्ति प्रत्युत्तर पर प्रभाव डालेगा।

सरकार द्वारा वित्तीय 2001-2002 वर्ष में निर्यातों की इस अधोगामी प्रवृत्ति को बदलने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें नौभरण-पूर्व और नौभरण-पश्च दोनों निर्यात ऋण दर में कमी करना, 300 से अधिक निर्यात उत्पादों से वर्धित शुल्क वापसी 400 से अधिक निर्यात मदों पर शुल्क हकदारी पास बही योजना (डी ई पी बी) मूल्य रोक की समाप्ति और चयनित अधिक मूल्य वाले निर्यातों, जिनका उच्च मूल्यवर्धन है और जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी हैं, के लिए विशेष वित्तपोषण पैकेज की घोषणा शामिल है। इन अल्पावधिक उपायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2002 को एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति अनावृत की गयी। यह कार्यनीति वर्तमान वैश्विक स्थिति का ध्यान रखती है और अगले पांच वर्षों में निर्यातों में मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, फार्म मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि मदों के निर्यात पर मात्रात्मक/पैकेजबंदी प्रतिबंधों को फरवरी, 2002 में हटाया गया था।

व्यापार संरचना

विदेशी व्यापार की संरचना से तात्पर्य आयात और निर्यात के स्वरूप से होता है। प्रायः किसी भी देश के विदेशी व्यापार की संरचना पर गौर करने से हमें उस देश की विकास प्रक्रिया के साथ-साथ उसके आर्थिक विकास के स्तर के विषय में भी पता चलता है। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि किसी देश विशेष के विदेशी व्यापार की संरचना पर ध्यान देने से यदि स्पष्ट होता है कि वह खाद्यान्नों और कच्चे पदार्थों का आयात और विनिर्मित वस्तुओं, मशीनों तथा सयंत्रों का निर्यात करता है तो हम विश्वास के साथ इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि यह देश आर्थिक विकास का उपरी स्तर प्राप्त कर चुका है। इसके विपरीत यदि कोई देश चाय, काफी, जूट, चीनी आदि वस्तुओं का निर्यात करता है और बदले में पूँजीगत उपकरणों और विनिर्मित माल का आयात करता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह देश वर्तमान में अल्प-विकसित है और इसमें औद्योगिक विकास की प्रक्रिया चल रही है।

यहाँ अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं के शुरू होने से पहले भारी मात्रा में विनिर्मित उपभोग वस्तुओं का आयात होता था और निर्यातों में जूट, चाय, सूती वस्त्र, खाले, मैगनीज, अभ्रक इत्यादि पदार्थ उल्लेखनीय थे। आयोजन काल में आयात और निर्यात दोनों ही के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिन्हें समझने के लिए विभिन्न समय बिन्दुओं पर आयात और निर्यात की वस्तुओं पर गौर करना जरूरी होगा।

भारत में आयातों की संरचना— वर्ष 1947-1948 में महत्व के अनुसार भारत के आयातों में सभी प्रकार की मशीनरी, तेल, अनाज, दालें, आटा, कपास, वाहन, कटलरी, लोहे का सामान औजार व उपकरण, रसायन, दवाइयों व औषधियों, रंग व रंग सामग्री, अन्य सूत तथा सूती कपड़ा, कागज, कागज के बोर्ड तथा लेखन सामग्री तथा लोहा इस्पात के अलावा अन्य धातुएँ प्रमुख थीं। कुल आयातों में इन सब आयात का हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक था। आर्थिक आयोजन प्रारम्भ होने के समय पूँजीगत वस्तुओं का आयात अधिक नहीं था। परन्तु महलानोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी योजना के अन्तर्गत आधारभूत उद्योगों की स्थापना को जब प्राथमिकता क्रम में ऊँचा स्थान दिया गया तो देश में बड़े पैमाने पर पूँजीगत उपकरणों का आयात शुरू हुआ। कुछ वर्षों बाद इन उपकरणों के रख-रखाव के लिए बड़े पैमाने पर कल पुर्जों तथा मशीनरी का आयात करना पड़ा। इस प्रकार अनुरक्षण आयातों में काफी वृद्धि हुई। भारत में आयातों की संरचना के बारे में 1960-61 से बाद की जानकारी तालिका संख्या 6.8 में दी गयी है।

तालिका सख्या 88

भारतीय आयातों की सरचना

वस्तुएं	1980-81		1970-71		1980-81		1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %
1 खाद्य सप्लोग वस्तुएं जिसमें अनाज एवं अनाज उत्पाद	449 380	19.1 16.1	321 282	14.8 13.0	481 127	3.0 0.8	-	2.1	137	0.4	291	0.7	231	0.6
2 कच्चे पदार्थों और मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुएं	1105	47.0	1176	54.4	12341	77.8	676	1.8	825	2.1	744	1.8	1665	4.0
(i) खाद्य तेल	8	0.4	31	1.4	857	5.4	676	1.8	825	2.1	744	1.8	1665	4.0
(ii) पेट्रोलियम तेल और डिज़ेल	145	6.1	180	8.3	6656	41.9	7526	20.5	10036	25.60	8164	19.7	6433	15.4
(iii) डबल एवं डबल सामग्री	27	1.1	113	5.3	1034	6.5	1683	4.6	911	2.3	1022	2.5	993	2.4
(iv) लोहा एवं इस्पात	258	11.0	194	9.0	1078	6.8	1446	3.9	1934	4.9	1421	3.4	1178	2.8
(v) रासायनिक तेल एवं यौगिक	82	3.5	90	4.2	453	2.8	2811	7.7	2925	7.5	299	0.7	395	0.9
(i) नौती और बहुमूल्य रत्न	2	0.1	33	1.5	527	3.3	2106	5.7	2925	7.5	3342	8.1	3762	9.0
3 पूंजीगत वस्तुएं	747	31.7	534	24.7	2416	15.2	85458	23.1	8414	21.5	7538	18.2	6945	16.6
(i) गैर विद्युतीय मशीनरी	426	18.1	341	15.8	1377	8.7	4297	11.7	4169	10.7	4044	9.7	3437	8.2
(ii) विद्युतीय मशीनरी	120	5.1	93	4.3	328	2.1	386	1.0	325	0.8	378	0.9	446	1.1
(iii) परिवहन सामग्री	151	6.4	88	4.1	597	3.8	1105	3.0	1484	3.8	1051	2.5	611	1.5
4 अन्य (अवर्गीकृत)	52	2.2	131	6.1	631	4.0	36678	100.0	391330	100	41484	100.00	41858	100.00
कुल	2353	100.00	2162	100.0	15869	100.0	36678	100.0	391330	100	41484	100.00	41858	100.00

नोट - 80 न0 का अर्थ कि आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत Government of India Economic Survey, 2000-2001 New Delhi 2001

सुविधा की दृष्टिकोण से भारतीय आयातों को चार वर्गों में बाँटा गया है—

- (1) खाद्य—उपभोग पदार्थ।
- (2) कच्चे पदार्थ तथा मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुएँ।
- (3) पूँजीगत वस्तुएँ।
- (4) अन्य तथा अवर्गीकृत वस्तुएँ।

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1960—61 में कुल भारतीय आयात 2353 मिलियन डालर था जिसमें इन चार वर्गों का हिस्सा क्रमशः 19.1, 47.0, 37.7 तथा 2.2 प्रतिशत था। समय के साथ—साथ इन चार वर्गों के सापेक्षिक महत्व में काफी परिवर्तन हुआ है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि खाद्य उपभोग वस्तुएँ, आयात के मामले में काफी तेजी से नीचे गिरी हैं। इसका प्रमुख कारण अनाज तथा अनाज उत्पाद के आयात में होने वाली कमी है। उदाहरणार्थ अनाज तथा अनाज उत्पाद का कुल आयात में भागीदारी 1960—61 में 16.3 प्रतिशत से कम होकर 1996—97 में 0.4 प्रतिशत ही रह गयी। वहीं दूसरी ओर कच्चे पदार्थों व मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में काफी तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण पेट्रोलियम व लुब्रिकेंट तथा रत्न, मोती व बहुमूल्य पत्थरों का बढ़ता हुआ आयात है। पूँजीगत वस्तुओं का आयात में हिस्सा 1960—61 में लगभग एक तिहाई था जो 1996—97 में कम होकर के 21.5 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1998—99 व 1999—2000 में भी कुछ प्रमुख आयातों में तीव्रता का रुख रहा। इन वस्तुओं का विवरण निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत है—

तालिका 69

तीव्रता से बढ़ने वाली आयातीत वस्तुएँ

(मिलियन अमरीकन डालर में)

वस्तुएँ	वजन	1998—99 (अप्रैल अक्टूबर)	1999—2000 (अप्रैल अक्टूबर)	प्रतिशत परिवर्तन
पेट्रोलियम तेल स्नेहक	15.4	3794.8	5795.9	52.7
उर्वरक	2.3	614.8	1028.1	66.6
जवाहरात, कीमती और कम कीमती पत्थर	9.0	2063.7	2973.2	44.1

लकड़ी एवं लकड़ी से बने उत्पाद	0.9	209.3	262.9	25.6
खाद्य तेल	4.0	1142.4	1286.3	12.6
कृत्रिम धूना, प्लास्टिक की सामग्री आदि	1.6	387.6	420.9	8.6
लूगदी एवं रद्दी कागज	0.6	141.6	146.2	3.2
मोतियों को छोड़कर भिन्न खनिज विनिर्मित उत्पाद	0.4	97.0	101.0	4.1
रसायन	9.0	2260.6	2323.3	2.8
धातुओं का विनिर्माण	1.0	252.9	261.9	3.6

स्रोत — आर्थिक समीक्षा वाणिज्य मन्त्रालय भारत सरकार, वर्ष 1999-2000 पृष्ठ 94 ।

वजन मूल्य वर्ष 1977-78 के हिस्से के आधार पर निकाला गया है।

इन वर्षों में आयात संरचना के मुख्य तथ्य—

(1) पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय में तेज वृद्धि हुई। वर्ष 1960-61 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट का आयात व्यय में जो हिस्सा 6.1 प्रतिशत तथा 1970-71 में 8.3 प्रतिशत था, वही 1980-81 में बढ़कर 41.9 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा पहले 1973-74 और पुनः 1978-79 में तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि किया जाना था। 1973-74 में जो तेल की कीमत 2.50 से 3.00 डॉलर प्रति बैरल था वह एकदम से बढ़कर 11.65 डॉलर प्रति बैरल कर दिया गया था। पुनः इसकी कीमत वर्ष 1978-79 में बढ़ाकर 35.00 डॉलर प्रति बैरल कर दिया गया। 1973-74 में की जाने वाली पहली वृद्धि के फलस्वरूप एक ही वर्ष के बीच पेट्रोलियम तथा लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय 597 करोड़ रुपये बढ़ गया था।¹ यह उस वर्ष आयात व्यय में होने वाली वृद्धि का 42 प्रतिशत था। 1979 में दूसरी बार तेल की कीमतों को बढ़ाये जाने से वर्ष 1978-79 से 1979-80 एक वर्ष के बीच पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय 1,589 करोड़ रुपये बढ़ गया। यह उस वर्ष आयात व्यय में होने वाली वृद्धि का 68 प्रतिशत था। अगले ही वर्ष 1979-80 से 1980-81 के बीच आयात व्यय 3,466 करोड़ रुपये बढ़ गया। इस वृद्धि में से 1931 करोड़ रुपये (अर्थात् 50.7 प्रतिशत) वृद्धि पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय बढ़ने के कारण थी। अस्सी के दशक में घरेलू तेल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथा तेल की कीमतों में नरमी आई। इन

¹ एस० के० मिश्रा एवं वी०के० पूरी, भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली पृष्ठ 503

प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट का आयात व्यय में हिस्सा काफी कम हो गया। 1992-93 में यह 27.0 प्रतिशत तथा 1995-96 में 20.5 प्रतिशत था। परन्तु 1996-97 में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेन्ट का आयात 10,036 मिलियन डालर तक पहुँच गया। जो कुल आयात व्यय का एक चौथाई (25.6 प्रतिशत) था। 1997-98 एवं 1998-99 में पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेन्ट के आयात कम होकर क्रमशः 8,164 मिलियन डालर तथा 6,433 मिलियन डालर रह गया। पुनः वर्ष 1999-2000 में यह तीव्र रूप से बढ़ कर 12,611 तथा 2000-2001 में 15,650 मिलियन डालर के उच्च स्तर तक पहुँच गया।

(2) इस्पात एवं लोहा के घरेलू उत्पादन बढ़ने के बाद भी इन सब का आयात अत्यधिक मात्रा में करना पड़ रहा है, क्योंकि माँग की तुलना में उत्पादन कम है। इस्पात एवं लोहा पर आयात व्यय कुल राशि के रूप में वर्ष 1970-71 में 194 मिलियन डालर से बढ़कर 1996-97 में 1,934 मिलियन डालर तक पहुँच गया, परन्तु प्रतिशत के रूप में यह 1970-71 में 9.0 प्रतिशत से घटकर 1996-97 में 4.9 प्रतिशत तथा वर्ष 1998-99 में मात्र 2.8 प्रतिशत ही रह गया है।

(3) आयात का गैर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण की वस्तुओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस मद में वर्ष 1970-71 में खर्च 341 मिलियन डालर था। जो 1996-97 में बढ़कर 4,169 मिलियन डालर हो गया। प्रतिशत के रूप में आयात व्यय में इस मद का हिस्सा 1970-71 में 15.8 प्रतिशत था जो 80 तथा 90 के दशक में 8 से 12 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 1998-99 में कुल आयात व्यय में गैर विद्युतीय मशीनरी व उपकरण का हिस्सा 8.2 प्रतिशत अर्थात् 3,391 मिलियन डालर था जो वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में इस मद में आयात व्यय क्रमशः 3,993 व 3,703 मिलियन डालर रहा। मूल्य के रूप में देखे तो वर्ष 1998-99 में इस मद में आयात व्यय 1,064 मिलियन डालर की तुलना में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में क्रमशः यह घटते हुए 884 व 781 मिलियन डालर रह गया।

(4) आयात व्यय उर्वरकों पर भी काफी हुआ। यह व्यय वर्ष 1970-1971 में 113 मिलियन डालर से बढ़कर 1995-1996 में 1,683 मिलियन डालर तक पहुँच गया। परन्तु वर्ष 1998-1999 में उर्वरकों पर आयात व्यय मात्र 1,010 मिलियन डालर रहा, जो आयात व्यय का 2.4 प्रतिशत था। यह आयात व्यय वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 1,283 मिलियन डालर हो गया किन्तु वर्ष 2000-2001 यह व्यय आधे से कम होकर 664 मिलियन डालर रह गया।

5 भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से कई वर्षों तक खाद्यान्नों का काफी मात्रा में आयात करना पड़ रहा था वर्ष 1960-1961 में तो इसका भाग कुल आयात व्यय के 16 प्रतिशत तक पहुँच गया। हरित क्रांति के पश्चात्

खाद्यान्नों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के बाद भी 1970-1971 में कुल आयात में खाद्यान्न आयात का हिस्सा 13 प्रतिशत था जो 1975-1976 में बढ़कर 25.5 प्रतिशत तक पहुँच गया। किन्तु इसके बाद के वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होने से आयातों में तेजी से कमी आई। हालांकि कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के भण्डार में वृद्धि करने के लिए उनका आयात किया गया। उदाहरण के लिए 1992-1993 में 334 मिलियन डालर मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया, परन्तु अब खाद्यान्नों का आयात नगण्य है 1995-1996 में मात्र 24 मिलियन डालर मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया जो 1996-1997 में थोड़ा बढ़कर 137 मिलियन डालर और 1998-1999 में 231 मिलियन डालर हो गया। पुनः जो वर्ष 1999-2000 में घटकर 222 मिलियन डालर तथा वर्ष 2000-2001 में मात्र 20 मिलियन डालर के न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया।

6 घरेलू माँग बढ़ने के कारण, विगत वर्षों में खाद्य तेलों का भी आयात अत्यधिक मात्रा में करना पड़ा है किन्तु 1989-1990 के वर्षों में घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात में कमी आई और इस वर्ष 127 मिलियन डालर मूल्य के खाद्य तेल आयात किये गये। 90 के दशक में घरेलू माँग के दबाव के कारण कुछ वर्षों में भारी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा। जैसे की 1998-1999 में 1695 मिलियन डालर मूल्य के खाद्य तेल आयात किये गये जो कुल आयात व्यय का 4 प्रतिशत था वर्ष 1999-2000 में खाद्य तेलों का आयात व्यय पुनः बढ़कर 1857 मिलियन हो गया जो कुल आयात हिस्सा 3.7 प्रतिशत था। वर्ष 2000-2001 में इसमें कमी आई और यह 1334 मिलियन डालर रहा जो कुल आयात व्यय का 2.9 प्रतिशत था।

7 वर्ष 2000-2001 में आयात वृद्धि, पेट्रोल तेल स्नेहक (पीओएल) आयात में महत्वपूर्ण उछाल आया जो मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय कच्चा तेल कीमतों की बढ़ती मजबूती की वजह से 24.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर पेट्रोल तेल स्नेहक आयात वर्ष के दौरान धीमी घरेलू माँग तथा साधारण औद्योगिक गतिविधि को दर्शाते हुए 5.9 प्रतिशत तक गिर गये। गैर पेट्रोल तेल स्नेहक आयातों में यह गिरावट खाद्य एवं सबद्ध मदों के कम आयातों पूँजी वस्तु आयात तथा अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं की वजह से हुई, वर्ष 2000-2001 में खाद्य एवं सबद्ध उत्पादों के आयातों में कमी अनाज, चीनी, दूध एवं क्रीम, खाद्य तेल, तिलहन, काजू तथा मसालों के आयात में तीव्र गिरावट के कारण हुआ। वर्ष 2000-2001 में मध्यवर्ती आयातों/कच्चा माल आयातों में गिरावट जो कम माँग का सूचक है, मुख्यतः मदों जैसे— रसायन, मोती, रत्न एवं अर्धरत्न, लौह एवं इस्पात, अलौह धातु, कृत्रिम रेजिन एवं प्लास्टिक सामग्री तथा धातुमय अयस्क एवं धातु स्क्रैप के कम आयातों के कारण थी। पूँजी वस्तु आयातों में गिरावट, परिवहन साधन तथा परियोजना

वस्तुओं के आयातों में हुई गिरावट विशेषतः तीव्र गिरावट के साथ, वर्ष 2000-2001 में जारी रही। ये बढ़ोतरी रुझान कुल निर्यातों के हिस्से में खाद्य एवं संबद्ध आयातों के लिए वर्ष 1999-2000 में 5.8 प्रतिशत से वर्ष 2000-2001 में 3.7 प्रतिशत की गिरावट, पूँजी वस्तुओं के लिए 12.0 प्रतिशत से 11.0 प्रतिशत, अन्य मध्यवर्ती आयातों हेतु 32.8 प्रतिशत से 29.8 प्रतिशत तथा उर्वरकों के लिए 2.8 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत की गिरावट की सूचना देते हैं। तदनुसार कुल आयातों में ईंधन आयातों का हिस्सा वर्ष 1999-2000 में 27.4 से 32.2 प्रतिशत हो गया।

8 वर्ष 2001-2002 वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में आयात बढ़ोत्तरी धीमी रही जो पिछले वर्ष की सगत अवधि में दर्शाई गई, 10.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1.5 प्रतिशत ही बढ़ी जो बहुत कम थी। तथापि, आयात वृद्धि गिरते पेट्रोल तेल स्नेहक आयातों जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों तथा ऊर्जा माँग में कमी में नियन्त्रण की वजह से 9.7 प्रतिशत तक कम हुए थे, के द्वारा नियंत्रित हो गयी। अतः वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान आर्थिक बहाली पर इंगित करते हुए अप्रैल-अक्टूबर 2001 के दौरान गैर तेल आयातों में पिछले वर्ष की सगत अवधि के दौरान 6.2 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बढ़ोत्तरी में खाद्य तथा संबद्ध उत्पादों (मुख्यतः दाल, मसाले तथा चीनी) और अन्य मध्यवर्ती उत्पादों के बढ़े हुए आयातों का योगदान हुआ। वर्ष के दौरान एक सकारात्मक घटना पूँजीवस्तुओं के आयातों के रुझान में उलटाव रहा जो अप्रैल-अक्टूबर, 2001 के दौरान 6.6 प्रतिशत तक बढ़ गया। वस्तुएँ जैसे दाल, विद्युत मशीनरी, रसायन, अलौह धातु, स्वर्ण एवं चादी तथा व्यावसायिक यन्त्र एवं प्रकाशीय वस्तुओं के आयातों ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान गैर पेट्रोल तेल स्नेहक आयातों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया।

भारत में निर्यातों की संरचना :-

भारत में निर्यातों की संरचना में स्पष्ट रूप से एक प्रवृत्ति यह दिखायी देती है कि समय के साथ निर्यातों में कृषि व उससे सम्बद्ध वस्तुओं का महत्व निरन्तर घटता गया है, तथा विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता गया है। उदाहरणार्थ कुल निर्यातों में कृषि सम्बद्ध वस्तुओं का हिस्सा वर्ष 1960-61 में 44.2 प्रतिशत था। जो कि वर्ष 1998-99 में कम होकर मात्र 18.5 प्रतिशत हो गया, वहीं इसके विपरीत उक्त अवधि में ही विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 78.7 प्रतिशत हो गया। यह अवस्था अर्थव्यवस्था की बदली हुई उत्पाद संरचना दर्शाती है। एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब भारत में एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। केवल एक ही विनिर्मित वस्तु ऐसी है जिसके निर्यात बढ़ नहीं पाये हैं और वह वस्तु है जूट। आजादी के तत्काल बाद हमारे निर्यातों में प्रमुख मदे, जूट,

चाय तथा सूती वस्त्र थे। और इनका निर्यात से प्राप्त आय में हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था। शनै-शनै देश की औद्योगिक संरचना में विविधकरण व मजबूती आया और निर्यात के नये अवसर प्राप्त होते गये। जहाँ आजादी के समय जूट, चाय तथा सूती वस्त्र का निर्यात हिस्सा आधा था वही वर्ष 1970-71 में 31 प्रतिशत व 1998-99 में मात्र 10 प्रतिशत के लगभग घटकर हो गया। इसके ठीक विपरीत इन्जिनियरिंग वस्तुओं का कुल निर्यात हिस्सा वर्ष 1960-61 में जो 3.4 प्रतिशत था वही वर्ष 1998-99 में 13 प्रतिशत बढ़कर हो गया। भारत के निर्यातों की संरचना के बारे में वर्ष 1960-61 से बाद की जानकारी तालिका संख्या 6.10 से स्पष्ट है।

तालिका संख्या 6.10 के अनुसार विगत कुछ समय से विनिर्मित निर्यातों के भाग में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है जो कि समेकित रूप से वर्ष 1995-96 के 75.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 77.8 प्रतिशत हो गया। यह प्रवृत्ति इस वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में कुल निर्यात में विनिर्मित निर्यातों के भाग में पुनः वृद्धि होते हुए 80.8 प्रतिशत सहित जारी रही। वर्ष 1998-99 में कम प्रमाणा के साथ-साथ इकाई कीमत वसूली में कमी के कारण अमेरिकी डालर की कीमतों में 11.7 प्रतिशत की कमी से कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों का भाग वर्ष 1996-97 में 20.4 प्रतिशत के उच्च शिखर से वर्ष 1998-99 में 18.5 प्रतिशत की गिरावट हुई। वर्ष 1995-96 से ही अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के कुल निर्यात के भाग में भी लगातार कमी हो रही है।¹

वर्ष 1998-99 में निर्यात की समस्त स्थूल श्रेणियों में कृषि और संबद्ध उत्पादों में 11.7 प्रतिशत अयस्क एवं खनिजों में 16.0 प्रतिशत, विनिर्मित वस्तुओं में 13 प्रतिशत, कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों में 74.6 प्रतिशत की कमी रही। 1998-99 में वृद्धि में इस प्रकार की कमी मुख्यतः वस्तुओं के भाग के रूप में खाद्य तेल (-50.8 प्रतिशत), अविनिर्मित तम्बाकू (-43.1 प्रतिशत), रंग/मध्यर्वी तथा कोलतार रसायन (21.0 प्रतिशत), इंजीनियरी सामग्रियों (-17.5 प्रतिशत), अयस्को और खनिजों (-16.0 प्रतिशत), सूती धागे और वस्त्र तथा सिले-सिलाए वस्त्र (-15.0 प्रतिशत), समुद्रीय उत्पादों (-14.0 प्रतिशत), और चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं (-11.3 प्रतिशत), का रहा। इस सबके बाद भी बहुत सी वस्तुओं जैसे- चावल (62.5 प्रतिशत), सिले-सिलाए कपड़े (14.4 प्रतिशत), जवाहरात और जेवरात (10.4 प्रतिशत), और हस्तशिल्प (5.3 प्रतिशत), में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

¹ आर्थिक समीक्षा, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, वर्ष 1998-99

तालिका संख्या 6 10

भारतीय निर्यातों की संरचना

	वस्तुएँ	1980-81		1970-71		1980-81		1985-86		1997-98		1998-99	
		मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %	मिलियन डालर	कुल का %
1	कृषि एवं संवर्द्ध उत्पाद जिसमें से	596	44.2	644	31.7	2601	30.6	6320	19.9	6840	19.5	6219	18.5
	(i) चाय एवं मेट	260	19.3	196	9.6	538	6.3	350	1.1	505	1.4	547	1.6
	(ii) काजू गिरी	40	3.0	76	3.7	177	2.1	370	1.2	379	1.1	383	1.1
	(iii) कपास	25	1.9	19	0.9	209	2.5	61	0.2	221	0.6	53	0.2
	(iv) मछली व मछली उत्पाद	10	0.8	40	2.0	274	3.2	1011	3.2	1207	3.4	1038	3.1
2	अयस्क और खनिज (कोयला के अतिरिक्त) जिसमें से	109	8.1	217	10.7	523	6.2	915	2.9	824	2.4	707	2.1
	कच्चा लोहा	36	2.6	155	7.6	384	4.5	515	1.6	476	1.4	380	1.1
	विनिर्मित वस्तुएँ	610	45.3	1021	50.3	4738	55.8	23984	75.4	26860	76.7	26497	78.7
3	(i) किले किलारे कपड़े	2	0.1	39	1.9	696	8.2	3676	11.6	3876	11.1	4444	13.2
	(ii) जूट उत्पाद	283	21.0	252	12.4	417	4.9	186	0.6	187	0.5	141	0.4
	(iii) बमड़ा व उससे निर्मित रमान	59	4.4	106	5.2	493	5.8	1731	5.4	1631	4.7	1620	4.8
	(iv) हस्त शिल्प जिसमें से	23	1.7	90	4.7	1204	14.2	6129	19.3	6282	17.9	6943	20.6
	रत्न एवं आभूषण	2	0.1	59	2.9	782	9.2	5275	16.3	5346	15.3	5904	17.5
	(v) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	15	1.1	39	1.9	284	3.3	2945	9.3	3684	10.5	3372	10.0
4	(vi) इंजिनियरिंग वस्तुएँ	46	3.4	261	12.9	1045	12.3	9358	13.7	5254	15.0	4367	13.0
	अन्य	31	2.4	149	7.3	624	7.4	578	1.8	482	1.4	236	0.7
	कुल	1346	100.0	2031	100.0	8486	100.0	31797	100.0	35006	100.0	33659	100.0

पेट्रोलियम उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, विनिर्मित वस्तुओं तथा मुख्यतः कृषि एवं सबद्ध उत्पादों में तीव्र वृद्धि रहने के कारण वर्ष 2000-2001 में निर्यातों में वृद्धि के साथ सभी मुख्य वस्तु श्रेणियों के निर्यातों में बढ़ोत्तरी हुई थी। इस कार्यनिष्पादन की महत्वपूर्ण विशेषता कृषि एवं सबद्ध उत्पादों का निर्यात जो वर्ष 1996-97 से घट रहा है, में हुआ बदलाव था। इस पुनर्जीवन के लिए उत्तरदायी मुख्य उत्पादों में स्पिरिट तथा मदिरा, शर्करा तथा चाशनी, मुर्गीपालन तथा डेयरी उत्पाद, प्रसंस्करित भोजन, मांस तथा मांस से बनी चीजे, समुद्री उत्पाद, कच्ची कपास, खली, दालें तथा अनाज शामिल हैं। तथापि बागवानी क्षेत्र में, मुख्यतः काफी के निर्यातों में गिरावट के कारण 69 प्रतिशत पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज होना जारी रहा। बढ़ी हुई घरेलू परिष्कृत क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में तीव्र वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। अयस्क एवं खनिजों में तीव्र वृद्धि लौह अयस्क तथा प्रसंस्करित खनिजों के आयातों द्वारा हुई। विनिर्मित वस्तुओं के बीच में इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात, रसायन एवं सबद्ध उत्पाद चमड़ा तथा चमड़ा निर्माता तथा वस्त्र जिसमें सिलेसिलाए कपड़े शामिल हैं, ने बड़ा लाभ कमाया। तथापि, रत्न तथा जेवरों का निर्यात, जो एक बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है, में वर्ष 2000-2001 के दौरान 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, ये गिरावट, स्वर्ण जेवरात क्षेत्र में बढ़ोत्तरी जारी रहने के साथ कटे तथा पालिश किए गये हीरो तक मुख्यतः सीमित रही। इस कार्यनिष्पादन के रहते कुल निर्यातों में विनिर्मित वस्तुओं तथा कृषि तथा सबद्ध उत्पादों का हिस्सा 1999-2000 में क्रमशः 80.7 प्रतिशत तथा 15.2 प्रतिशत से गिरकर 2000-2001 में क्रमशः 78.0 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत हो गया। तदनुसार, कुल निर्यातों में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों और अयस्क तथा खनिजों का हिस्सा वर्ष 2000-2001 में 4.2 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत बढ़ गया।

2001-2002 वित्तीय वर्ष में निर्यातों में कमी विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों द्वारा हुई, जो अप्रैल-अक्टूबर, 2001 के दौरान 7.1 प्रतिशत घट गया, इस प्रकार कुल निर्यातों में इन निर्यातों का हिस्सा और घटकर 7.6 प्रतिशत हो गया। वस्त्र जिनमें सिलेसिलाए वस्त्र शामिल हैं, रत्न एवं आभूषण हस्तशिल्प मंदो, कालीनो तथा चमड़ा तथा विनिर्माण के निर्यातों में गिरावट तथा रसायन और सबद्ध उत्पाद तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातों में तीव्र मंदी से इस महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र से निर्यातों में मुख्यतः कमी हुई। इन निर्यातों में इतनी कम कुल खरीद का आंशिक कारण वैश्विक मंदी की वजह से विकसित देशों में मांग की कमी आना है। अयस्क तथा खनिजों में भी मुख्यतः लौह अयस्क तथा प्रसंस्करित खनिजों के कम निर्यातों की वजह से गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में

अप्रैल-अक्टूबर, 2001 के दौरान बढोत्तरी जारी रही जिससे कुल निर्यातो मे इसका हिस्सा 53 प्रतिशत हो गया। कृषि तथा सबद्ध उत्पादो मे भी अनाज (मुख्यत गेहूँ), चीनी एव चाशनी, प्रसस्करित भोजन तथा मुर्गीपालन एव डेयरी उत्पादो के निर्यातो मे महत्वपूर्ण वृद्धि से 35 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। वर्ष 1998-99 एव 1999-2000 मे कई वस्तुओ मे तीव्रता का रुख रहा जिसे हम निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट कर सकते है -

तालिका 6.11

तीव्रता से बढने वाली निर्यात वस्तुएँ

(मिलियन अमेरिकी डालर)

निर्यात की वस्तुएँ	वजन .	1998-99 (अप्रैल-अक्टूबर)	1999-2000 (अप्रैल-अक्टूबर)	% परिवर्तन
काजू	1 1	252 3	395 8	56 9
परिवहन उपकरण	2 2	378 8	444 1	17 2
प्रारम्भिक और कम प्ररिष्कृत लोहा और इस्पात	1 5	301 9	357 6	18 4
जवाहरात एव जेवरात	17 5	3478 0	4250 2	22 2
धातुओ का विनिर्माण	3 2	574 3	705 0	22 8
बिजली का समान	1 5	282 4	335 8	18 9
हस्त शिल्प	3 7	709 2	817 1	15 2
सिले सिलाए कपडे	13 2	2299 6	2609 5	13 5
कपास के धागे से कृत्रिम वस्त्र	8 2	1583 2	1748 0	12 1
समुद्री उत्पाद	3 1	732 9	770 9	5 2

स्रोत - आर्थिक समीक्षा भारत सरकार वर्ष 1999-2000

- वजन वर्ष 1997-98 के मूल्यों के हिस्से के आधार पर निकाला गया है।

निर्यात संरचना के मुख्य तथ्य -

आजादी के समय से लेकर अब तक के निर्यातो का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर निष्कर्ष रूप मे निम्न तथ्य स्पष्ट होते है-

- 1 तालिका 6.10 को देखने से स्पष्ट है कि सबसे उत्साहवर्द्धक वृद्धि हस्तशिल्प वस्तुओ के क्षेत्र मे हुई। वर्ष 1970-71 मे इनके निर्यात से मात्र 96 मिलियन डालर की आय हुई थी, वही यह बढकर वर्ष 1998-99 मे 6943 मिलियन डालर की निर्यात आय हुई जो कि कुल निर्यात का 20.6 प्रतिशत है हस्तशिल्प के इस बढते हुए निर्यात मे सबसे अधिक योगदान जवाहरात व आभूषणो का है। वर्ष 1970-71 मे इनके निर्यात आय मात्र 59 मिलियन डालर कि तुलना मे वर्ष 1998-99 मे बढकर 5904 मिलियन डालर तक हो गया।

- 2 विगत वर्षों में सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात आय में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1970-71 में सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात मात्र 2 मिलियन डालर था वहीं विगत वित्तीय वर्ष 1998-99 में बढ़कर 4,444 मिलियन डालर की निर्यात आय हुई जो कुल निर्यात आय का 13.2 प्रतिशत था इस प्रकार हस्तशिल्प वस्तुओं के पश्चात सिले-सिलाए कपड़ों का दूसरा स्थान था।
- 3 औद्योगीकरण के व्यापक कार्यक्रमों के अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। 1960-61 में 46 मिलियन डालर कुल निर्यात आय था जो वर्ष 1970-71 में 261 मिलियन डालर तथा वर्ष 1998-99 में 4,367 मिलियन डालर इंजीनियरिंग वस्तुओं से निर्यात आय हो गया। जिसके कारण इन वस्तुओं का निर्यात हिस्सा 60-61 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 13 प्रतिशत हो गया। और इसका निर्यात के क्षेत्र में तीसरा स्थान रहा।
- 4 आर्थिक उदारीकरण के अन्तर्गत व्यापक कार्यक्रमों के अपनाने के बाद जूट का निर्यात लगातार कम हुआ है। आजादी के समय भारत का प्रमुख निर्यात जूट था। किन्तु जो निर्यात आय 1960-61 में 21 प्रतिशत था वहीं 1970-71 में 12.4 प्रतिशत तथा 1998-99 में मात्र 0.4 प्रतिशत निर्यात आय रह गया है।
- 5 मछली उद्योग में भी कुछ जूट जैसा ही निर्यात से आय प्राप्त हो रहा है। 1970-71 में मछली उत्पाद से प्राप्त निर्यात आय का हिस्सा 2.0 प्रतिशत था। जो 1994-95 में कुछ बढ़कर 4.3 प्रतिशत तो हुआ। किन्तु पुन 1998-99 में कम हो करके 3.1 प्रतिशत हो गया है।
- 6 आजादी के समय जूट के बाद सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु चाय थी किन्तु इसमें भी लगातार कमी आती जा रही है। 1960-61 में चाय का निर्यात आय में हिस्सा 19.3 प्रतिशत था जो 1970-71 में 9.6 प्रतिशत तथा 1998-99 में घटकर मात्र 1.6 प्रतिशत तक पहुँच गया।
- 7 उदारीकरण के परिणामस्वरूप चमड़ा व उससे निर्मित सामान का निर्यात आय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा। इससे प्राप्त आय वर्ष 1998-99 में 1620 मिलियन डालर था जो कुल निर्यात आय का 4.8 प्रतिशत है, और निर्यात आय में इस वर्ष पाँचवाँ स्थान रखता है।
- 8 सूती वस्त्र का भी निर्यात आय आजादी के समय से घटा है। आजादी के समय इसका स्थान निर्यात क्षेत्र में तीसरा था किन्तु 1960-61 में 10 प्रतिशत के हिस्से से घटकर 1998-99 में 8.2 प्रतिशत निर्यात से आय प्राप्त हुआ है।

9 कच्चे लोहे के निर्यात में वृद्धि हुई, इसका निर्यात 1970-71 में 155 मिलियन डालर था जो बढ़कर 1997-98 में 474 मिलियन हुआ परन्तु 1998-99 में पुन घटकर 1970-71 की 76 प्रतिशत की तुलना में 11 प्रतिशत निर्यात हिस्सा रह गया।

10 आजादी के पश्चात अपनाए गये तीव्र औद्योगीकरण के फलस्वरूप रसायन व सम्बद्ध उत्पादों में वृद्धि हुई। वर्ष 1970-71 में इन वस्तुओं का जो निर्यात से प्राप्त आय 39 मिलियन डालर थी बढ़कर वर्ष 1998-99 में 3,372 मिलियन डालर हो गयी जो कुल निर्यात का 10 प्रतिशत था। इस प्रकार इससे प्राप्त आय का हिस्सा कुल निर्यात आय में चौथा स्थान रहा।

आर्थिक उदारीकरण

दुनिया में जिन देशों की अर्थव्यवस्था में कम खुलापन था उनमें भारत भी एक है, कुल राष्ट्रीय आय और व्यापार का अनुपात चीन या रूस से भी कम है। पूर्वी एशिया या लातिन अमरीकी देशों की तुलना में तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम बंद सी है, और विश्व व्यापार में इसका हिस्सा आधा फीसदी से भी कम रह गया है। इस स्थिति में वैसे तो कोई खास हर्ज नहीं है, पर व्यापार के मामले में अलग-थलग पड़े रहने से भुगतान असंतुलन पैदा हो गया जिसकी वजह से विदेशों से आपातकालीन मदद या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय-समय पर ऋण लेने की जरूरत पड़ी। एक अनुमान के अनुसार भारत को 1956 से 1971 के बीच के 35 वर्षों में से 29 वर्षों में कम या ज्यादा भुगतान असंतुलन की मार झेलनी पड़ी है। इस प्रकार अपनी तरफ ही नजर रखकर विकास करने की जो रणनीति बनाई गई और जिससे भारत के आत्मनिर्भर और मजबूत होने की उम्मीद की गई थी उसने शुरू के कुछ वर्षों के बाद ही भारत को आत्मनिर्भर बनाना तो दूर समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय राहत अभियानों पर निर्भर बना दिया।¹ वैसे तो आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता को 1978 में महसूस कर लिया गया तथा स्व0 राजीव गान्धी की सरकार 1985 में इसके तरफ सकारात्मक कदम भी उठायी किन्तु 1991 के आर्थिक संकट ने सरकार एवं सरकारी तन्त्र को इस दिशा में व्यापक कदम उठाने के लिए विवश कर दिया। 1990-91 के गंभीर आर्थिक संकट को ध्यान में रखकर ही जुलाई 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के उपायों का सिलसिला प्रारम्भ किया। ये उपाय बहुआयामी थे। स्वतन्त्रोत्तर इतिहास में पहली बार संरक्षण के घटाने, उद्योगों तथा विदेशी पूँजी निवेश को नियन्त्रण से मुक्त करने तथा जड़ सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार कम करने तथा इन क्षेत्रों में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए सधे एवं समन्वित कदम उठाये गये। हाल की नीतियों के चलते

¹ विमल जलान, व्यापार एवं पूँजी का प्रवाह, पृष्ठ 81

विदेशी मुद्रा की स्थिति में स्थिरता आ गयी है। और वर्ष 1995-96 में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर आशा के अनुरूप ही रही। ये स्वागत योग्य उपलब्धियाँ थी। फिर यह साफ है कि अगर वृद्धि दर को 7-8 प्रतिशत तक ले जाना है और इसे लम्बे समय तक बनाए रखना है तो और भी बदलाव लाने की जरूरत है यदि यही वृद्धि दर 25 वर्षों तक बनी रही तो सन् 2020 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय चौगुनी हो जायेगी।

1977-78 में शुरू हुआ उदारीकरण उदारतावाद का नया दौर शुरू किया। तत्पश्चात् इसी क्रम में 1980-81 से 1984-85 की वार्षिक व्यापार नीतियों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक आगतों के आयात उपाय किये गये। परन्तु आयात उदारतावाद के क्षेत्र में प्रभावी कदम पहली बार 1985 में उठाये गये, जब तीन वर्षीय आयात नीतियों के घोषणा का क्रम शुरू हुआ। इस दशक की आयात निर्यात नीति के प्रतिपादन में तीन सरकारी समितियों के सुझावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये समितियाँ थी -

- 1 अलेक्जेंडर समिति
- 2 टडन समिति
- 3 हुसैन समिति

इन उक्त समितियों ने निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात उदारीकरण पर अत्यधिक जोर दिया और यह भी बात स्पष्ट होने लगी कि खुले सामान्य लाइसेन्स (ओ जी एल) के अधीन और मदों को आयात करने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार ओ.जी.एल. सूची में पूँजीगत वस्तुओं और कच्चे माल की और मदों को शामिल करके, आयात उदारीकरण की प्रक्रिया में इन्हे प्राथमिकता दी गई। प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए भी कदम उठाए गये। आखिरी दो, तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीतियों में निर्यातों पर और अधिक ध्यान दिया गया तथा 1990-92 की नीति सर्वाधिक निर्यात उन्मुख थी।

उदारीकरण की नीति को अस्सी एवं नब्बे के दशकों में बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के कारण आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। उदाहरणस्वरूप आयातों का मात्रा सूचकांक 1995-96 में 514.8 तथा 1997-98 में 562.1 तक पहुँच गया। (आधार 1978-79 = 100) अर्थात् लगभग दो दशकों में इसमें साढ़े पाँच गुना से अधिक वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में किए गये अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयात उदारीकरण के कारण निर्यातों की आयात गहनता में काफी वृद्धि हुई है। अमित भादुड़ी एवं दीपक नैयर ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध किया है कि निर्यातों की आयात गहनता जो कुल निर्यातों के अनुपात के रूप में 1972-73 में 6

9 प्रतिशत थी, 1984-85 में यह 23.5 प्रतिशत बढ़कर हो गयी।¹ बाद की अवधि के लिए कुछ ऑकड़े रिजर्व बैंक के सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के अध्ययन में मिलता है जो कि 1942 के कम्पनियों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था जिसमें मुख्य निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1 सर्वाधिक आयात गहनता इन्जीनियरिंग तथा रसायन उद्योगों में रही है। इनमें आयात गहनता जो 1984-85 में 16.2 प्रतिशत थी (आयातित कच्चे माल एवं कल पुर्जों का कुल प्रयुक्त कच्चे माल एवं कल पुर्जों के अनुपात में) 1986-87 में बढ़कर 20.34 प्रतिशत हो गयी। सभी उद्योगों की आयात गहनता में ऊपर व्यक्त 23 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इन्जीनियरिंग उद्योग में आयात गहनता में वृद्धि 11 प्रतिशत अधिक हो गयी।

2 सभी कम्पनियों में कुल प्रयोग होने वाले कच्चे माल एवं कल पुर्जों में आयातित कच्चे माल एवं कल पुर्जों का हिस्सा जो 1984-85 में 12.79 प्रतिशत था 1986-87 में बढ़कर 16.65 प्रतिशत हो गया।

3 रासायनिक उद्योग में आयात गहनता 1984-85 में 18.6 प्रतिशत थी जो 1986-87 में बढ़कर 24.01 प्रतिशत हो गयी। यह सभी उद्योगों की औसत 23 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 26 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इन तीन वर्ष की अवधि 1984-85 से 1986-87 के बीच आयात गहनता में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1985 के उदारीकरण के सन्दर्भ में उठाये गये कदमों के बाद भी नब्बे के दशक में आते आते देश गम्भीर आर्थिक तंगी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया और भुगतान सन्तुलन की देश के सामने गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी। इस स्थिति से निबटने के लिए नरसिम्हा राव की सरकार ने व्यापक रूप में उदारीकरण की नीति को अपनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और यह सिलसिला जारी है। परिणामतः अभी तक निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1 1966 के अवमूल्यन के पश्चात् 1973 में अधिकतर देशों की भाँति भारत सरकार ने भी निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली का त्याग कर दिया और भारतीय रुपये को पाँच प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों की मुद्राओं के साथ जोड़ दिया। 1990 के अन्त तक आते-आते यह विनिमय दर एक SDR = 25.71 रुपये तक पहुँच गया। 1991 के उदारीकरण के आरम्भ में भारत सरकार ने पाँच प्रमुख मुद्राओं (अमरीका के डालर, इंग्लैंड के पाउंड स्टर्लिंग, फ्रांस के फ्रैंक, जर्मनी के मार्क तथा जापान के येन) के सापेक्ष रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन कर दिया।

¹ बी० भट्टाचार्या, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, द इकनामिक्स टाइम्स, डेली न्यूज पेपर 12 मई, 1990 पृष्ठ - 7

जिसके परिणामस्वरूप पाँच प्रमुख मुद्राओं के मूल्य में रुपये के सापेक्ष, लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।¹

2 1992-93 के बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली की घोषणा की जिसके अन्तर्गत रुपए की आशिक परिवर्तनीयता की व्यवस्था थी और इसमें दोहरी विनिमय दर लागू की गई, जिसमें यह व्यवस्था दी गयी कि कुल अर्जित विनिमय आय का 40 प्रतिशत सरकारी विनिमय दर पर सरकार को देना होगा और शेष 60 प्रतिशत बाजार द्वारा निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाएगा।

3 बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को अपनाने के बाद 1995 तक तो रुपये में स्थिरता बनी रही, किन्तु अगस्त 1995 के पश्चात रुपए का मूल्य ह्रास पुनः शुरू हो गया और फरवरी 1996 तक आते-आते विनिमय दर गिरकर 1 डालर = 36.6 रुपए तक पहुँच गया। और ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा तब स्थिरता पुनः कायम हुई। लगभग अठ्ठारह महीने तक विदेशी विनिमय बाजार में स्थिरता की स्थिति बने रहने के बाद अगस्त 1997 में भारतीय रुपये ने पूर्वी एशिया में मुद्रा संकट से उत्पन्न प्रभाव का अनुभव किया। 16 जनवरी, 1998 आते-आते रुपए का मूल्य गिरकर 1 डालर = 40.36 रुपए हो गया। परन्तु उसके बाद रुपए ने थोड़ी मजबूती दिखायी और यह मार्च 1999 तक लगभग एक सी बनी रही। किन्तु अप्रैल 1999 से राजनैतिक परिवर्तनों से तथा कारगिल युद्ध से जनित अस्थिरता के कारण विनिमय दर पर असर पड़ा। और इस माह में डालर के सापेक्ष विनिमय दर 42.51 रुपये तक पहुँच गया जो सितम्बर तक आते-आते 43.60 रुपये तक हो गया। जनवरी 2000 के अन्त तक 1 डालर = 43.64 रुपए तथा मार्च 2002 तक आते-आते रुपये का मूल्य 1 डालर = 48.68 रुपये तक पहुँच गया है।

4 वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1992-93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली की घोषणा की। इस प्रणाली में रुपये की आशिक परिवर्तनीयता की व्यवस्था थी। इसके अन्तर्गत दोहरी विनिमय दर लागू की गयी। अर्थात् 60/40 परिवर्तनीयता के स्थान पर 100 प्रतिशत परिवर्तनीयता लागू की गई। यह परिवर्तनीयता, वस्तुओं का सम्पूर्ण आयात निर्यात तथा भुगतान शेष पर सभी प्राप्तियाँ (चाहे वे चालू खाते में हो अथवा पूँजी खाते में) क्षेत्रों में की गई। इसके साथ-साथ एकीकृत विनिमय दर की परिधि से बाहर की कुछ मदों के लिए सरकारी विनिमय दर को बनाए रखा गया। इस प्रकार 6 अदृश्य मदें चालू व पूँजी खातों में थी। इसके अलावा

रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गये कई विनिमय नियन्त्रणों को चालू रखा गया। हालांकि उनमें कुछ ढील अवश्य दी गयी।¹

5 रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीयता की दिशा में 19 अगस्त, 1994 को और कदम उठाए जब चालू खातों के भुगतान पर छूट व रियायतें दी गईं। वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में और कदम उठाते हुए, विदेशी विनिमय नियन्त्रणों में और ढील दी गई।

6 भारत ने चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति 19 अगस्त 1994 को ही प्राप्त की और 20 अगस्त 1994 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद 8 का दर्जा प्राप्त किया। अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए चालू खाते पर परिवर्तनीयता को विदेशी मुद्रा खरीदने अथवा बेचने की स्वतन्त्रता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है।

- (A) चालू व्यवसायों, सेवाओं तथा अल्पकालीन बैंकिंग व सुविधाओं तथा विदेशी व्यापार से जुड़े सभी भुगतान।
- (B) ऋणों पर ब्याज तथा अन्य निवेशों से निवल आय के रूप में देय भुगतान।
- (C) ऋणों को चुकाने अथवा प्रत्यक्ष निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए मामूली राशि का भुगतान।
- (D) परिवारों के निर्वाह व खर्चा पूरा करने के लिए मामूली प्रेरणाएं।

7 वित्त मंत्री जी के 1994-95 के अपने बजटीय भाषण में कहे अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय नियन्त्रणों को एक निर्दिष्ट सीमा तक उदारीकृत कर दिया। यह उदारीकरण निम्नलिखित क्षेत्रों में किया गया।

- 1 विदेशों में अध्ययन।
- 2 दान।
- 3 बुनियादी यात्रा कोटा।
- 4 विदेशी पक्षों द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं का भुगतान।
- 5 मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता।

¹ जीवन के 0 मुखोपाध्याय द इकोनामिक्स टाइम्स, डेली न्यूज पेपर, 15 मार्च, 1994

8 भारत में मुद्रा स्फीति की दर विकसित देशों की तुलना में अधिक होने के कारण, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में 1993-94 से 1997-98 के मध्य 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (REER का पाँच देशों का सूचकांक जिसका आधार वर्ष 1995 = 100 है, जो कि 1997-98 में 105.19 हो गया)। परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मई 1998 में REER 103.31 था और इसके बाद उसमें गिरावट होने लगी दिसम्बर 1998 में यह कम होकर 98.84 रह गया। 1999-2000 के प्रथम नौ महीनों में NEER और REER में सापेक्षिक रूप से स्थापित्व रहा। अप्रैल 1999 में NEER 82.97 तथा दिसम्बर 1999 में 80.29 था। अप्रैल 1999 में REER 101.30 तथा 1999 के अन्तिम माह में 98.55 था।¹

9 आयातों पर से परिणात्मक नियन्त्रण समाप्त करने के बहुलम्बित विवादित मामले को निपटाने के लिए भारत ने 12 नवम्बर 1997 को यूरोपीय संघ व आस्ट्रेलिया के साथ जेनेवा में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत भारत 2700 उत्पादों के आयात पर जारी परिणात्मक नियन्त्रण 6 वर्षों में समाप्त करने को सहमत हुआ। 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी इस 6 वर्षीय अवधि के दौरान भारत को सन् 2003 तक तीन चरणों में यह आयात नियन्त्रण समाप्त करना था, किन्तु निर्धारित समय सीमा के पूर्व ही इस सन्दर्भ में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जा चुका है।

समझौते के तहत पहले चरण में 3 वर्षों में (31 मार्च, 2000 तक) भारत 177 उत्पादों पर दूसरे चरण में अगले दो वर्षों में (31 मार्च, 2002 तक) 208 उत्पादों पर तथा तीसरे चरण में अगले एक वर्ष में (31 मार्च, 2003 तक) शेष सभी उत्पादों के आयात पर परिणात्मक नियन्त्रण समाप्त करने को सहमत हुआ। सार्वधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र के आधार पर किये गये इस समझौते के परिणाम स्वरूप इस समझौते के लाभ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों को भी उपलब्ध होंगे। इस प्रकार किसी अन्य सदस्य राष्ट्र के साथ भारत यदि अधिक रियायती समझौता करता है, तो उसके लाभ यूरोपीय संघ तथा आस्ट्रेलिया को भी उपलब्ध होंगे।²

¹ आर्थिक समीक्षा, वार्षिक पत्रिका, 1999-2000 स्टेटमेंट 6.6 पृष्ठ एस-80

² प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, अतिरिक्तांक, वर्ष 1999-2001
नोट एनईईआर तथा आरईईआर देशों के सूचकांक में अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और जापान को शामिल किया गया है।

आर्थिक उदारीकरण का भारतीय विदेशी व्यापार पर प्रभाव—

जुलाई 1991 में शुरू किये गए विदेशी व्यापार सुधारों व उदारीकरण के कारण विदेशी व्यापार क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और इनके परिणाम स्वरूप अन्तर्मुखी नीति के स्थान पर अब बाह्य उन्मुखी नीति को अपनाया जा रहा है। उदारीकरण के बाद से भारतीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 में आयात 19.4 मिलियन डालर तथा निर्यात 17.9 मिलियन डालर को मिलाकर कुल विदेशी व्यापार 37.3 मिलियन डालर था, जो इन उदारीकृत नीतियों के चलते वर्ष 1998-99 में बढ़कर, निर्यात 33.7 मिलियन डालर तथा आयात 41.9 मिलियन डालर अर्थात् कुल विदेशी व्यापार 75.6 मिलियन डालर हो गया। किन्तु इन सब के बाद भी वर्ष 1992-93 के बाद से (1993-94 को छोड़कर) आयातों की सवृद्धि दर लगातार निर्यातों की सवृद्धि दर से अधिक रही है। परिणामतः व्यापार शेष घाटे में तेजी से वृद्धि हुई, और यह 1991-92 में 1.5 मिलियन डालर से बढ़कर 1998-99 में 8.2 मिलियन डालर तक पहुँच गया है।

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् विदेशी व्यापार क्षेत्र के निष्पादन और उसमें हुए संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन रिजर्व बैंक की Report on Currency and Finance 1998-99, विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष हैं—

- 1 जहाँ वर्ष 1980-81 से 1988-89 के दौरान भारत में निर्यात में औसतन 8.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई, वहीं 1992-93 से 1998-99 तक के वर्षों में वृद्धि 9.8 प्रतिशत वार्षिक रही। इसी प्रकार जहाँ भारत के आयातों में पिछले दशक में 7.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई वही नब्बे के दशक में यह वृद्धि बढ़कर 12.0 प्रतिशत तक हो गयी।
- 2 उदारीकरण के काल को दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला 1992-93 से 1995-96 तथा दूसरा 1996-97 से अब तक की अवधि। पहली अवधि में भारत के निर्यातों और आयातों में क्रमशः 15.7 प्रतिशत तथा 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 1980-81 से 1990-91 तक की अवधि में दर्ज की गई वृद्धि क्रमशः 8.2 प्रतिशत व 7.8 प्रतिशत की तुलना में काफी ज्यादा थी। परन्तु द्वितीय अवधि काल भाग में निर्यातों एवं आयातों की औसत वृद्धि दर में गिरावट रही और यह क्रमशः केवल 2.0 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत रह गयी।
- 3 विदेशी व्यापार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत का व्यापार शेष, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी आयी। यह अस्सी के दशक में

27 प्रतिशत से घटकर नब्बे के दशक के दौरान 12 प्रतिशत रह गया साथ ही आयात निर्यात अनुपात भी वर्ष 1980-81 में 65.1 प्रतिशत था वही 1992-99 की अवधि में बढ़कर 87.0 प्रतिशत हो गया।

4 1980-89 की अवधि की तुलना में 1992-99 की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार हुआ और यह 5.0 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया। इसी दरम्यान आयात सकल घरेलू उत्पाद अनुपात भी औसतन 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया। रिजर्व बैंक के अनुसार इन अनुपातों में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि 1992-99 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में और खुलापन आया है।¹

5 निर्यात में भारत का हिस्सा जो 1984 से 1987 के बीच 0.52 प्रतिशत से कम हो कर 0.47 प्रतिशत रह गया था, वही 1992 से बढ़कर 0.53 प्रतिशत हो गया। जबकि 1996 के बाद भारत का निर्यात सवृद्धि दर में गिरावट आई। तथापि विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1997 से बढ़कर 0.62 प्रतिशत तक पहुँच गया जो इस बात का द्योतक है कि भारत का निर्यात प्रदर्शन विश्व के अन्य देशों की तुलना में सापेक्षिक रूप से बेहतर रहा।

6 मात्रात्मक प्रतिबन्धों का हटाना 'गैट' का अनुच्छेद 11 आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों (क्यू आर) के सामान्य निष्कासन का, इस शर्त पर कि आयातों को केवल टैरिफों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, प्रावधान करता है। तथापि इस शर्त के भी कई अपवाद हैं, जिनमें ऐसी स्थिति वाला एक अपवाद महत्वपूर्ण है जहाँ एक देश को अपनी विदेशी वित्तीय स्थिति का सुरक्षोपाय करना होता है। प्रावधानों में यह भी विचार किया जाता है कि ऐसे प्रतिबन्धों में उत्तरोत्तर छूट दी जाए ताकि भुगतान सतुलन की स्थितियों में सुधार हो सके तथा इन प्रतिबन्धों को तब हटा लिया जाए जबकि स्थितियाँ इसके अस्तित्व को और अधिक न्यायोचित न पाती हो।

भारत 'गैट' के विशेष समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत भुगतान सतुलन कारणों से मात्रात्मक प्रतिबन्ध को बनाए रखता आ रहा था। हम वर्ष 1991 जब आर्थिक सुधारों को प्रारम्भ किया गया था, से आयातों पर प्रतिबन्धों को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के लिए एक सतत नीति का पालन कर रहे हैं। टैरिफ क्रमवार आयात नीति की प्रथम घोषणा 31 मार्च, 1996 को की गई थी जिस दिन 10202 की कुल संख्या में से 6161 टैरिफ क्रम (एचएस-आईटीसी के 10 अंकीय स्तर पर) के आयात मुक्त थे। हमारे भुगतान-सतुलन में सुधार के फलस्वरूप, 488

¹ रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सर्वेक्षण, op, at P.IX-2.

टैरिफ क्रमों पर आयात प्रतिबन्धों को वर्ष 1996-97 में हटा दिया गया, वर्ष 1997-98 में 391 (8 अकीय स्तर पर), 1998-99 में 894 तथा 1999-2000 में 714 टैरिफ क्रमों को हटा दिया गया। भुगतान सतुलन आधार पर आयात प्रतिबन्धों के हटाने की प्रक्रिया को वर्ष 31 3 2001 को घोषित 'एक्विजम' नीति में शेष मदों पर प्रतिबन्धों के हटाने के साथ ही पूरा कर लिया गया है। टैरिफ भिन्न बाधाओं की किस्मों तथा उनको हटाने में की गई प्रगति के सम्बन्ध में वर्ष-वार ब्योरा नीचे दिया गया है।

तालिका 6 12
भारत के आयातों पर टैरिफ-भिन्न बाधाओं की विभिन्न किस्में

टैरिफ भिन्न बाधाओं की किस्म	1.4.96	1 4 97	1 4 98	1.4 99	1.4 2000	1 4.2001
निषिद्ध	59	59	59	59	59	59
प्रतिबधित	2984	232	2314	1183	968	479
सारणी	127	129	129	37	34	-
एस आई एल	765	1043	919	886	226	-
मुक्त	6161	6649	6781	8055	8854	9611*
जोड़	10096	10202	10202	10220	10141	10149

*राज्य व्यापार को अन्तर्गत 29 टैरिफ क्रम शामिल है।

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भारत के आयातों पर टैरिफ भिन्न बाधाओं या मात्रात्मक प्रतिबन्धों को उत्तरोत्तर उदारीकृत किया गया है। 1 4 96 की स्थिति के अनुसार आयात के लिए मुक्त 62 प्रतिशत टैरिफ क्रमों के स्तर से बिना प्रतिबन्ध वाली टैरिफ क्रमों का हिस्सा 1 4 2001 को लगभग 95 प्रतिशत तक बढ़ गया है। भुगतान सतुलन कवच के अतर्गत विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित टैरिफ क्रमों के प्रतिबन्धों (2714 मदों) को हटाए जाने पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तथापि, मात्रात्मक प्रतिबन्धों को गैट के अनुच्छेद 20 तथा 21 के अतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिक व्यवहार के आधारों पर अनुमेय टैरिफ क्रमों के 538 मद लगभग 5 प्रतिशत पर अभी तक बनाया रखा जा रहा है।

आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने का प्रभाव

सरकार एकपक्षीय रूप से आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध (क्यू0 आर) हटाकर वर्ष 1991 से आयातों का उदारीकरण करती रही है। निर्यात आयात नीति, 2001 ने दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से शेष 715 मदों पर भुगतान सतुलन के आधार पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों को विघटित करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसलिए यह आश्चर्य व्यक्त की गई है कि मात्रात्मक प्रतिबन्धों को इस प्रकार हटाने का परिणाम देश में आयातों का प्रवाह और जमाव होगा, जिससे

इस प्रकार घरेलू उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। तथापि ये आशकाएँ इस अवधि में आयात की वास्तविक वृद्धि से उत्पन्न नहीं हुई हैं। पूरे वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए उन 714 मदों जिनसे दिनांक 31-3-2000 से प्रतिबंध हटाया गया था, के लिए आयात संबंधी ऑकड़ों से ऐसे प्रतिबंध हटाए जाने के बाद उनके आयातों में किसी प्रवाह का पता नहीं चलता। इन 714 मदों में से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के पूर्व अथवा उसके बाद 151 मदों के लिए कोई आयात नहीं किया गया था। केवल 92 मदों ने 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आयात दर्ज किया। इन आयातों में हीरे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का हिस्सा 35 प्रतिशत था, और अन्य 14 प्रतिशत का योगदान दूरभाष/तार, उपस्कर, औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर तथा कैथोड रे पिक्चर ट्यूब, घरेलू औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आवश्यक मदों द्वारा किया गया था। यद्यपि तैयार खाद्य पदार्थों के आयात में कुछ वृद्धि देखी गई थी, फिर भी पेय पदार्थ और तम्बाकू, प्लास्टिक और रबड़, चमड़ा उत्पाद कोंच की बनी सामग्रियाँ, तापसह मृत्तिका उत्पाद और जूते तथा छाते जैसे उत्पाद, उपकरणों और उपस्करों के आयात की सम्पूर्ण मात्रा इन मदों के कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 300 सवेदी मदों के आयात पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले नौ महीने के दौरान इन सवेदी मदों के कुल आयात में (डालर के रूप में) मुख्यतः खाद्य तेलों, कपास, और रेशम, मसाले, रबर और सगमरमर तथा ग्रेनाइट के अत्यधिक आयातों के कारण केवल 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

7 व्यापार रक्षा आय

भारत के आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों के हटाने के साथ, चिंताएँ व्यक्त की जाने लगी कि इन्हें हटाने से घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा इससे देश में आयातों की वृद्धि तथा डपिग हो सकती है। तथापि घरेलू व्यापारी बनाम आयात के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने तथा सपाट मैदान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इन मात्रात्मक प्रतिबंधों हेतु उच्चतम सीमाशुल्क पर उचित टैरिफ प्रणाली को प्रभावी किया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों में आयातों की मुक्त सूची में रखे गये कई कृषीय तथा बागवानी उत्पादों को भी हमारे कृषकों के पर्याप्त संरक्षण के सुनिश्चय के लिए उच्चतम दर तक लाया गया है। ऐसे उत्पादों के लिए टैरिफ सीमा का महत्वपूर्ण उच्चतर स्तरों पर भी पुनः प्रबंध किया गया है। सरकार को अस्थायी सुरक्षोपाय के रूप में मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियों से निहित करने के लिए 1992 के विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम को संशोधित करने का भी निश्चय किया गया है। 31-3-2001 को घोषित एक्जिम नीति घरेलू

उत्पादको के संरक्षण के लिए इसके साथ ही निम्नलिखित उपाय करने की भी व्यवस्था करती है।

1 कृषि उत्पाद जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, अन्य अपरिष्कृत अनाज, गरी तथा नारियल तेल, के आयात को राज्य व्यापार की श्रेणी में रखा गया है। नामांकित राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक विचारणाओं के अनुसार इन वस्तुओं के आयातों का संचालन करेगा। इसी तरह पेट्रोलियम उत्पाद जिनमें पेट्रोल, डीजल तथा विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) शामिल है, को भी राज्य व्यापार की श्रेणी में रखा गया है। यूरिया का आयात भी राज्य व्यापार के तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

2 आयातों को विभिन्न मौजूदा घरेलू विनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत नियम, मॉस खाद्य उत्पाद आदेश, चाय अपशेष (नियंत्रण आदेश) के अधीन किया गया है और निषिद्ध रजकों के प्रयोग से बनी वस्त्र सामग्री का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है। सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय विचारणाएँ, पुराने तथा नये आटोमोबाइल्स का विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति दे दी गई है।

3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषीय उत्पाद देश में अन्य स्थानिक बीमारियों तथा कीटों की अवांछित घुसपैठ को न उत्पन्न करे, यह तय किया गया है। जीव उद्गम के आयात को 'जैव सुरक्षा एवं सैनेटरी तथा फाइटो-सैनेटरी परमिट' का विषय बनाया जाय।

4 मासिक आधार पर 300 सवेदी मदों के आयात की निकट देखरेख के लिए एक पूर्व चेतावनी तंत्र का गठन।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, विश्व व्यापार संगठन ढाँचा सदस्यों को कतिपय शर्तों के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी अनुमति देता है। इनमें सब्सिडी तथा डपिंग के प्रति कार्रवाई, सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षण आदि शामिल हैं। भारत जो डपिंग रोधी जाँच के मायने में एक अग्रणीय प्रयोक्ता रहा है, मैं सभी ऐसे प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सांस्थानिक 'सेट अप' मौजूद है। इस तरह, डपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने अपने प्रारम्भ से ही 112 मामले शुरू किये तथा महानिदेशक (सुरक्षा) ने 11 मामलों की जाँच की है। उपलब्ध सरकार घरेलू हित, विशेषतः कृषीय तथा लघु क्षेत्र के संरक्षण के लिए सभी उपलब्ध तंत्रों का प्रयोग करेगी।

आयात पर आनुभविक आँकड़े मात्रात्मक प्रतिबंध के हटने के बाद आयातों में किसी वृद्धि का सुझाव नहीं देती। विशेष उत्पादों से जुड़े मामलों, यदि कोई हो, को डपिंग रोधी निदेशालय

तथा सुरक्षा निदेशालय द्वारा जरूरी राहत दी गई है। वर्ष 2000-01 के दौरान घरेलू उद्योगों को 24 प्रारम्भिक निष्कर्षों तथा 17 अंतिम निष्कर्षों में अनुशसित डपिंग रोधी शुल्कों के तरीके से राहत प्रदान की गई। सुरक्षा शुल्क वर्तमान में तीन उत्पादों (फिनोल, एसिटोन तथा गामा फेरिक आक्साइड) पर प्रवृत्त है।

8 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले का वैश्विक सुधार पर प्रभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका पर दिनांक 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले ने मौजूदा वैश्विक धीमेपन को तीव्र करते हुए विश्व को एक गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया। इस हमले ने विश्व के लगभग सभी मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए अल्पावधिक अभिवृद्धि पूर्वानुमानों (वर्ष 2001 और 2002) का अधोगामी संशोधन करने के लिए बाध्य किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में निवेश स्तरों से संबंधित अनिश्चितताओं और उत्पादकता वृद्धि और व्यय में उपभोक्ता के विश्वास से संबंधित प्रत्यक्ष बोध के रूप में कई जोखिमों के कारण व्यापारिक वातावरण बहुत खराब हो गया। जापान में इक्विटी बाजार और कमजोर हो गया। यूरो क्षेत्र में, घरेलू माँग तेजी से कम हो गई और उसके साथ प्रौद्योगिक क्षेत्र में इक्विटी बाजार में गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर एशिया और लैटिन अमेरिका में गिरावट अधिक गंभीर होने के साथ इस आघात के लिए प्रतिकूल दर्शाई है।

संयुक्त राज्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हमले की प्रत्यक्ष लागत का अनुमान 214 बिलियन अमेरिकी डालर लगाया गया है, जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 0.25 प्रतिशत है। जबकि 16 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का संपत्ति (ढाँचा, उपस्कर और साफ्टवेयर) के क्षति के कारण हैं। और शेष विभिन्न बीमा हानियों से संबंधित हैं। हमले के परिणामस्वरूप घरेलू संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार में निजी खपत में तीव्र गिरावट हुई। उद्योग जो सबसे अधिक प्रभावित हुए, वे विमान सेवा, बीमा और होटल पर्यटन, ट्रेवल एजेंसियाँ, रेस्तराँ और विमान विनिर्माण जैसे अन्य सेवा उद्योग हैं।

दिनांक 11 सितंबर, 2001 के घटनाक्रम का विश्व अर्थव्यवस्था के सुधार पर दीर्घावधिक प्रभाव वैश्विक लेन-देन लागतों और वैश्विक उत्पादन पर उनके प्रभाव में वृद्धि की सीमा पर करेगा। सुरक्षा और बीमा प्रीमियमों पर अधिक व्यय के कारण व्यापार की वैश्विक प्रचालन लागतों में तीव्र वृद्धि संकल्पित है। माल सूची संग्रहण में विश्वव्यापी वृद्धि होने की संभावना है और उतनी ही वृद्धि ऋण दाताओं द्वारा अपेक्षित जोखिम प्रीमियम में होगी। आतंकवाद का सामना करने के लिए देश विशिष्ट प्रतिक्रियाओं में नागरिक से सैन्य प्रयोग में संसाधनों का

अत्यधिक पुर्नआबटन देखा जा सकता है। लेन-देन की उच्चतर लागते और सामग्रियो तथा सेवाओ के सीमा पार आवागमन मे बाधा से वैश्विक उत्पादन पर प्रभाव पडना सभावित है।

दिनांक 11 सितंबर, 2001 के घटनाओ का उभरते हुए बाजार और विकासशील देशो मे अभिवृद्धि की सभावनाओ पर दूरगामी प्रभाव पडने का पूर्वानुमान है। विदेशी मॉग पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले और अत्यधिक विदेशी वित्तपोषण की आवश्यकता वाले देशो के व्यापारिक विश्वास मे कमी और जोखिम प्रीमियम मे वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित होने की सभावना है। निर्यातो के लिए कमजोर वैश्विक मॉग और कम वस्तु मूल्य निम्न आय वाले देशो मे निर्धनता को और प्रबल कर सकते है। सीमा के आर पार शरणार्थियो के प्रवसन मे अवाछनीय वृद्धि, विदेशी निवेशको की बढे हुए जोखिम बोध के कारण निजी पूँजी प्रवाहो मे तीव्र गिरावट, पर्यटन से कम आय और व्यापारिक लेन-देन की अत्यधिक लागतो के रूप मे विकासशील विश्व के लिए कई अन्य बडी चिताए है। वैश्विक आर्थिक सुधार मे अधोगामी जोखिम मे वृद्धि के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओ को वैश्विक अभिवृद्धि मे नव जीवन सचार करने मे मुख्य भूमिका निभानी है। जबकि सयुक्त राज्य अमरीका और यूरो क्षेत्र मे उदार मौद्रिक नीतिगत उपाय अपनाये जा चुके हैं वही स्वचालित स्थिरको के लिए अबाधित कार्य करना महत्वपूर्ण है। वर्धित उत्पादकता अभिलाभो के लिए लक्षित दृढप्रतिज्ञ सरचनात्मक सुधार जापान (बैंकिंग और निगमित क्षेत्रो) और यूरोप (श्रम और उत्पादन बाजार) मे महत्वपूर्ण हैं।

बुनियादी ढाँचो को सुदृढ करने और अधोगामी जोखिमो को दूर करने के लिए अभिप्रेत सुदृढ और सहक्रियात्मक नीतियो उभरते हुए बाजारो और विकासशील देशो के लिए अनिवार्य है। विकासशील और निम्न आय वाले देशो मे निर्धनता मे कमी लाने को उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए धनी देशो द्वारा ओडीए (समुद्र पारीय विकास सहायता) के वर्धित सवितरण, निर्धन राष्ट्रो के लिए सहायता की लेन देन लागतो को कम करने, निवेश और अभिवृद्धि की दशाए सुधारने, वैश्विक सरकारी सामग्रियो का अधिक प्रावधान सुनिश्चित करने और अतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली मे निर्धन राष्ट्रो के लिए अधिक अवसर प्राप्त कराने की आवश्यकता होगी।

निर्यातों की स्थिति पर प्रभाव -

रिपोर्ट आन करेन्सी फाइनेन्स 1998-99 के अध्ययन के अनुसार वर्ष 1992 से 99 के बीच विदेशी व्यापार की तुलना 1987-88 से 1990-91 के बीच विदेशी व्यापार से की गई है और रिपोर्ट के अनुसार निर्यातों की निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट है -

1 आजादी के पश्चात व्यापक आधार पर विविधीकृत औद्योगिक संरचना के निर्माण के कारण भारत मुख्यतया प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक देश न रह कर विनिर्मित वस्तुओं का निर्यातक देश बन गया है। विनिर्मित वस्तुओं का कुल निर्यात में हिस्सा वर्ष 1984-85 तक आते-आते दो तिहाई तक पहुँच गया और यह 1991-92 तक 73.6 प्रतिशत बढ़ कर हो गया। उदारीकरण के पश्चात इन प्रवृत्तियों को और बल इस बात से मिलता है कि जहाँ 1987-91 के मध्य विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात आय में हिस्सा बढ़ कर औसतन 71.2 प्रतिशत था वही वर्ष 1992 से 99 के मध्य इन वस्तुओं का निर्यात आय में हिस्सा बढ़ कर औसतन 75.4 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-अक्टूबर) में यह बढ़कर 76.1 प्रतिशत हो गया। इसी दौरान प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात आय में हिस्सा 24.1 प्रतिशत से घटकर 21.8 प्रतिशत रह गया।

2 उदारीकरण के पश्चात कुछ वस्तुओं की निर्यात संरचना में परिवर्तन हुआ है और कच्चे माल का अधिक निर्यात किया जा रहा है। उदाहरणार्थ—लोहा व इस्पात उद्योग में कच्चे लोहे के निर्यात में कमी हुई है और प्राथमिक व अर्ध निर्मित इस्पात के निर्यात में वृद्धि।

3 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980-89 की अवधि में भारत के निर्यात ढाँचे में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का हिस्सा काफी अधिक और अन्तर्राष्ट्रीय माँग में वृद्धि अत्यधिक कम थी अर्थात् विदेशों में माँग एवं भारत की निर्यात संरचना में उचित तालमेल नहीं था। किन्तु उदारीकरण के पश्चात इस कठिनाई को दूर करने में काफी सफलता मिली है।

4 वर्ष 1980-99 की अवधि के मध्य 6 वस्तुओं को निर्यात प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार आया है। (क) काफी (ख) परिष्कृत खाद्य पदार्थ (ग) जूट और विविध परिष्कृत वस्तुएँ (घ) चावल (ङ) मसाले (च) कला वस्तुएँ तथा अन्य मदे। जहाँ 1980-89 के मध्य इन 6 मदों के निर्यात आय में 2.9 प्रतिशत की गिरावट हुई थी वही 1992-99 के मध्य 20.5 प्रतिशत की इसमें वृद्धि दर्ज की गयी। जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-अक्टूबर) में भी मसाले (1.5 प्रतिशत की कमी) को छोड़कर सभी वस्तुओं के निर्यात हिस्से में वृद्धि हुई है।

5 आर्थिक उदारीकरण का विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक खास बात यह रही है कि विनिर्मित वस्तुओं की निर्यात संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है कि परम्परागत विनिर्मित वस्तुओं के सापेक्षिक हिस्से में लगातार कमी हो रही है जबकि नये विनिर्मित वस्तुओं के सापेक्षिक हिस्से में वृद्धि हो रही है। विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद-समूहों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जिन वस्तुओं की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन हुआ, उनका निर्यात निष्पादन निराशाजनक रहा जबकि जिन उत्पाद समूहों के आन्तरिक संरचना में परिवर्तन हुए उनका निर्यात निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

6 इजीनियरिंग वस्तुओं की निर्यात संरचना में 1980 से 1999 के अवधियों में मशीनरी व उपकरणों का हिस्सा 30.6 प्रतिशत से कम होकर 21.7 प्रतिशत रह गया। जबकि प्राथमिक व अर्धनिर्मित लोहे व इस्पात का हिस्सा 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गया। रसायन व सम्बद्ध उत्पाद समूह में मूलभूत रसायनों, दवाइयों व प्रसाधन सामग्री का हिस्सा कम हुआ, जबकि प्लास्टिक व लिनोलियम के हिस्से में वृद्धि आई है। वस्त्र उत्पाद समूह में मानव निर्मित सूत, तंतु व वस्त्रों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि जूट, टेक्सटाइल के हिस्से में कमी हुई, जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 में भी जारी रही, और कपास के निर्यात हिस्से में 90.6 प्रतिशत की रिकार्ड कमी दर्ज की गई।

7 वर्ष 1993 से 1996 के मध्य देश के विनिर्मित निर्यातों का प्रदर्शन उत्साह वर्धक रहा। परिणामतः कुछ रसायन व सम्बद्ध उत्पादों तथा वस्त्र मदों को छोड़कर सभी मुख्य विनिर्मित निर्यात वस्तुओं का प्रदर्शन इस अवधि में 1980-89 की अवधि की तुलना में बहुत बेहतर रहा। हालांकि 1996 के पश्चात विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि रुक गयी है और संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में भी रुकावट आ गयी है। फिर भी कुल निर्यात आय में कुछ विनिर्मित उत्पादों के हिस्से में वर्ष 1992-2002 के अवधि में उदारीकरण के पूर्व की अवधियों की तुलना में, काफी वृद्धि हुई है। वही इसी अवधि में चमड़ा व चमड़े से निर्मित उत्पादों तथा जवाहरात व आभूषणों के हिस्से में गिरावट आयी है वर्ष 2001-2002 के वित्तीय वर्ष में इनमें क्रमशः 1.8 प्रतिशत व 12.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

8 कृषि व सम्बद्ध पदार्थों की निर्यात संरचना की दृष्टिकोण से कृषि में गिरता हुआ सार्वजनिक निवेश चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि यह सिंचाई, विद्युत, कृषि अनुसंधान, सड़क, बाजार और संचार जैसे आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए निर्णायक है। कृषि में निवेश वर्ष 1993-1994 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1989-99 में 1.3 प्रतिशत हो गया यह गिरावट कृषि में सार्वजनिक निवेश के वर्ष 1993-94 में 4467 करोड़ रुपये से वर्ष 1989-99 में 3869 करोड़ रुपये होने के कारण हुई थी। वास्तव में कृषि में वर्ष 1994-95 से वर्ष 1989-99 तक सार्वजनिक निवेश में निरन्तर गिरावट होती रही है। तथापि, सरकारी निवेश में गिरावट वर्ष 1999-2000 में रुक गयी। जब सरकारी क्षेत्र का पूँजी निर्माण पिछले वर्ष में 3869 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़कर 4122 करोड़ रुपये हो गया पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत के स्तर से संघ में कृषि में निवेश के हिस्से में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह हमारी नीतियों की समीक्षा की माँग करता है जिससे उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन से इतर

उर्वरको, ग्रामीण बिजली सिंचाई उधार एव अन्य कृषि निविष्टियों के लिए सब्सिडियों के रूप में न्यूनता वाले ससाधनों का भी विपथन हुआ है।

9 यद्यपि आर्थिक मन्दी व अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2001-02 में हमारे निर्यातों में न के बराबर वृद्धि हुई है फिर भी साफ्टवेयर निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कृषि उत्पादों का निर्यात -

कृषि निर्यात देश के कुल वार्षिक निर्यातों का लगभग 13 से 18 प्रतिशत भाग है। वर्ष 2000-01 में देश से 6 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया, जिनमें 23 प्रतिशत हिस्सा समुद्री उत्पादों का था। हाल के वर्षों में समुद्री उत्पाद देश से किये जाने वाले कृषि उत्पादों के एकल सबसे बड़े सघटक के रूप में सामने आए हैं, जिनका कुल कृषि निर्यातों में पाँचवे से अधिक हिस्सा है। अनाज (अधिकांशतया बासमती तथा गैर बासमती चावल), खली, चाय, काफी, काजू एव मसाले अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, जिसमें प्रत्येक का देश के कुल कृषि निर्यातों में लगभग 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा है। मॉस एव मॉस उत्पाद, फलों एव सब्जियों तथा प्रसस्कृत फलों एव सब्जियों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने में आयी है, लेकिन वर्तमान में वे प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक नहीं हैं।

हाल के वर्षों में भारत के कृषि निर्यातों में ठहराव के आंशिक कारण चावल, गेहूँ, खली, चाय, काफी आदि जैसे उत्पादों के लिए विकृत घरेलू मूल्य हो सकते हैं। निर्यात आधारभूत ढाँचे में कृषि उत्पाद-विशिष्ट कमजोरियों जैसे भण्डारण, पत्तन प्रहस्तन सुविधाएँ, भारी पैमाने पर प्रसस्करण प्रौद्योगिकी की कमी और निर्यात कोटा प्रतिबन्ध भारतीय पूर्ति स्रोतों को अविश्वसनीय बना देती हैं, और भारतीय कृषि निर्यातों की पूर्ण क्षमता की दोहन में रुकावट पैदा करती हैं।

अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से भारत के कृषि निर्यातों को हम सारणी द्वारा निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं -

तालिका 6.13
भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों का निर्यात

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

वस्तु	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	मूल्य	कुल कृषि निर्यात का %	मूल्य	कुल कृषि निर्यात का %	मूल्य	कुल कृषि निर्यात का %
चाय	538	8.9	412	7.3	433	7.2
काफी	411	6.8	331	5.9	259	4.3
मोटे अनाज	1495	24.8	724	12.9	744	12.4
तम्बाकू	181	3.0	233	4.2	191	3.2

मसाले	388	6 4	408	7 3	354	5 9
काजू	387	6 4	567	10 1	411	6 8
कुसुम और तिल के बीज	78	1 3	86	1 5	131	2 2
गुआरगम खली	173	2 9	188	3 4	132	2 2
खली	462	7 7	378	6 7	448	7 5
फल और सब्जियों	184	3 0	209	3 7	248	4 1
ससाधित फल और सब्जियों	69	1 1	86	1 5	122	2 0
मौस और मौस निर्मितियाँ	187	3 1	189	3 4	322	5 4
समुद्री उत्पाद	1038	17 2	1183	21 1	1394	23 2
अन्य	446	7 4	614	11 0	815	13 6
कृषि निर्यात	6037	100 0	5608	100 0	6004	100 0
कुल निर्यात की तुलना में कृषि निर्यात का प्रतिशत	18 2	-	15 2	-	13 5	-
कुल निर्यात	33218	-	36822	-	44560	

भारतीय कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के सन्दर्भ में हम संक्षेप में निम्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।

- 1 कृषि में विश्व व्यापार के उदारीकरण से अभिवृद्धि के नए परिदृश्य खुले हैं। भारत में निविष्टियों में लगभग आत्मनिर्भरता, तुलनात्मक रूप से निम्न श्रम लागत और विविधतापूर्ण कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण कृषि निर्यातों हेतु अनेक वस्तुओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। इन्हीं कारकों ने समुद्री उत्पादों, अनाजों, काजू, चाय, काफी, मसाले, खली, फलों व सब्जियों, अरंडी और तम्बाकू जैसे अनेक कृषि उत्पादों के निर्यात में सक्षम बनाया है। बासमती चावल जैसी खास वस्तुओं के लिए प्रतियोगिता के बावजूद भारत की अच्छी बाजार पहुँच है। देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का लगभग 18 से 14 प्रतिशत का बढ़ा हिस्सा है।
- 2 देश में कुल आयात में कृषि आयात लगभग 5 से 6 प्रतिशत है। केवल खाद्य तेल, कपास, दालें, और लकड़ी से बने उत्पाद जैसी कुछेक वस्तुएँ आयातित की जाती हैं।
- 3 कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुसार आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी स्तरों के अनुसार उत्पादकता का स्तर और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। अनेक वस्तुओं के लिए हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता विश्व औसत से कम है।
- 4 देश के भीतर, उत्पादकता स्तरों में व्यापक अंतर है। पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश ने विश्व स्तर के उत्पादकता स्तर को प्राप्त कर लिया लगता है। परन्तु अन्य क्षेत्र बहुत पीछे हैं।

इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता का मुद्दा खासकर एक क्षेत्र के लिए ही है। कृषि आर्थिक, जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विभेदक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हर क्षेत्र में उत्पादन की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सके। तुलनात्मक लाभ अपने आप में सबद्ध सकल्पना है और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक परिवर्तनों पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत द्वारा सामना की जा रही एक मुख्य समस्या घरेलू समर्थन का उच्चतर स्तर और कृषि निर्यातों हेतु विकसित देशों द्वारा की जा रही निर्यात सब्सिडियों हैं।

5 अतएव भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने और इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ठोस रणनीतियाँ बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजनार्थ, एक तरफ तो हमें विकसित देशों द्वारा कृषि को दिए जाने वाले समर्थन में भारी कटौती माँगनी चाहिए और दूसरी तरफ अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने व सुधारने के लिए भारतीय कृषि को सहायता की आवश्यकता होगी।

फूलों का विदेशी व्यापार —

फूलों की तिजारत में हिन्दुस्तान की हिस्सेदारी महज आधे से पौने एक प्रतिशत तक ही सीमित है, इसके बावजूद भारत में फूलों के कारोबार का भविष्य बहुत अच्छा है। इस आशावाद के दो कारण हैं पहला तो यह कि हिन्दुस्तान में फूलों की हजारों-हजार किस्में हैं जो न केवल सुगन्ध से भरपूर हैं अपितु सोख सौन्दर्य में भी उनका किसी से मुकाबला नहीं है। भारत में फूलों की खेती का भविष्य जिस दूसरी वजह से उज्ज्वल है, वह वजह है इनके उत्पादन में आने वाली लागत। हिन्दुस्तान का श्रम दुनिया के सबसे सस्ते श्रमों में से है। वैसे जहाँ तक सस्ते श्रम की बात है तो वह तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। कई अफ्रीकी देशों में भी श्रम बहुत सस्ता है। लेकिन उन देशों में भारत की तरह फूलों के विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु और उर्वर कृषि भूमि नहीं है। जबकि भारत में ये दोनों ही सुविधाएँ मौजूद हैं।¹

कुल मिलाकर दुनिया में बढ़ते फूलों के कारोबार में भारत की बेहतरी का भविष्य सुरक्षित है। इसका अनुमान हम मौजूदा कारोबार में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी से भी लगा सकते हैं। इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद फूलों का निर्यात ही वह दूसरा क्षेत्र है, जिसमें हम 20 से 28 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल कर रहे हैं। हालांकि भूमंडलीय मदी के चलते सन् 2000-01 में आई टी सेक्टर में भारत की निर्यात दर घटी है। और आई टी मैन पावर की निर्यात के बजाय कई देशों से उनकी उल्टे भारत वापसी हो रही है। लेकिन फूलों के कारोबार में ऐसा कोई नकारात्मक चिन्ह अभी तक देखने को नहीं मिला। 1996-97 में भारत का फूल

¹ हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ, 17 फरवरी, 2002

निर्यात कारोबार जहाँ महज 20 से 25 करोड रुपये तक ही सीमित था वही सन् 2000-01 तक यह बढ़कर 150 करोड रुपये से ऊपर पहुँच गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस निर्यात कारोबार के 225 करोड रुपये से भी ऊपर पहुँचने की उम्मीद है।

लेकिन जब फूलों के कारोबार की बात होती है तो उसका मतलब सिर्फ निर्यात भर नहीं होता। फूलों के आन्तरिक यानी देश के भीतर के कारोबार का पहलू भी इसमें शामिल होता है। अगर देश के भीतर की फूलों की कारोबारी गतिविधियों पर बात करे तो आश्चर्यजनक ढंग से यह बाहरी निर्यात बाजार से भी बेहतर है। फूलों के निर्यात में जिस तेजी से भारत अपनी जगह बना रहा है उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से भारत में आन्तरिक फूल बाजार विकसित हो रहा है। भूमण्डलीकरण के चलते रहन-सहन और खानपान की संस्कृति में आये बदलावों के कारण भारतीय उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के जीवन में फूलों के महत्व और इनकी सौम्य हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यह विदेशी टीवी प्रसारणों का ही असर है कि शहरी उच्च वर्ग में ताजे फूलों के प्रति लगाव तेजी से बढ़ रहा है। ताजे फूलों के प्रति ही नहीं इन प्रसारणों की बदौलत शहरी उच्च और उच्च मध्यम वर्ग में विदेशी परफ्यूम और डिजाइनर वियर की भी लोकप्रियता बढ़ रही है।

भारतीय महानगरों में चमचमाती 'फ्लोरिस्टो' की दुकानें पिछले एक दशक में ही उगी हैं। यही कारण है कि आज भारत में फूलों की प्रतिवर्ष जो खपत है उसमें 70 से 75 प्रतिशत तक शहरों में ही है। देश के अन्दर फूलों का सालाना कारोबार कोई 600 से 650 करोड रुपये का है जो कि हमारे समूचे निर्यात के चार गुने से भी ज्यादा है। फूलों के निर्यात और आन्तरिक खपत दोनों में तेजी से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि फूलों की उपज का रकबा भी तेजी से बढ़ रहा है। चार साल पहले तक देश में 60,000 हेक्टेयर के आसपास फूलों की उपज का रकबा था जो आज बढ़कर 80,000 हेक्टेयर के आसपास तक पहुँच गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फूलों की उपज के लिए रकबे में वृद्धि सबसे ज्यादा देश के बड़े महानगरों के आसपास हो रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली के आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश और खुद दिल्ली के गाँवों में पिछले कुछ सालों के भीतर फूलों की खेती का चलन बढ़ा है। यही हाल बगलौर, पुणे, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों का है। जहाँ तक राज्यवार फूलों की खेती का सवाल है तो फूलों की खेती सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा व पंजाब में होती है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु फूलों की खेती के लिए पारम्परिक रूप से प्रसिद्ध राज्य हैं। जबकि हरियाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फूलों की खेती का नया चलन है। इसलिए इन नए

फूल उत्पादक क्षेत्रों में फूलों की खेती ज्यादा व्यवस्थित और वैज्ञानिक नजरिये से की जाती है। इसलिये यहाँ ज्यादातर विदेशी और बढ़िया नस्ल के फूलों खासकर गुलाब के फूलों की खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में होने वाली फूलों की खेती शत प्रतिशत निर्यात आधारित उपक्रमों के लिए की जाती है। यही कारण है कि देश में इस समय मौजूद 100 से ज्यादा ग्रीन हाउस प्लान्ट में 72 प्लान्ट इन्हीं दो प्रदेशों में स्थित हैं।

फूलों की बड़े पैमाने पर खेती करने के बावजूद अगर भारत की विश्व फूल कारोबार में 0.5 प्रतिशत से 0.75 फीसदी की ही भागेदारी है तो इसका सबसे बड़ा कारण फूलों के व्यावसायिक कारोबार के लिए इन्हीं मूलभूत सुविधाओं और व्यावसायिक कुशलताओं का अभाव है। अगर भारत सिर्फ पैकेजिंग की बढ़िया व्यवस्था और फूलों को देर तक तरोताजा बनाये रखने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर ले तो विश्व फूल कारोबार में 3 से 5 फीसदी तक की हिस्सेदारी हो सकती है। लेकिन कुशलता पूर्वक सहेजने के अभाव में भारत को हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है।

आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाए जाते समय ऐसी आशा की जा रही थी कि उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आर्थिक साधनों का घरेलू क्षेत्र से निर्यात क्षेत्रों की ओर अंतरण होगा, जिससे निर्यातों का विस्तार होगा। परन्तु बड़ी हुई निर्यात आय की कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के निर्यातों में वृद्धि पर निर्भरता यह संदेश पैदा करती है, कि क्या निर्यात आय में विस्तार काफी मात्रा में है तथा क्या यह विस्तार भविष्य में भी जारी रह सकेगा अथवा नहीं। यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि विस्तार या सवृद्धि उन प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में हुई है जिनकी विश्व माँग के गिरावट की प्रवृत्ति है। एक और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों को निर्यातों में तेज वृद्धि का घरेलू आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार की यह आशा कि उदारीकरण के परिणामस्वरूप हमारे विनिर्मित वस्तुओं की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति बढ़ेगी, पूरी नहीं हो पायी है।

आयातों की स्थिति पर प्रभाव :-

व्यापार नीति पर उदारीकरण का आयातों के सन्दर्भ में विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जहाँ अस्सी के दशक में आयातों की संरचना परिवर्तन के सूचकांक में 27 प्रतिशत तक की कमी हुई थी। 1991 के बाद से आयात संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। यह बात निश्चय ही चौंकाने वाली है क्योंकि उदारीकरण की नीति को लागू करते समय यह आशा की जा रही थी कि इसके लागू होने के पश्चात् भारत के आयात नीति ढाँचे में परिवर्तन होने से आयात संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। मेहता के अनुसार इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि

उदारीकरण की अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं की सीमा शुल्क दरों के विश्लेषण या विस्तार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी कुछ परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों की चर्चा Report on Currency and Finance, 1998-99 में इस प्रकार की गई है—

1 तेल की कीमतों व आयात व्ययों में उतार चढ़ाव के कारण वर्ष 1988-91 के दौरान पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेन्ट पर आयात व्यय की औसत वृद्धि की औसत वार्षिक सवृद्धि दर 27.2 प्रतिशत थी। जबकि कुल आयात व्यय की औसत वार्षिक सवृद्धि दर 12.0 प्रतिशत थी। 1992-93 से 1998-99 के मध्य इस मद पर आयात व्यय में सवृद्धि दर अधिकतम वर्ष 1996-97 में 33.4 प्रतिशत और सबसे कम 1998-99 में -21.2 प्रतिशत रही। जबकि वर्ष 1992-93 से 1998-99 के दौरान 7,134 मिलियन डालर वार्षिक का आयात हुआ। जो वर्ष 1987 से 1991 के दौरान इस मद पर होने वाले औसत वार्षिक आयात व्यय 3,981 मिलियन डालर की तुलना में 79.2 प्रतिशत अधिक था। फलतः पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेन्ट का कुल आयात में हिस्सा 1987-91 में 19.4 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 22.5 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-अक्टूबर) में 29.3 प्रतिशत हो गया जो पिछले वित्तीय वर्ष 2000-01 से 9.7 प्रतिशत कम है।

2 विगत वर्षों में उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप सोने-चाँदी के आयात में वृद्धि हुई है। 1991 में स्वर्ण नियंत्रण आदेश को निरस्त करने के बाद सोने के आयातों के उदारीकरण की दिशा में कई कदम उठाये गये। उदाहरणार्थ जनवरी 1997 में लौट रहे अनिवासी भारतीयों को दस किलोग्राम तक सोना लाने की अनुमति प्रदान की गयी है विशेष आयात लाइसेन्स के जरिये भी सोने का आयात किया जा सकता है। इसके अलावा अक्टूबर 1997 से कुछ अधिकृत फर्मों को खुले सामान लाइसेन्स के अधीन सोना आयात करने की अनुमति दी गयी है ताकि जौहरियों और घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

3 अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों के उतार चढ़ाव व आयात व्यय बढ़ने के कारण विनिर्मित उर्वरकों पर भी वर्ष 1987-91 की अपेक्षा 1992-99 में औसत आयात व्यय 77.7 प्रतिशत अधिक हो गया था जबकि इस मद पर वार्षिक आयात सवृद्धि दर 1992-99 में मात्र 9.5 प्रतिशत थी किन्तु 1987-91 में यह दर 79.5 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 2000-01 व 2001-02 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान क्रमशः 46.1 प्रतिशत व 14.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

4. आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् भारत के कुल औसत वार्षिक आयात (सोना-चाँदी के आयात के अतिरिक्त) वर्ष 1992-99 के मध्य 31,692 मिलियन डालर था जो वर्ष 1987-91 के

मध्य होने वाले वार्षिक आयातों की तुलना में 54.7 प्रतिशत अधिक था। इन दोनों अवधियों के मध्य औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए आयातित मदों में 46.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अन्य वस्तुओं (अन्तिम उपभोग वस्तुएँ) के आयातों में 71.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5 आयात व्यय में वृद्धि उपभोग वस्तुओं के सन्दर्भ में अपेक्षाकृत कम (27.3 प्रतिशत) रही और कुल आयात में इनका हिस्सा जो 1987 से 1991 के मध्य 4.3 प्रतिशत था 1992 से 1999 के मध्य कम होकर 3.6 प्रतिशत रह गया किन्तु इसी वर्ग में खाद्य तेलों के आयात में 55.9 प्रतिशत और चीनी के आयात में 296.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6 वर्ष 2000-01 में देश का कृषि आयात केवल 1.8 बिलियन अमरीकी डालर था, जो देश से होने वाले 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के कृषि निर्यात से बहुत कम था। हाल के वर्षों में खाद्य तेल जिसका हिस्सा कुल कृषि आयातों के मूल्य का लगभग 60 से 70 प्रतिशत है, कृषि आयातों की एक मात्र सबसे बड़ी मद हो गयी है। कच्चे काजू, गिरी (सोराओ से अखरोट) और दालें प्रमुख कृषि आयातों में शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक का हिस्सा हाल के वर्षों में कुल कृषि आयातों का लगभग 5 से 10 प्रतिशत है। चीनी और मोटे अनाज जिनमें से प्रत्येक का हिस्सा भी हाल के वर्षों में देश की कृषि आयातों का 5 से 10 प्रतिशत है, ने वर्ष 2000-01 में मूल्य और हिस्से दोनों के रूप में पर्याप्त गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2000-01 में कृषि निर्यातों का कुल हिस्सा देश का छोटा भाग अर्थात् 3.7 प्रतिशत ही है। हाल के वर्षों में देश के कुल आयातों में कृषि आयातों का हिस्सा 5 से 6 प्रतिशत के आस पास बना रहा।

7 कुछ क्षेत्रों में इन चिन्ताओं के विपरीत कि कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के परिणाम स्वरूप आयातों को उदारीकरण से भारतीय किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए कृषि आयातों में वृद्धि होगी, कुल रूप में कृषि आयातों का मूल्य वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में क्रमशः 2.9 बिलियन अमरीकी डालर और 2.8 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर वर्ष 2000-01 में 1.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। भारत के पास कृषि उत्पादों के लिए विश्व व्यापार संगठन के अधीन टैरिफ, जो संरक्षण का उचित स्तर प्रदान करते हैं, लगाकर सस्ते कृषि आयातों से भारतीय बाजार को भर देने से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। सरकार ने वास्तव में चाय, काफी, दालों और खाद्य तेलों जैसे कई कृषि उत्पादों के लिए पिछले बजट (2001-2002) में आयात टैरिफ में वृद्धि की है। आयातों की वृद्धि का सामना करने के लिए सुरक्षा प्रावधानों के अधीन कार्य करने का विकल्प होने के अतिरिक्त निर्यातकर्ता देशों द्वारा कृषि उत्पादों को दी जा रही कार्य योग्य आर्थिक सहायता का प्रतिरोध

करने के लिए प्रतिकारी शुल्क भी लगाया जा सकता है। अध्ययन में सरलता की दृष्टि से हम कृषि में भारतीय आयातों को निम्न सारणी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।

तालिका 6 14
कृषि आयात

(मिलियन अमरीकी डालर)

वस्तु	1998-1999		1999-2000		2000-2001	
	मूल्य	कुल कृषि आयात का %	मूल्य	कुल कृषि आयात का %	मूल्य	कुल कृषि आयात का %
मोटे अनाज	288	9.9	222	7.8	19	1.0
दाले	169	5.8	82	2.9	109	5.9
दूध और मक्खन	3	0.1	25	0.9	2	0.1
काजू गिरी	230	7.9	276	9.7	211	11.3
बादाम और फल	159	5.5	136	4.8	175	9.4
चीनी	264	9.0	256	9.0	7	0.4
तिलहन	2	0.1	4	0.1	2	0.1
वनस्पति तेल	1,804	61.8	1,857	65.0	1,334	71.8
कुल कृषि आयात	2,919	100.00	2,858	100.00	1,858	100.00
कुल आयात में कृषि आयात का प्रतिशत	6.9	—	5.8	—	3.7	—
देश का कुल आयात	42,389	—	49,671	—	50,536	—

8 पूँजीगत वस्तुओं के आयातों में 56.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई जबकि कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयातों में 39.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहाँ तक पूँजीगत वस्तु समूह का सम्बन्ध है, उन पूँजीगत वस्तुओं के आयातों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई जिनका उपभोग धातुओं, मशीन टूल्स व बिजली की मशीनरी (इलेक्ट्रानिक व कम्प्यूटर सहित) के उत्पादन में किया जाता है, और उन पूँजीगत वस्तुओं के आयातों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जिनका उपयोग गैर बिजली मशीनरी और परिवहन उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है। यद्यपि कच्चे माल व मध्यवर्ती वस्तुओं के कुल आयातों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। तथापि निर्यात गतिविधियों से जुड़ी हुई आयात वस्तुओं तथा रसायनों के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई।

रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1998-99 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयातों की संरचना में उपरोक्त परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं -

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले परिवर्तन।
2. व्यापार नीति में परिवर्तन।
- 3 घरेलू माँग।

उदाहरणार्थ- पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेन्ट्स पर आयात व्यय में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन थे। इसी प्रकार विनिर्मित वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों

मे हाल के वर्षों मे काफी कमी हुई, जिससे उन पर आयात व्यय मे वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। वही दूसरी तरफ सोने-चौदी, खाद्य तेलो और उर्वरको के आयातो मे वृद्धि के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक सरकार की व्यापार नीति रही। इसी प्रकार, पूँजीगत वस्तुओ पर आयात प्रतिबन्धो मे कमी के कारण 1992 से 2001 मे इन पर आयात व्यय काफी बढ गया। जहाँ तक तीसरे कारक घरेलू माँग पैटर्न का सम्बन्ध है भारत मे औद्योगिक सवृद्धि और आयातो मे स्पष्ट सम्बन्ध दिखाई देता है। वस्तुतः भारत के आयातो का एक बडा हिस्सा औद्योगिक सेक्टर की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए है।

जहाँ आयातो मे उदारवादी नीति की आयात गहनता पर प्रभाव इस प्रकार पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, वहाँ इस नीति का निर्यातो पर क्या प्रभाव पडा, यह बता पाना बहुत कठिन है इसका मुख्य कारण यह है कि निर्यात सवर्द्धन मे बहुत से कारको का योगदान होता है। और आयात उदारता उनमे से केवल एक है। किन्तु दीपक नैयर के अध्ययन के अनुसार जहाँ एक ओर भारतीय निर्यातो की औसत आयात गहनता 1977-78 मे 13.7 प्रतिशत से बढकर 1984-85 मे 23.5 प्रतिशत हो गई, वही दूसरी ओर निर्यात आय मे औसत वृद्धि इस अवधि मे मात्र 11 प्रतिशत वार्षिक रही। जहाँ 1970-71 से 1977-78 के मध्य निर्यातो की मात्रा 58 प्रतिशत तथा इकाई मूल्य मे 122 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वही 1977-78 से 1984-85 के बीच निर्यातो की मात्रा मे केवल 30 प्रतिशत की इकाई मूल्य मे 68 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। इस प्रकार उदारवाद के शुरुआत मे आयातो मे उदारवादी प्रवृत्तियो का निर्यात सम्बर्द्धन प्रयासो पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पडा इसके प्रतिकूल ज्यो-ज्यो निर्यातो की आयात गहनता बढती गई, विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय कम होती गयी।

आर0जी0 नाम्बियर, बी0एल0 मुगेकर तथा जी0ए0 टाइस के नवीनतम प्रकाशित अध्ययन से ज्ञात होता है कि 1978-79 मे लेकर 1989-90 के मध्य भारत मे विनिर्मित वस्तुओ के निर्यातो मे लगभग 50 प्रतिशत मध्यवर्ती व पूँजी वस्तुएँ हैं। वर्ष 1991-92 के बाद से विनिर्मित निर्यात वस्तुओ का हिस्सा काफी बढ गया। वर्ष 1989-90 मे यह हिस्सा 50.6 प्रतिशत था जो 1996-97 तक बढकर 72.5 प्रतिशत हो गया। वही दूसरी ओर कुल विनिर्मित निर्यातो मे मध्यवर्ती वस्तुओ का हिस्सा 1989-90 में 38.5 प्रतिशत से कम होकर 1996-97 से 12.6 प्रतिशत रह गया। जहाँ तक आयातो का सम्बन्ध है पूँजीगत वस्तुओं के हिस्से मे लगातार वृद्धि हुई है। विनिर्मित आयात वस्तुओ मे पूँजीगत वस्तुओ का हिस्सा 1978-79 में 36.6 प्रतिशत से बढकर 1996-97 मे 62 प्रतिशत तक पहुँच गया। इन लेखको के मतानुसार आयात उदारीकरण का बुरा असर उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर कम तथा मध्यवर्ती एवं पूँजीगत वस्तु उद्योगो पर

अधिक है। इन दोनों क्षेत्रों में भी पूँजीगत वस्तु उद्योगों पर अधिक बुरा असर पड़ा है। क्योंकि मध्यवर्ती एवं पूँजीगत वस्तु उद्योगों का आय व रोजगार सृजन अवसरों से सीधा संबंध है इसलिए उनमें गिरावट होने का रोजगार व वर्धित मूल्य सृजन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा भारत के औद्योगिक आधार पर भी इन प्रवृत्तियों का बुरा असर पड़ने की आशंका है।¹

विदेशी व्यापार की दिशा

आजादी से पहले भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तुलनात्मक लागत लाभ स्थितियों के द्वारा निर्धारित न होकर ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों द्वारा निर्धारित थी। दूसरे शब्दों में, भारत किन देशों से आयात करेगा और कहाँ पर अपना माल बेचेगा, यह ब्रिटिश शासक अपने देश के हित में तय करते थे। यही कारण है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और उसके मित्र राष्ट्रों के साथ था। यही प्रवृत्ति आजादी के बाद कुछ वर्षों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि तब तक भारत को अन्य देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पायी थी। उदाहरण के लिए, 1950-51 में भारत की निर्यात आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42 प्रतिशत था। उसी वर्ष भारत के आयात व्यय में उनका हिस्सा 39.1 प्रतिशत था। अन्य पूँजीवादी देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि और समाजवादी देशों जैसे सोवियत रूस, रोमानिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि के साथ बहुत थोड़ा व्यापार था। जैसे-जैसे इन देशों के साथ राजनैतिक सम्बन्धों का विकास हुआ वैसे-वैसे आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत होने लगे इस प्रकार बहुत से देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के विकास करने के अवसर खुलने लगे। अब स्थिति काफी बदल चुकी है और 51 वर्षों के आयोजन के बाद व्यापारिक सम्बन्ध काफी कुछ बदल चुके हैं।

आयातों की दिशा .-

व्यापार की दिशा का अध्ययन करने के लिए भारत के 'व्यापारिक सहयोगियों' को पाँच बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है—आर्थिक सहयोग विकास संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पूर्वी यूरोप, विकासशील देश, तथा अन्य। 1960-61 से 1997-98 के दौरान, आर्थिक सहयोग विकास संगठन का हमारे आयात व्यय में हिस्सा कम हुआ है। 1960-61 में

¹ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली, 13 फरवरी, 1999

यह हिस्सा 78 प्रतिशत था जो 1998-99 में 51.0 प्रतिशत रह गया। तेल निर्यातक देशों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। 1960-61 में भारत के आयात व्यय में इस वर्ग का हिस्सा मात्र 4.6 प्रतिशत था जो 1980-81 में बढ़कर 27.8 प्रतिशत हो गया। 1998-99 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का भारत के आयात व्यय में हिस्सा 18.7 प्रतिशत था। इसका कारण यह है कि भारत को इस वर्ग के देशों से भारी मात्रा में पेट्रोलियम तेल का आयात करना पड़ता। समाजवादी देशों के बढ़ते हुए आर्थिक सम्बन्धों के परिणाम स्वरूप, भारत के आयात व्यय में पूर्वी यूरोप का हिस्सा जो 1960-61 में केवल 3.4 प्रतिशत था, 1980-81 में बढ़कर 10.3 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में साम्यवादी देशों की सरकारों के पतन से (तथा विशेष रूप से सोवियत संघ का विघटन होने से) आयात व्यय में पूर्वी यूरोप का हिस्सा कम हुआ है। 1998-99 में यह हिस्सा मात्र 1.6 प्रतिशत था। भारत के आयात व्यय में, विकासशील देशों का हिस्सा (खास तौर पर एशियाई देशों का हिस्सा) पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है। अब भारत के आयात व्यय में इस वर्ग का हिस्सा 21.1 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। इस प्रकार अब भारत के कुल आयात व्यय का पाँचवा हिस्सा विकासशील देशों को जाता है। विभिन्न देशों पर भारत की आयात-निर्भरता तालिका सख्या 6.15 से स्पष्ट है।

1950-51 में भारत के आयातों में इंग्लैण्ड का हिस्सा 20.8 प्रतिशत तथा अमेरिका का हिस्सा 18.3 प्रतिशत था। इस प्रकार इन दो देशों का कुल हिस्सा 39.1 प्रतिशत था। यह देश के औपनिवेशिक सम्बन्धों का सूचक था। एक दशक के भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगे। पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने लगे। इंग्लैण्ड और अमेरिका की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा अमेरिका प्रथम स्थान पर आ गया। उसके बाद यह स्थिति अमेरिका ने (एक दो वर्षों को छोड़कर) हमेशा बनाए रखी। पूरे योजना काल में भारत ने सबसे अधिक आयात अमेरिका से किया। उस देश से भारत ने बड़ी मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा खाद्यान्नों का आयात किया। जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत संघ से व्यापारिक सम्बन्धों का विस्तार होने के कारण इंग्लैण्ड पर निर्भरता कम हो गयी। 1960-61 में भारत के आयातों में इंग्लैण्ड का हिस्सा 19.4 प्रतिशत था जो कम होते-होते 2000-2001 में 6.3 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर जापान का आयात व्यय में हिस्सा 1950-51 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 1960-61 में 5.4 प्रतिशत तथा 2000-2001 में 3.6 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग किया है। जिससे उस देश से आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

तालिका सख्या 6 15

आयात व्यापार की दिशा

										(करोड़ रुपये में)	
		1960-61	70-71	80-81	90-91	95-96	98-99	99-00	00-01		
1.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें से										
	(i) यूरोपीय संघ जिसमें										
	a	15	12	296	2718	5693	1203	15952	13112		
	b	21	21	280	1304	2812	3027	3084	2928		
	c	123	108	694	3473	10520	9006	7978	8039		
	d	11	19	215	793	1907	1953	2041	1999		
	e	217	127	731	2864	6415	11028	11745	14472		
	यूनाइटेड किंगडम										
	(ii) उत्तरी अमेरिका										
	a	347	570	1851	5804	14191	16937	17076	15588		
2.	(iii) अन्व आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें										
	a	20	117	332	559	1275	1622	1649	1814		
	b	328	453	1619	5245	12916	15314	15427	13774		
	अन्व आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसमें										
	a	18	37	170	1464	3418	6079	4692	4855		
	b	61	83	749	3245	8254	10373	10988	8416		
	पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन जिसमें										
	(i)	52	126	3488	7041	25586	32711	48394	11885		
	(ii)	30	92	1339	1018	2001	1993	4721	465		
	3.	(iv) सऊदी अरब									
(i)		2	3	753	496	01	636	865	32		
(ii)		0	6	838	363	6590	6315	5680	515		
(iii)		14	24	540	2899	6773	7705	10483	2838		
पूर्वी यूरोप जिसमें											
(i)		38	220	1296	3377	4217	2864	3354	2968		
(ii)		3	19	44							
(iii)		5	17	97	50	496	182	87	99		
जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य*											
(i)		16	106	1014	2548	2864	2295	2700	2365		
रूस**											

4.	अन्य कम विकसित देश जिसमें	132	239	1966	7965	22509	37630	44585	40347
	(i) अफ्रीका	63	169	205	959	2763	5146	6603	3838
	(ii) एशिया	64	54	1431	6033	17723	29391	33844	33149
	(iii) लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	5	16	313	974	2022	3092	4139	3360
5	अन्य	25	7	59	1505	6112	13163	26382	83583
	जोड़	1122	1634	12549	43198	122678	178332	215236	230873

स्रोत Government of India, Economic Survey, 2001-2002

@ आकड़े एकीकृत जर्मनी के लिए।

@ @ 1992-93 से पूर्व यू0एस0एस0आर0 के सन्दर्भ में।

. जर्मनी के एकीकरण के साथ जर्मन संघीय गणराज्य (उपरोक्त मद 1 i.c) के अन्तर्गत शामिल।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाजवादी देशों तथा विशेषतौर पर भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापारिक संबंधों में तेज वृद्धि हुई। 1950-51 में सोवियत संघ से आयात नगण्य थे। 1960-61 में यह मात्र 16 करोड़ रुपये थे। परन्तु उसके बाद द्विपक्षीय समझौतों के कारण उस देश से आयातों में तेज वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप 1960-61 में 14 प्रतिशत से बढ़कर भारत के आयातों में सोवियत संघ का हिस्सा 1970-71 में 65 प्रतिशत तक पहुँच गया। कई वर्षों में, भारत के आयातों में, अमेरिका के बाद सोवियत संघ का स्थान दूसरा रहा है। उदाहरण के लिए, 1980-81 से 1983-84 तक भारत के आयात में अमेरिका का प्रथम तथा सोवियत संघ का दूसरा स्थान था। 1984-85 में आयातों में सोवियत संघ का हिस्सा 104 प्रतिशत हो गया और उसने अमेरिका को विस्थापित कर प्रथम स्थान ले लिया। इसके बाद तबदीली हुई। 1985-86 में अमेरिका प्रथम, जापान द्वितीय तथा सोवियत संघ तृतीय थे। 1990-91 में अमेरिका का आयातों में हिस्सा 121 प्रतिशत था और उसका स्थान प्रथम था। उसके बाद दूसरा स्थान जर्मनी का था जिसका हिस्सा 80 प्रतिशत था (यहाँ संयुक्त जर्मनी के आँकड़े दिये गये हैं) जापान का स्थान तीसरा था (हिस्सा 75 प्रतिशत) तथा चौथे स्थान पर दो देश थे—इंग्लैण्ड तथा सऊदी अरब (हिस्सा 67 प्रतिशत) पाँचवे स्थान पर 63 प्रतिशत के साथ बेल्जियम था जबकि सोवियत संघ छठे स्थान पर था (हिस्सा 59 प्रतिशत)। सोवियत संघ का विघटन होने से आयातों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए, 1998-99 में भारत के आयातों में अमेरिका का स्थान प्रथम (हिस्सा 86 प्रतिशत), इंग्लैण्ड का स्थान दूसरा (हिस्सा 60 प्रतिशत), बेल्जियम का स्थान तीसरा (हिस्सा 60 प्रतिशत), जापान का स्थान चौथा (हिस्सा 57 प्रतिशत), जर्मनी का स्थान पाँचवा (हिस्सा 51 प्रतिशत), सऊदी अरब का स्थान छठा (हिस्सा 45 प्रतिशत) था।

आयातों के स्रोतों की एक जाँच ओ.ई.सी.डी. देशों से आयातों के एक कम हिस्से को उजागर करती है जो 1999-2000 में 43.0 प्रतिशत से 39.9 प्रतिशत हो गया। क्योंकि इस क्षेत्र से आयातों में वर्ष 2000-01 में 5.6 प्रतिशत गिरावट आई। इसी प्रकार पूर्वी यूरोप, ओपेक क्षेत्र तथा विकासशील देशों से आयातों का हिस्सा वर्ष के दौरान 13 प्रतिशत, 51 प्रतिशत तथा 17.5 प्रतिशत पर कम था। तदनुसार, आयातों की अवशिष्ट श्रेणी से कुल आयातों के हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान उच्चतर स्तरों पर कच्चे तेल के कीमतों की सापेक्षिक स्थिरता अवशिष्ट गन्तव्यों से आयातों के हिस्से में वृद्धि के साथ-साथ ओपेक क्षेत्र से आयातों के हिस्से में गिरावट से वर्ष के दौरान ओपेक क्षेत्र से दूर तेल आयातों के उद्गम में परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। ओ.ई.सी.डी. क्षेत्र में कुल आयातों में आयात का हिस्सा वित्तीय वर्ष

2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान 38.3 प्रतिशत तक और गिर गया, बावजूद इसके कि उन देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से अप्रैल-अक्टूबर 2001 के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ हुई थी। जबकि पूर्वी यूरोप का हिस्सा कायम रखा गया है, ओपेक और विकासशील देशों से आयातों के हिस्से क्रमशः 5.7 प्रतिशत तथा 19.1 प्रतिशत तक बढ़ गये। चुनिंदा पूर्वी एशियाई देशों से आयातों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान लगभग 12 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

निर्यातों की दिशा -

भारत के निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक सहयोग विकास संगठन (ओईसीडी) के देशों को जाता है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन का भारत के निर्यातों में हिस्सा 1960-61 में 66.1 प्रतिशत तथा 1998-99 में 58.0 प्रतिशत था। इनमें से 45 प्रतिशत निर्यात यूरोपीय संघ के देशों को किये जाते हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन को 1960-61 में 4.1 प्रतिशत निर्यात भेजे गये जो 1998-99 में बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गये। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्वी यूरोप के देशों तथा विशेष तौर पर सोवियत संघ को निर्यात में हुई। उदाहरण के लिए कुल निर्यात में पूर्वी यूरोप का हिस्सा 1960-61 में मात्र 7.0 प्रतिशत था। 1980-81 तक बढ़ते-बढ़ते यह 22.1 प्रतिशत तक पहुँच गया। पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी देशों में हो रही उथल-पुथल के कारण तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण, पूर्वी यूरोप को किए जाने वाले निर्यातों में भारी कमी हुई है। 1998-99 में पूर्वी यूरोप का भारत के निर्यातों में हिस्सा मात्र 2.7 प्रतिशत रह गया। अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का भारत की निर्यात आय में हिस्सा लगभग एक चौथाई है। इस वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण एशिया के देश हैं। वस्तुतः 1998-99 में एशियाई देशों का भारत की निर्यात आय में हिस्सा 19 प्रतिशत था (जो कुल निर्यात आय का लगभग पाँचवाँ भाग था)।

1950-51 में योजना प्रक्रिया के शुरू होने से पहले भारत की कुल निर्यात आय में इंग्लैण्ड का हिस्सा 23.3 प्रतिशत था। 1970-71 में यह गिरकर 11.1 प्रतिशत और 1998-99 में मात्र 5.7 प्रतिशत तथा 2000-01 में 5.2 प्रतिशत रह गया। 1950-51 तथा 1960-61 में दूसरा स्थान अमेरिका का था जिसका हिस्सा इन वर्षों में क्रमशः 19.3 प्रतिशत तथा 16.0 प्रतिशत था। इससे यह सिद्ध होता है कि 1950-51 तथा 1960-61 में भारत अपनी निर्यात आय के क्रमशः 42.6 प्रतिशत तथा 43 प्रतिशत के लिए इंग्लैण्ड और अमेरिका पर निर्भर था। अन्य पूँजीवादी देशों और समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध अविकसित रहने के कारण उनका निर्यात आय में योगदान बहुत कम था। परन्तु 1960-61 के बाद इन अन्य देशों के साथ भारत के

व्यापारिक सम्बन्धों का तेजी से विकास हुआ। उदाहरण के लिए जहाँ सोवियत संघ ने 1950-51 में भारत से कुल 11 करोड़ रुपये का माल खरीदा था वहाँ उसने 1970-71 में 210 करोड़ रुपये तथा 1985-86 में 2,006 करोड़ रुपये का माल खरीदा। वस्तुतः 1985-86 में उसका भारत की निर्यात आय में प्रथम स्थान था। दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा स्थान क्रमशः अमेरिका, जापान, इंग्लैण्ड तथा पश्चिमी जर्मनी का था। इसके बाद स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ और 1986-87, 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में प्रथम स्थान अमेरिका का था। इन सभी वर्षों में दूसरा स्थान सोवियत संघ का तथा तीसरा स्थान जापान का था। 1990-91 में भारत की निर्यात आय में सोवियत संघ का स्थान प्रथम था (हिस्सा 16.1 प्रतिशत)। अमेरिका का स्थान दूसरा (हिस्सा 14.7 प्रतिशत) तथा जापान का स्थान तीसरा था (हिस्सा 9.3 प्रतिशत)। सोवियत संघ का विघटन होने से इसके बाद निर्यात दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1998-99 में भारत के निर्यातों में रूस का हिस्सा मात्र 2.1 प्रतिशत था इस वर्ष अमेरिका का भारत के निर्यातों में हिस्सा 21.8 प्रतिशत था और उसका स्थान प्रथम था। दूसरा स्थान इंग्लैण्ड का था जिसका हिस्सा 5.7 प्रतिशत था। जर्मनी का स्थान तीसरा (हिस्सा 5.6 प्रतिशत) तथा जापान का स्थान चौथा (हिस्सा 4.9 प्रतिशत) था।

वर्ष 2000-01 में निर्यातों की दिशा में उन गन्तव्यों जैसे ओईसीडी, ओपीईसी तथा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में विकासशील देशों को भारत के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ दर्शायीं। अमेरिकी डालर मूल्य में निर्यात ओईसीडी में 1.2 प्रतिशत, ओपेक में 24.6 प्रतिशत तथा वर्ष 1999-00 में क्रमशः 10.0 प्रतिशत 9.5 प्रतिशत तथा 16.1 प्रतिशत की अल्प वृद्धियों की तुलना में अन्य विकासशील देशों 25.9 प्रतिशत तक बढ़ गया। विकासशील देशों के मध्य, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्रों को निर्यात 50.0 प्रतिशत, अफ्रीकी क्षेत्र को 27.1 प्रतिशत तथा एशियाई क्षेत्र को 23.8 प्रतिशत बढ़ गये। तथापि पूर्वी यूरोप को निर्यातों में वर्ष 2000-01 में पिछले वर्ष के 24.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी कुल निर्यातों में क्षेत्र-वार हिस्से के सम्बन्ध में, जिस समय ओईसीडी तथा पूर्वी यूरोप के हिस्से में वर्ष 2000-01 में गिरावट आई, वही ओपेक तथा अन्य विकासशील देशों के हिस्सों में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई। ओईसीडी देशों को कुल निर्यातों में हिस्सों में आयी गिरावट के बावजूद, इस क्षेत्र में विकसित देशों जैसे फ्रांस, यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम तथा जापान को निर्यातों में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धियाँ दर्ज की गयीं। मुख्य देशों ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकसित देशों जिनमें थाईलैण्ड, मलेशिया, चीन, श्रीलंका,

सिंगापुर, बांग्लादेश, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको तथा चिली शामिल हैं, को निर्यातो के बढ़ते हिस्से में योगदान किया।

ओईसीडी तथा पूर्वी यूरोप क्षेत्रों में गिरते हिस्से तथा ओपेक और अन्य विकासशील देशों के क्षेत्रों के लिए बढ़ते हिस्से के व्यापक रुझान वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान जारी रहे। ओईसीडी क्षेत्र को निर्यात अप्रैल-अक्टूबर, 2001 के दौरान पिछले वर्ष की सगत अवधि में 13.8 प्रतिशत की एक वृद्धि की तुलना में, इस क्षेत्र में माँग में साधारण मंदी को दर्शाते हुए, 12.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी हुई। इस क्षेत्र में बड़े देशों जिनमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया तथा यूके शामिल हैं, के निर्यातों में गिरावट देखी जा रही है। पूर्वी यूरोप को निर्यातों में गिरावट मुख्यतः रूस तथा हंगरी को कम निर्यातों की वजह से हुई। ओपेक क्षेत्र तथा अन्य विकासशील देशों को निर्यात में वृद्धि भी वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान काफी धीमी रही। भारत के निर्यातों की दिशा का विवरण देश अनुसार तालिका सख्या 6.16 से स्पष्ट है।

वर्ष 2000-01 में यूके, बेल्जियम, जर्मनी तथा जापान, के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान स्विटजरलैंड पाँचवें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा (अमेरिका, यूके, बेल्जियम तथा जर्मनी के बाद)। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जो वर्ष 2000-01 तथा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान लगभग 26 प्रतिशत बढ़ गयी। वर्ष 2000-01 के दौरान जहाँ चीन को अमेरिकी डालर मूल्य में हमारे निर्यात 53.9 प्रतिशत बढ़े, वहीं चीन से आयात 14.1 प्रतिशत से अधिक थे। अप्रैल-अक्टूबर 2001 के दौरान जहाँ निर्यात 20.5 प्रतिशत बढ़ गये, वहीं चीन से आयात 29.5 प्रतिशत बढ़े। दूसरी ओर, भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि मुख्यतः नेपाल को हमारे निर्यात में 6.9 प्रतिशत की कमी के कारण वर्ष 1999-2000 में 16.8 प्रतिशत हो गयी। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अब तक, जहाँ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई, वहाँ नेपाल से आयात हमारे 57.7 प्रतिशत बढ़े हुए निर्यात की तुलना में 85.1 प्रतिशत बढ़ गया है। व्यापार संबंधी भारत-नेपाल संधि में उचित संशोधन/परिवर्तन घरेलू उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए विचाराधीन है। 5 दिसंबर, 2001 से तीन महीनों की एक अवधि के लिए संधि के सीमित विस्तार पर सहमति हो चुकी है ताकि संधि की वार्ताएँ निष्पादित की जा सकें।

तालिका सख्या 6 16

निर्यात व्यापार की दिशा

		1960-61	70-71	80-81	90-91	95-96	98-99	99-00	00-01
1. आर्थिक सहयोग और विकास सगठन जिसमें		425	769	3126	17428	59223	80744	91461	10724
(i)	यूरोपीय सघ जिसमें से	232	282	1447	8951	28157	36361	39445	46123
	a बेल्जियम	5	20	145	1259	3748	5418	5926	6718
	b फ्रांस	9	18	147	766	2499	3491	3888	4660
	c जर्मनी	20	32	385	2549	6614	7792	7533	8718
	d नीदरलैंड	9	14	152	644	2572	3212	3838	4021
(ii)	e यूनाइटेड किंगडम	173	170	395	2128	6726	7806	8817	10502
	उत्तरी अमेरिका	120	235	806	5077	19487	32279	38886	45509
	a कनाडा	18	28	62	281	1022	1990	2506	2999
(iii)	b संयुक्त राज्य अमेरिका	103	207	743	4797	18466	30289	36380	42510
	अन्य आर्थिक सहयोग और विकास सगठन जिसमें	65	234	708	3401	8870	8818	9330	10341
	a आस्ट्रेलिया	22	25	92	321	1257	1630	1747	1854
2. पैट्रोलियम निर्यातक देश सगठन जिसमें	b जापान	35	204	598	3039	7411	6950	7303	8198
	(i) ईरान	26	99	745	1831	10300	14992	16910	22223
	(ii) इराक	5	27	123	141	514	669	659	1037
	(iii) कुवैत	3	10	52	44	2	153	214	384
	(iv) सऊदी अरब	3	16	97	74	453	693	669	910
3. पूर्वी यूरोप जिसमें	(i) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	45	323	1486	5819	4092	3811	4894	4964
	(ii) रोमानिया	3	25	49					
	(iii) रूस	1	14	58	96	100	74	54	56
		29	210	1226	5255	3496	2985	4108	4061

(करोड़ रुपये)

4.	अन्य कम विकसित देश जिसमें "									
	(i)	अफ्रीका	95	305	1286	5465	27324	34218	40906	54282
	(ii)	एशिया	40	129	350	668	3584	5081	4841	6489
	(iii)	लैटिन अमेरिका और करेबियन	45	166	900	4665	22613	26815	33391	43566
			10	10	36	132	1128	2322	2674	4228
5.		अन्य	51	39	68	2010	5414	5987	5390	14861
		जोड़	642	1535	6711	32553	106353	139752	159561	203571

स्रोत : Government of India, Economic Survey, 2001-2002

@ आकड़े एकीकृत जर्मनी के लिए।

@ 1992-93 से पूर्व यूएसएसआर के सन्दर्भ में।

* जर्मनी के एकीकरण के साथ जर्मन सघीय गणराज्य (उपरोक्त मद 1 i c) के अन्तर्गत शामिल।

** ओपेक के सदस्यों के अतिरिक्त।

व्यापार दिशा पर प्रभाव —

उदारीकरण के पूर्व की अवधि को दृष्टिगत करते हुए यदि हम देखे तो भारतीय विदेशी व्यापार पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जिसके परिणाम स्वरूप आयातों एवं निर्यातों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 1987-88 से 1990-91 एवं 1992-93 से 1998-99 के मध्य यदि हम भारतीय निर्यातों की दिशा पर पड़ने वाले प्रभाव को देखे तो जहाँ जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ का भारत की कुल निर्यात आय में हिस्सा 80 के दशक एवं 90 के दशक के दौरान लगभग 50 प्रतिशत पर स्थिर रहा, वहाँ परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों के हिस्से में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जैसा कि निम्न से स्पष्ट है—

1 1987-91 में पूर्वी यूरोप का निर्यात आय में हिस्सा 17.7 प्रतिशत से घटकर 1992-99 के मध्य मात्र 3.8 प्रतिशत रह गया। इस कमी का प्रमुख कारण सोवियत संघ का टूटना था अर्थात् सोवियत संघ का निर्यात आय में हिस्सा 1987-91 में 14.7 प्रतिशत था। जबकि 1992-99 में रूस का निर्यात आय का हिस्सा मात्र 3.1 प्रतिशत रहा।

2 निर्यात संभावनाओं की दृष्टि से भविष्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की निर्यात आय में विकासशील देशों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हो रही है। 1987-91 की अवधि में विकासशील देशों का भारत की निर्यात आय में हिस्सा औसतन 16.0 प्रतिशत था। जो 1992-99 के दौरान बढ़ कर 27.8 प्रतिशत हो गया। कुछ एशियाई देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैण्ड के निर्यातों में उत्साहजनक वृद्धि हुई है।

3 देश के निर्यात आय में यूरोपीय संघ का हिस्सा 1987-91 की अवधि में औसतन 25.6 प्रतिशत था जो 1992-99 की अवधि में थोड़ा बढ़ कर 26.7 प्रतिशत हो गया। इसी मध्य अमेरिका का हिस्सा 16.7 से बढ़कर 19.3 प्रतिशत तथा जापान का हिस्सा 10.0 प्रतिशत से कम होकर 6.5 प्रतिशत हो गया।

4 तेल निर्यात देशों का भारत के निर्यात आय में हिस्सा 1987-91 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 1992-99 में 9.9 प्रतिशत हो गया। जिसका प्रमुख कारण इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात का निर्यात वृद्धि था।

5 भारत का जहाँ तक वस्तु अनुसार विभिन्न देशों को निर्यात का सम्बन्ध है उसके अनुसार 1987-91 से 1992-99 की अवधियों के दौरान अमेरिका का महत्व काफी, तम्बाकू, मसाले, काजू, चमड़ा व चमड़े से निर्मित वस्तुएँ, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, सिले सिलाएँ कपड़ें तथा गलीचे जैसी कई वस्तुओं के लिए बढ़ा है। अन्य औद्योगिक देशों के सम्बन्ध में इटली का महत्व काजू

के लिए और जापन का महत्व गलीचो के लिए बढ़ा है। विकासशील देशों के सम्बन्ध में यदि देखें तो संयुक्त अरब अमीरात को कई भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है। जिनमें चाय, मसाले, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं और सिले-सिलाए कपड़े शामिल हैं। सिंगापुर का महत्व मसालों व खली के लिए तथा हागकाग का महत्व जवाहरात व आभूषण के लिए बढ़ा है। इसके अलावा 90 के दशक में चीन का महत्व समुद्री उत्पाद तथा कच्चे लोहे के लिए सऊदी अरब, बांग्लादेश तथा दक्षिण अफ्रीका का महत्व चावल के लिए, दक्षिण कोरिया तथा इंडोनेशिया का महत्व खली के लिए तथा ईरान का महत्व कच्चे लोहे के लिए बढ़ा है।

जहाँ तक आयातों की दिशा में परिवर्तन का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में भारत के आयातों में विकासशील देशों के महत्व में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि औद्योगिक देशों के महत्व में कमी आयी है जैसे 1997-91 में औसतन 18.0 प्रतिशत से बढ़कर भारत के आयात व्यय में विकासशील देशों का हिस्सा 1992-99 के मध्य 23 प्रतिशत तक पहुँच गया। जिसका प्रमुख कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के नए उभर रहे औद्योगिक देशों से बढ़ते हुए आयात हैं। जहाँ तक आयात व्यय में वृद्धि में विभिन्न वस्तुओं के योगदान का सम्बन्ध है, उसमें मलेशिया तथा सिंगापुर से पेट्रोलियम तेल व उत्पादों, कोरिया और सिंगापुर से रसायन पदार्थों तथा हागकाग, कोरिया, मलेशिया एवं थाईलैण्ड से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात का महत्व बढ़ा है।

ओईसीडी समूह के देशों का वर्ष 1987-91 में भारत के आयात व्यय में हिस्सा 59.4 प्रतिशत था जो 1992-99 की अवधि में कम हो कर 52.1 प्रतिशत रह गया। इस समूह में यूरोपीय संघ का सापेक्षिक हिस्सा 1987-91 में 31.8 प्रतिशत से कम होकर 1992-99 में 26.6 प्रतिशत रह गया। जहाँ तक यूरोपीय संघ के देशों का सम्बन्ध है डेनमार्क, यूनान, आयरलैण्ड तथा इटली के हिस्से में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि जर्मनी नीदरलैण्ड, स्वीडन तथा इंग्लैंड के हिस्से में अपेक्षाकृत धीमी बढ़त हुई। इंग्लैंड का भारत के आयात व्यय में हिस्सा जो 1987-91 के दौरान 7.9 प्रतिशत था जो 1992-99 के मध्य कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गया। ओईसीडी समूह के अन्य देशों में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तथा स्वीटजरलैंड से आयातों में सापेक्षिक रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई। स्वीटजरलैंड का भारत के आयात व्यय में हिस्सा जो 1987-91 में मात्र 1.1 प्रतिशत था 1992-99 में बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गया। इसका प्रमुख कारण इस देश से सोना एवं चाँदी के आयात थे। तेल निर्यातक देशों के समूह का भारत के आयात व्यय में भागीदारी 1987-91 में 14.5 प्रतिशत थी जो 1992-99 के मध्य बढ़कर 21.9 प्रतिशत हो गया। इसका प्रमुख कारण पेट्रोलियम व लुब्रिकैंट पर बढ़ता हुआ आयात व्यय था, जिसके लिए प्रमुख कारणों में मुख्यतः तेल की बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमते जिम्मेदार थीं। पूर्वी यूरोपीय देशों का

आयात व्यय में हिस्सा 1987-91 में 81 प्रतिशत था जो घटकर 1992-99 में मात्र 29 प्रतिशत हो गया।

मूल्यांकन — देश में वर्ष 1991 से प्रारम्भ किये गये व्यापार नीति सुधारों ने विदेशी व्यापार में व्यापक परिवर्तन ला दिए हैं, और अब सरकारी नीति अन्तर्मुखी न होकर बाह्य उन्मुख है। उदारीकरण के वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी व्यापार का हिस्सा काफी बढ़ गया है। 80 के दशक में यह हिस्सा 15 प्रतिशत के आसपास था जो 1995-96 में बढ़कर 24 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। देश में उदारीकरण का जो व्यापक दौर जारी है उसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों को जो संरक्षण मिलता रहा है, उसमें तेज कमी हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने सीमा शुल्कों में काफी कटौती की है तथा ऐसी कई वस्तुओं के आयात को बहुत उदार बना दिया है जिनका आयात या तो पहले किया ही नहीं जा सकता था या जिनके आयात पर कई तरह के प्रतिबन्ध थे। अपने अध्ययन में मेहता ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 55 क्षेत्रों पर आधारित 1989-90, 1993-94 तथा 1995-96 के लिए मौद्रिक तथा प्रभावी संरक्षण दरों की गणना की है। उनके अध्ययन से पता चलता है कि प्रभावी संरक्षण दर जो 1989-90 में 87 प्रतिशत थी, 1993-94 में कम होकर 62 प्रतिशत तथा 1995-96 में और कम होकर मात्र 30 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, मौद्रिक संरक्षण दर 1989-90 में 89 प्रतिशत से कम होकर 1993-94 से 63 प्रतिशत तथा 1995-96 में और कम हो कर 31 प्रतिशत रह गई।¹ कोटा या गैर व्यापार अवरोधों का जहाँ तक संबंध है, उनके बारे में उदारीकरण की अवधि से पहले के सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं परन्तु मेहता ने अनुमान लगाया है कि लगभग 90 प्रतिशत आयातों पर इस प्रकार के कोई न कोई प्रतिबन्ध अवश्य थे। इसके विपरीत, 1995-96 में किसी न किसी प्रकार के गैर-व्यापार अवरोधों के अधीन भारत की 44 प्रतिशत आयात वस्तुएँ थी। अर्थात् उदारीकरण के कारण गैर-व्यापार अवरोधों में भी तेज कमी आई है।

हाल के वर्षों में विदेश व्यापार नीति में उदारीकरण की जो व्यापक प्रक्रिया चल रही है उससे कई सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में यह विश्वास जागने लगा है कि भारत के विकास में अब विदेश व्यापार क्षेत्र 'अग्रणी क्षेत्र' की भूमिका अदा करेगा और इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर सकेगी। परन्तु इस जोश व विश्वास में हमें निम्न तीन मुद्दों को नहीं भूलना चाहिये जो दीपक नैयर के अनुसार, औद्योगीकरण के आयोजन में मूलभूत महत्व रखते हैं— घरेलू बाजार का सापेक्षिक महत्व, सरकारी हस्तक्षेप का स्वरूप व उसकी मात्रा, तथा प्रौद्योगिकी की अन्य देशों से प्राप्ति या उसका स्वयं विकास।

¹ Rajesh Mehta "Trade Policy Reforms, 1991-92 to 1995-96" *Economic and Political weekly*, April 12, 1997 P 780

जहाँ तक घरेलू बाजार के सापेक्षिक महत्व का प्रश्न है, दीपक नैयर के अनुसार, भारत जैसे बड़े देशों में जिनमें घरेलू बाजार बहुत व्यापक व महत्वपूर्ण है, सतत औद्योगीकरण केवल घरेलू बाजार के विकास पर ही निर्भर हो सकता है। इन परिस्थितियों में या तो घरेलू बाजार के लिए, आयात-प्रतिस्थापन नीति की मदद से उत्पादन करने की जरूरत है या फिर विदेशी बाजारों को निर्यात करने के लिए उत्पान किया जा सकता है। औद्योगीकरण की उपयुक्त नीति के परिप्रेक्ष्य में आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के बीच एक सतुलन की स्थिति पैदा करना, 'दो टागो पर' (अर्थात् सतुलन बना कर) चलने के बराबर है। ऐसा वातावरण जो निर्यात निष्पादन के लिए अत्यन्त लाभकारी स्थितियाँ पैदा करता है, दक्ष आयात प्रतिस्थापन तथा तेज आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है।

जहाँ तक औद्योगीकरण की प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप का प्रश्न है बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध इस बात का प्रमाण है कि देर से औद्योगीकरण करने वाले देशों के सफल विकास का मूलधार, सरकार के दिशा निर्देश तथा उसकी समर्थक भूमिका रहे हैं। यह बात न केवल पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के लिए सही है अपितु पूर्वी एशिया के तेजी से विकास कर रहे देशों (जिन्हें एशियन टाइगर्स की सज़ा दी गई है) के लिए भी सही है। दीपक नैयर के अनुसार जहाँ तक सरकारी हस्तक्षेप का सबंध है, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्द्धन में कोई खास अन्तर नहीं है। आयात-प्रतिस्थापन की स्थिति में सरकार घरेलू उत्पादकों की घरेलू बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा करती है। जबकि निर्यात संवर्द्धन की स्थिति में सरकार घरेलू उत्पादकों की विश्व बाजार में विदेशी उत्पादकों से सुरक्षा करती है। महत्वपूर्ण बात है सरकारी हस्तक्षेप का "स्वरूप"। औद्योगीकरण के कार्यक्रमों का आयोजन करते समय विदेशी व्यापार क्षेत्र में इस सरकारी हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा और हस्तक्षेप किस सीमा तक किया जाएगा ये बातें निर्णायक सिद्ध होंगी। "भारतीय अनुभव यह दर्शाता है कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अल्पाधिकारी स्थिति पैदा की जा सकती है ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोरिया गणराज्य का अनुभव यह दर्शाता है कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा एक अल्पाधिकारी वातावरण में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा की जा सकती है।"

जहाँ तक प्रौद्योगिकी के मुद्दे का प्रश्न है, नैयर का तर्क है कि मौजूदा बाजार संरचना और नीति-ढाँचा मिलकर कोई ऐसा वातावरण पैदा नहीं कर सके जिसमें आयातित प्रौद्योगिकी का घरेलू अर्थव्यवस्था में आसानी से विलयन हो सके तथा घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके या जो नयी खोजों और विसरण के लिए सहायक बन सके। यहाँ इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों व समयावधियों में प्रौद्योगिकी विकास के

आयोजन में सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी के आयात के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाय जिसमें प्रौद्योगिकी के आरम्भिक आयात से लेकर देश में उसके पूर्णतया उपयोग तथा विसरण के लिए उपयुक्त कदम उठाने की व्यवस्था हो, अनुसंधान और विकास के लिए ससाधनों का आबटन किया जाए, तथा राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए निश्चित दिशा निर्देश हो।

दीपक नैयर के इन सब तर्कों से यह सिद्ध होता है कि देश के विदेशी व्यापार क्षेत्र और औद्योगीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बीच "समष्टि आर्थिक अतः सम्बन्ध" अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान केवल विदेशी व्यापार क्षेत्र में परिवर्तनों द्वारा (या उस पर आधारित नीतियों द्वारा) नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यह बात सच है कि विदेश व्यापार क्षेत्र की समस्याओं का काफी हद तक समाधान, देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर निष्पादन व बेहतर प्रबंधन से किया जा सकता है।

निर्यात के नये आयामों में, वर्तमान समय में विशेषकर उदारीकरण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, भारत के आयात-निर्यात में कई नये महत्वपूर्ण आयाम जुड़े हैं। चूँकि हमारा निर्यात बढ़ाने पर अधिक जोर है, न कि आयात पर, इसलिए निर्यात के महत्वपूर्ण आयामों को हम देखें तो उसमें कृषि उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, फल-फूल, कम्प्यूटर के नये क्षेत्र, सेटेलाइट एव मिसाइल आदि महत्वपूर्ण हैं। कृषि उत्पादों में वर्ष 1998-99 के 2919 मिलियन अमरीकी डालर आयात की तुलना में निर्यात 6037 मिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 1999-2000 में 2858 मिलियन अमरीकी डालर आयात की तुलना में निर्यात 5608 मिलियन अमरीकी डालर तथा वर्ष 2000-01 में कृषि उत्पाद आयात 1858 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में कुल कृषि उत्पाद निर्यात 6004 मिलियन अमरीकी डालर रहा। कम्प्यूटर के क्षेत्रों में असीम संभावनाएँ हैं क्योंकि इस समय पूरे विश्व की नजर भारतीय कम्प्यूटर उद्योग पर टिकी हुई है। कच्चे माल तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के साथ-साथ भारत में कुशल तकनीकी विद्वानों की भरमार है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सन् 2003 तक प्रत्येक स्कूल पॉलीटेक्नीक कॉलेज और विश्वविद्यालय में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराने तथा अगले पाँच वर्षों में विदेशी व्यापार की दृष्टि से साफ्टवेयर विकास में 60 प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी है जिसमें सन् 2008 तक प्रतिवर्ष 50 अरब अमरीकी डालर के साफ्टवेयर निर्यात आय प्राप्त करने का लक्ष्य है, इस प्रकार विल गेट्स के अनुसार यह वातावरण भारत को साफ्टवेयर के क्षेत्र में सुपर पावर बना देगा।

हमारे निर्यात उद्योग के नये आयामों का अनुमान कुछ नवीनतम सूचनाओं एवं ऑकड़ों से लगाया जा सकता है।¹

- 1 हमारा साफ्टवेयर निर्यात लगभग शत प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में नम्बर एक अमरीका अर्थव्यवस्था नम्बर दो जापान को हम साफ्टवेयर निर्यात कर रहे हैं। जापान को साफ्टवेयर का निर्यात 1994-95 में 26 करोड़ रुपये था जो 1999-2000 में 400 करोड़ तक पहुँच गया।
- 2 हमारा हार्डवेयर निर्यात जो 1999-2000 में 600 करोड़ था 2000-2001 में 1250 करोड़ रुपये हो गया है।
- 3 विश्व के कठिनतम बाजारों में से एक यूरোपियन यूनियन में बीपीएल, वीडियोकॉन एवं ओनिडा द्वारा हाल में 15 लाख टीवी सेट निर्यात करने का आदेश प्राप्त हुआ है।
- 4 हमारी विश्व प्रसिद्ध दवा कंपनियों रैनवैक्सी, एव डा० रेड्डीज लैब जीवन रक्षक दवाइयों अन्य विदेशी कंपनियों की तुलना में आधे दाम पर आपूर्ति करने में सक्षम है।
- 5 सेटेलाइट पार्ट्स एवं पद्धति, अमरीका एवं यूरोप जैसे समृद्ध देशों को हम निर्यात कर रहे हैं निर्यात बाजार की सूचनाएँ भी हम सेटेलाइट के द्वारा निर्यात करने जा रहे हैं।
- 6 हाल में भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एवं सफल परीक्षित मिसाइल "ब्रह्मोस" हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जल्द लाने जा रहे हैं।

मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य सार्वभौम आर्थिक बहाली करने के लिए महत्वपूर्ण अधोमुखी जोखिमों को आश्रय देती है। 11 सितंबर, 2001 की घटनाओं ने मदी को तीव्र किया और सर्वभौम आर्थिक बहाली के अधोमुखी जोखिमों को बढ़ाया। सार्वभौम मन्दी के इस विस्तार और गहनता ने विश्व अर्थव्यवस्था की अतिसवेदनशीलता बढ़ा कर आघात पहुँचाया और स्व-सबलता को अधोगामी बना दिया। मध्यावधि में बहालता की संभावना मुख्यतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों पर निर्भर करती है और इन नीतियों का प्रभाव बढ़े हुए अधोगामी जोखिमों को कम करने के लिए पड़ेगा। भारत इसके सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी क्षेत्र के तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण सार्वभौम मदी से यथोचित रूप से सरक्षित रहा है। फिर भी उन्नत आर्थिक बाजारों में अधोमुखी परिवर्तन भारतीय निर्यातों की माँग को बढ़ा सकता है। निर्यात के लिए ऐसी अपेक्षाकृत अधिक माँग अर्थव्यवस्था में समग्र माँग

¹ डा० ए०ए० सिद्दीकी, इण्डियाज न्यू प्राइवेट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट, लिविंग थ्रु एक्सेलेन्स एण्ड वियान्ड, मोती लाल नहरू रिजनल कालेज इ०वि०वि०, इलाहाबाद, 2002

स्तरो पर निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकती है और भारत को मौजूदा आर्थिक मन्दी से बाहर निकालने के लिए घरेलू उपायो के समर्थन में सहायता कर सकती है।

भारत का वैदेशिक क्षेत्र 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी चुनौतियों और घरेलू आघातों का सामना करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक सुदृढ़ता के साथ उभरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब पहले की तुलना में कहीं अधिक मुक्त है। चूंकि अर्थव्यवस्था अब और मुक्त हो रही है इसलिए यह क्षमता का लाभ प्राप्त करेगी परन्तु यह व्यापार और वित्तीय सपकों के माध्यम से बाहरी आघातों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत देश को आर्थिक आधारभूत सिद्धान्तों को और सुदृढ़ करके ऐसे आघातों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा कर सकता है। इसके लिए निर्यातों, पीओएल के आयातों, पर्यटन की आय, साफ्टवेयर सेवा निर्यातों, विदेशी निवेश प्रवाह और घरेलू मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के क्षेत्र में लगातार नीतिगत सुधार करने की अपेक्षा है निर्यात एक सतत बने रहने वाले भुगतान सतुलन की कुजी है। चालू खाते के घाटे का स्तर वर्ष 1995-96 के बाद मुख्य रूप से तेल विभिन्न आयातों की कम माँग के कारण निम्न रहा है। तेल भिन्न आयातों की धीमी वृद्धि मुख्यतः औद्योगिक वृद्धि में मंदी को प्रतिबिम्बित करती है। औद्योगिक मंदी ने यहाँ तक कि सतुलित पूँजी अन्तर्प्रवाहों के समावेशन को कम किया है। जिसके परिणाम स्वरूप, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के निर्माण में काफी वृद्धि हुई है। जैसा कि दसवी योजना में परिकल्पना की गयी है, जब आर्थिक वृद्धि तीव्र होती है, तेल भिन्न आयातों की माँग में वृद्धि होती है और चालू खाता घाटा अधिक होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि निवल पूँजी प्रवाह, चालू खाते पर अपेक्षाकृत अधिक घाटे का वित्तपोषण करने के लिए वर्तमान स्तर से पर्याप्त रूप से बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमें ऋण-भिन्न सृजनकारी पूँजी प्रवाहों विशेषकर विदेशी निवेश प्रवाहों, को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके अतिरिक्त मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का स्तर बहुत अनुकूल है और विदेशी क्षेत्र को अधिक मजबूत स्रोत प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लम्बे समय में प्रारक्षित भंडार की मात्रा और जोखिम समायोजित पूँजी प्रवाहों का आकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुरूप होगा।

विगत हाल में अनेक उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, भारत को पूँजी लेखे उदारीकरण के प्रति एक चिन्हाकित दृष्टिकोण का अनुपालन करना जारी रखना चाहिये। इससे भारत को व्यवहार्य भुगतान-सतुलन के पर्यावरण में वृद्धि करने, यथोचित रूप से स्थायी विनिमय दर वहनीय विदेशी ऋण रूपरेखा और टिकाऊ सुदृढ़ता और वर्धन में अल्पावधिक सहायता मिलेगी।

अध्याय सात
निष्कर्ष एवं सुझाव

स्वभाव तथा ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन आये हैं, इतना ही नहीं उसकी दिशा में भी परिवर्तन हुआ है। प्रस्तुत शोध में हमने भारत के विदेशी व्यापार का अध्ययन इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए किया है।

जहाँ तक भारत के विदेशी व्यापार का प्रश्न है तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि इसका सफर अत्यन्त प्राचीन काल से है इतिहास के अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि ईसा से 1100 वर्ष पूर्व भी भारतीय व्यापारी दूर-दूर तक वस्तुओं का अदान-प्रदान करते थे। प्राचीन काल में भारत की बनी हुई वस्तुएँ जैसे— सूती कपड़े, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला, आदि की माँग मिस्र, यूनान, रोम तथा इरान आदि स्थानों पर बहुत थी। इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया में अपने उपनिवेश बनाए थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनों जल और थल दोनों ही मार्गों से होता था। भारत में प्राचीन काल में आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान सोना चाँदी से करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश में करोड़ों रुपये का सोना आता था और देश में भुगतान सतुलन प्रतिकूल होने का प्रश्न ही नहीं था। किन्तु बाद में देश की सत्ता विदेशियों के हाथ में चले जाने के पश्चात् देश का विदेशी व्यापार कई युद्धों एवं माहायुद्धों से होते हुए एवं आर्थिक मंदी (1929—30) को झेलते हुए, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारत भी विश्व व्यापार का एक स्वतंत्र सदस्य बना। स्वतंत्रता से पूर्व देश के आयात और निर्यात की दृष्टि से जो नीतियाँ अपनायी गयी थी, उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एवं जीवन स्तर की प्रगति बन गया। स्वतंत्रता के पूर्व देश का विदेशी व्यापार निश्चित रूप से अनुकूल था। हमारे निर्यात ने आयात को बढ़ावा दिया। भारत निर्यात में वाणिज्यिक प्रधान होने के कारण यूरोपियन देश और अन्य देश भारत के साथ ज्यादा व्यापार सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापार की यह महत्वपूर्ण स्थिति तब तक बनी रही, जब तक अंग्रेजों ने देश के ऊपर पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण नहीं स्थापित कर लिया। 1700 ई० में भारत लगभग एक मिलियन सूती कपड़े और 12,000 रेशमी कपड़े ब्रिटेन को निर्यात करता था इन उद्योगों को तथा रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र क्षेत्र को गम्भीर चोट पहुँचने से ये उद्योग तितर-बितर हो गये।¹

¹ कृष्ण बाल, कामार्सियल रिलेशन विटविन इण्डिया एण्ड इंग्लैंड (1601—1751) लन्दन, 1924 पृष्ठ संख्या 208

उपनिवेश क्षेत्र में ब्रिटेन ने दो पक्षीय व्यापार नीति अपनायी, वही से देश में निर्मित माल के निर्यात की अवनति हुई, लेकिन उनके आयात में वृद्धि हुई। लगभग 2% या 3% भारतीय आर्थिक बढ़ोत्तरी को सन् 1757 से 1939 तक प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन में भेज दिया जाता था, अगर उसी स्तर का विनियोग देश के अन्दर हुआ होता, तो 18 वीं सदी के दौरान आर्थिक विकास यू0एस0ए0 और यू0के0 से थोड़ा ही कम होता। भारत के निर्यात की रकम लगभग 300 करोड़ रुपये वार्षिक था। 1520 से 1926 में वह पॉचवा सबसे बड़े व्यापारिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, जूट और जूट माल, चाय, सूती धागे, तिलहन, मसाले, चमड़े और तम्बाकू निर्यात में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था लेकिन 1930 में निर्यात आय में अचानक गिरावट आयी और भारत का निर्यात लगभग 150 करोड़ रुपये तक नीचे आ गया।¹

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो कारणों से भारतीय निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ— पहला ब्रिटेन को अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता थी, जैसे— चमड़े, कपड़े भोजन और सीमेन्ट, ताकि वह युद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए भारत ने लगभग 17,360 मिलियन रुपये का व्यापार किया। दूसरा विदेशी विनिमय कठिनाईयों को कम करने की दृष्टि से जो ब्रिटेन शासन के द्वारा कुछ विदेशी विनिमय नियन्त्रण में डाला गया था, इसके कारण आजादी के बाद उनको अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया।

जब भारत ने स्वतंत्र देश के रूप में निर्यात करना शुरू किया तो पहले वर्ष में उसने 1,736 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। आजादी के बाद कुछ ही वर्षों में भारतीय सरकार ने इस शुद्ध मुनाफे का यथाशीघ्र उपयोग करने का कार्य किया। उस समय निर्यात पर कोई भी दबाव नहीं था। देश की आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के कार्य और औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता के लिए बहुत बड़े पूँजीगत माल की आवश्यकता थी। इन पूँजीगत मालों का विकसित और औद्योगिकृत देशों से एक कमजोर औद्योगिक आधार के साथ आयात करना पड़ा। उपलब्ध विदेशी विनिमय स्रोत उस प्रकार के आयात माल से बड़ी मांग के लिए पूर्ण नहीं थे। जब 1951 में योजना बनाना शुरू किया गया, तब इस बात पर ध्यान दिया गया कि देश में आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के प्रवाहन के लिए निर्यात के द्वारा विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाय।

आजादी के पहले दशक और लगभग 60 वीं के शुरुआत तक हमारे विदेशी व्यापार के सन्दर्भ में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। विश्व व्यापार 8% वार्षिक की दर से 50 वीं

¹ भाट वी0वी0, भारत में आर्थिक परिवर्तन और नीति की छवि (1800—1960 बम्बई, 1963, पृष्ठ 51)

और मध्य 60 वीं दशक में प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा था। 1947 में निर्यात में विश्व व्यापार लगभग 50 बिलियन डालर कमाया था, और इसमें भारत का भाग लगभग 12 मिलियन डालर था, जो कि विश्व व्यापार का 2.4% है।¹

वर्ष 1951 से योजना काल के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम दशक में हमारे कुल आयात 7947.3 करोड़ रुपये तथा कुल निर्यात 5541.6 करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार इस दशक में कुल 2405.7 करोड़ का घाटा हुआ। यद्यपि सरकार ने इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिए वर्ष 1957 में कठोर आयात नीति की घोषणा की किन्तु व्यापार शेष की प्रतिकूलता को रोक नहीं जा सका।

आजादी के दूसरे दशक में देश में जहाँ वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ वहीं वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ-साथ देश को बाढ़ एवं सूखा की विमिषिका को भी झेलना पड़ा। फलतः आयात को हतोत्साहित तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आजाद देश में पहली बार 6 जून 1966 को रुपये का 36.5% का अवमूल्यन करना पड़ा। इस अवमूल्यन का तात्कालिक लाभ यह रहा कि वर्ष 1966 के बाद हमारे व्यापार शेष 1970-71 तक लगातार घटते रहे यह क्रमशः वर्ष 1966-67 में 806 करोड़ से घटकर 1967-68 में 788 करोड़, वर्ष 1968-69 में 373 करोड़ तथा 1969-70 में 169 करोड़, वर्ष 1970-71 में मात्र 99 करोड़ तक पहुँच गया। पुनः अगले वित्तीय वर्ष 1971-72 में हमारे व्यापार शेष में बढोतरी हो कर 216 करोड़ हो गया, किन्तु अगले ही वर्ष 1972-73 में हमारे व्यापार शेष अनुकूल होकर 173 करोड़ के लाभ में हो गया। इस प्रकार सरकार ने भारतीय विदेशी व्यापार के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए और सरकार ने निर्यात सम्बर्द्धन के लिए कई कदम उठाये। इन उपायों के अन्तर्गत अवमूल्यन के साथ-साथ उदारीकृत निर्यात नीति, सस्थागत नीतियों की मजबूती, विभिन्न सम्बर्द्धन योजनाओं को चलाना और निर्यात सम्बर्द्धन सगठन की स्थापना करना एवं प्रोत्साहन देना आते हैं। परिणाम स्वरूप वार्षिक औसत निर्यात में 753 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस अवधि के दौरान स्वतंत्र वाणिज्य मन्त्रालय पर नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय की स्थापना, व्यापार नीति और सम्बर्द्धन कार्यों को देखने के लिए तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गयी। इन सबके बाद भी हमारा औसत वार्षिक घाटा 509.5 करोड़ रुपये का था, क्योंकि हमारा कुल निर्यात 9459 करोड़ तथा आयात 14580 करोड़ रुपये रहा। चीन एवं पाकिस्तान से हुए

¹ पटेल, आई0जी0 भारत का भुगतान सन्तुलन, विदेशी व्यापार पुनर्दृष्टि की एक समालोचना, भारती विदेशी सस्थान, नई दिल्ली, वाल्यूम XVI, 1981 पृष्ठ 212-214

युद्ध के कारण इस अवधि के दौरान अत्यधिक मात्रा में रक्षा सामग्री का आयात करने तथा साथ ही बाढ़ एवं सूखा की बजह से खाद्यान्नों का भी आयात करने से हमारे अर्थव्यवस्था को यह धक्का लगा।

सत्तर के दशक में भारतीय सरकार ने पहली बार निर्यात की आवश्यकता का अनुभव किया और एक धनात्मक नीति का सूत्रीकरण किया। जिसका नाम निर्यात नीति हल 1970 रखा गया और संसद में पेश किया गया। अपने देश के निर्यात के इतिहास में यह हल एक सीमा चिह्न की तरह है। ये नीतियाँ सावधानी पूर्वक लागू की गईं।

1973 में तेल की कमी से देश के निर्यात प्रभाव में अवनति हुई। तेल कमी के अलावा पॉंचवी योजना के दौरान परिस्थित पहले, दूसरे, तीसरे योजना की तुलना में अच्छी थी। निर्यात आय, आयात आय के 86% के बराबर थी। पॉंचवे योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1974-75 में 3,329 करोड़ रुपये और 1977-78 में 5,408 करोड़ रुपये के बीच में था। आजादी के बाद 1976-77 के दौरान दूसरी बार देश ने 68 करोड़ रुपये का व्यापार लाभ उठाया। पॉंचवी योजना के दौरान विपरीत व्यापार सन्तुलन 612 करोड़ रुपये 1977-78 में 1,190 करोड़ रुपये तथा 1975-76 में 1223 करोड़ रुपये के मध्य रहा।

1987-90 के दौरान भारत का निर्यात प्रदर्शन 1978-79 के 5,726 करोड़ तक आँका गया, जो पिछले वर्ष में 65% अधिक था। 1979-80 में निर्यात की रकम 6,418 करोड़, 121% बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करती है। पॉंचवी योजना के पहले तीन साल के दौरान हुए प्रगति दर सीमा जो कि 1931% और 31% के बीच था, उसकी तुलना में यह वार्षिक वृद्धि बहुत कम था। दो वर्षों के दौरान धीमी प्रगति और देश के प्रमुख निर्यात ब्याज के उत्पाद में वास्तविक गिरावट आ गयी। इस दशक (1970-1980) में कुल आयात 44,710 करोड़ रुपये का तथा निर्यात 37,743 करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार इन वर्षों में देखा जाय तो वर्ष 1972-73 व 1976-77 की व्यापार अनुकूलता के बाद भी व्यापार शेष पिछले दो दशकों से ज्यादा प्रतिकूल रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्षों के दौरान व्यापार घाटा लगभग 5,000 करोड़ रुपये हो गया। इस योजना के दौरान सबसे कम घाटा, इसके अन्तिम वर्ष (1984-85) में 5,390 करोड़ रुपये हुआ। औसत वार्षिक घाटा इस योजना के दौरान 5,716 करोड़ रुपये का रहा। इस अवधि के दौरान निर्यात आय केवल आयात के 60% ही हो सकी, और छठी योजना के दौरान व्यापार घाटा बहुत ज्यादा रहा। इस योजना अवधि के दौरान सी0एन0पी0 के द्वारा दिखाए गये घाटे के प्रतिशत से बाजार में कमी आयी। यह कमी 1980-81 में 51% से 1983-84 में 34% हो गयी। इस योजना अवधि के दौरान कच्चा तेल एक प्रमुख निर्यात वस्तु

के रूप में सामने आया। कच्चे तेल का निर्यात 1981-82 में 211 करोड़ रुपये से 1982-83 में 1,157 करोड़ रुपये व 1983-84 में 1,400 करोड़ रुपये और 1984-85 में 1,817 करोड़ रुपये बढ़त हासिल कर ली।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (1985-86 से 1989-90) कांग्रेस (ई) सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति की तरफ जनता दल सरकार ने भी कदम बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत वार्षिक निर्यात केवल 17,382 करोड़ रुपये तक पहुँच पाया, और 7,730 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक घाटा पैदा हो गया। सातवें योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1985-86 में 10,895 करोड़ रुपये और 1989-90 में 27,658 करोड़ रुपये के बीच रहा। इतना भारी व्यापार घाटा उत्पन्न हो जाने के कारण भारत सरकार को मजबूर हो कर विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 करोड़ डालर का ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र भेजना पड़ा। भारत सरकार ने बढ़ते हुए आयात को रोकने के लिए आयात लाइसेन्सों की उदार नीति पर अकुश लगाया। आजादी के इस चौथे दशक में देश का कुल व्यापार 3,54,721 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयात 2,19,300 करोड़ रुपये तथा निर्यात 1,35,421 करोड़ रुपये रहा। इस प्रकार इस अवधि में कुल व्यापार शेष 8,3879 करोड़ रुपये रहा। इस अवधि में हमारे व्यापार असन्तुलन का मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थों व खाद्यान्नों के मुल्यों में वृद्धि का रुख जारी रहना तथा कांग्रेस (ई) व जनता दल सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाया जाना रहा।

आजादी के पाँचवें दशक के प्रारम्भिक वर्ष 1990-91 में हमारा व्यापार घाटा 10,645 करोड़ रुपये का रहा, लेकिन हमारी सरकार के निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास के कारण निर्यात बढ़कर 32,553 करोड़ रुपये का हो गया इस दौरान निर्यात में 153% की वृद्धि हुई। 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा 3,810 करोड़ रुपये का रहा। निर्यात में 425% की गिरावट आयी। 1991-92 में 44,041 करोड़ रुपये का निर्यात तथा आयात 47,851 करोड़ रुपये रहा। सरकार ने नई व्यापार नीति में निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए। जैसे— निर्यात-आयात स्क्रिप्स की इजाजत दिया, नकद क्षतिपूर्ति आलम्बन और रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन किया, फिर भी ये सभी उपाय निर्यात को प्रोत्साहित करने में विफल रहे। 1992-93 के दौरान व्यापार घाटा 9,687 करोड़ रुपये का हुआ। हमारा विदेशी व्यापार जो वर्ष 1991-92 में 91,892 करोड़ रुपये था बढ़कर वर्ष 1993-94 में 11,7063 करोड़ रुपये व वर्ष 1998-99 में 31,7703 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह बढ़त आगे के वर्षों में भी जारी है, और हमारा व्यापार वर्ष 1999-2000 में 37,4797 करोड़, वर्ष 2000-2001 में 43,4444 व वर्ष 2001-2002 (अ)

(अप्रैल-दिसम्बर) में 33,6198 करोड़ रुपये रहा है। वर्ष 1991 से 2001 तक देश का व्यापार घाटा क्रमशः 3,810, 9,687, 3,350, 7,297, 16,325, 20,103, 24,076, 38,580, 55,675, व 27,302 करोड़ रुपये का रहा। उक्त आंकड़ों को देखने से यही ज्ञात होता है कि वर्ष 1983-84 को छोड़कर हमारा व्यापार शेष लगातार बढ़ा है। स्पष्ट है कि हमारे निर्यात उस गति से नहीं बढ़े जिस गति से हमारे आयात बढ़ रहे हैं। वाणिज्य मन्त्रालय ने सन् 2001 में 4456 बिलियन डालर के निर्यात को बढ़ाकर 2006-2007 तक 8048 बिलियन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

देश के विदेशी व्यापार की दिशा आजादी के पूर्व ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और उसके मित्र राष्ट्रों के साथ था, यह प्रवृत्ति आजादी के कुछ वर्षों तक देखने को मिलती है, क्योंकि तब तक भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पायी थी। जैसे-जैसे इन देशों के साथ राजनैतिक सम्बन्धों का विकास हुआ, वैसे-वैसे आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत होने लगे। अब स्थिति काफी बदल चुकी है और 51 वर्षों के आयोजन के बाद व्यापारिक सम्बन्ध काफी बदल चुके हैं, हमारा विदेशी व्यापार किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित नहीं है, जैसा कि स्वतन्त्रता के समय था, बल्कि विकेन्द्रित है। अपने विदेशी व्यापार की पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका पर से निर्भरता धीरे-धीरे घट रही है, और पूर्वी यूरोप के देशों विशेष रूप से यू0एस0एस0 आर0, जर्मनी आदि तथा आसियान देशों जैसे- जापान तथा ओपेक देशों से हमारा विदेशी व्यापार बढ़ रहा है। इस प्रकार पहले की अपेक्षा अब निर्यात के लिए अधिक बाजार तथा आयात के लिए अधिक स्रोत खुले हैं। इससे एक बात यह भी सामने आती है कि भारत का विदेशी व्यापार ओपेक देशों, जापान, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका देशों में बढ़ सकता है।

1950-51 में भारत के आयातों में इंग्लैण्ड का हिस्सा 20.8% तथा अमरीका का 18.3% था, अर्थात् दोनों देशों का कुल हिस्सा मिलाकर 39.1% था। एक दशक के भीतर ही पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए जाने के कारण इंग्लैण्ड और अमरीका की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, तथा अमरीका प्रथम स्थान पर आ गया। एक दो वर्षों को छोड़ दिया जाय तो अमरीका की यह स्थिति लगातार बनी रही, और सर्वाधिक आयात अमरीका से ही किया गया है। जापान, जर्मनी तथा सोवियत संघ से व्यापारिक सम्बन्धों के विस्तार होने के साथ इंग्लैण्ड पर निर्भरता कम होती गयी। वर्ष 1960-61 में भारत के आयातों में इंग्लैण्ड का हिस्सा 19.4% था जो कम होते-होते 2000-2001 में 6.3% रह गया। दूसरी ओर जापान का आयात व्यय में हिस्सा 1950-51 में 1.5% से बढ़कर वर्ष

1995-96 में 67% तक पहुँच गया था, किन्तु भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण 13 मई 1998 को अमेरिका द्वारा लगाये प्रतिबन्धों के कारण आयात हिस्सा पुनः कम होकर वर्ष 2000-2001 में 36% रह गया है। हाल के वर्षों में भारत कई क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग किया है जिससे उस देश के आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह रहा कि समाजवादी देशों, विशेष तौर पर भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में तेजी से वृद्धि हुई। 1950-51 में सोवियत संघ से आयात नगण्य था 1960-61 में मात्र 16 करोड़ रहा, किन्तु उसके बाद आयातों में तेजी से वृद्धि हुई और उसका हिस्सा वर्ष 1960-61 में 14% से बढ़ कर 1970-71 में 65% तक पहुँच गया, तथा कई वर्षों में भारत के आयातों में अमेरिका के बाद सोवियत संघ का दूसरा स्थान रहा। तत्पश्चात् 1984-85 में आयातों में सोवियत संघ का हिस्सा 104% हो गया तथा उसने अमेरिका को विस्थापित कर प्रथम स्थान ले लिया। पुनः परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 1985-86 में अमेरिका प्रथम जापान द्वितीय तथा सोवियत संघ तृतीय स्थान पर पहुँच गया। आज वर्तमान समय में सोवियत संघ विघटन के कारण भारत के आयात में उसका हिस्सा 1960-61 में 14% से कम होकर 2000-2001 में मात्र 100% रह गया है। जबकि अमेरिका आज भी अपनी पूर्व स्थिति प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वर्ष 2000-2001 में आयातों में 56% की गिरावट आयी है इसी प्रकार पूर्वी यूरोप, ओपेक क्षेत्र तथा विकासशील देशों से आयातों का हिस्सा उक्त वर्ष के दौरान क्रमशः 13%, 51% तथा 175% पर कम था।¹ तदनुसार आयातों की अवशिष्ट श्रेणी से कुल आयातों के हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई थी। उक्त वर्ष के दौरान उच्चतर स्तरों पर कच्चे तेल की कीमतों की सापेक्षिक स्थिरता अवशिष्ट गतव्यों से आयातों के हिस्से में वृद्धि के साथ-साथ ओपेक क्षेत्र से दूर तेल आयातों के उद्गम में परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। ओईसीडी क्षेत्र में कुल आयातों में आयात का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान 383% तक और गिर गया, बावजूद इसके कि उन देशों जैसे — फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से अप्रैल-अक्टूबर, 2001 के दौरान आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ हुई थी, जबकि पूर्वी यूरोप का हिस्सा कायम रखा गया है, ओपेक और विकासशील देशों के आयातों के हिस्से क्रमशः 57% तथा 191% तक बढ़ गये। चुनिंदा पूर्वी एशियाई देशों से आयातों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान लगभग 12% पर स्थिर रहा।

¹ आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001-02

हमारे निर्यातो की दिशा में 1950-51 में योजना प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व इंग्लैंड का हिस्सा कुल निर्यात में 23.3% था जो 1970-71 में ही गिर कर 11.1% तथा वर्ष 2000-2001 तक आते आते मात्र 5.2% रह गया है। अमेरिका का भारतीय निर्यात में हिस्सा वर्ष 1950-51 में 19.3% तथा 1960-61 में 16.0% था, इस प्रकार यह दूसरे स्थान पर था। स्पष्ट है कि भारत का निर्यात हिस्सा क्रमशः 42.6% तथा 43.00% इंग्लैंड तथा अमेरिका के साथ था। व्यापारिक सम्बन्ध अविकसित रहने के कारण अन्य देशों के साथ निर्यात आय में योगदान कम था। किन्तु 1960-61 के पश्चात् व्यापारिक सम्बन्धों में तेजी से परिवर्तन हुआ जहाँ सोवियत संघ को 1950-51 में 11 करोड़ के स्थान पर 1970-71 में 210 करोड़ तथा 1985-86 में 2,006 करोड़ का निर्यात किया गया। भारत के निर्यात आय में वर्ष 1985-1986 में इसका प्रथम स्थान, अमेरिका का द्वितीय, तीसरा जापान, चौथा इंग्लैंड तथा पाँचवा स्थान पश्चिमी जर्मनी का था। पुनः स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप 1989-90 तक अमेरिका का प्रथम स्थान, सोवियत संघ का दूसरा तथा जापान का तीसरा स्थान रहा। वर्ष 1990-91 में 16.1% के निर्यात हिस्सेदारी के साथ सोवियत संघ का प्रथम स्थान तथा 14.7% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी देशों में हो रही उथल-पुथल के कारण तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण, पूर्वी यूरोप को किए जाने वाले निर्यात में भारी कमी हुई है। सत्र 2000-2001 में रूस का भारतीय निर्यात में मात्र 2.0% का हिस्सेदारी रहा है। उक्त वित्तीय वर्ष में अमेरिका का प्रथम, इंग्लैंड द्वितीय जर्मनी तृतीय, जापान चतुर्थ एवं बेल्जियम पंचम स्थान पर रहा। इस वर्ष में निर्यात की दिशा में उन गन्तव्यों जैसे— ओईसीडी, ओपीडीसी तथा एशिया, अफ्रीका, लैटिन, अमेरिका में विकाशील देशों को भारत के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ दर्शाईं। विकासशील देशों के मध्य लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्रों को निर्यात 50.0%, अफ्रीकी क्षेत्र को 27.1% तथा एशियाई क्षेत्र को 23.8% बढ़ गये हैं। तथापि पूर्वी यूरोप के निर्यातों में वर्ष 2000-2001 में पिछले वर्ष के 24.7% की वृद्धि की तुलना में 3.8% की गिरावट दर्ज की गयी। कुल निर्यात में क्षेत्र वार हिस्से के सम्बन्ध में जिस समय OECD तथा पूर्वी यूरोप के हिस्से में वर्ष 2000-2001 में गिरावट आयी, वहीं ओपेक तथा अन्य विकासशील देशों के हिस्से में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई। OECD देशों को कुल निर्यातों के हिस्से में आयी गिरावट के बाद भी इस क्षेत्र में विकसित देशों जैसे, फ्रांस, यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम तथा जापान के निर्यातों में उक्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य देशों में एशिया, अफ्रीका, तथा लैटिन अमेरिका के विकसित देशों जिनमें थाइलैंड, मलेशिया,

चीन, श्रीलंका, सिंगापुर, बंगलादेश, मिस्र, केन्या नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको तथा चिली शामिल हैं, के निर्यातों के हिस्से में योगदान किया।

OECD क्षेत्र को निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 2001 के दौरान पिछले वर्ष की सगत अवधि में 13.8% की वृद्धि की तुलना में इस क्षेत्र में साधारण मंदी को दर्शाते हुए 12.8% की महत्वपूर्ण कमी हुई। इस क्षेत्र के बड़े देशों जिनमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, तथा यू0के0 शामिल हैं, के निर्यातों में गिरावट देखी जा सकती है। वर्ष 2001-2002 में यू0के0, बेल्जियम, जर्मनी तथा जापान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। तथापि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान स्विटजरलैंड पाँचवें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2000-2001 तथा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पहले सात महीनों के दौरान लगभग 26% बढ़ गयी। वर्ष 2000-2001 के दौरान जहाँ चीन को अमेरिकी डालर मूल्य में हमारे निर्यात 53.9% बढ़े, वही चीन से आयात 14.1% से अधिक थे। अप्रैल-अक्टूबर 2001 के दौरान जहाँ निर्यात 20.5% बढ़े, वही चीन से आयात 29.3% बढ़े। दूसरी तरफ भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि मुख्यतः नेपाल को हमारे निर्यात में 6.9% की कमी के कारण वर्ष 1999-2000 में 30.2% से घट कर वर्ष 2000-2001 में 16.8% हो गयी। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अब तक जहाँ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई वहाँ नेपाल से आयात हमारे 57.7% बढ़े हुए निर्यात की तुलना में 85.1% बढ़ गया है। व्यापार सम्बन्धी भारत-नेपाल संधि में उचित संशोधन परिवर्तन घरेलू उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए विचाराधीन है। 5 दिसम्बर, 2001 से तीन महीनों की एक अवधि के लिए संधि के सीमित विस्तार पर सहमति हो चुकी है, ताकि संधि की वार्ताएँ निष्पादित की जा सकें। निर्यात के नये आयामों में वर्तमान समय में विशेषकर उदारीकरण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात् भारत के आयात निर्यात में कई नये महत्वपूर्ण आयाम जुड़े हैं। चूँकि हमारा निर्यात बढ़ाने पर अधिक जोर है, न कि आयात पर। इस लिए निर्यात के महत्वपूर्ण नये आयामों को हम देखें तो उसमें कृषि उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, फल, फूल, कम्प्यूटर के नये क्षेत्र, सेटेलाइट एव मिसाइल आदि महत्वपूर्ण हैं। कृषि उत्पादों में वर्ष 1998-99 में 2,919 मिलियन अमेरिकी डालर आयात की तुलना में निर्यात 6,037 मिलियन अमेरिकी डालर, वर्ष 1999-2000 में 2,858 मिलियन अमेरिकी डालर आयात की तुलना में निर्यात 5,608 मिलियन अमेरिकी डालर तथा वर्ष 2000-2001 में कृषि उत्पाद आयात 1,858 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में कुल कृषि उत्पाद निर्यात 6,004 मिलियन अमेरिकी डालर रहा। वर्तमान समय में भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा गेहूँ निर्यातक देश बन गया है। गेहूँ

के विश्व कारोबार में गिरावट के बावजूद इस समय करीब 20 देश भारत से गेहूँ का आयात कर रहे हैं।¹

कम्प्यूटर के क्षेत्र में भी असीम सम्भावनाएँ हैं क्योंकि इस समय पूरे विश्व की नजर भारतीय कम्प्यूटर उद्योग पर टिकी हुई है। कच्चे माल तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के साथ-साथ भारत में कुशल तकनीकीविदों की भरमार है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सन् 2003 तक प्रत्येक स्कूल, पॉलीटेक्नीक कालेज, और विश्व विद्यालयों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराने तथा अगले पाँच वर्षों में विदेशी व्यापार की दृष्टि से साफ्टवेयर विकास में 60% वृद्धि की आशा की गयी है। जिसमें सन् 2008 तक प्रतिवर्ष 50 अरब अमेरिकी डालर के साफ्टवेयर निर्यात आय प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस प्रकार बिल गेट्स के अनुसार यह बतावरण भारत को साफ्टवेयर के क्षेत्र में सुपर पावर बना देगा। वर्तमान में हमारा साफ्टवेयर निर्यात लगभग शतप्रतिशत के हिसाब से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था में नम्बर एक अमरीका व अर्थव्यवस्था नम्बर दो जापान को हम साफ्टवेयर का निर्यात कर रहे हैं। वर्ष 1994-95 में 26 करोड़ रुपये साफ्टवेयर के निर्यात के स्थान पर वर्ष 1999-2000 में 400 करोड़ रहा, वही हमारा हार्डवेयर निर्यात जो 1999-2000 में 600 करोड़ का था 2000-2001 में 1250 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।²

विश्व के कठिनतम बजारों में से एक यूरোपियन यूनियन में बी० पी० एल०, विडियोकॉन एव ओनिडा द्वारा हाल में 15 लाख टी० वी० सेट निर्यात करने का आदेश प्राप्त हुआ है। हमारी विश्व प्रसिद्ध दवा कम्पनियाँ, रैनवैक्सी एव डा० रेड्डीज लैब, जीवन रक्षक दवाईयों अन्य विदेशी कम्पनियों की तुलना में आधे दाम पर आपूर्ति करने में सक्षम हैं। जहाँ तक सेटेलाइट क्षेत्र की बात है तो उसमें भी हम सेटेलाइट पार्ट्स एव पद्धति, अमरीका एव यूरोप जैसे देशों को निर्यात कर रहे हैं। निर्यात बजार की सूचनाएँ भी हम सेटेलाइट के द्वारा निर्यात करने जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत एव रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एव सफल परीक्षित मिसाइल "ब्रह्मोस" हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यथाशीघ्र लाने जा रहे हैं। हाल के वर्षों में निर्यात आयात नीति में कई प्रकार के उपायों का उल्लेख किया गया है। कुछ कर रियायतें दी गई हैं, कुछ कार्यप्रणालियों को मुक्ति युक्त बनाने का प्रयास किया गया है, मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा दिए गये

¹ दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दिनांक 7.7.2002

² डा० ए०ए० सिद्दीकी, इण्डियाज न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट, लिविंग थ्रु एक्सलेन्स एण्ड वियान्ड, मोती लाल नेहरू रिजनल कालेज इ० वि०, इलाहाबाद-2002

है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। इन सब उपायों से यह आशा की जाती है कि दसवी योजना के दौरान निर्यात में 11.9% की औसत वार्षिक वृद्धि होगी और वे सन् 2007 तक बढ़कर 80 अरब यू0एस0 डालर के स्तर पर पहुँच जाएंगे। यह एक अभिनन्दनीय पहल है। इस नीति का एक और सकारात्मक लक्षण अफ्रीका के देशों पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि अफ्रीका के देशों को होने वाले भारतीय निर्यात को बढ़ावा प्राप्त हो सके। इस पहल से सम्भवतः भारतीय निर्यात इस बढ़ते हुए बाजार में प्रवेश कर सकेंगे जिसकी अभी तक उपेक्षा की जा रही थी।

एक और महत्वपूर्ण पहल जिसका उल्लेख करना अनिवार्य है, वह है भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएँ खोलने की अनुमति देना। इसका उद्देश्य निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय दरो पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त उपलब्ध कराना है। इससे निर्यातकों के लिए उधार की लागत कम हो जाएगी और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। यह पहल जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रित किया जाएगा, इस नीति का एक और अभिनन्दनीय पहलू है।

किन्तु आलोचकों ने इस निर्यात आयात नीति के सन्दर्भ में कई मुद्दे उठाये हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है। चाहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री मारन ने 11.9% औसत वार्षिक निर्यात का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों के लिए रखा है, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या दशवी योजना में समस्त देशीय उत्पाद की औसत 8% वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए यह लक्ष्य प्रयाप्त है? दशवी योजना के लिए 14-15% औसत वार्षिक निर्यात दर प्राप्त करने के लक्ष्य का सुझाव दिया गया है। अतः निर्यात आयात नीति (2002-2007) द्वारा निर्धारित लक्ष्य दसवी योजना की आवश्यकता के लिए नाकाफी है। दूसरे 1991-2000 के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.8% रही और इस कारण 11.9% के लक्ष्य को मर्यादित ही कहा जा सकता है और किसी भी दृष्टि से "साहसपूर्ण" की सजा नहीं दी जा सकती।

निर्यात नीति, कृषि के निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है, और इस कारण यह गेहूँ के निर्यात को बढ़ाना चाहती है, ताकि देश में 1 जनवरी 2002 तक एकत्रित 580 लाख टन के विशाल वफर स्टॉक को कम किया जा सके। सरकार के सामने दो विकल्प हैं— एक तो यह कि खाद्यान्नों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाय और दूसरा इस खाद्यान्न का प्रयोग रोजगार के लिए खाद्य कार्यक्रम में प्रयोग किया जाय, और इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम में रोजगार कायम किया जाए। यह बात अत्यन्त निराशाजनक है कि भारतीय खाद्य निगम गेहूँ को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पशुओं के चोर के रूप में मिट्टी के भाव पर बेच रहा है। प्रश्न उठता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त गेहूँ की किस्म इतनी घटिया क्यों है? जबकि

सरकार साल दर साल किसानों के लिए गेहूँ के समर्थन मूल्य में वृद्धि करती रही है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों में भारी भ्रष्टाचार विद्यमान है। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य सरकार को खाद्यान्न उठाने के लिए राजी करने में विफल हुई है, और यह बात सर्वविदित है कि जहाँ सन् 2000-2001 में 2855 लाख टन चावल और गेहूँ का आवटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया गया, वहाँ राज्य सरकारों द्वारा केवल 72 लाख टन उठाया गया अर्थात् आवटन का केवल 41%। इसका मुख्य कारण खाद्यान्नों की ऊँची कीमत निश्चित करना था, और यह नीति विवेकहीन थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने खुले बाजार से खाद्यान्नों को खरीदने में तरजीह दी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपलब्ध होने वाले घटिया अनाज को नकार दिया। यदि सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहती है तब इसे गेहूँ और चावल की किस्म को उन्नत करने की ओर ध्यान देना होगा ताकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त की जा सके सके।

सरकार 2001 में चालू किए गये कृषि निर्यात क्षेत्रों की अवधारणा को और आगे बढ़ाना चाहती है। उद्यान आधारित कृषि उत्पादों के लिए 20 ऐसे क्षेत्रों को स्वीकृति दी गयी है। सरकार ताजा एवं ससाधित फलों, सब्जियों, दुग्ध एवं पुष्प तथा गेहूँ एवं चावल के निर्यात के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। यह प्रत्याशा की जाती है कि परिवहन सुविधा से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सरकार को परिवहन सुविधा को एक प्रभावी उपकरण मान कर इस पर निर्भर रहना चाहिए, या इस समस्या के अधिक स्थिर और टिकाऊ समाधान के लिए कुशल परिवहन प्रणाली का विकास करना चाहिए। जाहिर है कि परिवहन सुविधा, एक कुशल परिवहन प्रणाली का प्रतिस्थापक नहीं बन सकता।

अपने कृषि उत्पादों के लिए ऊँची कीमत प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य-ससाधन पर बल दिया जाय। इस उद्देश्य के लिए खाद्य-प्रसस्करण के लिए एक अलग मन्त्रालय कायम किया गया, परन्तु अभी तक इस मन्त्रालय का कार्य पूरी तरह निराशाजनक रहा है। कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि 15-20 प्रतिशत रही है जबकि यह विकसित देशों में शत प्रतिशत से भी अधिक है। भारत के खाद्य प्रसस्करण द्वारा मूल्य वृद्धि को बढ़ाने की ओर प्रयास करना चाहिए।

निर्यात-आयात नीति में विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर भारी बल दिया गया है, जो कि पहले प्रोन्नत किए जा रहे निर्यात-प्रोन्नति क्षेत्र और निर्यात प्रेरित इकाईयों का ही नया स्वरूप हैं।

परन्तु निर्यात-प्रोन्नति क्षेत्रों और निर्यात प्रेरित इकाईयों का अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है। ये दोनों मिलाकर कुल निर्यात का 12 प्रतिशत कारोबार करते हैं। बहुत सी कार्यविधि सम्बन्धी अडचनों के कारण बेहतर निष्पादन दिखा नहीं पाये। यह अधिक वाछनीय होगा, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अत्यधिक अधिकारतन्त्रीय रुकावटें खड़ी न की जाएं और उन्हें निर्यात-बजारों में प्रवेश के लिए समर्थन दिया जाय। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि चीन में विशेष निर्यात क्षेत्रों द्वारा कुल निर्यात का 40% निर्यात किया जाता है। भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निष्पादन को उन्नति करने के लिए सबक लेना चाहिए। निर्यात-आयात नीति में कुटीर तथा हस्ताशिल्प क्षेत्र और लघु-स्तर क्षेत्रों के लिए जो कि देश के कुल निर्यात में 35% योगदान देते हैं, कुछ रियायतें दी गयी हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नीति में इस क्षेत्र के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् बैंक उधार का विस्तार करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि उदारीकरण-उपरान्त काल में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए उधार उपलब्ध कराने पर कम बल दिए जाने के परिणामस्वरूप, लघु स्तर इकाईयों को पर्याप्त मात्रा में उधार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसमें सशोधन होना चाहिए।

निर्यात-आयात नीति (2002-2007) में कुछ पहले चल रही रियायतें एव राहते कायम रखी गयी हैं। ये हैं शुल्क अर्हता पासबुक स्कीम, अग्रिम लाइसेन्स, निर्यात सवर्धन पूजी वस्तु स्कीम। इन योजनाओं का मूल आधार यह है कि यदि निर्यातक इन आयातित आदानों का प्रयोग करता है तो इसे ये शुल्क मुक्त प्राप्त होने चाहिए। परन्तु इन सभी रियायतों और प्रोत्साहन के बावजूद 2001-02 में हमारे निर्यात में केवल 15% नाम मात्र वृद्धि ही हो पायी। 1991-2000 की अवधि के दौरान आयात की वृद्धि दर निर्यात वृद्धि दर की अपेक्षा ऊँची रही है। इसका तात्पर्य यह है कि विदेशी भारतीय बाजार में प्रवेश करने में अधिक सफल हुए हैं, और इसकी तुलना में भारतीय विदेशी बाजारों में अपेक्षाकृत कम प्रवेश कर पाये हैं। अतः जब तक केन्द्र एव राज्य सरकारें बन्दरगाहों पर वस्तुओं की गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार संरचना को उन्नत नहीं करती, तब तक इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इस नीति में गैर तराशे हीरो पर सीमा शुल्क हटा कर इन्हें शुल्क-मुक्त कर दिया गया है। परन्तु यदि हम रत्नों एव आभूषणों के कुल निर्यात में इनके शुद्ध निर्यात का परीक्षण करें तो यह पता चलता है कि इनका भाग 1995-96 में 60.1% से कम होकर 1999-2000 में 28% हो गया

और फिर थोड़ा सा उन्नत होकर 34.9% हो गया। इससे यह बात रेखांकित होती है कि केवल आयात शुल्क में कोटौती से इनके निर्यात को आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा।¹

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि केवल वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय ही निर्यात को बढ़ाने के लिए उचित वातावरण कायम नहीं कर सकता। इसके लिए उसे ऊर्जा मन्त्रालय एवं परिवहन मन्त्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि निर्यात के लिए माल की दुलाई में विलम्ब को कम किया जा सके। इसी प्रकार वाणिज्य मन्त्रालय को, वित्त मन्त्रालय को इस बात के लिए राजी करना होगा, कि आधार संरचना विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराये। न कि केवल केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपने निर्यात बढ़ाने के उपायों में तालमेल बिठाना होगा। यह उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाए। इसके लिए निर्यात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में सुधार करना होगा और एक कुशल आधार संरचना का विकास करना होगा। निर्यात-आयात नीति (2002-2007) का केन्द्र बिन्दु शुल्क कोटौती और कुछ रियायतों को उपलब्ध कराने तक सीमित रहा है, इसकी सफलता के लिए इसका विस्तार करना होगा।

भारत में दवा में काम आने वाले पौधों की संख्या 80 हजार से भी अधिक है और हम इन पौधों के निर्यात में विश्व में नम्बर एक पर आ सकते हैं, परन्तु हमारा यह निर्यात विश्व में ऐसे पौधों के निर्यात का केवल 2.5% है, जबकि केवल चीन का हिस्सा 40% है।² इसी प्रकार कृषि निर्यात में भी इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना आवश्यक होगा। उसके लिए नई तकनीकों का प्रयोग आवश्यक होगा। उदाहरणार्थ अमरीका में खेतों का औसत आकार 1.23 हेक्टेयर है, और चावल का औसत उत्पादन 5500 किलोग्राम है जबकि जापान में यह संख्या क्रमशः 2 हेक्टेयर व 6300 किलोग्राम है। इन सब के साथ हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी और ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस क्षेत्र में असीम सम्भावनाएँ हैं। अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रमाणीकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना आवश्यक है, तभी हम यूरोपियन संघ जैसे देशों में जहाँ ISO 9000 जैसे प्रमाण पत्र आवश्यक है, में प्रवेश कर पायेंगे। जिन देशों में भारतीय मूल के निवासी अधिक रहते हैं वहाँ हमारा निर्यात तुलनात्मक रूप से अधिक है। फिक्की द्वारा 22 देशों के अध्ययन से यह सूचना प्राप्त की गयी है। अतः ऐसे देशों में अपना निर्यात बढ़ाने के कदम अधिक कारगर हो सकते हैं।

¹ रुद्र दत्त (अर्थ चर्चा) राष्ट्रीय सहारा 1 मई 2002, पृष्ठ संख्या 8।

² डा० ए०ए० सिद्दीकी, इण्डियाज न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट, लिविंग थ्रु एक्लेन्स एण्ड वियान्ड, मोतीलाल नेहरू रिजनल कालेज, इ०वि०वि० इलाहाबाद-2002।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

पुस्तके

- ✍ अग्रवाल, डॉ० एस०एस० एव डॉ० सी० एस० बरला "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा - 3।
- ✍ अग्रवाल अमरनाथ एव लाल कुन्दन "आर्थिक आयोजन के सिद्धांत" द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।
- ✍ अग्रवाल ए० एन० "पोजिशन एण्ड प्रास्पेक्ट्स आफ इण्डियाज फारेन ट्रेड" ए सर्वे आई ट्रेड कमीशनर्स चण्डीगढ़।
- ✍ काली पांडा देव "एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया" सुल्तान चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।
- ✍ कृष्ण बाल "कामर्सियल रिलेशन, विटविन इण्डिया एण्ड इंग्लैंड" (1601 से 1757), लन्दन।
- ✍ कृष्ण मनमोहन "नव आर्थिक व्यवस्था एव आर्थिक संगठन" हेराईजन पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
- ✍ गुर्तू डॉ० डी० एन० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" कालेज बुक डिपो जयपुर।

- ✍ गोपाल बाल टी० ए० एस० "निर्यात प्रबन्धन" हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई ।
- ✍ गोवल एच० "द थियरी आफ फ्री इकोनामिक्स एक्टवीटी जोन्स" सीमेन प्रेस यूनिवर्सिटी मीमको ।
- ✍ चिस्ती सुमीत्रा इण्डियाज टर्मस आफ ट्रेड" ओरियेन्ट लगमेन लि० नई दिल्ली ।
- ✍ जालान विमल "भारत की अर्थ नीति" राज कमल पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
- ✍ जालान विमल "भारत का आर्थिक सकट" नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली ।
- ✍ जालान विमल "इण्डियाज इकोनोमिक पॉलिसी प्रिपेरिंग फार द 21वीं सेचुरी" पेग्विन पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
- ✍ जैन प्रो० पी० के० "भारतीय अर्थव्यवस्था" विशाल प्रकाशन मन्दिर, मेरठ-2 ।
- ✍ जैन डॉ० जे० के० "क्रियात्मक प्रबन्ध" प्रतीक प्रकाशन इलाहाबाद ।
- ✍ जैन पी० सी० "भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति" हन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

- ✍ झिगन डॉ० एम० एल० "विकास का अर्थशास्त्र एव आयोजन" बृदा पब्लिसिंग प्रा० लि०, दिल्ली - 91 ।
- ✍ दत्त रूद्र एव के० पी० एम० सुन्दरम् "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लि० रामनगर, नई दिल्ली - 5 ।
- ✍ देवराज विवेक फारेन ट्रेड पालिसी चेजेज एण्ड डेवैल्यूशन करेन्ट परसपेक्टिव, नई दिल्ली ।
- ✍ धीगरा ईश्वर "भारतीय अर्थव्यवस्था" सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, दारियागज, नयी दिल्ली ।
- ✍ नागर डॉ० विष्णुदत्त एव गुप्त डॉ० राम प्रताप "आर्थिक विकास के सिद्धांत एव समस्याएँ द मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
- ✍ नैयर दीपक "इण्डियाज एक्सपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी, कैम्ब्रीज विश्व विद्यालय प्रेस, ब्लाकी एण्ड सन्स (इ०) लि० ।
- ✍ नैयर दीपक, एव अमित भदुडी "उदारीकरण का सच" राज कमल पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
- ✍ पटेल आई० जी० "भारत का भुगतान सन्तुलन विदेशी व्यापार पुनर्दृष्टि की एक सम आलोचना" भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, वालयूम XVI, नई दिल्ली ।

- ✍ पोपोव यू० "राजनीतिक अर्थशास्त्र प्रवेशिका विकासमान देश" प्रगति प्रकाशन, पिपुल्स पब्लिशिंग हाऊस (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
- ✍ प्रकाश डॉ० जे० सिन्हा डॉ० वी० सी० "भारतीय कृषि उद्योग व्यापार एव यातायात" लोक भारती प्रकाश, इलाहाबाद।
- ✍ बार्णोय डॉ० जी०सी० एव डॉ० शर्मा "विकास का अर्थशास्त्र एव नियोजन" साहित्य भवन, आगरा।
- ✍ भगवती जगदीश एन० एव देशी पद्मा "प्लानिंग फार इंडस्ट्रीलाइजेशन, इंडस्ट्रीलाइजेशन एण्ड ट्रेड" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन।
- ✍ मेमोरिया डॉ० चतुर्भज एव जैन डॉ० एम० सी० "भारतीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन आगरा।
- ✍ मिश्र जगदीश नारायण "भारतीय अर्थव्यवस्था" किताब महल, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
- ✍ मिश्र डॉ० एस० के० एव बी० के० पूरी "भारतीय अर्थव्यवस्था" हिमालय पब्लिसिंग हाऊस, मुम्बई - 4।
- ✍ लाल डॉ० एस० एन० "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लोक वित्त" शिव पब्लिसिंग हाऊस, इलाहाबाद।
- ✍ वर्मा डॉ० एम० एल० "इन्टरनेशनल ट्रेड" विकास पब्लिशिंग हाऊस (प्रा०) लि० नई दिल्ली।
- ✍ वैश्य एम० सी० "मुद्रा बैंकिंग एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा० लि० नई दिल्ली - 2।

- ✍ वैश्य एम० सी० एव सिंह सुदामा "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" अक्सफोर्ड एण्ड आई० बी० एच० पब्लिशिंग कम्पनी प्रा० लि० नई दिल्ली।
- ✍ सिधई डॉ० जी०सी० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन, आगरा - 3।
- ✍ सिद्धीकी डॉ० ए० ए० "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव प्रशुल्क नीति" प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- ✍ सिद्धीकी डॉ० ए० ए० "इण्डियाज न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू वर्ल्ड मार्केट" लिविंग थ्रु एक्लेन्स एण्ड वियान्ड, मोतीलाल रीजनल कालेज, इलाहाबाद विश्व विद्यालय इलाहाबाद।
- ✍ सिद्धीकी डॉ० ए० ए० "द कामर्स जर्नल" वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्व विद्यालय इलाहाबाद।
- ✍ सिन्हा डॉ० बी०सी० "मुद्रा बैंकिंग, विदेशी विनिमय तथा व्यापार" लोक भारती प्रकाशन, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद-1।
- ✍ सिन्हा डॉ० बी०सी० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" आक्सफोर्ड एण्ड आई०बी०एच० पब्लिशिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
- ✍ शर्मा राम शरण प्राचीन भारत एव मध्यकालीन भारत, एन० सी० ई० आर० टी०।

- ✍ शर्मा विद्यासागर "सहकारी समाज" हिन्दी प्रकाशन मन्दिर,
इलाहाबाद।
- ✍ शर्मा विद्यासागर "सहकारिता का उदय और विकास" हिन्दी
प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद।
- ✍ शाहू एल० एव बाधवा आर०के० "फारेन इन्वेस्टमेन्ट ला एण्ड पॉलिसी इन
सेलेक्ट डेवलपिंग कन्ट्रीज" इण्डियन
इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली।
- ✍ श्रीवास्तव एस० जी० पी० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" विकास पब्लिशिंग,
हाऊस प्रा० लि० नई दिल्ली।

दैनिक समाचार – पत्र

- ⇒ दैनिक जागरण, वाराणसी एव कानपुर
- ⇒ राष्ट्रीय सहरा, लखनऊ एव गोरखपुर
- ⇒ हिन्दुस्तान, लखनऊ एव नई दिल्ली
- ⇒ आज, वाराणसी
- ⇒ अमृत प्रभात, इलाहाबाद
- ⇒ अमर उजाला, इलाहाबाद एव कानपुर
- ⇒ नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद
- ⇒ जनसत्ता, नई दिल्ली

- ⇒ नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली
- ⇒ फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली
- ⇒ दि इकोनामिक टाइम्स, नई दिल्ली
- ⇒ बिजनेस स्टैण्डर्ड नई दिल्ली

रेडियो प्रसारण

वाशिगटन रेडियो, आर्थिक परिचर्चा, डा0 कावरा दिनांक 28 12 2000 समय 10 00 पी0 एम0 ।

सरकारी प्रकाशन

- * आर्थिक समीक्षा वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली,
- * वार्षिक रिपोर्ट वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली
- * योजना सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली,
- * एनूवल रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
- * सातवी पचवर्षीय योजना योजना आयोग, भारत सरकार 1985-90 Vol-1
- * रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड रिजर्व बैंक आफ इण्डिया फाइनेन्स
- * मन्थली रिव्यू स्टेट बैंक आफ इण्डिया
- * इयर बुक आफ इन्टरनेशनल यूनाईटेड नेशन्स न्यूयार्क ट्रेड स्टैटिस्टिक्स
- * इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्मेन्ट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ कामर्स वाल्यूम - 1

- * फारेन कोलोबोरेसन्स इन इन्डस्ट्री फोर्थ सर्वे रिपोर्ट आई० वी० आई० इण्डिया बम्बई
- * एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टस आफ एन० सी० ई० आर० डीजल इन्जिन्स
- * रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड इकोनामिक्स रिब्यू वाल्यूम 1 फाइनेन्स,
- * वर्ल्ड डेवपमेन्ट रिपोर्ट विश्व बैंक
- * वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- * एशियन इकोनोमिक आउलुक एशियाई विकास बैंक
- * वर्ल्ड इनवेस्टमेन्ट रिपोर्ट अकटार्ड

पत्रिकायें

- प्रतियोगिता दर्पण भारती अर्थव्यवस्था, अतिरिक्ताक, उपकार प्रकाशन, 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर आगरा - 2 ।
- यूथ कम्पिटिशन इण्डिया, 12 चर्च लेन इलाहाबाद - 2 ।
- क्रानिकल पब्लिकेशन प्रा० लि० 208-209 शिवलोक हाऊस, नई दिल्ली -1 ।
- फारेम ट्रेड बुलेटिन भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, नई दिल्ली ।
- प्रतियोगिता सम्राट दीवान पब्लिकेशन प्रा० लि० नई दिल्ली ।

- इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल दीपक नैयर समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन नई वीकली दिल्ली।
- फारेन ट्रेड रिव्यू आई० आई० टी० एफ० नई दिल्ली।
- द कामर्स जर्नल वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्व विद्यालय इलाहाबाद।
- विदेशी व्यापार – प्रवृत्तिया एव भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान, नई दिल्ली। वृत्तात